खण्ड–495, अंक–10
गुरुवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(25 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–58
तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	58–59
प्रश्नकाल की समाप्ति के उपरान्त कार्य–सूची के अवशेष प्रश्नों के उत्तर मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	59
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	59–61
जनपद मुजफ्फरनगर के प्रमुख तीर्थ शुकतीर्थ स्थल पर गंगा की पवित्र धारा का प्रवाह बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	61
नोएडा विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर–1 गुरूकुल पार्क में बाउन्ड्री तोड़कर गेट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद कानपुर के सी0ओ0डी0 कालोनी में सीवर लाइन एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	62
जनपद गाजियाबाद के वार्ड 51 में साईं मन्दिर से पार्क के चारों तरफ के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु रेलवे क्रासिंग की जगहों पर पाइप चेकिंग किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत बाजार सरायमीर के गांव नदाव को जोड़ने वाली सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा अन्तर्गत मवाना पौड़ी पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र मधुबन विकास खण्ड बड़रांव चौराहे से कटिहारी बुजुर्ग की जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	64–65

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद फतेहपुर की बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तेलिपानी के अन्तर्गत खराब हुए कतिपय मार्गों का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	65

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सुल्तानपुर कादीपुर विधान सभा के अन्तर्गत सूरापुर (भवानीपुर) से इब्राहिमपुर तक की सड़क का चौड़ीकरण और जल्द बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65
पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष कानपुर को फर्जी मुकदमे में फंसाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र ग्राम ऐंचाना से सुरहा तथा कबरई से कुन्हैटा मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद गोरखपुर महानगर में नौसड़ तिराहे पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण समितियों की बैठक न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	68–69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) का नवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) का दसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	69–70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी समिति (2015–2016) के प्रतिवेदन की रिपोर्ट शासन द्वारा न मानने के सम्बन्ध में शिकायत	70
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा क्षेत्र में स्थित पहासू रोड पर महाराणा प्रताप नगर/मुरारी नगर में समुचित जल निकासी तथा पक्की नाली निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र कुमार राघव आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	70
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा सुभाष रोड से ईदगाह तक की क्षतिग्रस्त मार्ग को आवास विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने विषयक श्री निजाम मलिक आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा सिटी तेलिया घाट रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक श्री छत्तरपाल शर्मा आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 71

विषय	पृष्ठ–संख्या
परी चौक यमुना एक्सप्रेस–वे के समानान्तरण परी चौक नोएडा से आगरा तक प्रस्तावित मार्ग को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री लायक राम सिंह आदि निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जहांगीरपुर चीनी मिल जेवर के बन्द पड़े कार्य को पूर्ण कराकर मिल चालू कराये जाने विषयक श्री भगत सिंह आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	71
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत राधा नगर (फाउण्ड्री नगर) के अधूरे नाले निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री उदय कुमार अग्रवाल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	71
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में छलेसर से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 तक नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजीत कुमार आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत खंदौली को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री विनोद शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	72
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत बरहन को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री प्रभात जैन आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में अति पिछड़े क्षेत्र भेड़ियारी टोला घाट पर लघु सेतु बनाये जाने विषयक श्री राजेश पाल आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	72
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही के सिसवा से अहिरौली दान के बीच राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक डा0 अजय सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका	72

(उपस्थित की गयी) ... ...

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत ग्राम सभा बांसगांव टोला खैरवा में बांसी नदी के खैरवा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरिलाल गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 73

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत अमवा बुढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वकील गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	73
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर राज्य मार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाला पुल सकरा, जर्जर एवं पुराने पुल का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र गुप्ता आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	73
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के अन्तर्गत भरतपुर से उत्तर पैलानी मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	73
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में आर0सी0सी0/इण्टरलाक एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भगवान सिंह वर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	73
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री रामकिशन कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	74
जनपद कासगंज की तहसील सहावर से कासगंज तक एवं सहावर से अर्मापुर होते हुए काली नदी तक मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री वीरपाल सिंह शाक्य आदि निवासीगण जनपद कासगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	74
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	74–87
वित्तीय वर्ष (2016–2017) के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा ...	88–164
कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	164–165
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	165–168

नत्थियां ... ... 169—207

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–279

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकरनगर
7. अताउररहमान, श्री बरेली
8. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
9. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
10. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
11. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
12. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
13. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
14. अमित गौरव यादव, श्री एटा
15. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
16. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
17. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
18. अराधना मिश्रा 'मोना' श्रीमतीप्रतापगढ़
19. अरूण कुमार, डा0 बरेली
20. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
21. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
22. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
23. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
24. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
25. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
26. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
27. आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
28. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
29. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
30. आलमबदी, श्री आजमगढ़
31. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
32. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
33. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
34. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
35. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
36. इकबाल महमूद, श्री संभल
37. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
38. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
39. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
40. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती

41. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
42. उदयराज, श्री उन्नाव
43. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
44. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
45. उमाशंकर, श्री बलिया
46. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
47. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
48. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
49. कपिल देव अग्रवाल, श्रीमुजफ्फरनगर
50. काली चरन सुमन, श्री आगरा
51. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
52. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
53. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
54. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
55. गजराज सिंह, श्री हापुड़
56. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
57. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
58. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
59. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
60. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
61. गोमती यादव, श्री लखनऊ
62. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
63. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
64. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
65. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
66. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
67. जफर आलम, श्री अलीगढ़
68. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
69. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
70. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
71. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
72. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
73. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
74. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
75. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
76. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
77. तसलीम, श्री बिजनौर
78. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
79. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
80. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
81. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
82. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
83. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
84. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
85. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
86. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
87. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
88. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
89. धर्मराज, श्री बाराबंकी
90. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
91. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
92. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
93. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
94. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
95. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
96. नारद राय, श्री बलिया
97. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
98. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर

99. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
100. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
101. पीतमराम, श्री पीलीभीत
102. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
103. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
104. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
105. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
106. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
107. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
108. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
109. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
110. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
111. फेरन लाल, श्री ललितपुर
112. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
113. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
114. बदलू खां, श्री उन्नाव
115. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
116. बाबूलाल, श्री गोण्डा
117. बावन सिंह, श्री गोण्डा
118. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
119. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
120. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
121. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
122. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
123. बैजनाथ, श्री मऊ
124. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
125. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
126. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
127. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
128. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
129. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
130. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
131. मनीष रावत, श्री सीतापुर
132. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
133. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
134. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
135. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
136. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
137. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
138. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
139. माता प्रसाद पाण्डेय, श्रीसिद्धार्थनगर
140. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
141. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
142. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
143. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
144. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
145. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
146. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
147. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
148. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
149. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
150. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
151. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
152. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
153. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
154. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
155. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
156. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
157. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
158. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़

159. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
160. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
161. रणजीत सुमन, श्री एटा
162. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
163. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
164. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
165. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
166. रवि शर्मा, श्री झांसी
167. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
168. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
169. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
170. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
171. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
172. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
173. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
174. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
175. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
176. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
177. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
178. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
179. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
180. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
181. राधे श्याम, श्री अमेठी
182. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
183. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
184. राम गोविन्द, श्री बलिया
185. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
186. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
187. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
188. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
189. राम मगन, श्री बाराबंकी
190. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
191. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
192. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
193. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
194. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
195. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
196. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
197. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
198. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
199. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
200. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
201. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
202. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
203. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
204. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
205. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
206. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
207. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
208. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
209. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
210. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
211. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
212. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
213. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
214. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
215. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
216. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
217. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
218. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
219. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
220. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
221. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
222. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
223. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा

224. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
225. वीरपाल राठी, श्री बागपत
226. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
227. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
228. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
229. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
230. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
231. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
232. शाकिर अली, श्री देवरिया
233. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
234. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
235. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
236. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
237. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
238. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
239. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
240. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
241. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
242. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
243. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
244. संजय कपूर, श्री रामपुर
245. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
246. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
247. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
248. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
249. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
250. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
251. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
252. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
253. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
254. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
255. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
256. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
257. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
258. सीमा, श्रीमती जौनपुर
259. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
260. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
261. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
262. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
263. सुधाकर, श्री मऊ
264. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
265. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
266. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
267. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
268. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
269. सुरेश राणा, श्री शामली
270. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
271. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
272. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
273. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
274. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
275. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
276. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
277. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
278. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

279. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :—माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनायें

"01–श्री नदीम जावेद, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि दूध की मात्रा बढ़ाने के लिये संचालित कामधेनु योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से जनवरी, 2016 तक प्रदेश में कुल कितनी डेयरियों की स्थापना की गयी एवं उससे कितना दुग्ध उत्पादन बढ़ा है ? क्या सरकार जनपदवार स्थापित इकाइयों का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)–

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो/माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना/कृत्रिम गर्भाधान एवं पशुओं के बांझपन निवारण की योजना।

प्रदेश में दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिये संचालित 100 पशुओं की कामधेनु डेयरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से जनवरी, 2016 तक प्रदेश में कुल 212 डेयरियों की स्थापना की गयी है तथा उससे प्रतिदिन लगभग 1,20,000 लीटर दुग्ध उत्पादन बढ़ा है।

जी हां। स्थापित कामधेनु इकाइयों की जनपदवार सूची संलग्न है।[४]

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नदीम जावेद–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। पूरी दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में है और खपत भी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ आबादी में 20 मिलियन टन का उत्पादन है और देश का सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन अध्यक्ष जी, जो बाकी राज्यों के आंकड़े हैं जिसमें राजस्थान की आबादी 7 करोड़ है और उसमें जो दुग्ध का उत्पादन है वह 13 मिलियन टन है। जो आन्ध्र प्रदेश है उसकी आबादी 5 करोड़ है और उसका जो दुग्ध का उत्पादन है वह 12.7 मिलियन टन है। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है और उसका जो दुग्ध का उत्पादन है वह 9.7 मिलियन टन है। हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है और उसका जो दुग्ध का उत्पादन है वह 7.5 मिलियन टन है। मेरा जो प्रश्न है, वह यह है कि जो देश के दूसरे राज्यों के आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध का उत्पादन है वह काफी कम है नम्बर एक। नम्बर

---

[४] (देखिये नत्थी 'क' 169–181 आगे पृष्ठ पर)

दो यह कि राज्य सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसमें एक मिनी कामधेनु योजना है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 52 लाख रुपये का वह पूरा प्रोजेक्ट है उसमें 39 लाख रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, 13 लाख रुपये किसान को देना पड़ता है तो क्या जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं और भारत सरकार के एक आंकड़े के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 78 प्रतिशत किसान उससे प्रभावित हैं तो क्या राज्य सरकार वह 13 लाख रुपये जो किसान का है उसको कम करेगी या समाप्त करेगी और जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे लगाने में सहयोग करेगी नम्बर एक। नम्बर दो, दूसरा एक प्रश्न और है कि उसमें एक माइक्रो कामधेनु योजना है उसमें जो टोटल प्रोजेक्ट है वह 27 लाख रुपये का है, उसमें 19 लाख रुपये सरकार के द्वारा लोन है और उसमें 6 लाख रुपये किसान को अपनी तरफ से देना पड़ेगा। जो राज्य सरकार ने यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि किन जिलों में इन योजनाओं को पिछले वर्षों में लागू किया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। तीसरा प्रश्न उसी में है क्योंकि मा0 मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे। वह यह है कि इसमें अधिकतर जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जबकि गरीबी की सीमा रेखा के जो आंकड़े राज्य सरकार के हैं उसमें आर्थिक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड ज्यादा प्रभावित हैं तो क्या राज्य सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुन्देलखण्ड में इस तरह के प्रोजेक्ट को लगाने में सहयोग करेगी ?

श्री राजकिशोर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 विधायक जी जो अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का जो परसेण्टेज है वह अन्य प्रदेशों से कम है। इसके पहले किसी सरकार ने इस तरीके की दूध की बढ़ोतरी नहीं की है। पशुओं की जो वैरायटी उत्तर प्रदेश से खत्म हो रही थी, पशुओं की वैरायटी अच्छी हो इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री जी को इन्होंने सरकार बनने के तुरन्त बाद कामधेनु योजना दी और कामधेनु योजना के बाद जब जनता की डिमाण्ड आई और उसका रिसपान्स अच्छा मिला तो आपने देखा होगा कि मिनी कामधेनु योजना आई और उसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की आपने बात की, जहां छोटे–छोटे हमारे किसान हैं, बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर है, रोजगार वहां नहीं मिल रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी ने माइक्रो कामधेनु डेरी देने का काम किया और आज की डेट में अध्यक्ष जी, पिछली सरकारों को देख लीजिए और आज देख लीजिए कि लगभग 7 लाख 20 हजार लीटर दूध एक्सट्रा पैदा हो रहा है और उत्तर प्रदेश में लगभग 65 हजार अच्छी नस्ल के पशु आ चुके हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश सबको फाँद जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह ही नहीं हमारी तमाम योजनाएं बांझपन के लिए योजनाएं चल रही हैं लगभग 70 हजार ऐसे बांझ पशु थे, जिनको हम लोगों ने

दवा–उपचार के माध्यम से अच्छा किया और आज भी वह गाय–भैंसे बच्चा देने का काम कर रही हैं और इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहां बैठे हैं भारत सरकार ने पूरे देश का मूल्यांकन किया और उत्तर प्रदेश को पूरे देश को सर्वोच्च पशुधन राज्य घोषित करने का काम भारत सरकार ने किया इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपकी जो पीड़ा है निःशुल्क कर दिया जाए। अगर कोई चीज इस तरह की योजना हम निःशुल्क कर देंगे तो अध्यक्ष जी स्वाभाविक रूप से वह योजना फेल हो जायेगी, जिनकी रुचि है वही लोग इसे करते हैं और इसमें लगभग 10362 लोगों को अब तक रोजगार मिल चुका है। अभी हमारी सारी डेरियां संचालित नहीं हो पायी हैं, तमाम सैंक्शन हुई हैं। कहीं सौ की डेरी तो 50 पशु आये, 60 पशु आये, ये लगातार आ रहे हैं और यह हमारी 2017 तक की योजना है, जिस दिन हमारी यह योजना पूरी कम्प्लीट हो जायेगी, हम जानते हैं कि 25 से 30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैदा होगा और पशुओं के नस्ल में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो जायेगा। उत्तर प्रदेश सबसे खुशहाल हो जायेगा और सबसे ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में पशुधन विभाग के माध्यम से मिलेगा।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक छोटी–सी बात और है कि जो माइक्रो कामधेनु है, उसमें भी काफी बड़ी यूनिट लगती है। आमतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बुन्देलखण्ड में बहुत छोटे किसान हैं तो क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि जो यह छोटी–यूनिट है उसको और छोटा कर दिया जाए और 5 से 10 के बीच में जानवरों को इकट्ठा करके इस तरह का प्रोजेक्ट लगाया जाए तो शायद छोटे किसानों को बेहतर सुविधा हो सकेगी।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कहीं खूंटा बदल न हो जाए। बहुत पहले आपने देखा होगा कि 2–4 पशुओं की योजना चली थी, उसमें तमाम खूंटा बदल की योजना हो रही थी। कहीं खूंटा बदल न हो जाये कहीं इस योजना की जो गंभीरता है जिसको भारत सरकार से लेकर पूरा देश सराह रहा है, अन्य प्रांतों के लोग हमारी गाइडलाइन मांग रहे हैं। कहीं हम छोटी योजना कर दें तो यह योजना हमारी फ्लॉप न हो जाए, हंसी की पात्र न हो जाए। इसलिए इस तरह की योजना लाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। इसमें जो 100 गाय की डेरी खोले हैं, मुख्य मंत्री जी ने इसमें 5 लाख रुपये अलग से सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। कोई भी 100 गाय की डेरी खोले तो उसको 5 लाख रुपये अलग से देने की हमारी व्यवस्था है। मिनी पर ढाई लाख और जो माइक्रो है उस पर सवा लाख रुपये का अतिरिक्त पुरस्कार दिये जाने का काम किया जाए।

(सदस्य, श्री बंशी सिंह पहाड़िया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें आप क्या पूछेंगे, अग्रवाल साहब को पूछ लेने दें, आपका सवाल भी नहीं है बंशी सिंह पहाड़िया जी आप बैठें। अग्रवाल साहब का सवाल है, बेकार आप हर मामले में कूद पड़ते हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तृत और बेहतर जवाब है लेकिन आपकी इस कामधेनु डेरी योजना के बारे में जो व्यावहारिक समस्या है, बहुत प्रैक्टिकल समस्या है जो आपकी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उनके पास खेती की जमीन होती है। बैंक उनको खेती की जमीन के नाम पर ऋण नहीं देते और उनसे कहते हैं कि आप उसका भू–प्रयोग परिवर्तित कराइये, जिसमें उन नागरिकों का जो इस योजना में आना चाहते हैं, बहुत लंबा खर्च हो जाता है। दूसरा यह कि आपकी इस योजना में जो 12 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी है, बहुत अच्छी सब्सिडी है। प्रॉब्लम यह है कि साल भर में दो बार डेरी पर चिकित्सकों के द्वारा जांच की जाती है, उसकी रिपोर्ट लगायी जाती है और जब वह रिपोर्ट सी0वी0ओ0 (चीफ वेटनरी ऑफिसर) के पास, पहुंचती है, तब सरकार द्वारा भेजा हुआ अनुदान बैंक में भेजा जाता है, यह एक शोषण का रास्ता है और हर 6 महीने पर 10 हजार रुपये एक लाभार्थी खर्च करता है, गोरखपुर के लाभार्थी इसमें शामिल हैं। आप उन्हें भी जानते हैं, राज नर्सिग होम एक है, मैं उनसे प्रत्यक्ष बात करके आपको समस्याओं के बारे में बता रहा हूं कि 10 हजार रुपये प्रति 6 माह पर जब एक डेरी का लाभार्थी खर्च करता है जब यह दूध लेकर पराग डेरी में जाते हैं तो फैट कन्टेन्ट के नाम पर जो अधिकतम रुपया दिया जाता है वह 22 रु0 या 25 से 27 रुपये प्रति लीटर। अध्यक्ष जी, मूल समस्या यहां है, डेरी खरीदती है 22 रुपये 25 रुपये 27 रुपये प्रति लीटर पर और डेरी बेचती हे, 48 रुपये प्रति लीटर तक। जो डेरी का ओरिजनल किसान है जो पशुपालक है जिसने दूध पैदा किया उस तक 25 रुपया और नागरिकों तक पहुंचते–पहुंचते 48 रुपये उसका फल क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

यह दुग्ध मंत्रालय का सवाल आप कर रहे है ?

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल–

नहीं अध्यक्ष जी यह दुग्ध मंत्रालय का सवाल नहीं है यह डेरी का सवाल है। डेरी योजना है यह अगर डेरी लगाने वाले घाटे पर चल रहे हैं अगर डेरी लगाने वालों का दूध एक लीटर पैदा करने की लागत 45 रुपये आ रही है और आप उन्हें 25 से 27 रुपया दे पा रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये डेरियां बन्द हो जायेंगी। मेरा प्रश्न यह है कि यह जो आर्थिक शोषण इन एजेन्सियों के द्वारा किया जा रहा है क्या सरकार इस पर नियंत्रण लगाने का कोई प्राविधान करेगी ? अन्यथा यह योजना शुरू हुई है और बन्द हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह दुग्ध मंत्रालय का सवाल है ?

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, यह दुग्ध मंत्रालय का प्रश्न नहीं है यह इस योजना के सफल होने और असफल होने का प्रश्न है। अभी जो योजना चल रही है यह 2–3 साल के अन्दर असफल हो जायेगी। आप बताना चाहेंगे ?

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस डिपार्टमेन्ट का मंत्री हूं और हर जनपदीय स्तर के अधिकारी हमारे यहां है और तमाम डेरियों से हमारी बातें भी होती हैं। इसके पहले दूध की मारा–मारी तमाम जगहों पर आप देखे होंगे, छापा मारी की दूध अच्छा नहीं मिल रहा है। आज की डेट में कोई भी डेरी हो गांव के इन्टीरियर में खोल दीजिये वहां डिब्बे ले लेकर दूध लेने के लिए लोग पहुंचते हैं कि ओरिजनल दूध मुझे मिल जाये हो सकता है कहीं आपके जनपद में ऐसी समस्या हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में डेरियों का दूध आपने अवधेश सिंह का ढाबा देखा है आप रोज उसी रास्ते से जाते हैं। उस ढाबे पर 25 रुपये बट्टे में दूध बेचते हैं और 12 बट्टा दूध एक लीटर में होता है तो आप अन्दाजा लगा लीजिये कितने रुपये लीटर दूध हो गया। इसलिए तमाम डेरियां लाभ में हैं और कोई ऐसी डेरी नहीं है जो घाटे में है और जो आपने कहा शोषण, इस योजना के अन्दर अगर एक पैसे का शोषण हो तो इस सदन में इस्तीफा दे दूं। कोई आदमी किसी अधिकारी कर्मचारी की हैसियत नहीं है पूरे प्रदेश में।

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल–

इनका उत्तर सही नहीं है, अवधेश ढाबा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आप भी उस रास्ते से जाते हैं मैं भी जाता हूं। अवधेश ढाबे के आधार पर इस कामधेनु का मूल्यांकन नही किया जा सकता। मूल्यांकन उन लोगों के आधार पर किया जायेगा जो आम डेरी चलाते हैं और यह सत्य है अभी हमारे एक विधायक ने पश्चिम की बात की कि 22 रुपया हम आपको पूर्वान्चल की बात बता रहे हैं 25 रुपया। आखिर 25 रुपये में हम बेच रहे हैं और वह 50 रुपये मे बेच रहे है यह जो 25 रुपये की मार्जिन वह ले रहे है जिसके नाते पूरे प्रदेश में दूध का दाम बढ़ गया। जब पराग डेरी 50 रुपये लीटर दूध बेचेगी इसी लखनऊ में बेचती है तो स्वाभाविक रूप से एक आम दूध बेचने वाला भी 50 रुपये में ही बेचेगा। यह जो दूध का दाम बढ़ गया आखिर माननीय मंत्री जी को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए अगर हम हर चीज की लागत मूल्य की बात करते हैं तो आखिर दूध की लागत मूल्य की बात करेंगे या नहीं।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको यह भी पता है कि कोई योजना सफल होगी कि नहीं होगी इस पर भी तमाम लोगों को शंका रहती है। हमारी सरकार, मुख्य मंत्री जी लगातार आप देख रहे होंगे चाहे पराग हो चाहे और जो भी संस्थायें इस तरीके का कार्यक्रम कर रही हैं उनको प्रदेश के तमाम जनपदों मे धीरे–धीरे बढ़ाया जा रहा है।

आने वाले समय में हमारी पूरी डेरियां आप से हमने कहा कि पूरी डेरियां पूरे तरीके से स्थापित नहीं हो पाई हैं और जिस दिन पूरी डेरियां स्थापित हो जायेंगी अपने आप उत्तर प्रदेश में पराग जैसे तमाम लोग आकर क्योंकि आप जानते हैं आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है दूध। आदमी को कुछ मिले या न मिले दूध मिले तो आदमी हम जानते है सबसे सकून से रहता है। हम भी शाम को एक गिलास दूध जरूर पीते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो छोटे–छोटे किसान हैं हम उनकी योजना को इसलिए नहीं चलाना चाहते हैं कि वह फ्लाप हो जायेगी। यह बड़ी कामधेनु योजना चला लिया बड़े बड़े लोगों के लिए, एक कामधेनु डेरी लगाने में सवा करोड़ की लागत आती हैं तो यह तो बहुत बड़े लोगों का काम हो गया वह जो छोटे छोटे किसान थे अगर उनको 2–2 गाय, 3–3 बकरी पाल करके, हम सिर्फ गाय की बात कर रहे हैं अगर उनके आय के साधन नहीं बढ़ायें जायेंगे तो आखिर वह किसान आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे ? क्या सरकार सिर्फ धनी लोगों को धनी बनाना चाहती है या गरीब किसानों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती है और इस योजना को चलाने पर फिर से विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो जवाब दे दिया उन्होंने।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, आपको पूरी जानकारी हो सकता है न हो, माननीय दुग्ध मंत्री जी यहां बैठे हैं हमारी 4 गाय भैसों की योजना भी चल रही है वह किसानों के लिए पहले से हैं। छोटे छोटे पशुपालकों के लिए यह योजना हमारे पास है और वह योजना दुग्ध मंत्री जी देखते हैं, यह बतायेंगे दुग्ध मंत्री जी और जो कामधेनु एक अलग योजना है गुरू जी, और जो आपने कहा दूध नहीं बिकता है कहां 25 रुपया किलो दूध है उत्तर प्रदेश में दिला दीजिए, कहीं उत्तर प्रदेश में 25 रुपये में शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये में है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं इसी डेरी वाले से दिला दूंगा। अध्यक्ष जी, यह बात आ गयी कि एक छोटे किसानों की योजना चल रही है माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि चला रहे हैं। क्या सरकार यह बतायेगी कि इस योजना में वास्तविक रूप से कितने किसान आये और उनकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

छोड़िये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु योजना की जानकारी विषयक

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु क्या सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करने के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)–

जी हां। कृषकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिये कृषि विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :–

(1) नेशनल मिशन आन सस्टनेबुल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का संचालन किया जाना। इसके अन्तर्गत रसायन एवं पैस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाता है जिससे कृषि लाभकारी होगी एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार होगा।

(2) नेशनल मिशन आन सस्टलेबुल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का संचालन किया जाना। इसके अन्तर्गत कृषकों के मृदा के नमूनें संकलित कर प्रयोगशालाओं में उसका परीक्षण कर रासायनिक उर्वरकों का सन्तुलित मात्रा में प्रयोग हेतु कृषकों को संस्तुति किया जाना।

(3) जैव उर्वरक उत्पादन किया जाना। इसके अन्तर्गत राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर कल्चर, फास्फोरस साल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया का उत्पादन कर कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक करने का मौका दिया आपको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग सदन में बैठे हुये, सभी सदस्य छोटे बड़े सब किसान है। सब बात तो यह है कि यह लम्बे समय से जो यह योजनायें है यह कागजों तक मात्र रह गयी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पूरी योजना बताई है आपने वह तो रूटीन में सारी योजनायें आपने बता दी। कोई विशेष पैकेज, विशेष कोई प्रोत्साहन राशि आप देंगे क्या और दूसरा, जो दुष्परिणाम है, रसायनिक खाद का जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, भिन्न प्रकार की जो बीमारी पैदा हो रही है आज उनको रोकने के लिये और कोई ऐसी योजना आप लेकर के आयेंगे क्या ? इसके साथ जो गो–शाला है चूंकि अगर जैविक खाद तैयार होगा तो निश्चित रूप से गो–शालाओं के माध्यम से होगा या डेरी के माध्यम से होगा अभी इससे पहले इससे संबंधित प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, यही चल रहा था। वास्तविकता यही है मैं सामान्य

किसान परिवार से आता हूं और मेरे परिवार के लोगों ने जो मंत्री जी की योजना है वह डेरी लगायी है उसको चलते हुये दो साल हो गये और वास्तविक स्थिति यह है कि जो डा0 राधा मोहन जी कह रहे थे माननीय मंत्री जी यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है लेकिन सच मायने में वह खुद भी काम करते है हमारे उसके तहत और परिवार के लोग भी लगे रहते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि वह माइनस में जा रहे है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने सवाल पर पूछिये वहां कहां चले गये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह वास्तविकता है यह बन्द हो जायेगी आने वाले समय में आप देखियेगा।

अच्छी सोच के साथ आपने इसकी शुरूआत की, लेकिन इसमें और योगदान देने की आवश्यकता है डेयरी वालों को। तो मेरा प्रश्न यह है कि गौ–शालाओं की खाद को और इन गौ–शालाओं को इस जैविक खेती से जोड़ने पर क्या आप विचार करेंगे और क्या सरकार गौ–शालाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर कोई विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अब ये तो अलग–अलग विभाग से सम्बन्धित है। गौ–शाला माननीय मंत्री जी के पास है नहीं और रासायनिक खाद पर बात कर रहे है, इनसे सम्बन्धित सवाल आप पूछिये ना।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, गौ–शालाओं में जो गोबर इकट्ठा होता है, वहीं तो जैविक खाद के रूप में आता है। इसलिये मैंने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते है कि क्या आप जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जैविक खेती पर अभी वर्ष 2015–2016 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश में नीति लागू की गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत चिन्ता है कि रासायनिक उर्वरक से तमाम रोग पैदा हो रहे है, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है। इस नाते प्रदेश में 15 जनपदों का चयन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, कन्नौज, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, पीलीभीत को मिलाकर 15 जनपदों का चयन कलस्टर के माध्यम से किया गया है, जिसमें जैविक खेती कराने की सरकार की योजना है। इसके लिये वर्ष 2015–16 में लगभग 25 करोड़ से कुछ अधिक धनराशि दी गई है, जिसमें से अभी तक एक करोड़ कुछ ज्यादा रुपये खर्च किये गये हैं। माननीय विधायक की चिन्ता है कि जानवर से जो खाद पैदा होती है, तो यह सही है कि जानवर की खाद इसमें बहुत उपयोगी होगी। इस पर विचार करने की

जरूरत नहीं है, इसमें आप अपने सुझाव दे दीजिये, उसको हम इसमें लागू कराने का काम करेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है और आज के समय में जैविक खाद को उपयोगिता को अगर नहीं बढ़ाया गया, तो आने वाले समय में हर घर में जैसे बीमारियाँ फैल रही है, तो और बीमारियां बढ़ेगी। मान्यवर, अभी हमारे जनपद शाहजहांपुर में एक एन0जी0ओ0 है विनोवा भावे सेवा आश्रम, उनके यहां गौ–शाला में गौ–मूत्र से और उसके गोबर से वह जैविक खाद बना रहे है। इसमें उन्होंने अभी एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी और हमारे विधान सभा क्षेत्र में ही उसे लगाया था। तो आपके माध्यम से मेरा सुझाव भी है और मंत्री जी से प्रश्न भी है कि जो ऐसी संस्थायें हैं जो जैविक खाद बनाकर बेचने का काम भी कर रही हैं उनको बढ़ावा देते हुए सरकार उनसे कुछ ऐसा अनुबन्ध करेगी कि जिससे किसानों को यह जैविक खाद उपलब्ध हो सके ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने जैविक खाद के लिये एन0जी0ओ0 के माध्यम से एक टेण्डर कराया है कि कौन सा ए0जी0ओ0 इसमें काम करेगा। दो–तीन ए0जी0ओ0 के टेण्डर इसमें आये हैं और उसी के माध्यम से यह जिले एलाट किये जायेंगे और उन्हीं एन0जी0ओ0 के माध्यम से उस जिले में जैविक खेती कराने का काम करेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का समय दिया। प्रश्न यह था कि जैविक खाद प्रयोग करने के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन क्या सरकार देगी ? प्रश्न का मुख्य मकसद है कि जैविक खाद को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ? अभी आश्वासन समिति में भी यह सवाल आये थे। माननीय महाना जी और हमने इस विषय पर काफी डिस्कशन किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैविक खाद के लिये सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है ? पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि केचुआ की खाद इसके लिये सबसे उपयोगी है। जहां पर भी यह डेयरी है, उनके गोबर को केचुआ बहुत तेजी से खाकर बिल्कुल यूरियाटाइप और डी0ए0पी0 टाइप खाद बनाता है। दूसरी बात कि इसके लिये मैकेनिकल यंत्र भी बने हैं आर0बी0आर0आई0 में। अभी हमारी समिति ने एक उप समिति गठित करके वहां पर भेजी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये केचुआयुक्त खाद और मैकेनिकल यंत्रों की व्यवस्था कराने के लिये किसानों को अनुदान देकर सहयोग करने पर विचार कर रही है ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह–

यह जो है इसमें अनुदान रु0 9.00 प्रति पैकेट मात्रा 200 ग्राम का है, जिसमें 75 प्रतिशत का अनुदान किसानों को भुगतान राजकीय कृषि बीज भण्डार के माध्यम से दिया जा रहा है और केचुये की खाद का जहां तक प्रश्न है, यह भी जैविक खाद में ही तो इस पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और जैविक खाद के प्रोत्साहन के लिये जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 करोड़ की व्यवस्था की है। सरकार की गम्भीरता इस बात से परिलक्षित होती है कि 15 करोड़ से मात्र एक करोड़ सरकार ने खर्च किया है तो सरकार की यह गम्भीरता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न क्या बना। आपका कहना है कि जितना पैसा आवंटित था उसमें मात्र एक करोड़ खर्च किये तो इसे आप गम्भीरता से लीजिये।

श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, लगता है माननीय विधायक जी सुन नहीं पाये। यह आवंटित तो 25.42 करोड़ है। लेकिन अभी तक जो इस कार्यक्रम में खर्च हुआ, उसमें 1 करोड़ 91 लाख का व्यय हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

वही बता रहे है कि जरा इसे गम्भीरता से लीजिये।

श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह–

इसे पूरी गम्भीरता से खर्च करना है और अगर और कोई सुझाव भाई लोकेन्द्र जी का हो तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश में सूखा, बेमौसम वर्षा से परेशान किसानों के लिये सरकार द्वारा बचाव हेतु कोई योजना की मांग

'02–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखा, बेमौसम वर्षा और कृषि उत्पादों के लागत मूल्य की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या इससे बचाव हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार स्तर पर गठित कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाती है। कृषकों को प्रमुख फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग (सांख्यिकीय अनुभाग) द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में एवं राज्य कृशि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से

आच्छादित जनपदों में उत्पादन लागत सर्वेक्षण कराते हुये फसलों के उत्पादन लागत आंकलित किये जाते हैं जिसे प्रदेश में गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करते हुये कृषि लागत और मूल्य आयोग को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करने हेतु संस्तुति के रूप में प्रेषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर सदस्य श्री धर्मपाल सिंह जी अनुपस्थित थे)

प्रदेश में उत्पादित यूरिया में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक गैस पर लगने वाले विशेष प्रकार के 'प्रवेश कर' को समाप्त किये जाने की मांग

'03–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्पादित यूरिया में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक गैस पर लगने वाले विशेष प्रकार के 'प्रवेश कर' (ए0सी0टी0एन0) की वजह से राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में यूरिया के दाम प्रति बोरी 100/– अधिक होने के कारण बिहार, उत्तराखण्ड तथा हरियाणा राज्यों से तस्करी कर सस्ती यूरिया खरीदने से राज्य को राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विशेष प्रकार के 'प्रवेश कर' (ए0सी0टी0एन0) को समाप्त कर राज्य में उत्पादित यूरिया के बिक्री को प्रोत्साहित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में उत्पादित यूरिया में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस का वैट अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले अतिरिक्त कर का अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता न होने के कारण यूरिया के प्रति बैग की बिक्री पर रु0 47.00 ए0सी0टी0एन0 उनके द्वारा वसूला जाता है, जो एम0आर0पी0 के अतिरिक्त होता है।

सीमावर्ती राज्यों से यूरिया की तस्करी एवं राजस्व की हानि की सम्भावना क्षीण है।

जी नहीं।

प्राकृतिक गैस का प्रयोग यूरिया के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाइयों के द्वारा भी किया जाता है तथा प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त कर समाप्त करने से राज्य के राजस्व में काफी हानि होगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार कृषकों की सरकार है और कृषकों के विषय में विशेष दृष्टिकोण रखती है। इसलिये मैंने यह सवाल लगाया था और कृषि कार्य में यूरिया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिस पर पूरी खेती निर्भर करती है। आपका यह कहना है कि 47 रुपया जो अतिरिक्त कर के रूप में ले रहे हैं वह भारत सरकार उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करती है इसलिये यह 47 रुपया वसूला जाता है। मैंने यह कहा था कि ऐसा न करने से जो अतिरिक्त वैट है, वह लगा रहने से जो दूसरे पड़ोसी राज्य है वहां इसका दाम कम है इसलिये यहां के जो व्यापारी है वह वहां से इसकी तस्करी करके यहां लाते हैं और कृषकों को कम दाम पर बेचते हैं तो इस दृष्टि से कृषकों को यह सुविधा भी मिले और यहां के जो इस उद्योग में लगे हुये हैं, उनको

प्रोत्साहन भी मिले, इस दृष्टि से क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि यह जो 47 रुपया अतिरिक्त लगाना पड़ रहा है, वह न लगाया जाय और आपने यह भी कहा है कि राजस्व हानि की संभावना क्षीण है तो क्षीण है हानि से इंकार नहीं है सरकार को। लेकिन उनका कहना है कि क्षीण है तो इसे तो सरकार मान रही है कि हानि है। तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह इतनी बड़ी राशि हो सकती है जिसे कि सरकार उठाने में अक्षम है और अगर इसको उठाकर कृषकों को कुछ लाभ दिया जाय, यहां के इस उद्योग में लगे हुये लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाय तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)–

एडिश्नल कास्ट ड्यू टू नॉन रिकग्नाइज्ड इनपुट टैक्सेशन प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है मान्यवर, यह भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है और उनके द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। जहां तक अपने प्रदेश में यूरिया के मूल्य की बात है जो मान्यवर ने 100 रुपए का अन्तर बताया यह सही नहीं है। यूरिया का प्रति बैग मूल्य उत्तर प्रदेश में 334 रुपए, मध्य प्रदेश में 286.50, राजस्थान में 284 रुपए, उत्तराखण्ड में 284 रुपए, बिहार में 284 रुपए, हरियाणा में 270.50 और दिल्ली में 270 रुपए है इस प्रकार प्रतिबैग में अन्तर मात्र 50–60 रुपए का तो है लेकिन 100 रुपए का अन्तर सही नहीं है। दादा जी सदन के अति वरिष्ठ हैं मेरे जैसे लोग तो तमाम आपसे सीखते हैं मुझे यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि जब यूरिया की कमी है नहीं, यूरिया का बाहुल्य है और खेती से जुड़ी तमाम चीजों की कोई कमी नहीं है तो आपको इतनी चिन्ता हो गई और तब चिन्ता आपको बिल्कुल नहीं होती थी जब खाद मांगी जाती थी और बदले में पुलिस की लाठी दी जाती थी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 मंत्री जी जिस परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं यह तो केन्द्र सरकार की कृपा है, केन्द्र सरकार यूरिया की इतनी सप्लाई कर रही है कि यहां कमी नहीं है तो इसमें तो आप केन्द्र सरकार को धन्यवाद् दीजिए। हम लोग यह सवाल उठाते रहे हैं, मैं कृषक नहीं हूं लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की तमाम परेशानियों पर चिन्ता व्यक्त करने का अधिकार मुझको है तो अगर आपने कहा कि यह केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तो आप इसकी प्रतिपूर्ति करके यहां के उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहते ?

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, भारत सरकार के पास तो असीम अपार क्षमता है और साधन हैं लेकिन प्राकृतिक गैस का प्रयोग यूरिया के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाइयों के द्वारा भी किया जाता है तथा प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त कर समाप्त करने से राज्य के राजस्व में 800 करोड़ रुपए की क्षति होगी और यह धनराशि जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जा सकती है। मान्यवर, जहां तक सीमा पर तस्करी की बात है तो लगे क्षेत्र में, लगे पड़ोस में लोग दूसरे किसी काम से जाते होंगे और दो–चार बोरी लाते होंगे, वह न ला पायें और तस्करी न होने पाये इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने।

श्री अध्यक्ष–

यह तो पूछा ही नहीं जा रहा है।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, इसके लिए प्रदेश सरकार ने 2016 में तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस पर कठोरता का पालन करें। प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क और सजग है कि सीमाओं पर तस्करी न होने पाये।

(सदस्य श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या के बोलने पर)

श्री विजय बहादुर पाल–

आप क्यों इतनी जोर–जोर से बोल रहे हैं आपको किसानों से क्या मतलब, आपको पांच साल मिले तो थे जरा आप उसे याद कर लीजिए। दादा जी का सवाल है उन्हें उत्तर दे देने दीजिए वह तो स्वयं विद्वान हैं और अपनी बात कहने में सक्षम हैं। आप तो व्यर्थ में वकालतनामा लगा रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जब मा0 मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अन्य प्रदेशों की तुलना में यूरिया प्रतिबोरी 50, 60 रुपए मंहगी है और मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश है जिसमें उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका होती है ऐसी हालत में जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखण्ड में। यूरिया में प्रयोग होने वाली प्राकृतिक गैस कर मुक्त हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ? मान्यवर, जब अन्य प्रदेशों में 50–60 रुपया मंत्री जी के ही मुताबिक प्रति बोरी यूरिया खाद सस्ती हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ? देश के अन्य प्रदेशों में यूरिया खाद 50–60 रुपये प्रति बोरी कम कीमत पर मिल रही है तो अन्य प्रदेशों की भांति क्या उत्तर प्रदेश में वो सुविधा आप उपलब्ध करायेंगे ?

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, यह जो ए0सी0टी0एन0 है इसे लगाने में भी प्रदेश वाइज बड़ा पक्षपात किया गया है पक्षपात किया गया है इनके द्वारा। मैं आंकड़े पढ़ रहा हूं। 2011–12 में उत्तर प्रदेश में 14.45, गुजरात में तब 10 प्रतिशत, 2012–13 में उत्तर प्रदेश में 18.20 तब गुजरात में 9.45, 2013 से 2014 तक उत्तर प्रदेश में 25.75 लेकिन गुजरात पर बड़ी कृपा 20.50 और 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश में 47 रुपये लेकिन गुजरात पर केवल 15 रुपया। आप तो हमारे विपक्ष के नेता हैं, आप तो समझ गये होंगे पूरी तरह तिकड़म पेंच। मैं दादा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। दादा जी को व्यक्तिगत रूप से किसानों पर प्रेम उमड़ गया होगा लेकिन किसान और भारत सरकार का कहीं दूर–दूर तक कोई नाता–रिश्ता नहीं है। यह प्रश्न पढ़कर मुझे लगा कि कम से कम केन्द्र सरकार का कोई नाता–रिश्ता हो या न हो लेकिन दादा जी को है इसलिए इन्हें प्रणाम।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, अब बहुत हो गया। नत्थी 'ग'।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना गंभीर प्रश्न पर भारत सरकार पर निशाना मारकर यह सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती है। जब मैंने यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि तमाम प्रदेशों में यूरिया में प्रयोग होने वाली प्राकृतिक गैस पर कर मुक्ति की व्यवस्था है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ? दूसरे, जब माननीय मंत्री जी इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं और जिसको उन्होंने अपनी सूचना के माध्यम से फलां–फलां प्रदेशों का आंकड़ा देते हुए अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में मात्र 50–60 रुपये प्रति बोरी यूरिया मंहगी मिलती है। जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों पर यह अतिरिक्त भार क्यों, टैक्स क्यों ? सरकार इसका जवाब न दे करके किसानों के साथ धोखा कर रही है, छलावा कर रही है इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये, वह प्रश्न खत्म हो गया। नत्थी 'ग', तारांकित प्रश्न सं0 1 डा0 धर्मपाल सिंह।

श्री सतीश महाना–

नहीं अध्यक्ष जी, किसानों के इतने शुभ चिन्तक हैं प्रश्न लगाया नहीं, प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी ने लगाया। (ब0स0पा0 के दो–तीन मा0 सदस्यों के आपस में बात करते रहने पर) मान्यवर, पहले यह तय कर लें कि वाकआउट किया या सदन के अंदर हैं, पहले तय कर लें। अभी तो यही प्रश्न चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, बैठिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने जिस मुद्दे पर वॉक–आउट किया है उनका अधिकार है जब चाहें बैठें, जब चाहे चले जांए लेकिन उन्हें यह मालुम होना चाहिए नेता जी मुख्य मंत्री थे और मैं को–ऑपरेटिव मिनिस्टर था भारत सरकार ने एक बोरे पर 50 रुपये की ड्यूटी बढ़ा दी थी उसी वक्त हमारी और नेता जी की बात हुई और मैं पत्रावली लेकर नेता जी के पास गया और कहा कि यह 50 रुपये किसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या सुझाव है ? हमने कहा कि यह 50 रुपये सरकार दे। तभी से प्रति बोरी 50 रुपये सरकार देती है किसान नहीं देता है। तो मान्यवर, यह तो हमारा किसान से रिश्ता है। टैक्सेस के मामले में मान्यवर बहुत से टैक्स ऐसे हैं जो भारत सरकार के लगाये हुए होते हैं और उन्हें राज्य सरकार नहीं कम कर सकती और किसानों के लिये समाजवादी पार्टी की क्या नीति है किसान के इस्तेमाल की

चीज है यूरिया, हाथी के इस्तेमाल की चीज नहीं। इसे हाथी प्रयोग में नहीं लाता किसान प्रयोग में लाता है। सरकार बहुत हितैषी है किसानों की इस बारे में जो भी विचार किया जा सकता होगा उसकी रियायत के लिये, सरकार करेगी।

तारांकित प्रश्न

बेमौसम भारी बारिश व ओलावृष्टि से होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई करने हेतु सरकार द्वारा बैंकों को दिशा–निर्देश दिये जाने की मांग

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि फरवरी, 2015 से बेमौसम भारी बारिश व ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान होने के कारण प्रदेश के क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को बैंक से मिलने वाले ऋण के साथ ही उनका बीमा भी अनिवार्य रूप से किया जाता है लेकिन किसानों को उनकी फसल से नुकसान होने पर बैंकों द्वारा उन्हें बीमे की रकम नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को वर्ष 2015–2016 में फसल बीमा की धनराशि मिलने हेतु बैंकों को निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

1–फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों को अनिवार्य रूप से बीमा योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है। फसल बीमा योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमित क्षेत्र में बीमित फसल पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज का आंकलन किया जाता है तथा उपज में कमी के अनुरूप नियमानुसार बीमा क्षतिपूर्ति का आंकलन का बीमित किसानों को भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित बैंक शाखाओं, जहां से कृषक ने बीमा करवाया था, के माध्यम से कृषक के खाते में प्रेषित किया जाता है। रबी 2014–15 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 8.57 लाख कृषकों को रुपये 566.15 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

वाणिज्यिक बैंक भारत सरकार के अधीन हैं। अतएव भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे समस्त बैंकों को निर्देशित करें कि जिस किसी भी बैंक शाखाओं द्वारा प्रदेश के ऋणी कृषकों को योजना के अन्तर्गत नियमानुसार कवरेज प्रदान नहीं किया जा रहा है, योजना के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित बैंकों द्वारा स्वयं अपने स्तर से क्षेत्र के ऋणी कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में बैंकों द्वारा कहीं भी खुद सरकार ने माना कि नियमों के अनुसार बीमित किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा सरकार ने जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितने किसान बीमित हैं। सरकार ने जवाब दिया है कि 8.57 लाख को हमने प्रदान कर दिया है। मैं टोटल संख्या जानना चाहता हूं प्रदेश में। हमारे आगरा में माननीय अध्यक्ष जी अभी तो बंटना ही नहीं शुरू हुआ है। किसी भी किसान को जो

क्रेडिट किसान धारक थे किसी को भी अभी तक इसका पैसा नहीं दिया गया है। आपके माध्यम से यह दो छोटे–छोटे प्रश्न हैं माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, सूचना है कि कितने कृषक हैं जो बीमित हैं।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न में माननीय विधायक जी ने यह पूछा नहीं था तो यह सूचना हम माननीय विधायक जी को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मेरा व्यक्तिगत केस दर्ज किया है इसी प्रकरण के सम्बन्ध में। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कहीं कोई शिकायत हो तो हमें बतायें। मैंने खुद इस बार ऋण लिया। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा इन्टरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवाल है, पूरा सदन इसको सुने। मैंने स्वयं ऋण लिया अपने गभाना स्टेट बैंक की शाखा से। जब मैं वहाँ देखने गया अपना एकाउन्ट तो मुझे पता लगा कि मेरे ही खाते से आई0सी0आई0सी0आई0 लोमार्ट कम्पनी जो बीमा का काम करती है उसको मेरे खाते से 7 हजार रुपया काट के चेक दे दिया गया। जब पूरे प्रदेश में यह हंगामा था और पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि और सूखे से सेन्ट परसेन्ट किसान ग्रसित थे तो मैंने कहा कि आपने हमारा यह बीमा बिना हमारे पूछे और बिना पॉलिसी दिये कर दिया तो पूरा प्रदेश उससे पीड़ित है, आप हमें बीमा का क्लेम दिलवाइये। तो उस कम्पनी के मैनेजर ने कहा कि यह तो हम पर ऊपर से दबाव है कि किसान ले या न ले पॉलिसी। धर्मपाल जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका, किसान ले या न ले पॉलिसी। हर किसान को बीमा की किश्त इसी ऋण में से काट ली जाती है। जो आई0सी0आई0सी0आई0 लोमार्ट कम्पनी है उसकी सेटिंग बहुत बड़े–बड़े लोगों से है। पूरे प्रदेश में करोड़ों–करोड़ रुपया कम्पनी को जाता है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक उस कम्पनी ने किसी भी किसान को कभी बीमा का एक पैसा नहीं दिया है। मैंने उस कम्पनी के खिलाफ एक मुकदमा कायम कराया है थाना गवाहाना जनपद अलीगढ़ में अपराध संख्या–148/15 धारा 420 के तहत लोमार्ट कम्पनी का मैनेजर बैंक का मैनेजर फील्ड अफसर जो लोग भी इसमें इनवाल्व हैं उनके खिलाफ मैंने एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है। डी0जी0पी0 महोदय ने मेरी यह एफ0आई0आर0 आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित कर दी है। मैं आपके माध्यम से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरे प्रश्न की तरफ भी मुखातिब हो लें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इसमें वक्तव्य जरूर चाहूंगा। मैंने यह मुकदमा कायम कराया है। डी0जी0पी0 ने मेरा यह मुकदमा आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित कर दिया है। इसलिए अगर इस केस पर कार्यवाई हो जाएगी तो यह जितनी भी बीमा कम्पनी किसानों का जबर्दस्ती जो पैसा ले रही है वह सब इनको देना पड़ेगा। मेरे केस में कार्यवाही हो गई तो सबको सबक मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने केस के बारे में कह रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह–

यह सभी किसानों पर लागू है। जनरल सबके लिए है।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोमार्ट जनरल इंश्योरेंस कम्पनी जो है अलीगढ़, पीलीभीत, औरैया, जालौन, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद इतने जनपद में काम कर रही है और क्षतिपूर्ति इन्होंने जो दिया है अलीगढ़ को रु0 733 लाख 75 हजार, पीलीभीत को रु0 1285.97 लाख, औरैया को रु0 901.21 लाख, जालौन को रु0 5980.18 लाख, वाराणसी को रु0 288.74 लाख, गाजीपुर को रु0 985.88 लाख, गोरखपुर को रु0 941.15 लाख, कुशीनगर को रु0 410.32 लाख, रायबरेली को रु0 370.46 लाख, सीतापुर को रु0 1664.34 लाख, खीरी को रु0 78.09 लाख और फैजाबाद को रु0 58.03 लाख यह भुगतान उन्होंने किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में किया है। लेकिन जहां तक सवाल माननीय विधायक जी का है उसको हम दिखवा लेंगे अगर एफ0आई0आर0 हुआ है और सही है कि जितने भी बीमा कम्पनी के लोन होते हैं उस पर भारत सरकार की गाइड लाइन है। लोन के आधार पर किश्त काटकर बैंक बीमा कम्पनी को दे देते हैं इसकी शिकायत है और एफ0आई0आर0 की कापी माननीय विधायक जी ने हमको दे दी है इसकी जाँच करायेंगे और दोषी पाए जाने पर बीमा कम्पनी के खिलाफ कार्यवाई करेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह–

आगरा का भी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने जो जिले बताये उसमें आगरा नहीं है। आप मंत्री जी से पूछ लीजिए।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा में कितने किसानों को क्षतिपूर्ति मिल गई है।

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

आगरा रिलायन्स कम्पनी जनरल इंश्योरेंस कर रही है और इसमें 167.59 लाख रुपया क्षतिपूर्ति किसानों को मिली है। लाभार्थी कृषक हैं 1451 मान्यवर, आगरा तो बड़ा शहर है आगरा के अगल बगल जहाँ किसानी है जहां खेती होती है वहां अगर कोई समस्या है तो आप अपना सुझाव लिखकर दे दें। हमारी सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के लिए विशेष योजना चला रहे हैं सूखा, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि विभाग का बजट भी बहुत बड़ा रखा है कि किसानों की मदद किस तरह से किया जाय जिससे किसानों की

परेशानी दूर हो मैं सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग सुझाव दीजिए आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और किसानों की मदद करेगी किसानों की समस्या पूरे सदन की समस्या है। यह जो उठकर सदन छोड़कर चले जाते हैं इनकी जब सरकार थी तब यह लोग कहते थे कि हमारा वोटर गन्ना ही नहीं बोता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी प्रश्नों का उत्तर तो माननीय मंत्री जी दे नहीं पाते हैं पिछली सरकार की गन्ना की बात करते हैं शायद इनको यह नहीं मालूम कि 125 रूपया से लेकर ढाई सौ तक बढ़ाने का हमने काम किया चार साल में 280 पर खूंटा गाड़ दिया है यह सरकार किसानों की आंख में धूल झोंककर आज अपनी हंसी उड़ाकर बड़ी वाहवाही लूटना चाहती है माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल प्रश्नों का उत्तर दिया जाय उसके बजाय इधर उधर बहकने का काम न किया जाए और सदन को गुमराह भी न किया जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बिल्कुल सही सुझाव है इधर उधर नहीं बहकना चाहिए। गन्ने का दाम बढ़ाया दांत निकाल लिए कारखाने बेच दिए और गन्ने का दाम बढ़ा दिया जब दांत ही नहीं होंगे तो गन्ने का किसान करेंगे क्या। गन्ने का कारखाना ही नहीं रहा सारे कारखाने बेच लिए। हमारे रामपुर का कारखाना वहां दो कारखाने थे सिविल लाइन्स एरिया में हीरे की कीमत कम होगी जो जमीन की कीमत थी वह भी आपने बेच लिया वह तो हाईकोर्ट से स्टे के कारण आज तक बचा हुआ है तो आपने कारखाने ही कहां छोड़े आपने दांत ही नहीं छोड़े तो खाएगा कहां से। आपका तो बड़ा योगदान है उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी संसदीय कार्य मंत्री जी को यह भलीभांति मालूम है कि वह चीनी मिलें जो 15 साल 20 साल से बन्द पड़ी थीं वह बेची गईं और वह भी पैसा उत्तर प्रदेश के खजाने में आया है किसी की व्यक्तिगत जेब में नहीं गया। दूसरी चीज समाजवादी पार्टी सरकार चीनी मिल मालिकों की गोदी में बैठकर आज किसानों के बकाए का भुगतान न किया जाए लेकिन हम चीनी मिल मालिकों पर मेहरबान नहीं थे किसानों पर हम मेहरबान होते हैं इसीलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने उनका बकाया भुगतान डण्डा मारकर करवाने का काम किया है जिन चीनी मिलों ने भुगतान में आना कानी की उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। सरकार को अपने उत्तर का जवाब देना चाहिए इसके अलावा कोई बात करेंगे तो उसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बहुत हल्के से जवाब देना चाहूंगा आपने जो मिल बेची थीं उनकी बुनियादों में जितने का पानी लगा था उतने में पूरी मिल और जमीनें बेची थीं आपने कौड़ी के दाम कूड़े के दाम। यह कौड़ी और कूड़े का दाम तो खजाने में गया और सच्चा माल कहां गया आप भी जानते हैं उसकी असल कीमत कहां गई जहां तक किसानों को पैसा देने की बात है आप रिकार्ड निकाल लीजिए अगर इस सरकार ने किसानों को पैसा ऐतिहासिक तौर पर न दिया हो आज तक इतनी रकम किसी बजट से न जारी हुई हो किसी सरकार ने न दी हो तो मैं समझता हूं कि हमें भी यहां बैठने का अधिकार नहीं है। किसानों के बारे में या गन्ना किसानों के बारे में जितनी बरबादी हुई है उसकी शुरूआत आपने की उसको अन्त तक भी आपने ही पहुंचाया आज जो गन्ने का किसान भुगत रहा है वह आपकी कृपा से भुगत रहा है इसीलिए मैंने कहा कि दांत हैं नहीं, अब चने दे रहे हो जब दांत नहीं हैं। जब दांत थे तब चने तो आप खा गये। इसलिये इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। गन्ने की बात अगर मा0 मंत्री जी ने कही तो सिर्फ एक जिक्र में बात आ गई थी, न आप इतनी बात बढ़ाते। 'मैंने जब अपने गिरेबां के किये थे टुकड़े, तुमको क्यों अपना गिरेबां याद आया'।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, इनको शायद यह नहीं मालूम कि आपकी सरकार में डालाचुक्र सीमेण्ट फैक्ट्री बेची गयी थी, 21 मजदूरों पर गोली चलाई गयी थी, 21 मजदूर मौत के घाट उतारे गये थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिकों की गोदी में खेलने का शौक समाजवादी पार्टी सरकार को हो सकता है, लेकिन किसान के हितों के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और वह रक्षा हमनें की है। इसलिये अगर सरकार विषय बदलकर इस प्रश्न प्रहर को निगलना चाहती है तो अपने बचाव के लिये भले ही कोई दायें–बायें का खेल खेल ले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज सभी मुद्दों पर इनका जवाब देने के लिये भी तैयार है और मैं फिर से कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्या जी, यह प्रश्न प्रहर है, प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, तो आप इधर क्यों रोकते हैं ? आप उधर भी रोकिये।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सबको रोकूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आपका निर्णय सर्वोपरि है। अगर आप मुझे रोकते हैं तो सत्ता पक्ष को भी रोकिये। सत्ता पक्ष अगर बेनकेल बोलेगा तो उसका जवाब भी सुनने के लिये उसे तैयार रहना पड़ेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष का यह अधिकार है कि किसी भी समय बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आप नहीं बोल रहे हैं। यह क्या हो रहा है ? इस तरह से कैसे चलेगा ? यह समाजवादी पार्टी अराजकता के रास्ते पर जा रही है जो मा0 अध्यक्ष जी के निर्णय को भी नहीं मान रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न और प्रत्युत्तर देते रहेंगे तो कैसे और क्या किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार की भी मजबूरी है कि वह आपको आईना दिखाती रहे, यह हमारी मजबूरी है। देखिये, छोटी–सी गलती की बड़ी सजा मिलती है। कहां बैठे हैं, यह दो साल में कहां पहुंच गये, मैं वही बता रहा हूं। किसानों के बारे में और खासतौर से गन्ना किसानों के बारे में आप कितनी ही छलांगें लगा लें, कितना ही चीख–पुकार लें, लेकिन आपने जो उनकी बरबादी की है तो तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखा है। 'लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई'। वह सजा तो आपको अभी ठीक से मिली ही नहीं है, 2017 का इंतजार कीजिये।

(सदस्य, डा0 धर्मपाल सिंह तथा सदस्य, श्री अजय कुमार ''लल्लू'' के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब इस प्रश्न पर अब बहुत चर्चा हो गयी, अगला प्रश्न लेने दीजिये। लल्लू जी, आपने तो प्रश्न किया नहीं था, प्रश्न डाक्टर साहब का था। अब दूसरा प्रश्न लेने दीजिये। डाक्टर साहब ने आगरा का कहा था, आगरा का मा0 मंत्री जी ने बता दिया।

(सदस्य, श्री अजय कुमार ''लल्लू'' के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

ठीक है, आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये, लेकिन आप प्रश्न तो पूछते नहीं हैं, दूसरे के प्रश्न में सप्लीमेंट्री क्यों पूछते हैं ?

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने इस गम्भीर विषय पर मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जैसाकि किसान क्रेडिट कार्ड में इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति देने की बात कही गयी है। एक हमारा पिपराघाट गांव हैं जहाँ पिछले वर्ष बाढ़ से कटान हो गयी थी और एक अहरौलीदान भी है, उसके बारे में हमनें तमाम पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 राजस्व मंत्री जी को भी लिखा और बताया कि यह जो गांव हैं, इसके तमाम किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था, जिनकी सारी खेती नदी में कट गयी, उसके बाद भी आज भी उनसे पैसा किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लिया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बना था, जिन किसानों की पूरी की पूरी खेती ही समाप्त हो गयी। जब किसान यह किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है तो उसकी खेती का इंश्योरेंस रहता है, तो क्या यह सरकार उन किसानों का जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था और जिनका इंश्योरेंस भी है, उन सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह कर्जा माफ करने की व्यवस्था करने की बात नहीं है। मा0 विधायक जी ने जो शिकायत की है, यह लिखकर दे दें, हम जांच कराकर अगर वह कटान हुई है और फसल का नुकसान हुआ है तो हम उस बीमा कम्पनी पर दबाव बनाकर उससे किसानों को पैसा दिलाने का कार्य करेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह–

अध्यक्ष जी, किसानों की सरकार है, आपके संज्ञान में होगा, कोई भी बैंक, जो रिटेल लोन्स हैं, किसी पर भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है, केवल किसानों पर 1 से 3 लाख तक 1700 रुपये प्रति लाख ली जाती है और अगर क्रेडिट कार्ड धारक किसान 03 लाख रुपये से ज्यादा लोन लेता है तो 700 रुपये प्रति लाख और जुड़ जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजेगी कि किसानों के लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क माफ करेगी?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

मान्यवर, प्रोसेसिंग फीस माफ करने की जो बात माननीय विधायक जी कह रहे हैं, इस पर भारत सरकार को पत्र 12 फरवरी को ही भेजा गया है। अब भारत सरकार को इसमें कार्यवाई करनी है, वह करेंगे, हम लोग तो सब चाहते हैं।

'02–श्री सुरेश राणा–

ख्बहुत अधिक ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त,

प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में चलने वाले सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क का मदवार निर्धारण किये जाने की मांग

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्याप्त सरकारी महाविद्यालय न होने के कारण प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में छात्र/छात्राओं को स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में दाखिला लेने को मजबूर होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के शुल्क मदवार निर्धारित न होने के कारण प्रबन्धतंत्र द्वारा छात्र/छात्राओं से मनमाने ढंग से शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले शिक्षण सत्र के लिये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में चलने वाले सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क का मदवार निर्धारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं के साथ–साथ प्रदेश की कठिन अर्थोपाय के दृष्टिगत उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने की व्यवस्था है।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–6(92)/2002 दिनंक 02–07–2003 द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। मनमाने ढंग से शुल्क वसूल किये जाने की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है।

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब प्रश्न सं0–3।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 40 लाख से ऊपर ऐसे छात्र–छात्राओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न है, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर है और जो महाविद्यालयों की कमी है, उससे जूझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के उत्तर से कितनी निराशा झलकती है, सरकार स्वयं इसमें लिख रही है कि 'प्रदेश में संचालित राजकीय शिक्षण संस्थाओं के साथ–साथ प्रदेश की कठिन अर्थोपाय के दृष्टिगत उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने की व्यवस्था है।' मान्यवर, यह हालत तब है, जब इस बात का दावा है कि 03 लाख 47 हजार करोड़ का बजट इस बार प्रदेश का है और उच्च शिक्षा में 137 राजकीय विद्यालय हैं, पिछले चार वर्षों में मात्र सरकार एक बढ़ा पायी है और एडेड 331 थे, 331 हैं तथा निजी क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, 4689 विद्यालय हैं। आप समझ लीजिए, 90 प्रतिशत बच्चे–बच्चियाँ इन निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। मेरे प्रश्न के पीछे के दो भाग थे, एक तो जब हमारे पास अच्छे विद्यालय नहीं हैं या राजकीय विद्यालय नहीं हैं और सरकार खुद मान रही है तो बच्चों को मजबूरन स्ववित्त पोषित विद्यालयों में जाना पड़ता है। वहां उनके ऊपर मनमानी फीस लगती है, उसके ऊपर सरकार यह उत्तर दे रही है कि मनमाने ढंग से शुल्क वसूल किए जाने की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है। यह सदन गवाह है कि निजी क्षेत्र के जो महाविद्यालय हैं, जिसमें सरकार ने 05 हजार रूपया स्नातक के लिए और 06 हजार रुपया स्नातकोत्तर विषयों के लिए सालाना फीस निर्धारित की है। क्या इतने ही पैसे यह कालेज ले रहे हैं ? अगर शिकायत नहीं आ रही है तो मेरा सीधा–सीधा सवाल है कि रजिस्ट्रार और आपका जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी है, ये इन विद्यालयों से मिले बैठे हैं और पानी में रह कर मगर से कौन बैर करेगा ? जो बच्चा मजबूरी में निजी विद्यालय में पढ़ेगा, वह शिकायत कैसे करेगा ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से सीधे–सीधे यह सवाल करना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत से ऊपर जो उच्च शिक्षा क्षेत्र के विद्यालय हैं, उनमें शिक्षा की गुणवत्ता, मानक, छात्रों से सही फीस लेना और शिक्षकों को सही वेतन देना। शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। सरकार इसके लिए कोई मिशन मोड पर कोई निगरानी कमेटी बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आपने सुन लिया। कोई निगरानी कमेटी बनायेंगे। आपका कहना है कि फीस में ज्यादा पैसा लिया जाता है। बहुत से स्कूल हैं जहां पूरे पांच हजार भी नहीं देते।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)–

मान्यवर, निगरानी समिति पहले से ही है और मा0 मुख्य मंत्री जी प्रदेश को बनाना चाहते हैं उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश के लिए अनिवार्य है उत्तम शिक्षा और उत्तम शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षण संस्थायें हों, पर्याप्त महाविद्यालय हों, पर्याप्त विश्वविद्यालय हों, टेक्निकल एजूकेशन हो, शिक्षा की गुणवत्ता में विद्यार्थी विद्यालय जायें, महाविद्यालय जायें और शिक्षक और प्रोफेसर उन्हें पढ़ायें। इस बात के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालय में मा0 सदस्य ने कहा कि शिक्षा के लिए बहुत भटकना पड़ता है। शिक्षा के लिए बड़ा प्रदेश है जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। शिक्षा की आवश्यकता की भी अनुभूति की जा रही है। राज्य विश्वविद्यालय हैं 14, एक प्रक्रियाधीन। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है एक, डीम्ड विश्वविद्यालय एक, निजी विश्वविद्यालय 22, राजकीय महाविद्यालय 138, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय 331।

श्री मनीष असीजा–

यह तो मैंने पूछा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी आपका एक ही उत्तर काफी है, निगरानी समिति बनायेंगे या नहीं बनायेंगे। बस खत्म।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, शिक्षा सर्वसुलभ हो। पहले जैसी साजिशों के लोग शिकार न हों कि गिने चुने पढ़ें। और कोठियों वाले पढ़ें और कुटियों वाले जो हैं वह घुटघुटकर मर जायें। यह सरकार चाहती है कि शिक्षा का पर्याप्त प्रचार–प्रसार हो। जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता की बात है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, मंत्री जी, एक जवाब होना था निगरानी समिति है। बस खत्म बात। काहे को इतना भाषण कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, असीजा जी बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं और यह सवाल भी उनका बहुत अच्छा था। शिक्षा से प्रेम का सवाल था। लेकिन एक सच है पूरी दुनिया का कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं हावर्ड युनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जो प्राइवेट शैक्षिक संस्थायें हैं वह दुनिया में सबसे अच्छा काम करती हैं। सरकार नहीं करा पाती। खुद हमारे उत्तर प्रदेश में और भारत में भी जितने इंस्टीट्यूशन्स हैं मैं उनके नाम नहीं लूंगा नोएडा में हैं, मेरठ में हैं

वही बड़े इंस्टीट्यूशन्स हैं और वहॉ के निकले हुये इंजीनियर्स बहुत कामयाब रहते हैं। हमारे अपने आई0आई0टी0 हैं। प्राइवेट शिक्षा की एक मजबूरी यह है कि उनके अपने संसाधन सिर्फ बच्चों से फीस लेने के ही हैं। कोई उन्हें ग्रान्ट नहीं मिलती। जिन स्कूल, कालेज या यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट मिलती है उनके आप रिजल्ट देख लें और प्राइवेट कालेज और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट देख लें। यहां आये दिन बेसिक शिक्षा पर बहस होती है। लेकिन क्या वजह है कि हम आज भी सी0बी0एस0ई0 बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि वह जो फीस लेते हैं तो वह पढ़ाते भी हैं। उनके मां–बाप को जवाबदेह भी हैं कि आप इतनी फीस लेने के बाद हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे खयाल से आपको यह मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें रूलिंग हो गयी है कि इसमें सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के लिए जो फीस तय करेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स बाध्य नहीं होंगे वह अपनी फीस खुद तय करेंगे। तो इसमें यह तो आप कहिये कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन्स में अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि हम फीस ज्यादा ले रहे हैं या जितनी फीस ले रहे हैं उसके मानकों के हिसाब से शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हमारा वह स्टेण्डर्ड नहीं है तो यह बात सही है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन्स को आप इस तरह से रोकेंगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स बंद होना शुरू हो जायेंगे तो यह बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। क्योंकि आज भी अगर शिक्षा को कोई बचाये हैं तो प्राइवेट इदारे ही बचाये हुये हैं।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की कुछ बातों से सहमत हूं। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

कहिये न, सवाल पूछिये।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें से कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं उन महाविद्यालयों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त पेशा का रूप ले चुके हैं। मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा। दबंगों के और राजनेताओं के हाथ में विद्यालय चला गया है और डिग्री बेचने का काम चल रहा है। आपका जो 2003 का जी0ओ0 है, उसमें आपने फीस निर्धारित की हुई है, 6000/– रुपये स्नातकोत्तर की और मैं यहां पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पूरे प्रदेश में एम0एस0सी0 का कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें फीस 20000/– से ऊपर बच्चों से नहीं ली जा रही हो। मान्यवर, एक नैक का सर्वेक्षण होता है जो सरकारी विद्यालय कराते हैं, प्राईवेट विद्यालय अभी भी एक मैकेनिज्म हैं, ये यूनिवर्सिटियों के हाथ में हैं, रजिस्ट्रार उनके ऊपर है और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी है, इनके ऊपर किसी की नकेल नहीं है, यह बच्चों से मन–मानी फीस लेते हैं, वहां पर कोई शैक्षिणिक वातावरण नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब तो दे दिया मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने। आप कोई दूसरा सवाल पूछिये।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि यदि इनका मैकेनिज्म आप नहीं कर सकते, मंजूर है, आप दूसरी बात कर दें कि यह जो उत्तर लिखा है कि कोई शिकायत नहीं आई है, तो पूरे प्रदेश में जांच करा लें, जितने भी निजी क्षेत्र में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय चल रहे हैं, उसमें एम0एस0सी0 के कोर्स हैं, उसमें क्या आपके द्वारा निर्धारित 6000/– रुपये लिये जा रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 20000/– से कम कहीं नहीं लिये जा रहे हैं और ऐसे बच्चों की संख्या 40 लाख से ऊपर है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसका उत्तर तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया था, यह सब बातें आप अपने भाषण में करते, इतनी बातें तो उचित होता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है, 'प्रदेश के कठिन अर्थोपाय के दृष्टिगत उच्च शिक्षा के आवश्यक' मा0 मुख्य मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया और कहा कि देश का यह दूसरा सबसे बड़ा बजट है, साढ़े 14 परसेण्ट की वृद्धि हुई है। मैं उस बजट को देख रहा था, उच्च शिक्षा में कुल मिला कर के 03 लाख 47 हजार करोड़ में,

श्री अध्यक्ष–

यह सब बातें आप जब बजट पर बोलियेगा, तब कहियेगा, यह प्रश्न तो फीस से सम्बन्धित है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह जवाब है कठिन अर्थोपाय, जब आपने उच्च शिक्षा में बजट की व्यवस्था की नहीं सिर्फ 2585 करोड़ की व्यवस्था की, उच्च शिक्षा को आप इतना महत्व देते हैं कि 03 लाख 47 हजार करोड़ में उच्च शिक्षा के लिए आपने सिर्फ 2585 करोड़ दिया और फिर आप कहते हैं कि कठिन अर्थोपाय के नाते यह निजीकरण हो रहा है। तो क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि उच्च शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

नहीं ऐसा नहीं है, आप बैठिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, आप इसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, दरअसल उच्च शिक्षा के लिए जो आज के दिन सवालिया निशान पूरे देश में बना हुआ है, वह फीस नहीं है, वैचारिक है कि क्या हम उच्च शिक्षा को अपने हिसाब से चलायेंगे। उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ हम क्या करेंगे, हम टीचर्स के साथ क्या करेंगे, तो आज यह परेशानी है, मान्यवर फीस परेशानी नहीं है। मैं

यह इसलिए कह रहा हूं कि असीजा जी के प्रश्न में जो बात थी, यह उससे बिल्कुल भिन्न बात है। मान्यवर, मैं क्योंकि एक इन्स्टीट्यूशन चला रहा हूं, हमारे यहां बहुत कम फीस होने के बावजूद भी न एम0ए0 में न एम0एस0सी0 में बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि गर्ल्स डिग्री कालेज भी है वहां, गर्ल्स–ब्वाज कालेज भी है, वहां फीस बहुत कम है, बच्चे वहां जाते हैं। प्राईवेट कालेज आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं इतना, मैं नहीं जानता किस कालेज की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसकी जांच हो जायेगी, अगर आप लिखकर दे देंगे, लेकिन प्राईवेट कालेज में फीस ज्यादा होने की वजह से बच्चे जाते ही नहीं हैं, उनके आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि उनके खर्चों को बरदास्त कर सकें। तो यह सूचना बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से किसी एक–आध जगह की हो तो आप दे दीजिए, उसमें जांच हो जायेगी।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, इस समय 40 लाख से ऊपर बच्चे उच्च शिक्षा में हैं और यह बात आप सही कह रहे हैं कि जब राजकीय महाविद्यालय का विकल्प है, तो कोई स्ववित्त पोषित में नहीं जाता और यही मेरी मूल भावना है कि अगर हम 137 राजकीय विद्यालय को 138 कर पाये चार साल में, तो मेरा यह निवेदन है, यह अपेक्षा है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जिन बच्चों में आप दिलचस्पी रखते हों, आप भेज दीजिए, सिर्फ हास्टल फीस दे दें, हम बिल्कुल फ्री पढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठ जाइये, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

'4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति की जानकारी एवं स्थापित नये उद्योगों की जानकारी

'05–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा कोई औद्योगिक नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2012 से अक्टूबर, 2015 तक प्रदेश में कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं तथा कितने उद्योग पलायन कर गये हैं ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 बनायी गयी है।

उपलब्ध सूचनानुसार प्रदेश में अप्रैल, 2012 से अक्टूबर, 2015 तक 158229 सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्यम/उद्योग स्थापित हुए हैं।

किसी उद्योग के पलायन की सूचना नहीं है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री से संबंधित बहुत विस्तार से इस विधान सभा में चर्चा होती है। सरकार भी बड़ी चिन्तित है। कई प्रकार के सबमिट किए हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हुआ है, वह बात अलग है लेकिन फोटो बढ़िया आज छपी थी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इन उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी की गयी है बाकी आस–पड़ोस के स्टेट्स में बिजली के दाम कम हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले जो उसका रॉ–मैटेरियल होता है, वह बिजली होती है, दूसरा उसका टैक्स स्ट्रक्चर होता है, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में इन उद्योगों को दी जा रही बिजली को सब्सिडाइज करेंगे, उसके दाम कम करेंगे ? क्या उनको आकर्षित करने के लिए किसी प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करेंगे। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे और अंतिम प्रश्न यह है कि इन उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश में विगत चार वर्षों के अंतर्गत कितना निवेश आया है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

2012 से 2015 तक का तो आ गया, इतने सूक्ष्म उद्योग हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कोटे से डीजल भी लेते हैं, कोयला भी लेते हैं, बिजली की चोरी भी करते हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इनके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट बिजली की चोरी करते हैं। इसका यह उत्तर है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप इंडस्ट्री के विकास की बात करेंगे अगर हम इंडस्ट्री को सब्सिडाइजड बिजली देने की बात करेंगे तो उत्तर यह आयेगा कि उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट बिजली चोरी करते हैं, तो अगर यह सरकार का उत्तर है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

यह औद्योगिक नीति का सवाल है, बिजली पर कहां चले गए आप ? यह तो आपने प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा कोई औद्योगिक नीति बनायी गयी है, उन्होंने कहा जी हां, अब आप औद्योगिक नीति का पूछिए न।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 15 तक 1,63,421 उद्यम स्थापित किए गए। इसमें कुल 24,368.13 करोड़ का निजी निवेश हुआ है तथा 12,67,581 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष हुआ 24 लाख 3 हजार 18 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष, कुल 15,10,599 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए निजी सहभागिता के माध्यम के अलावा अवस्थापना सुविधाओं की विकास की परियोजनाओं हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी तथा शेष को 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी वह बता रहे हैं जो पढ़ कर आए हैं। मेरा इसीलिए समय के कारण यह निवेदन है कि जो माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं पढ़कर देते हैं। पढ़ा हुआ तो जो उनको लिखकर दिया गया है वह है लेकिन सरकार की नीतियों के बारे में यह कुछ बता नहीं पाएंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर बता देंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट आना भी चाहता है तो वह भी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में न तो इंडस्ट्री का वातावरण है, न माहौल है न सबिस्डी है, न उनको आकर्षित करने के कोई कारण हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बाहर जाना चाहते हैं क्या ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, नहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वह बिना पढ़े भी कुछ बता दें।

श्री राम मूर्ति वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग के ठेकेदार आप नहीं हैं। उद्योग को लगाने का ठेका आपके पास नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास है।

श्री सतीश महाना–

हमारे पास ठेका है, जितना सरकार के पास ठेका है, उससे ज्यादा ठेका हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, पहले मंत्री जी को सुन लीजिए, जब वे बैठ जाएं तब आप खड़े होईए, आप तो पहले ही कहने लगते हैं। जब वे बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों खड़े हो गए। जब वे बोल रहे हैं तो आप बैठिए।

श्री राममूर्ति वर्मा–

यह मुख्य मंत्री जी के पास है, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है और पूरी दुनिया के उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं, उद्योग लगाने जा रहे हैं, काम शुरु करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र–छात्रों को दिये जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति की जानकारी व छात्रों की संख्या विषयक

'06–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की विगत वर्षों 2014–15 व 2015 अक्टूबर तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति करायी गयी है ? यदि हां, तो किन–किन कक्षाओं व कोर्सों में कितने–कितने छात्रों को दी गयी है तथा क्या शेष छात्रों को भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

जी हां।

वर्ष 2014–15 में दश्मोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोर्सवार भेजी गयी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण/सूची संलग्न है।[४४]

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं प्राप्त हुयी है, उनके सम्बन्ध में नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्र–छात्राओं द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति के 46,525 छात्र–छात्राओं हेतु रुपया 11345.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के 9190 छात्रों हेतु रुपया 1100.00 लाख की धनराशि भुगतान हेतु संस्तुत की गयी है।

वर्ष 2014–15 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रुपया 11345.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के भुगतान की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत–प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है। भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होने पर वर्ष 2014–15 की देय धनराशि रुपया 1100.00 लाख की शुल्क प्रतिपूर्ति का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

'07–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया,

प्रदेश में अवस्थापना सुविधा को विकसित करने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई निवेश नीति का विवरण व उक्त नीति के निवेश हेतु की गयी धनराशि की जानकारी

'08–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

---

[४४] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 182–183 पर)

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना सुविधा को विकसित करने के लिये कोई निवेश नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? उक्त नीति के फलस्वरूप प्रदेश में वर्ष 2015 में अब तक कुल कितनी धनराशि के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उद्योगों की अधिकारिक स्थापना कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 बनायी गयी है।

वर्ष 2015 में 116 इच्छा पत्र (निवेश हेतु प्रस्ताव) रु0 10652 करोड़ के दाखिल हुये हैं।

सी0एस0ई0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में किसानों की तबाह फसलों हेतु क्षतिपूर्ति दिलाया जाने विषयक कार्य योजना बनाये जाने की मांग

'09–श्री नदीम जावेद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0एस0ई0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में किसानों की लगभग 78 प्रतिशत फसलें तबाह हुई हैं ? यदि हां, तो इस भारी तबाही के अनुपात में किसानों को क्षतिपूर्ति के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

सी0एस0ई0 की रिपोर्ट कृषि विभाग में प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रदेश में राजस्व (राहत) विभाग द्वारा 33 प्रतिशत या उससे अधिक कृषि फसलों की दैवीय आपदा यथा–बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा आदि से प्रदेश में हुयी क्षति का आंकलन जिलाधिकारीगणों से प्राप्त कृषि क्षतिपूर्ति रिपोर्ट के आधार पर राहत के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से कृषि निवेश अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

कृषि विभाग में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत बीमित कृषकों को ही क्षतिपूर्ति का आंकलन करके धनराशि बीमा कम्पनी के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में फरवरी/मार्च, 2015 में दैवीय आपदा से हुयी क्षति के आंकलन के आधार पर स्वीकृत/भुगतान की गयी धनराशि (परिशिष्ट 'क') तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत/भुगतान की गयी धनराशि (परिशिष्ट 'ख') का जनपदवार विवरण संलग्न है।[४]

प्रश्न नहीं उठता।

'10–श्री धर्मपाल सिंह–

[४] (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ–194–207)

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

वित्तीय वर्ष 2015–16 को किसान वर्ष घोषित करने पर अनुमन्य सुविधा उपलब्ध करवाने विषयक

'11–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 को किसान वर्ष घोषित करते हुए किसानों की स्थिति सुधारने हेतु 1000 एग्री जंक्शन स्थापित करने की योजना बनाकर बजट भी आवंटित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि व्यापक किसान हित की उक्त योजना जमीनी स्तर पर लागू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

योजनान्तर्गत 1000 एग्री जंक्शन स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 1000 एग्री जंक्शन स्थापित करने वाले लाभार्थियों का चयन पूर्ण कर लिया गया है।

सभी चयनित लाभार्थियों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षणोपरान्त सभी लाभार्थियों को बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों के विक्रय हेतु अनुज्ञा (लाइसेंस) जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

चयनित लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिये जनपदवार बैंकों का निर्धारण कर उद्यम सम्बन्धी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराई जा रही है।

'12–श्री लोकेन्द्र सिंह–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में कृषि उपज को बढ़ावा देते हुये कार्य योजना की मांग

'13–डा0 अरुण कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उपज एवं कृषि आधारित उद्योग/व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये कोई कारगर योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

प्रदेश में कृषि उपज एवं कृषि आधारित उद्योग/व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये ''कृषि नीति–2013'' के अन्तर्गत मुख्य रूप से कृषि उपज को बढ़ाने वाले तकनीकी कारकों को कृषकों तक पहुंचाने, पंक्तिबद्ध बुवाई, कृषि यंत्रीकरण, बीज एवं प्रजाति प्रतिस्थापन दर में वृद्धि तथा कृषि लागत, घटाने की दृष्टि से सोलर पम्प की स्थापना इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

- पंक्तिबद्ध बुवाई फसलों की उपज वृद्धि में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्य रूप से धान की पंक्तिबद्ध बुवाई हेतु ड्रम सीडर के प्रयोग को प्रदेश में विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिये न्याय पंचायत स्तर पर ड्रम सीडर के प्रयोग के प्रदर्शन कराये जाते हैं।
- रबी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं की पंक्तियों में बुवाई के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं, जिसे किसान देखकर सीखता है और प्रयोग में लाता है। धान के अतिरिक्त अन्य फसलों की बुवाई हेतु सीडड्रिल एवं फर्टिसीडड्रिल को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों का सही उपयोग किया जा सका है।
- कृषि में मजदूरी की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके दृष्टिगत प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण यथा–रोटावेटर, सीडड्रिल, लेवलर, हैरो, स्प्रेयर तथा कम्बाईन आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे उपज वृद्धि के साथ–साथ कृषि लागत में कमी आ रही है।
- गुणावत्तायुक्त प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सीड–रोलिंग प्लान तैयार किया गया है जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि आगामी पांच वर्षों में प्रमाणित बीजों के वितरण के फलस्वरूप बीज प्रतिस्थापन दर लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त किया जा सके।
- बीज प्रतिस्थापन दर के साथ प्रजाति प्रतिस्थापन दर हेतु सीड–रोलिंग प्लान में नई प्रजातियों से पुरानी प्रजातियों को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य भी निर्धारित है जिसके फलस्वरूप नई प्रजातियों के बीज विगत् वर्षों की तुलना में अधिक मात्रा में कृषकों को उपलब्ध हुये हैं।
- प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था तथा कृषि लागत दर को कम करने में सोलर पम्प की अहम भूमिका है। कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा सोलर फोटो वोल्टिक सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है तथा कृषकों के खेतों पर 3617 सोलर पम्प की स्थापना भी करायी जा चुकी है। कृषकों में यह लोकप्रिय हुआ है।
- मृदा परीक्षण द्वारा मृदा स्वास्थ्य की जानकारी कृषकों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण के उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपलब्धता के द्वारा दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप किसान खाद/उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0प्र0

मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–17(क)(1)(क) एवं मण्डी नियमावली, 1965 के नियम–137 के अन्तर्गत रु0 5.00 करोड़ से अधिक लागत वाली संयंत्र और मशीनरी वाली नयी प्रसंस्करण इकाइयों को शासन द्वारा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु मण्डी शुल्क से अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दिये जाने का प्राविधान है।

<u>उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0</u>

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये उ0प्र0, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन) तथा कृषि उत्पाद एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिये अनेक प्रकार का वित्तीय अनुदान एवं रियायतें अनुमन्य की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

'14–श्री दलवीर सिंह–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों/मजरों को जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 04–09–2015 पर की गई कार्रवाई की जानकारी

01–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में 05 ग्रामों/मजरों को जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10683608, दिनांक 04–09–2015 निदेशक, कृषि मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों/मजरों को चयन हेतु विचारार्थ सूचीबद्ध कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत में वर्ष 2013 से 2015 के मध्य निर्मित सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा मानक के अनुसार गुणवत्ता की मांग विषयक

02–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जनेश्वर मिश्र योजना में वर्ष 2013 से 2015 के मध्य बनी सड़कों की गुणवत्ता जांचने के दौरान बड़े पैमाने पर घटिया स्तर का निर्माण वास्तविक लम्बाई के स्थान पर कम लम्बाई पाया जाना आदि अनियमितताओं की शिकायतें संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं मानकानुसार गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत अवधि में जनपद फिरोजाबाद में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामों में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त खराब होने की बात जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा संज्ञान में लाई गई थी।

रैन्डम आधार पर 11 जनेश्वर मिश्र ग्रामों की विभागीय जांच एवं 22 ग्रामों की एग्रीकल्चरल फाइनेंस कार्पोरेशन से करायी गई थर्ड पार्टी जांच में कार्य मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में मे0 श्री सीमेन्ट की फैक्ट्री के लगने के बाद उसके आस–पास फैले प्रदूषण की जांच रिपोर्ट की जानकारी

03–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरबाद में मे0 श्री सीमेन्ट की फैक्ट्री के लगने के बाद क्या फैक्ट्री के आस–पास सरकार ने वायु प्रदूषण की जांच करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थित में यू0पी0 ग्राइन्डिंग यूनिट–

श्री सीमेन्ट लि0 एक सीमेन्ट ग्राईन्डिंग उद्योग है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में सीमेन्ट ग्राइन्डिंग उद्योग के आस–पास हेतु परिवेशीय वायु गुणता के मानक निर्धारित नहीं है।

जनपद आगरा, मथुरा व एटा के सौरू (ब्रज क्षेत्र) में आने वाले करोड़ों देशी–विदेशी पर्यटकों के लिये आगरा में ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाये जाने की मांग

04–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि आगरा, मथुरा व जनपद एटा के सौरू (बृज क्षेत्र) में एक साल में करीब पांच करोड़ देशी–विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिये आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा में ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत स्थलों पर भारी संख्या में देशी–विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक–निजी–सहभागिता के आधार पर एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई

अड्डा बनाये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है जिसके अनुसरण में चयनित कन्सलटेन्ट (राइट्स लिमिटेड एवं मेसर्स के0पी0एम0जी0 एडवाइजरी सर्विसेज) द्वारा हिरणगांव, तहसील–टुण्डला, जनपद–फिरोजाबाद तथा भदरौली, तहसील–बाह, जनपद आगरा स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त स्थलों के सम्बन्ध में साईट क्लीयरेन्स हेतु नागर विमानन मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) विकलांग पेंशन योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19–11–15 द्वारा जानकारी

05–डा0 अरुण कुमार–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) में बरेली महानगर में कितने लोगों को विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र संख्या–क–5/378407, दिनांकित 19–11–2015 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उपलब्ध न कराने का क्या कारण है ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी)–

बरेली महानगर में वित्तीय वर्ष 2014–15 में 2767 विक्लांगजनों को तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) में 2765 विकलांगजनों को विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

जी हां।

जिला विकलांगजन विकास अधिकारी, बरेली द्वारा अपने पत्र संख्या–927/वि0ज0वि0/ 2015–16, दिनांक 28–11–2015 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है।

जनपद बरेली शहर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) सहयोग राशि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19–11–15 के सम्बन्ध की गई कार्यवाई विषयक

06–डा0 अरुण कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) में बरेली शहर में कितने लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की सहयोग राशि प्राप्त हुई तथा कितने लोगों को मिलनी शेष है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5/378405, दिनांकित 19–11–2015 समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत बरेली शहर में 419 व्यक्तियों को सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं वर्ष 2014–15 के 46 आवेदन–पत्र भुगतान हेतु लम्बित हैं। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में (दिसम्बर, 2015 तक) 83 आवेदकों को आर्थिक सहायता अनमन्य करायी जा चुकी है तथा 82 आवेदकों के आवेदन–पत्र भुगतान हेतु अवशेष हैं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

07–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

खदिनांक 16–02–2016 को अता0प्र0सं0–197 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में मण्डी समितियों द्वारा दस वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी जीर्ण–शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराने की विषयक

08–श्री संजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मंडी समितियों द्वारा निर्मित दस वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी जीर्ण–शीर्ण सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समितियों की वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिगत जीर्ण–शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में स्थित नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया के यू0पी0एस0आई0डी0 क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कराये जाने की जानकारी

09–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में स्थित नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया के यू0पी0एस0आई0डी0 क्षेत्र में छोटे–बड़े कारखाने स्थापित हैं परन्तु कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निगम के औद्योगिक क्षेत्र में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा सार्वजनिक शौचालय निर्मित कराये जाने का प्राविधान नहीं है। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने कार्मिकों के लिये स्वयं इस प्रकार की सुविधायें अपने परिसर में विकसित की जाती हैं।

जनपद इलाहाबाद में स्थित नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया एवं गंगा तट पर स्लाटर हाउस कम्पनियों तथा कारखानों व नगर क्षेत्र का सीवरयुक्त जहरीला पानी गंगा नदी में बहाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर कार्रवाई विषयक

10–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में स्थित नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया एवं गंगा तट पर स्थित स्लाटर हाउस कम्पनियों तथा कारखानों व नगर क्षेत्र का सीवरयुक्त जहरीला पानी सीधा गंगा नदी में बहाये जाने के कारण गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कम्पनियों व कारखानों का जहरीला एवं गंदे पानी को गंगा नदी में गिरने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में जल प्रदूषणकारी प्रकृति के निम्नलिखित दो उद्योग स्थापित हैं :–

1–मै0 रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0।

2–मै0 देवप्रयाग पेपर मिल प्रा0 लि0।

उक्त दोनों उद्योगों में पर्याप्त क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयन्त्र स्थापित है। वर्तमान में क्रम सं0–01 पर उल्लिखित उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द है। क्रम सं0–02 पर उल्लिखित उद्योग द्वारा बोर्ड मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

गंगा तट पर कोई भी स्लाटर हाउस स्थापित नहीं है।

नगरीय क्षेत्र में जनित सीवेज की मात्रा लगभग 260 एम0एल0डी0 है। वर्तमान में सीवेज के शुद्धीकरण हेतु 06 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित हैं जिनकी क्षमता निम्नवत् है :–

1–एस0टी0पी0, सलोरी	29 एम0एल0डी0
2–एस0टी0पी0, नैनी	80 एम0एल0डी0
3–एस0टी0पी0, राजापुर (वर्तमान में 30 एम0एल0डी0)	60 एम0एल0डी0
4–एस0टी0पी0, पोंगहट	10 एम0एल0डी0
5–एस0टी0पी0, नुमायाडाही	50 एम0एल0डी0
6–एस0टी0पी0, कोडरा	25 एम0एल0डी0

उक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट्स के माध्यम से कुल 224 एम0एल0डी0 सीवेज का शुद्धीकरण किया जा रहा है। शेष नालों के उत्प्रवाह को वर्तमान में बायो–रेमेडियेशन की सहायता से शुद्धीकृत किया जा रहा है। उपरोक्त एस0टी0पी0 से शुद्धीकृत उत्प्रवाह की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के रुधौली कस्बे में स्थापित बजाज ग्रुप की अठदमा चीनी मिल द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण करने वाले दोषी प्रबन्धक/अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई विषयक

11–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुधौली कस्बे में स्थापित बजाज ग्रुप की अठदमा चीनी मिल द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के कारण स्थानीय जनता त्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल में दूषित जल को साफ करने के लिये लगे औद्योगिक संयंत्र न चलाकर सीधे दूषित जल उत्सर्जित करने वाले दोषी प्रबन्धक/अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के अठदमा रुधौली में बजाज ग्रुप की शुगर एवं डिस्टलरी इकाई स्थापित है। शुगर इकाई में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु पूर्ण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित है। इकाई द्वारा उत्प्रवाह की मात्रा कम करने हेतु एक्सेस कन्डेन्सर में ठण्डा कर रिसाइकिल किया जाता है तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को लैगून में एकत्र कर सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। शेष शुद्धीकृत उत्प्रवाह सतनरया नाला में निस्तारित किया जाता है। उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत वर्ष 2015 तक सहमति प्रदान की गयी थी।

उद्योग में ईंधन के रूप में बैगास का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 65 मी0 ऊंची चिमनी के साथ वेट स्क्रबर स्थापित हैं उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत वर्ष 2015 तक सहमति प्रदान की गयी थी।

मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0 डिस्टलरी इकाई में जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। पूर्व में इकाई द्वारा टैंकर से स्पेण्टवाश को परिसर के बाहर निस्तारित पाये जाने के फलस्वरूप उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–27(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। उद्योग द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 5 स्टेज मल्टीइवापरेटर स्थापित किये गये हैं। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10–12–2015 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि इवापरेटर के माध्यम से जनित रॉ–स्पेण्टवाश एवं शुद्धीकृत स्पेण्टवाश को एकत्र कर बायो कम्पोस्टिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जा रहा है। उद्योग में

शुन्य उत्प्रवाह निस्तारण तकनीक स्थापित है। शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत वर्ष 2016 तक सहमति प्रदान की गयी है।

उद्योग में ईंधन के रूप में बैगास का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 45 मी0 ऊंची चिमनी के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर स्थापित है। उद्योग का दिनांक 10–05–2015 को उत्सर्जन का अनुश्रवण किया गया था जिसमें प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी थी। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत वर्ष 2016 तक सहमति प्रदान की गयी है।

प्रदेश में ओ0बी0सी0 के अन्तर्गत आने वाली 17 जातियों को एस0सी0 का दर्जा दिलाने के लिये प्रदेश सरकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की जानकारी विषयक

12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओ0बी0सी0 के अन्तर्गत आने वाली केवट, निषाद, मल्लाह, नाई, कश्यप, धीमर आदि 17 जातियां आती हैं, को एस0सी0 का दर्जा दिलाने के लिये प्रदेश सरकार कोई औपचारिक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

शासन के पत्र संख्या–1059/प्र0स0स0क0/2013, दिनांक 15–02–2013 द्वारा 17 पिछड़ी जातियों (कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ) को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। उक्त सूची में 'नाई' जाति शामिल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सन् 1997 में सृजित जनपद–चन्दौली में सेल्सटैक्स कार्यालय स्थापित कराये जाने विषयक

13–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1997 में सृजित जनपद चन्दौली में अब तक सेल्सटैक्स का कार्यालय स्थापित न होने से व्यवसायियों को जनपद वाराणसी में सेल्सटैक्स संबंधी कार्य के लिये जाना पड़ता है जिससे उनको काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद चन्दौली में सेल टैक्स आफिस बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–चन्दौली में वाणिज्य कर कार्यालय स्थापित न होने से असुविधा की शिकायत लगभग नगण्य रही तथापि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वाणिज्य कर

कार्यालय के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान/भवन तथा मूलभूत सुविधाओं/संसाधनों की आवश्यकता पर अभिमत प्रेषित करने का अनुरोध पूर्व में जिलाधिकारी, चन्दौली से किया गया है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2014–2015 के बजटीय प्राविधान में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के स्थापना का कार्य प्रारम्भ कराने की जानकारी विषयक

14–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2014–2015 के बजटीय प्राविधान में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की गई थी किन्तु अभी तक विश्वविद्यालय के स्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

इलाहाबाद में एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा दिनांक 02–01–2013 को की गयी थी। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 10 करोड़ का बजटीय प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 50 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा प्रस्तावित सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चिन्हित 100 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग को भूमि हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात विश्वविद्यालय का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की मांग

15–श्री ललितेश पति त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज के अभाव में एवं नक्सली क्षेत्र होने के कारण गरीब छात्र/छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 01 राजकीय महाविद्यालय तथा 05 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

जनपद–बरेली में मिलिटरी हवाई अड्डे में एक सिविल इन्क्लेव बनाने की योजना की जानकारी विषयक

16–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में मिलिटरी के हवाई अड्डे में ही एक सिविल इन्क्लेव बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा एवं नागरिकों को आवागमन के लिये ये सिविल इन्क्लेव कब तक उपलब्ध हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर एक नये सिविल इन्क्लेव निर्माण की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कार्य योजना है।

सिविल इन्क्लेव का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। उनसे अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत प्रयोजनार्थ अपेक्षित 25 एकड़ भूमि के क्रय की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है और वे सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई आरम्भ करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 के कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7–9–2015 पर की गई कार्रवाई की जानकारी

17–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 में सतबरी रोड से चर्च तक, सतबरी रोड सब्जी मंडी से यादव डेरी होते म0नं0–105 आनन्द भवन, न्यू आजाद नगर तक, न्यू आजाद नगर सब्जी मंडी चौराहा मन्दिर से बाई पास तक, मंगला विहार पराग पार्लर के बगल वाली सड़क, न्यू आजाद नगर हंस मंदिर के पीछे वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का निदेशक, मण्डी, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित पत्र अंकित दिनांक 07–09–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–बरेली महानगर में वर्ष 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2015 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी पात्र महिलाओं को धनराशि उपलब्ध न होने की जानकारी के सम्बन्ध में

18–डा0 अरुण कुमार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–2015 में 31 दिसम्बर, 2015 तक बरेली महानगर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी पात्र महिलाओं को धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है ? क्या सरकार उक्त पात्र महिलाओं को भी इसी वर्ष धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2015 तक बरेली महानगर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 46 पात्र महिलाओं को धनराशि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

जी हां।

31 मार्च, 2016 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 15–01–2016 एवं 31/12 के सम्बन्ध में विकलांगजनों के पेंशन दिलाये जाने की जानकारी के सम्बन्ध में

19–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित, मा0 शमशेर बहादुर, सदस्य विधान सभा, उ0प्र0, का पत्र दिनांक 15–01–2016, दि0 31–12–2014 को विकलांग जन विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जो 2/551, जानकीपुरम् वार्ड जानकीपुरम् द्वितीय जिला–लखनऊ के विकलांगजनों को पेंशन दिलाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

जी हां।

आवेदन–पत्र में उल्लिखित आवेदक श्री मुकेश कुमार दुबे का पेंशन का आवेदन–पत्र स्वीकृत कर पेंशन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या–31322017927 है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मछुआ समुदाय के लोगों को मछुआ आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की जानकारी के सम्बन्ध में

20–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष 2015–2016 में पूर्व की भांति प्रदेश के मछुआ समुदाय के लोगों को मछुआ आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रियाज अमहद)–

केन्द्र पोषित योजना के रूप में मछुआ आवास योजना 2014–15 तक संचालित की जाती रही है। वर्ष 2015–16 में इस मद में केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण लाभार्थियों को मछुआ आवास हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना होने के कारण केन्द्रांश की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की गरीब एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु अनुदान धनराशि (दस हजार) वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक 18–1–16 तक उपलब्ध बालिकाओं की संख्या के जानकारी के सम्बन्ध में

21–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की गरीब एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु रु0 10000/– (दस हजार) की अनुदान धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–2015 एवं वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दिनांक 18–1–16 तक कितनी बालिकाओं को दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु संचालित शादी/बीमारी योजना का क्रियान्वयन सीमित संसाधनों के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से स्थगित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी उक्त योजना हेतु आय–व्ययक में मात्र रुपया एक हजार का सांकेतिक प्राविधान उपलब्ध होने के कारण गत वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक 18–1–16 तक पिछड़ा वर्ग की किसी भी गरीब एवं पात्र परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

प्रदेश में बन्द ईंट भट्ठा को चलवाने हेतु जानकारी विषयक

22–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द, ईंट भट्ठा को चलवाने हेतु सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेन्स अधिसूचना, 2006 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत आच्छादित परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है। प्रदेश स्तर पर स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कमेटी तथा स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट अथारिटी का गठन इस सम्बन्ध में किया गया है।

ईंट भट्ठों की संख्या अधिक होने के कारण उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये सरलीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–125, दिनांक 15–01–2016 एवं अधिसूचना संख्या–166, दिनांक 20–01–2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली माइनिंग परियोजनाओं हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) का गठन किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश के ईंट भट्ठों को पर्यावरणीय क्लीयरेन्स जिला स्तर से जारी होगी।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को उपरोक्त के अनुपालन हेतु शासनादेश दिनांक 25–01–2016 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मण्डी परिषद् में पिछले 2 वर्षों से हुई आय से फिरोजाबाद की जर्जर एवं टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग पर विचार

23–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में मण्डी परिषद् को विगत 2 वर्षों में कुल कितनी आय किन–किन मदों में हुयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मण्डी समिति फिरोजाबाद की टूटी एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत उक्त आय से करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2013–14, 2014–15 में हुई आय का मदवार विवरण [४]संलग्न है।

मण्डी समिति फिरोजाबाद की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण मार्गों की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली शहर में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों को पेंशन दिलाये जाने की मांग की जानकारी व शेष बचे हुये आवेदन–पत्रों को पेंशन देने की नीति की जानकारी

24–डा0 अरुण कुमार–

---

[४] (देखिये नत्थी 'घ'––आगे पृष्ठ पर)

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 में बरेली शहर में वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए तथा परीक्षणोंपरान्त कितनों को वृद्धावस्था पेंशन दे दी गई है ? शेष आवेदन–पत्रों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बरेली शहर में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत कुल 302 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये। सत्यापनोपरान्त 135 आवेदन–पत्र पात्र पाये गये हैं, जिनकी आनलाइन फीडिंग करा दी गयी है।

शेष आवेदन–पत्र अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिये गये है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के कतिपय गांवों को पिछले दो वर्षों से लगातार पड़ रहे सूखे के कारण सरकार द्वारा सब्सिडी दिलाये जाने की मांग

25–श्री दीपक पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में दो वर्षों से लगातार पड़ रहे सूखे के कारण प्रदेश सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका, करछना तथा कौंधियारा में कितने किसानों ने उक्त हेतु पंजीयन करवाया और कितने किसानों को इसका लाभ मिला तथा कितने किसानों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है ? क्या सरकार शेष किसानों को इसका लाभ उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका में 1530, करछना में 3866 तथा कौंधियारा में 3172, कुल 8568 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है तथा 729 किसानों को बीज क्रय करने पर उन्हें अनुदान का लाभ दिया गया है। बीज क्रय करने वाले समस्त किसानों को लाभ दिया गया है।

बीज क्रय करने वाले किसानों को ही अनुदान का लाभ देने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद स्थित नैनी इण्डस्ट्रीयल एरिया के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में मजदूर व कर्मचारियों के लिये रैन बसेरा एवं टीन शेड की व्यवस्था कराने की मांग

26–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद स्थित नैनी इण्डस्ट्रीयल एरिया के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में मजदूरों व कर्मचारियों के वास्ते रात्रि रुकने हेतु कहीं भी रैन बसेरा की व्यवस्था या टीन शेड की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एरिया में स्थलों का चयन कर रैन बसेरा या टीन शेड की व्यवस्था करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निगम के औद्योगिक क्षेत्र में रैन बसेरा अथवा टीन शेड निर्मित कराये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद बलिया में ग्रामीण स्टेडियम खोलने की मांग पर विचार विषयक

27–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में ग्रामीण स्टेडियम खोलने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूजर)–

जी नहीं।

शासनादेश–10(4)/35–आ–1/2011–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना समाप्त कर दी गयी है।

28–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

खदिनांक 16–02–2016 को अता0प्र0सं0–191 द्वारा उत्तरित,

जनपद लखनऊ में विधायक निवास नया बी–ब्लाक, दारुलशफा में लिफ्ट बदलने की मांग

29–डा0 मो0 अयूब–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास, नया बी–ब्लाक, दारुलशफा लखनऊ की लिफ्ट काफी दिनों से खराब होने के कारण इसका संचालन बंद है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिफ्ट के स्थान पर बदलकर नयी लिफ्ट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। ओटिस कम्पनी की रिपोर्ट के आधार पर लिफ्ट संचालन योग्य नहीं रह गयी है। इसे बदलकर नयी लिफ्ट लगाने हेतु शासनादेश 08–10–2015 द्वारा रु0 36.11 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों के लिए वन स्टाप शॉप एग्री जंक्शन प्रारम्भ करने की योजना एवं खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में एग्री जंक्शन प्रारम्भ करने की संख्या पर विचार करने की मांग

30–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के लिए वन स्टाप शॉप एग्री जंक्शन प्रारम्भ करने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में कितने एग्री जंक्शन प्रारम्भ किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जी हां।

02 (दो)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टर कालेजों में शिक्षारत पिछड़ी जाति के पात्र गरीब छात्र/छात्राओं को शिक्षा सत्र 2014–15 में छात्रवृत्ति विषयक एवं पिछड़ी जाति के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में

31–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टर कालेजों में शिक्षारत् पिछड़ी जाति के कितने पात्र गरीब छात्र/छात्राओं को शिक्षा सत्र 2014–15 में छात्रवृत्ति प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि अधिकांश जनपदों में 50 प्रतिशत से ज्यादा छात्र/छात्राओं का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार एक समान नीति लागू करते हुए पिछड़ी जाति के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

शैक्षिक सत्र 2014–15 में प्रदेश के इण्टर कालेजों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 10 के अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के 264184 छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति मद में रु0 18.76 करोड़ एवं कक्षा 11 व 12 के 429736 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति मद में रु0 128.68 करोड़ तथा 434660 छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति मद में रु0 16.44 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे अन्तरित करायी गयी है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन लखनऊ द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 में निर्धारित अवधि तक ऑनलाइन भरे गये छात्र/छात्राओं के आवेदन–पत्रों में से शिक्षण संस्थान स्तर से सत्यापित/अग्रसारित किये गये कक्षा 9 व 10 के कुल 416058 छात्र/छात्राओं तथा कक्षा 11 व 12 के कुल 889802 छात्र/छात्राओं के डाटा की स्क्रूटनी/जांच का कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित विभागों यथा–जाति, आय एवं निवास, प्रमाण–पत्रों का मिलान राजस्व परिषद् की वेबसाइट से, हाईस्कूल, इण्टर अनुक्रमांक/वर्ष का मिलान सम्बन्धित शिक्षा परिषद् की वेबसाइट तथा बैंक सम्बन्धी विवरण का सत्यापन पी0एफ0एम0एस0 सर्वर के माध्यम से कराया गया, जिसमें से कक्षा 9 व 10 के कुल 262284 छात्र/छात्राओं का डाटा शुद्ध (करेक्ट) श्रेणी में तथा 85637 छात्र/छात्राओं का डाटा संदेहास्पद (सस्पेक्ट) श्रेणी में पाया गया था। इसी प्रकार कक्षा 11 व 12 में कुल 476405 छात्रों का डाटा शुद्ध (करेक्ट) श्रेणी में तथा 403891 छात्रों का डाटा संदेहास्पद (सस्पेक्ट) श्रेणी में पाया गया था।

जिन छात्रों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन–पत्र में बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, जाति, आय एवं निवास प्राण–पत्र इत्यादि से सम्बन्धित त्रुटियां की गयी थीं, के आवेदन–पत्र 26 बिन्दुओं पर स्क्रूटनी के उपरान्त उनके डाटा संदेहास्पद श्रेणी में हो गये थे, को जनपद स्तर पर गठित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से स्वीकृति/निरस्त का अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से अपात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को निरस्त एवं पात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को स्वीकृत कर लॉक किया गया। तत्पश्चात् ही उपरोक्त पात्र पाये गये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया गया।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना फण्ड लिमिटेड योजना है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियाँ उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेगी एवं अग्रेणीत, नहीं होगी। उक्त स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं को उपलब्ध बजट सीमा के अनुसार ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जाता है।

जहां तक एक समान नीति लागू करते हुये पिछड़ी जाति के सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रश्न है, पात्रता एवं बजट की उपलब्धता तक सभी पात्र छात्र/छात्राओं को पहले ही छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों/मजरों को जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18–9–2015 पर की गई कार्रवाई की जानकारी

32–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों/मजरों का जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयन कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0 10689019 पत्र संख्या : सीएम/वि0को0/एम0/ पी0जी0 10689019/2015, दिनांक 18–09–2015 पर आदेश निदेशक कृषि मण्डी परिषद्, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में अंकित ग्रामों/मजरों को चयन हेतु विचारार्थ सूचीबद्ध कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर विचार

33–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गूजर–

जी हां।

शासनादेश संख्या 1809/बयालिस–2006–1/ए0क्यू0 04/05, दिनांक 11–09–2006 द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश की शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

34–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

जनपद बुलन्दशहर को ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने की मांग

35–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर को शामिल किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश सरकार किसानों के जीवन स्तर के उन्नयन के लिये फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। कृषि के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिये बीज एवं यंत्रों पर अनुदान सीधे कृषकों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

किसानों को लाभान्वित करने वाली योजनायें निम्नवत् है :–

भारत सरकार द्वारा सहायतित प्रमुख योजनाएं

- एन0एम0ओ0ओ0पी0 (नेशनल मिशन आन ऑयल सीड एण्ड ऑयल पाम)।
- एन0एम0ए0ई0टी0 (नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी)।
- एन0एम0एस0ए0 (नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर)।
- एन0एफ0एस0एम0 (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)।

- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।
- आर0के0वी0वाई0 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)।

<u>राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें</u>

- प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना।
- संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना
- विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना।
- कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना एवं डी0बी0टी0 योजना।
- सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना।
- प्रदेश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषक सहायता योजना।
- मृदा स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक/जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण योजना।
- भूमि सेना योजना।
- नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2015–16 को सरकार द्वारा किसान वर्ष पर लागू होने वाले योजना की जानकारी

36–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015–16 को सरकार किसान वर्ष के रूप में मना रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु सरकार किसानों के लिये क्या–क्या कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

जनपद बुलन्दशहर में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना दिनांक 22–09–2015 से लागू की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में किसान बाजार योजना शुरू करने की मांग विषयक

37–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों द्वारा अपने जनपद में सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने हेतु शुरू की गयी किसान बाजार योजना समाप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा एक बाजार बुलन्दशहर में स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी परिषद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत बुलन्दशहर में किसान बाजार स्थापित किये जाने में कठिनाई है।

प्रदेश में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं की वर्ष 2015–16 की छात्रवृत्ति जारी कराने की मांग विषयक

38–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं की वर्ष 2015–16 की छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई है ? यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्ति कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री साहब सिंह सैनी–

शैक्षिक सत्र 2015–16 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार राज्य स्तर पर डिजिटली लॉक किये गये डाटा के आधार पर बिल बनाने तथा धनराशि अन्तरण करने की कार्यवाही की अन्तिम तिथि 26 फरवरी, 2016 से 15 मार्च, 2016 तक निर्धारित है, जिसके अनुसार पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 15 मार्च, 2016 तक किया जाना सम्भव हो सकेगा। साथ ही जिन छात्रों के डाटा को जनपद स्तर से नियमानुसार डिजिटली लॉक कर दिया गया है, के भुगतान की कार्रवाई विभाग स्तर से की जा रही है। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरित किये जाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम तेन्हुआ असनहरा में मण्डी परिषद् द्वारा हाट बाजार केन्द्र को संचालित किया जाना

39–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड रामनगर के ग्राम तेन्हुआ असनहरा उर्फ करमहिया तथा ब्लाक रूधौली में मण्डी परिषद् द्वारा हाट बाजार केन्द्र बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त हाट बाजार केन्द्रों को संचालित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार व्यापारियों एवं किसानों के हित में उक्त दोनों हाट बाजारों को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई–टेन्डरिंग लागू होने के पश्चात् प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 20–1–2016 के कृत की गई कार्रवाही की जानकारी

40–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई–टेन्डरिंग लागू होने के पश्चात् प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का पत्र दिनांक 20–01–2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बड़हलगंज में राजकीय ग्रामीण मिनी स्टेडियम का ग्राउण्ड एवं हाल की मरम्मत किया जाना

41–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के बड़हलगंज में राजकीय ग्रामीण मिनी स्टेडियम का ग्राउन्ड ऊबड़–खाबड़ है और हॉल जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राउन्ड को समतल तथा हॉल के शीशे, फाटक ठीक कराने एवं एक तरफ अधूरी चहारदीवारी पूरी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सकल गूजर–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुरक्षण मद में ग्रामीण स्टेडियम की मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में स्थित सेंट जोसेफ कालेज फार वूमेन द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से बी0सी0ए0 कोर्स चलाये जाने विषयक

42–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित सेंट जोसेफ कालेज फार वूमेन द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से बी0सी0ए0 कोर्स चलाया जा रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि अध्ययनरत छात्राओं को पढ़ाई पूर्ण होने के बाद उनकी परीक्षा नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सत्र 2013–14 में प्रवेश लेने के बाद इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बी0एच0यू0 कैम्पस वाराणसी द्वारा समन्वयक को कन्वर्जेन्स स्कीम के तहत उक्त पाठ्यक्रम को बन्द करने का आदेश दिया गया, जिससे सम्बन्धित छात्रों की परीक्षा नहीं हुई तथा छात्रों से लिया गया शुल्क उन्हें वापस कर दिया गया है।

पाठ्यक्रम बन्द करने का निर्णय केन्द्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत आता है। अतः राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के चकगंजरिया फार्म हाउस लखनऊ में बन रहे आई0टी0 सिटी में अविलम्ब शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में

43–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चकगंजरिया फार्म हाउस में बन रहे आई0टी0 सिटी का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से उक्त आई0टी0 सिटी में नौकरी एवं शिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आई0टी0 सिटी लखनऊ परियोजना को कुल 10 वर्षों की अवधि में दो चरणों में क्रियान्वित किया जाना है। प्रथम चरण का कार्य नियत तिथि से 05 वर्षों की अवधि में अर्थात् अक्टूबर, 2020 तक तथा द्वितीय चरण का कार्य अगले 05 वर्षों में अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

आई0टी0 सिटी में कौशल विकास केन्द्र का परिचालन 01 नवम्बर, 2016 से किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, पूर्व निदेशक, शिक्षण शोध एवं प्रकाशन संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी जिनका दिनांक 08–10–2009 को सेवाकाल में निधन एवं अदेयता

प्रमाण–पत्र (नोड्यूज) विश्वविद्यालय से अब तक न मिलने के कारण उनकी विधवा को पूर्ण पारिवारिक पेंशन का लाभ के सम्बन्ध में

44–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, पूर्व निदेशक, शिक्षण शोध एवं प्रकाशन संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी जिनका दिनांक 08–10–2009 को सेवाकाल में निधन हो गया था, के अदेयता प्रमाण–पत्र (नोड्यूज) विश्वविद्यालय से अब तक न मिलने के कारण उनकी विधवा को पूर्ण पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अदेयता प्रमाण–पत्र जारी कराकर प्रकरण में लाभार्थी को पूर्ण पारिवारिक पेंशन का लाभ का ब्याज सहित अविलम्ब भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

स्व0 हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, पूर्व निदेशक, शिक्षण शोध एवं प्रकाशन संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी जिनका दिनांक 08–10–2009 को सेवाकाल में निधन हो गया था, के कार्यकाल में वर्ष 2001–2010 तक की अवधि में दुर्लभ पुस्तकों/पाण्डुलिपियों के मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु शासन से प्राप्त कुल रु0 10,20,22,000/– के भुगतान में अनियमितता बरती गयी है। उक्त अवधि में बिना मुद्रित पुस्तकें/पाण्डुलिपियों पर किये गये भुगतान रु0 5,68,23,642/– की पुस्तकें अद्यतन प्राप्त न होने का सत्यापन होने के पश्चात् सम्बन्धित धनराशि राइट–आफ करने हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् को सन्दर्भित किया गया है।

विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् की आगामी बैठक में स्व0 हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी को अदेयता प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में नौकरियों में प्रतिनिधित्व को पूर्ण करने की सरकार की योजना की जानकारी

45–श्री दीपक पटेल–

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व ना के बराबर है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जनसंख्या के अनुपात में इनके प्रतिनिधित्व को पूर्ण कराने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)–

जी नहीं।

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये

आरक्षण) अधिनियम, 1994'' (यथासंशोधित) के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 50 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है।

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994'' (यथासंशोधित) के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 50 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। मा0 न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के क्रम में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रकार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, यदि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण अनुमन्य किया जाता है, तो आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी, जिससे मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना होगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु प्रमाण–पत्र जारी करके जनजातियों के छात्रों कि शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था किया जाना

46–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–सी0एम0–27/ 26–3–81/58(14)/81, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के अनुसार उ0प्र0 में स्थाई निवास करने वाली 31 जनजातियां एवं घूमंतू सं0–39 जनजातियों के कल्याण हेतु विमुक्त जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के निर्देश के साथ–साथ यह भी उल्लिखित है कि शिक्षा में प्रवेश हेतु विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करा जाये ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद के उपरोक्त जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में आरक्षण हेतु विमुक्त जाति प्रमाण–पत्र जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश संख्या–सी0एम0–27/26–03–81/58(14)/81, दिनांक 17–09–1981 काफी प्रयास के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं हो सका।

अपितु वर्तमान में शासनादेश संख्या–22 सी0एम0/26–3–2013, दिनांक 10–06–2013 प्रभावी है, जिसमें विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम के आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हे उक्त वर्ग के अन्तर्गत ही मिलने वाला आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य है।

उपर्युक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में 5 ग्रामों को जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयनित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाई की जानकारी

47–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में उल्लिखित 5 ग्रामों को जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयनित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10681023, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10681023/2015, दिनांक 31–08–2015 प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि कार्रवाई होगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों/मजरों को चयन हेतु विचारार्थ सूचीबद्ध कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में स्थित बलरामपुर चीनी मिल से निकलने वाली राख तथा प्रदूषित पानी को रोकने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में कार्रवाई की जानकारी

48–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में स्थित बलरामपुर चीनी मिल की चिमनी से निकलने वाली राख तथा प्रदूषित पानी को रोकने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10497301/2014, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बलरामपुर में स्थित बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, बलरामपुर की क्रेन क्रासिंग क्षमता 12000 टन/दिन की है एवं पावर कोजनरेशन यूनिट स्थापित है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 18 मेगावाट है। उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। बोर्ड अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 09–12–2015 को किया गया, निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र संचालित पाया गया। उक्त तिथि को एकत्रित उत्प्रवाह नमूने में विभिन्न परिचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी।

उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया में ईंधन के रूप में लगभग 2600 टन/दिन बैगास का प्रयोग ब्वायलर में किया जाता है। प्रक्रिया से जनित गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण

हेतु ब्वायलरों से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई क्रमशः 30, 33, 50, 40, 40 एवं 65 मीटर है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई0एस0पी0 एवं वेट स्क्रबर स्थापित है। स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जांच बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 09–12–2015 को की गई। निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी। उद्योग की गैसीय उत्सर्जन अनुश्रवण आख्या दिनांक 10–12–2015 बोर्ड मानकों के अनुरूप है। ब्वायलर्स से जनित फ्लाई ऐश का निस्तारण उद्योग द्वारा निचली भूमि की भराई में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12ण्20, तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 20 प्रश्न लगते है, लगना चाहिए और यह है कि 20 प्रश्नों का उत्तर भी आ जाए। आप इस पर कृपा करें कि प्रश्न प्रहर में जो आपसी नोंक–झोंक होती है, उसमें कई प्रश्नों का समय समाप्त हो जाता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आगे आने वाले प्रश्न नहीं आ पाते।

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। अगर यह सदन सहमत हो तो जो मा0 सदस्य प्रश्न पूछें और विधान सभाओं में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखण्ड में, गुजरात में जो प्रश्न पूछते हैं वही सदस्य उसकी सप्लीमेण्ट्री भी पूछते हैं और हमारे यहां प्रश्न प्रहर में सभी मा0 सदस्य सप्लीमेण्ट्री/अनुपूरक पूछते हैं तो उसमें बहुत समय चला जाता है। अगर आप समस्त सदस्य सहमत हों तो एक प्रश्न पर दो अनुपूरक, मैक्सिमम तीन अनुपूरक कर दिया जाए। चाहे यह प्रश्नकर्ता करे, चाहे दूसरे लोग करें। अगर यह सदन सहमत हो तो कल से मैं इसे लागू कर दूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जो अति लोकमहत्व के प्रश्न रहते है। स्वाभाविक रूप से उस पर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और कभी–कभी यह भी देखा जाता है कि अल्पसूचित तारांकित और तारांकित, कभी–कभी तो कार्यवाही के एजेण्डे में मात्र 3–3, 4–4 प्रश्न ही रहते हैं तो ऐसे हालात में हम 5 मिनट में ही क्वेश्चन आवर खत्म करके फिर सीधे जीरो आवर में प्रवेश करें तो इसलिए जो आपकी व्यवस्था रहती है उसके अनुसार घटाया भी जाता है, बढ़ाया भी जाता रहता है तो अलग से इस पर किसी प्रकार के सदन से राय लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका विशेषाधिकार है कि किस पर आप कितना समय देते हैं, किस पर आप कम समय देते हैं। लोकमहत्व के प्रश्नों के लोकमहत्व को ध्यान में रखते हुए उस पर ज्यादा अनुपूरक भी पूछे जा सकते हैं और कम भी पूछे जा सकते हैं इसलिए इस पर बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं इस पर नेता प्रतिपक्ष के सुझाव से सहमत हूं। मान्यवर, आपका तो हर वक्त अधिकार है। आप एक भी प्रश्न न पूछने दीजिए तो यह अधिकार आप में ही रहना चाहिए। आप वहां इसीलिए बैठे हैं कि जो चीज पूरा सदन महसूस नहीं कर रहा है वो आप महसूस करें तो यह आपका अधिकार है, एक पूछे या दो पूछें। यह सही है कि बाज़े–बाज़े प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें समय ज्यादा लगता है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम आप लोगों से सहमत है।

प्रश्न काल की समाप्ति के उपरान्त कार्य–सूची के अवशेष प्रश्नों के उत्तर–मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग बड़ी मेहनत से प्रश्न लगाते है और आपकी कृपा होती है, स्वीकार भी होते है। अभी पिछले दिनों सदन किन्हीं कारणों से नहीं चलाया गया तो मेरा आपसे केवल इतना आग्रह है कि जो प्रश्न हमने लगाए थे, वे उन दिनों में आए और वे दिन निकल गए तो कम से कम उनके उत्तर तो हमको दिलवा दिए जाएं। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम देखते हैं नियमों में होगा तो देखेंगे।

ख12ण्24 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25–02–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गई।

पहली सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल (नये सदस्य) की जनपद मुजफ्फरनगर के प्रमुख तीर्थ शुक्रतीर्थ स्थल पर गंगा को पवित्र धारा का प्रवाह बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्रीमती बिमला बाथम की नोयडा विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर–एक, गुरूकुल पार्क में बाउण्ड्री तोड़कर गेट लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर के सी0ओ0डी0 कालोनी में सीवर लाइन एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह (अनुपस्थित)

छठीं सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के वार्ड–51 में सांई मन्दिर से पाक्र के चारों तरफ के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु रेलवे क्रासिंग की जगहों पर पाइप चेकिंग किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत बाजार सरायमीर के गांव नदाव को जोड़ने वाली सड़क का ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

नवीं सूचना श्री प्रभु दयाल की जनपद मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा अन्तर्गत मवानापौड़ी पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

दवसीं सूचना श्री इरफान सोलंकी की (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)

ग्यारहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र मधुबन विकास खण्ड बड़रांव चौराहे से कटिहारी बुजुर्ग की जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर की बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तेलिपानी के अन्तर्गत खराब हुए कतिपय मार्गों का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री जाकिर अली की (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)

चौदहवी सूचना श्री राम चन्द्र चौधरी की जनपद सुल्तानपुर कादीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सूरापुर (भवानीपुर) से इब्राहिमपुर तक की सड़क का चौड़ीकरण और जल्द बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं सूचना डा0 मो0 अयूब खां की पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष कानपुर को फर्जी मुकदमें में फंसाने के सम्बन्ध में।

एक तो मैंने राकेश प्रताप सिंह के स्थान पर चौ0 गजेन्द्र सिंह का लिया है, इरफान सोलंकी की जगह पर राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज जी और जाकिर अली की जगह पर विजय बहादुर यादव की सूचना ली जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं– श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री राजीव गुम्बर, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सन्त प्रसाद, श्री सतीश महाना, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री रामचन्द्र यादव, श्री मनीष असीजा, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री सुरेश राणा, श्री दलवीर सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री राजकुमार रावत, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री काली चरन सुमन, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री परवेज अहमद टंकी, श्रीमती लालमुन्नी सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री गजराज सिंह, श्री संजय कपूर, श्री उमा शंकर, श्री रामवीर उपाध्याय, डा0

रमेश चन्द्र बिन्द, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री भीम प्रसाद सोनकर (दो सूचना), श्री राधे श्याम जायसवाल, श्री बंशी सिंह पहाड़िया।

अब आप लोग बैठें।

श्री संजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का एक भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आपका संख्या बल भी तो कम है। बैठिए।

(सदन की सहमति से स्वीकृति सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद मुजफ्फरनगर के प्रमुख तीर्थ शुकतीर्थ स्थल पर गंगा की पवित्रि धारा का प्रवाह बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिलदेव अग्रवाल–

ख्मान्यवर, शुकतीर्थ जनपद मुजफ्फरनगर के पश्चिमी उ0प्र0 का प्रमुख तीर्थ है। करीब 5500 वर्ष पूर्व श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी इसीलिये इस स्थान को श्रीमद् भागवत की उद्गत स्थली भी कहा जाता है। वह विशाल वट वृक्ष यहां आज भी कथा के साक्षी के रूप में स्थित है। महानसंत स्वामी कल्याणदेव जी महराज ने यहां शुकतीर्थ के राष्ट्रीय स्तर का विशिष्ट पहचान दिलाने में शिक्षा मनीषी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। श्री गणेश, श्री हनुमत, श्री शिव घाट, पार्वतीधाम, श्री दुर्गा धाम, मा0 नगलामुखी की गगनचुम्बी प्रतिमाएं की वजह भी देश भर के तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। यहां हजारों वर्ष से बह रही गंगा का स्वरूप लगभग विलुप्त होने की स्थिति में है और सोलानी नदी का प्रवाह है शेष भी गंगा का पवित्र धारा का तेज प्रवाह यहां से होगर पिकले इसकी क्षेत्र जनपद एवं देशभर के तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष महत्व है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गंगा की पवित्र धारा का प्रवाह बढ़ाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

नोयडा विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विमला बाथम–

ख्मान्यवर, नोयडा विधान सभा में कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है। जिससे यहां की छात्राओं को लगभग 20 कि0मी0 दूर बादलपुर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। जबकि यहां की आबादी भी लगभग 15 लाख है। जनहित में छात्राओं के भविष्य को देखते हुये कन्या डिग्री कालेज खुलवाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

नोटः–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर एक गुरुकुल पार्क में बाउण्ड्री तोड़कर गेट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

ख्मान्यवर, जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर–एक में मकान नं0–1/165, 1/166 एवं 1/167 के सामने गुरुकुल पार्क में बाउण्ड्री तोड़कर गेट लगा दिया गया है जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बाउण्ड्री को तोड़कर गेट लगाने से पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति भी नहीं ली गयी। गेट लगाने के बाद यहां पर अतिक्रमण करके गाड़ी खड़ी की जा रही है जिससे नागरिकों को आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से बाउण्ड्री तोड़कर गेट लगाया जाना सर्वथा अनुचित है जिसको पूर्ववत् किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है। इसको लेकर जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर के सी0ओ0डी0 कालोनी के सीवर लाइन एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्मान्यवर, कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में मोहल्ला सी0ओ0डी0 कालोनी में पानी का निकास नहीं हो रहा है, जिससे जलभराव के कारण अधिकतर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। स्थानीय निवासी गंदगी के कारण संक्रामक रोगों से त्रस्त हैं। विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर कई लोगों की पूर्व में मृत्यु भी हो चुकी है। आये दिन इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशासन से अपनी पीड़ा भी बतायी गयी परन्तु कोई समाधान नहीं हो सका है जिससे आमजन में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में सी0ओ0डी0 कालोनी में नई सीवर लाइन, पानी निकासी का उचित प्रबन्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए छावनी क्षेत्र, कानपुर स्थित सी0ओ0डी0 कालोनी में सीवर लाईन ठीक कराते हुए नाली निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के वार्ड 51 में साईं मन्दिर से पार्क के चारों तरफ के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड 51 एच0 ब्लाक में एक मुख्य सड़क जो साईं मंदिर से लेकर पार्क के चारों तरफ होते हुए एच–253 मुनीफा चौहान के मकान तक जाती है, पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। जगह–जगह गड्ढे हो चुके है, जिसके कारण नाले का गन्दा पानी सड़कों पर जमा रहता है व गंभीर बीमारी फैलने का भी भय रहता है। वास्तव में इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने से यहां के निवासियों को बड़ी असुविधा है। यहां काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है व इस सड़क पर लोगों का निकलना भी दूभर है।

अतः जनहित में, इस सड़क के पुनःनिर्माण कराये जाने का अनुरोध करता हूं। मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद वाराणसी कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु रेलवे क्रासिंग की जगहों पर पाइप चेकिंग किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्मान्यवर, वाराणसी कैण्ट विधान सभा में अनेकों वार्ड में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर (कमच्छा) जंगमबड़ी के लोग बहुत परेशान हैं। कई बार यह परेशानी 301 के अन्तर्गत विधान सभा में भी दी गयी है। हर बार स्वच्छ जल आपूर्ति की योजनाएं ही उत्तर में आती है। यह योजना अभी तक फलीभूत नहीं हुई है और ऐसा कोई कार्य योजना कार्यान्वित होते दिखाई नहीं पड़ रही है जिससे निकट भविष्य में स्वच्छ जल आपूर्ति का भरोसा हो। जरूरत इस बात की है कि उपरोक्त क्षेत्रों में सीवर लाइन व पेयजल पाइप लाइन एक दूसरे के ऊपर है, विशेष कर सड़कों के क्रासिंग पर उन जगहों के पाइप की चेकिंग हो जाए, जिससे दोनों पाइप अलग–अलग हो जाय और क्रमशः स्थिति सुधर जाय।

मैं जनहित में लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त पेयजल पाइप लाइन की जांच व आवश्यक कार्रवाई की मांग करती हूं।,

जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत बाजार सरायमीर के गांव नदाव को जोड़ने वाली सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी–

ख्मान्यवर, मैं आप द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नदाव गांव सरायमीर बाजार से 8 किमी0 दूरी पर स्थित है। वर्तमान सड़क केवल 3 मीटर चौड़ी है इसका बाजार का भाग बरसात में नाले में परिवर्तित हो जाता है और जनता को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति मा0 बराक ओबामा के सलाहकार श्री फ्रैंक इस्लाम जी इसी नदाव गांव के मूल निवासी है इधर इनका भी आना–जाना रहता है और इनके प्रोग्राम में काफी भीड़ एकत्र होती है। सड़क की खराब हालत के कारण विभाग व जनप्रतिनिधि की बदनामी होती है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त सड़क का उच्चीकरण व चौड़ीकरण अति आवश्यक है इस कार्य को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

जनता आपकी आभारी रहेगी।,

जनपद मेरठ के हस्तिनापुर विधान सभा अन्तर्गत मवाना पौड़ी पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु दयाल–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर जनपद मेरठ के अन्तर्गत मवाना पौडी मार्ग पर स्थित अनूप शहर नहर का पुल काफी दिनों से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण चलने फिरने में जनता को काफी परेशानी हो रही है, क्षेत्रीय जनता द्वारा तत्काल नये पुल बनाये जाने का निवेदन किया जा रहा है। उपरोक्त नया पुल के बन जाने से लाखों लोगों का आना–जाना आसान हो जायेगा, आम जनता की समस्या को देखते हुए बड़ा पुल का निर्माण किया जाना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मवाना पौडी नया पुल को तत्काल बनाये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र मधुबन विकास खण्ड बड़रांव चौराहे से कटिहारी बुजुर्ग की जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड–बडरांव के अन्तर्गत ग्राम बढ़रांव चौराहे से कटिहारी बुजुर्ग गांव तक (ल0 लगभग 06 कि0मी0) की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उक्त क्षतिग्रस्त सड़क में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो गया है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की निर्माण/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर की बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तेलिपानी के अन्तर्गत खराब हुए कतिपय मार्गों का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद फतेहपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र 239, बिन्दकी के विकास खण्ड तेलिपानी के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से खानपुर तक, जोनिहा फतेहपुर मार्ग से धारूपुर तक, ग्राम अल्लीपुर से आदमपुर तक, ग्राम चखेड़ी से झाऊ मेदनीपुर लिंक मार्ग, ग्राम करसवा से अस्ता, भैरमपुर से बुधइयापुर, जी0टी0 रोड नउनवन बाग से उमरापुर लिंग मार्ग, तारापुर मोड़ से बादलपुर तक, चखेड़ी मोड़ से झाऊ मेदनीपुर तक, जी0टी0 रोड से कोराई होते हुए कांछी तक की सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सुल्तानपुर कादीपुर विधान सभा के अन्तर्गत सूरापुर (भवानीपुर) से इब्राहिमपुर तक की सड़क का चौड़ीकरण और जल्द बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी–

ख्मान्यवर, आपका ध्यान सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र कादीपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर बलिया मार्ग के सूरापुर (भवानीपुर) से इब्राहिमपुर–गोमती नदी के पुल तक सड़क जर्जर हो गयी है। बड़े–बड़े गड्ढे हो गये है, चलने लायक नहीं रह गयी है। जबकि इलाहाबाद पट्टी से अम्बेडकरनगर का आवागमन प्रतिदिन रहता है। लगभग बीसों वर्ष से उसकी मरम्मत भी कायदे से नहीं हुई है। भवानीपुर सूरापुर से इब्राहिमपुर तक की सड़क को चौड़ीकरण कराते हुए उसे जल्द बनवाने का आदेश दिया जाये, जिससे आवागमन सुलभ हो सके।,

---

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष कानपुर को फर्जी मुकदमें में फंसाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मो0 अयूब खां–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शाहिद, साबिर व हामिद हुसैन पुत्रगण स्व0 जाहिद हुसैन, निवासी 43/10 अजीतगंज कालोनी व 132/35 बाबूपुरवा थाना, बाबूपुरवा कानपुर नगर, अपराधिक पृष्ठ भूमि के लोग है और इनका काम पुलिस के सहयोग से आम नागरिकों का धन दोहन करना है। पीस पार्टी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष कानपुर नासिर खान के विरुद्ध षडयंत्र रचकर फर्जी मुकदमा थाना बाबूपुरवा में 23–03–2014 को तहरीर दिखाया जबकि मुकदमा एक दिन पहले 22–03–2014 को दर्ज है तथा 02–02–2015 को धारा 82 की नोटिस चस्पा करके उनका अनुचित उत्पीड़न करवा रहे हैं। एक और षडयंत्र के तहत मु0अ0सं0–392/2013, थाना बाबूपुरवा वादी साबिर हुसैन ने 307 जैसी गम्भीर धाराओं में नासिर खां को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसी प्रकार शाहिद हुसैन ने मु0अ0सं0–493/2012 में मोहम्मद उजेर सिद्दीकी के विरुद्ध थाना बाबूपुरवा में मुकदमा दर्ज कराया जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 02–04–2014 को पीस पार्टी के मंच से मोहम्मद उजेर सिद्दीकी को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया गया।

अतः लोक महत्व के उक्त गम्भीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामों की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत आने वाले अनेकों गांवों सम्पर्क मार्गों की हालत बहुत ही जर्जर है जिन पर वाहन निकलना तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इन गांव के मार्गों पर किसानों के भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली, भैसा बुग्गी, घोड़ा तांगे जब भी मण्डी के लिए कोई सामान बिक्री के लिए जाता है तो उनके उपरोक्त सारे वाहन पलट जाते है जिससे अनेक जान–माल की हानि तो होती ही है, वर्तमान में गन्ने का सीजन आने वाला है जिसके चलते इन मार्गों पर पचासों गांवों के गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिल तक नहीं ले जा सकेंगे। ऐसी स्थिति में इन सड़कों का तत्काल बनवाये जाना अति महत्वपूर्ण है। उक्त मार्गों का हालत अत्यन्त खराब है जो कि बड़े–बड़े गड्ढों के रूप में दिखाई देती है, चीनी मिल पर किसान अपना माल लेकर इसी रास्ते से होकर आते हैं। उन्हें रोज वहां वाहन पलटने से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

1–स्याना बुलन्दशहर रोड लखावटी ब्लाक से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–अनूपशहर बुलन्दशहर रोड खलौर सम्पर्क मार्ग।

3–स्याना बुलन्दशहर लखावटी इण्टर कालेज से पसौली महेशपुर सेगली मार्ग।

4–औरंगाबाद से चीनी मिल होते हुए बिहिरा मुक्तेश्वरा होते हुए जमालपुर सम्पर्क मार्ग तक।

5–औरंगाबाद से बालका मार्ग तक।

6–स्याना बुलन्दशहर मार्ग से भावसी होते हुए लोहरका तक सम्पर्क मार्ग।

7–जहांगीराबाद अहार मार्ग सखानी से ककरई तक सम्पर्क मार्ग।

8–बुलन्दशहर अनूपशहर रोड रोरा से जहांगीराबाद सम्पर्क मार्ग।

9–बुलन्दशहर स्याना रोड से पसौली, पिपाला खेड़ी भैसरौली सम्पर्क मार्ग।

10–पिपाला खेड़ी रोड से सेगली सम्पर्क मार्ग।

उक्त मार्गों का निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त सड़कों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र ग्राम ऐंचाना से सुरहा तथा कबरई से कुन्हैटा मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र महोबा में प्रदेश के अन्य जगहों की तरह मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महोबा में ग्राम ऐंचाना से सुरहा तथा कबरई से कुन्हैटा मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है इन सड़कों से अनेक ग्रामों का आवागमन जुड़ा हुआ है, क्षेत्र की प्रमुख सड़कें होने के कारण आम जनता को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में भी सदन में उपरोक्त सड़कों के निर्माण कार्य हेतु मामला उठा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त कम्पनी के खिलाफ शासन से दण्डात्मक कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर महानगर में नौसड़ तिराहे पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, गोरखपुर महानगर में नौसड़ तिराहे पर प्रतिदिन यातायात का दबाव होने के कारण घण्टों जाम की समस्या से आम जन को जूझना पड़ता है। यह तिराहा गोरखपुर से वाराणसी मार्ग को जोड़ता है साथ ही गोरखपुर से लखनऊ मार्ग को भी जोड़ता है जिससे यातायात का दबाव अधिक रहता है। इस मार्ग पर स्थानीय लोगों के अलावा सैलानियों का भी अधिक आना–जाना रहता है जो पड़ोसी देश नैपाल से होकर बनारस एवं कुशीनगर तक की यात्रा करते हैं। यह तिराहा दिन में 9 बजते ही यातायात के अधिक दबाव होने के कारण सायं 6 बजे तक जाम की वजह से लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। यातायात को सुगम बनाने एवं जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु नौसड़ तिराहे पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नौसड़ तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

ख12ण26, विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण समितियों की बैठक न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत सतीश महाना जी का है कि नियमावली का नियम–201(4) में प्राविधान किया गया है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष, जो सदन की कई समितियों के पदेन सभापति होते हैं का पद रिक्त होने के कारण उक्त समितियों की बैठक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसमें महाना जी क्या आप बोलेगे भी, यह तो बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो बात बहुत दिनों से चल रही है, कभी–न–कभी सही हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी करवा दें उपाध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दें। (श्री मोहम्मद आजम खां की ओर इंगित करते हुए)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

पार्लियामेन्ट में नेता प्रतिपक्ष करा दें, हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में मान्यवर, और नियमावली में दोनों जगह पर इस बात की व्यवस्था है कि विधान सभा के माननीय सदस्य एक अध्यक्ष को चुनेंगे जिसके लिए आप से उपयुक्त इस सदन में और कोई भी नहीं हो सकता। आप उस कुर्सी पर विराजमान है। उसके साथ ही मान्यवर, यह भी व्यवस्था है कि विधान सभा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी और उस उपाध्यक्ष की यह कुर्सी खाली है, बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, वह कुर्सी किसकी है। वह बताते है कि उपाध्यक्ष की, पता नहीं ये उपाध्यक्ष क्या होता है। मान्यवर, बहुत सारे लोग 4 साल से इस विधान सभा में पहली

बार चुनकर आये हैं, उनको मालूम ही नहीं कि उपाध्यक्ष होता क्या है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत जो एक व्यवस्था दी गई है और नियमावली में व्यवस्था दी गई है, उसमें उपाध्यक्ष की व्यवस्था होना अनिवार्य है। ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जाकर वहां पर बैठ जाये ये संवैधानिक आवश्यकता है और संविधान के अन्तर्गत जो व्यवस्था दी गयी है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। मान्यवर, चार साल हो गए, हर विधान सभा के सत्र में हम इसको उठाते हैं। आप भी मान्यवर चाहते हैं कि आपका सहयोगी कोई–न–होई हो, क्योंकि बहुत–सी समितियों के उपाध्यक्ष सभापति होते है आपको उसकी दूसरी व्यवस्था कर दी। वैकल्पिक व्यवस्था में और ओरिजनल व्यवस्था में बहुत सारी चीजें होती है। एक असली आदमी होता है और एक नकली आदमी होता है। अब नकली आदमी और असली आदमी में बड़ा फर्क होता है।

(डा0 राधामोहन दास के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप दोनों लोग तय कर लीजिए कि क्या कहा जाय ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक असली आदमी और वहां पर दूसरे असली आदमी को बैठाना चाहिए था। वहां पर इस बात के शुरू होने से पहले ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वहां पर नेता प्रतिपक्ष, वहां पर भी आपके पास पांच मेम्बर हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, वहां उनको कहिए उस विषय को उठायेंगे तो वह भी सोचेंगे कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। यहां तो हमने और आपने सोचना है, यहां पर हमने उस विषय को उठाना है। मान्यवर, आप से विनम्र निवेदन है कि उस कांस्टीट्यूशनल व्यवस्था के अन्तर्गत, नियमावली के अन्तर्गत जो व्यवस्था दी गयी। मान्यवर, अब चली चला की बेला है कम से कम यह आ जायेगा कि उपाध्यक्ष यहां चुन कर आ जाये। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है क्योंकि यह बजट का आखिरी सत्र है इसके बाद जो सत्र होंगे वह छोटे–छोटे होंगे इसी सत्र कार्यकाल के अन्तर्गत यहां उपाध्यक्ष के चुनाव की कोई तिथि तय कर दीजिये। अभी मान्यवर संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे कहेंगे कि यह आपका प्रोवोगेटिव है और आपने तय करना है। जब सब लोग कह रहे हैं कि आपने तय करना है तो आप उसे तय कर दीजिये इसका चुनाव हो जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमने ही वहां बैठाया भी था, इन्हीं के साथी को बैठाया था, आप बुला लीजिये बात कर लीजिये जैसा भी तय हो जाये लेकिन महाना जी अगर बैठ जायेंगे तो कम से कम उनका मुंह (हाथ से अपना मुंह बन्द करते हुए दिखाया।)

श्री अध्यक्ष–

जो आपने प्रश्न उठाया था उस पर संसदी कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया। आपने एक प्रश्न यह उठाया था कि उपाध्यक्ष विभिन्न समितियों के चेयरमैन होते है यानी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उसमें नियम में परिवर्तन कर दिया गया था जब उपाध्यक्ष नहीं थे तो नियम को बदल कर 202(4) में कर दिया गया था कि जो अन्य समितियों के चेयरमैन होंगे वे इन समितियों में अध्यक्ष नामिनेट कर देंगे उन समितियों की अध्यक्षता

करेगा। समितियों का काम तो कोई बाधित नहीं होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सब उत्तर दे दिया इससे मैं अग्राह्य करता हूं।

ख12ण32 बजे, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल दल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) का 9वां प्रतिवेदन[४]

श्रीमती आशा किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016), उक्त समिति का 9वां प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग बेसिक शिक्षा तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) का 10वां प्रतिवेदन४

श्रीमती आशा किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016), उक्त समिति का 10वां प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग बोसिक शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं पर आधारित है, को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ।

ख12ण33 बजे, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2015–2016) के प्रतिवेदन की रिपोर्ट शासन द्वारा न माने जाने के सम्बन्ध में शिकायत

श्रीमती सीमा–

जो हमारा चेयरमैन है हम उस कमेटी का मेम्बर है। अभी हमारी पूरी कमेटी चन्दौली गयी थी, बनारस गयी थी।

श्री अध्यक्ष–

यह इसमें नहीं अलग से रखें।

श्रीमती सीमा–

अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लाजिये, हमारी कमेटी में जो हमने क्षेत्रीय दौरा किया जो कमी हमने देखी जो उसकी रिपोर्ट दी वह सरकार नहीं मानती है। मेरा यह कहना है कि अगर कोई कमेटी कोई रिपोर्ट देती है तो सरकार उसको जरूर माने। हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सुझाव है हमारी कमेटी गयी थी हमारे जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में सूचना के बाद भी महिला सी0एम0एस0 नहीं आई।

श्री अध्यक्ष–

---

[४] छापा नहीं गया।

यह यहाँ नहीं कहना है जब आप वहाँ गयी और वह नहीं मिली कमेटी में नोटिस देकर उनको बुलायें और पूछे कि वह क्यों नहीं थीं। यहां इसका कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती सीमा–

अध्यक्ष जी, हम सब यह कहना चाह रहे है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी है, शासन उस रिपोर्ट को मान ले क्योंकि हमको तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपको वह रिपोर्ट मुझे देनी चाहिए थी मैं शासन को भेजता। अब बैठिये।

ख12ण34 बजे, जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा क्षेत्र स्थित पहासू रोड पर महाराणा प्रताप नगर/मुरारी नगर में समुचित जल निकासी तथा पक्की नाली निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र कुमार राघव आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा क्षेत्र में स्थित पहासू रोड पर महाराणा प्रताप नगर/मुरारी नगर में समुचित जल निकासी तथा पक्की नाली निर्माण कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र कुमार राघव व श्री सुभाष चन्द्र शर्मा निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा सुभाष रोड में ईदगाह तक की क्षतिग्रस्त मार्ग को आवास विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने विषयक श्री निजाम मलिक आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा सुभाष रोड से ईदगाह तक की क्षतिग्रस्त मार्ग को आवास विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने विषयक श्री निजाम मलिक व श्री नदीम कुरेशी निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा सिटी तेलिया घाट रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक श्री छत्तर पाल शर्मा आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा सिटी तेलिया घाट रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज/ओवर ब्रिज का निर्माण जनहित में कराये जाने विषयक

---

[४] छापी नहीं गयी।

[४] छापी नहीं गयी।

श्री छत्तरपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

परी चौक यमुना एक्सप्रेस–वे के समानान्तरण परी चौक नोएडा से आगरा तक प्रस्तावित मार्ग को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री लायक राम सिंह आदि निवासीगण जनपद गौतमबुद्ध नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परी चौक यमुना एक्सप्रेस–वे के समानान्तरण परी चौक नोएडा से आगरा तक प्रस्तावित मार्ग को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री लायक राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जहांगीरपुर चीनी मिल जेवर के बन्द पड़े कार्य को पूर्ण कराकर चालू कराये जाने विषयक श्री भगत सिंह आदि निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के अन्तर्गत जहांगीरपुर चीनी मिल जेवर बन्द पड़े कार्य को पूर्ण कराकर मिल चालू कराये जाने विषयक श्री भगत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख12ण35 बजे, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत राधा नगर (फाउण्ड्री नगर) अधूरे नाले निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री उदय कुमार अग्रवाल आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

डा0 धर्मपाल सिंह–

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत राधा नगर (फाउण्ड्री नगर) के अधूरे नाले निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री उदय कुमार अग्रवाल व श्री रविन्द्र दत्त शर्मा निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में शहरी क्षेत्र में छलेसर से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 तक नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विवेक कुमार आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में छलेसर से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 तक नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजीत कुमार व श्री विवेक कुमार निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

[४] छापी नहीं गयी।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत खंदौली को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री विनोद शर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत खंदौली को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री विनोद शर्मा व श्री शीतल दुबे निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत बरहन को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री प्रभात जैन आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत बरहन को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक श्री प्रभात जैन व श्री संजय सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख12ण36 बजे, जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में अति पिछड़े क्षेत्र भेड़ियारी टोला घाट पर लघु सेतु बनाये जाने विषयक श्री राजेश पाल आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में अति पिछड़े क्षेत्र भेड़ियारी टोला घाट पर लघु सेतु बनाये जाने विषयक श्री राजेश पाल व श्री रमाकान्त गुप्ता निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही के सिसवा से अहिरौली दान के बीच राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक डा0 अजय सिंह आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सेवरही के सिसवा से अहिरौली दान के बीच में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक डा0 अजय सिंह व श्री सुशील सिंह निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत ग्राम सभा बांसगांव टोला खैरवा में बांसी नदी के खैरवा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरिलाल गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

---

४ छापी नहीं गयी।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत ग्राम सभा बासगांव टोला खैरवा में बांसी नदी के खैरवा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरिलाल गुप्ता व श्री भिखारी गुप्ता निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत अमवा बुढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वकील गुप्ता आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत अमवा बुढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वकील गुप्ता व श्री दीनानाथ सिंह पटेल निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

ख12ण्37 बजे, जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर राज्य मार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाला पुल सकरा, जर्जर एवं पुराने पुल का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र गुप्ता आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर राज्य मार्ग पर निगोही के पास कैमुआ नाला पुल सकरा, जर्जर एवं पुराने पुल का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के अन्तर्गत भरतपुर से उत्तर पैलानी मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के अन्तर्गत भरतपुर से उत्तर पैलानी मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नरेन्द्र कुमार व श्री सत्येन्द्र गुप्ता निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

ख12ण्38 बजे, जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में आर0सी0सी0/इण्टरलाक एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भगवान सिंह वर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री कालीचरन सुमन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में आर0सी0सी0/इण्टरलॉक एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भगवान सिंह वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री रामकिशन कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका [४]

श्री कालीचरन सुमन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री रामकिशन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद कासगंज की तहसील सहावर से कासगंज तक एवं सहावर से अर्मापुर होते हुए काली नदी तक मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री वीरपाल सिंह शाक्य आदि निवासीगण जनपद कासगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४]

श्री ममतेश शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कासगंज की तहसील सहावर से कासगंज तक एवं सहावर से अर्मापुर होते हुये काली नदी तक मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री वीरपाल सिंह शाक्य व श्री इकरार अहमद निवासीगण जनपद कासगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 12, 13 तथा 14 इसमें कुछ नहीं है।

ख12ण40 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25.02.2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित तीन सूचनायें चयनित की गई, प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा और शेष सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में लगाये जा रहे नये विद्युत मीटर के तेजी से चलने व उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री जगन प्रसाद गर्ग एवं श्री योगेन्द्र उपाध्याय की है जो आगरा शहर के मध्य स्थित नजूल की भूमि को व्यावसायिक उपयोग में लाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, श्री रामचन्द्र यादव की है, जो जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के थाना मवई ग्राम पंचायत बघेड़ी निवासी पाल की 15 वर्षीय पुत्री के दिनांक 16–02–2016 को मिले शव के उपरान्त पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। शेष सूचनाओं को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि माननीय सदस्यों ने नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी थी, वह बहुत छोटे–छोटे मामलों से संबंधित थी, इसमें बहुत बड़े मामले नहीं थे। आज

[४] छापी नहीं गयी।

आय–व्ययक पर चर्चा है, तो हमारा कहना यह है कि जब भाषण में उनको मौका मिलेगा तो वह सारी बातें कह लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जायेगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी सूचना को स्वीकार करने का अनुरोध करने पर)

आप लोग बैठ जाईये। जिनकी सूचनायें स्वीकार हुई हैं, पहले उनको बोल लेने दीजिये। भड़ाना जी, गजेन्द्र सिंह जी आप लोग बैठे। अगर आप लोग आय व्ययक पर भाषण न करें तो फिर इसी पर बहस करा दें। बैठिये, आप लोग बैठिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि इन सूचनाओं पर आपने ही व्यवस्था दी थी कि आय व्ययक पर चर्चा है इसलिये हम संक्षेप में सबको सुनेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप दो–दो मिनट में माननीय सदस्यों की बात सुन लें, क्योंकि मान्यवर, इसमें सरकार की व्यवस्था आ जाती है। हो सकता है कि सरकार संज्ञान लेकर तत्काल उस पर प्रभावी कार्यवाही कर दे। इसलिये आप ज्यादा समय न दें, तो कम से कम दो–दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आज कुल 18 सूचनायें आई हैं, जिसमें दो–तीन महत्वपूर्ण थी। हम दो को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं और एक पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि आप दो–तीन सूचनायें हमेशा सुनते हैं, तो दो–तीन सूचनाओं को संक्षेप में सुनकर शेष पर आप व्यवस्था देने का निर्णय दे दीजियेगा। बस हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। श्री श्यामदेव राय चौधरी जी, आप बोलिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की ग्राह्यता पर आपने बोलने का मुझे अवसर दिया है, जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर पूरा सदन चिन्तित रहता है, चिन्ता भी व्यक्त करता आ रहा है। पावर कारपोरेशन में जो लाइन लासेज हैं, चाहे वह विद्युत चोरी से होता हो, चाहे जिन भी कारणों से होता हो, उन लाईन लासेज को कम करके दिखाने के फेर में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अपनी गलती को छिपाने के लिए अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जिसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है और उसके लिए वह असह्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बताना चाहता हूं कि फिक्स चार्ज है, मिनिमम चार्ज है, केन्द्र लेटरी सरचार्ज विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि है और साधारण जो उपभोक्ता

है, जो घरेलू उपभोक्ता है जो गरीब व्यक्ति होता है जिसके यहां पहले से एक किलोवाट का कनेक्शन स्वीकृत है और विभाग यह कर रहा है कि मनमाने रूप से बिना उसकी स्वीकृति के बिना किसी जांच के उसका लोड बिल में दो किलोवाट, तीन किलोवाट कर दे रहा है। उसका असर यह हो रहा है कि आम घरेलू उपभोक्ता पर जो खर्च का भार है, वह बढ़ जा रहा है और इस प्रकार से जनता का उत्पीड़न हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का जो मनमानापन है और जो इस तरह से लगातार अपनी कमी को छिपाने के लिये और जो विद्युत टैरिफ है, जो प्रति यूनिट चार्ज की दर है, उसमें बेतहाशा वृद्धि कर दी जा रही है तो इस तरह से जो यह सरकार है इसे संवेदनशील होने का प्रमाण देना चाहिये कि इस तरह से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जो अधिकारीगण हैं, वह अपनी आय में बढ़ोत्तरी दिखलाने के लिये और अपनी कमी को छिपाने के लिये यह जो घरेलू कनेक्शन है, एल0एम0बी0 वन के, यह जो एक तरह से मनमाने ढंग से उसका लोड बढ़ा दे रही है और दूसरा प्रति यूनिट चार्ज बढ़ा दे रही है और लाइन लॉस तो अपनी जगह है, उसकी भी बड़ी भागीदारी है तो मैं सरकार से सिर्फ इतना चाहता हूं कि यह जो विषय मैनें उठाया है इस पर सरकार अपना कोई वक्तव्य दे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं वह कोई इस पर चुटकी न लें। इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ, जो आम जनता है जिसकी यह सरकार हिमायती है उसके कष्ट में कुछ कमी आवे, इस दिशा में कोई उत्तर देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, दादा का तो यह टापिक ही नहीं है, पता नहीं, किसने रटाकर आपको भेज दिया। आप तो देखिये हमारे यहां आप उन बड़े बुजुर्गो में हैं कि बस आप आर्शीवाद दिया कीजिये और सरकार को मशवरा दिया कीजिये और हम आपके मशवरों पर काम करेंगे मान्यवर। अच्छा सुझाव है आपका।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मैनें आपसे फिर वही कहा कि चुटकी लेने का काम मत करिये। जनता के दर्द पर मलहम लगाने वाला काम आप करिये। मेरा आर्शीवाद नहीं, जिनके आर्शीवाद से मैं यहां चुनकर आता हूं और सभी लोग आते हैं चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों इन्हीं के आर्शीवाद का फल है कि आप संसदीय कार्य मंत्री है, कोई मुख्य मंत्री है और आप सर्वशक्ति सम्पन्न हैं। बहुत कद्दावर मंत्री हैं, आपकी एक हनक है, पुलिस की हनक हो न हो लेकिन आपकी हनक है। तो आप इतनी कृपा करें कि मैंने जो बहुत छोटे–छोटे तीन–चार विषय उठाये हैं कि एक तो आम उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता कनेक्शन धारक हैं के विषय में है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कह दिया कि आपके सुझाव पर विचार करेंगे, बस बात खत्म हो गयी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मैं केवल तीन बिन्दु आपके सामने उठाता हूं कि उनके जो कनेक्शन का स्वीकृत भार है, उसको मनमाने तरीके से बिना उपभोक्ता को विश्वास में लिये, बिना उसको जायज कारण बताये दो किलोवाट तीन किलोवाट का विद्युत बिल बना कर भेज दिया जा रहा है, दूसरी बात जो लाइन लासेस है उसको कम करने के लिये हर सरकार कोशिश करती है लेकिन यह जो नौकरशाही है यह अपनी गलतियों पर परदा डालने के लिये उपभोक्ता को, उनके टैरिफ में वृद्वि करना लाजिमी है ऐसा बता करके उनके ऊपर बोझ डाल रही है और यह जो बिल की गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कराने के लिये जो उपभोक्ता हैं, जो गरीब उपभोक्ता है जिनकी आवाज आप हैं, हम हैं, हम आर्शीवाद नहीं, बल्कि इस समस्या को आपके समक्ष रख रहे हैं कि आप उनके कष्टों पर कुछ मलहम लगायेंगे तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि यह जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है उनके साथ जो मनमानी हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए आप कुछ तो करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपको याद होगा कि लाइन लासेज को रोकने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम अंडरग्राउन्ड सिस्टम शुरू कर रहे हैं और कई जिलों के नाम भी उन्होंने बताये थे तो जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जायेगी तो लाइन लासेज खुद कम हो जायेंगे, बिजली की चोरी में भी कमी आयेगी। आप स्वयं जानते हैं कि गरीब और कमजोर आदमी बिजली का इस्तेमाल करता है और सरकार यह नहीं देखती कि इसका कनेक्शन है भी या नहीं है, यह सच है। अगर कहीं कोई खास शिकायत आपकी है वह मिल जाए तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे, आपके सुझाव यकीनन अच्छे हैं और ऐसे लोगों के लिए हैं जो वाकई उपेक्षित हैं।

(सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप पूरा सुन तो लीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, इसमें मुख्य विषय में से एक विषय छूट गया है इसलिए मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं वह यह है कि आम लोगों की शिकायत है कि जो अब नये मीटर लगाये जा रहे हैं वह इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि उनके बिल बहुत अधिक आ रहे हैं, यह भी मेरा एक विषय था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, असल में हुआ यह कि दिल्ली में सरकारों ने एक तजुर्बा किया और रिलायंस को काम दिया, रिलायंस वालों ने भी अपने मीटर यह समझ करके लगाये कि हम पैसे ले लेंगे मगर रिलायंस वाले भी अपने मीटर उतारकर ले गये और कहते हैं कि भाई जो तुम दे दोगे वह हम ले लेंगे। तो मान्यवर, मीटर तो उतना ही भागेगा जितना उसे भगाया जायेगा, खुद से मीटर नहीं भागता है, रोका तो जा सकता है उसे आगे

भगाया नहीं जा सकता है फिर भी जो कमजोर लोग हैं उनके लिए ही सरकारें होती हैं और आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

(सदस्य श्री मनीष असीजा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात भाषण में कह लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले उपाध्याय जी अपनी बात कहेंगे उसके बाद हम एक बात कह देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हम लोग जनता के पहरुए हैं। कहीं–कहीं कोई सार्वजनिक क्षेत्र गड़बड़ हो रही हो तो उसके पहले पहरेदार बनकर या तो रोकें या उच्च सदन में उससे अवगत करायें। आगरा में एक बड़ा भूमि घोटाला हो रहा है, गड़बड़झाला हो रहा है, उस घोटाले के पर्दे के पीछे कुछ रिटायर्ड नौकरशाह है। नौकरशाह क्या करते हैं इसे हम सब जानते हैं। पर्दे के पीछे ऐसे ही लोग हैं जो अभी तक सरकार के संज्ञान में नहीं होंगे। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि करीब हजार वर्ग मीटर जमीन नजूल की लैण्ड जो कभी छात्रावास के लिए दी गई थी, हैरीटेज सेन्टर स्थपना के नाम पर कुछ लोग उसे हड़पना चाहते हैं ऐसा पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। मैं उस जमीन का इतिहास बताऊं कि उसमें लगभग 9 हजार 242 वर्गमीटर नजूल लैण्ड है और 1730 वैश्य वेस्ट बोर्डिंग हाउस, आगरा के नाम दर्ज है। अर्थात् इस पूरी 10 हजार 672 वर्गमीटर को, यहां 1891 में एक छात्रावास का निर्माण हुआ था। निर्धन और वैश्य वर्ग के छात्रों के लिए। उसके बाद वहीं पर खेल का मैदान भी बना उसी में खेल के मैदान के लिए भी जमीन दी गई थी। उद्देश्य था छात्रावास का निर्माण और खेल का मैदान। लगभग 60 वर्ष पूर्व सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों की औपचारिकता को पूर्ण करते हुए वहां पर 13 दुकानों का निर्माण छात्रवास के वित्तपोषण के लिए किया गया। अचानक मेरठ और गुड़गांव के रिटायर्ड आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 की निगाह इस जमीन पर चली गई। उन्होंने दिल्ली में एक सोसायटी गठित की। आगरा की वैश्य बोर्डिंग हाउस की तरह एक मिलती जुलती हमनाम थी वह वी0बी0एच0 वेलफेयर सोसायटी उसे दिल्ली में रजिस्टर्ड करते हैं और अपने उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य डालते हैं, दिल्ली में रजिस्टर्ड और पता गुड़गांव का और पहला उद्देश्य है ''टू प्रमोट, डेवलप टर्न एकाउन्ट एक्जिस्टिंग एसेट्टल ऑफ वैश्य बोर्डिंग हाउस आगरा फॉर प्रमोटिंग ए वर्ल्ड क्लास एजूकेशनल कम कल्चरल सेन्टर''। मान्यवर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वहां दिल्ली, गुडगांव पर बैठे लोग आगरा के वेलफेयर की चिन्ता कर रहे हैं। जबकि वहां बहुत पहले से छात्रावास निर्धन छात्रों के लिए बना हुआ है, वर्षों से चला आ रहा है और 32 रुपये बिला पट्टा पर अंग्रेंजी काल में उनको

दिया गया है। प्ले–ग्राउण्ड है जिससे खेल–खिलाड़ियों का विकास होता है। साजिश के रचयिता इसके माध्यम से पर्दे के पीछे से आकर घुसना चाहते हैं। जब आगरा के वैश्य बोर्डिंग हाउस को पता चला तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि उनका रजिस्ट्रेशन न हो तो लगता है कि अब दोनों का अलिखित समझौता हो गया। उस अलिखित समझौते में यह तय हुआ कि वैश्य बोर्डिंग हाउस आगरा के नाम पर ही उस जमीन को ले लें और उस पर फिर बाद में कल्चरल एक्टीविटी के नाम पर आपस में मिलकर व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करेंगे ? यह सब सरकार की नाक के नीचे होता रहा। उस दिल्ली वाली सोसाइटी में रिटायर्ड आई0पी0एस0, आई0ए0एस0 हैं और यहां पर इनकी मिलीभगत है जिस सोसाइटी के नाम पर यह दी गयी, आगरा के जिलाधिकारी ने विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को 26 मार्च, 2011 को लिखा कि ये संस्था इसका पंजीकृत होना और इसके अधिकार का अस्तित्व ही संदिग्ध है और इसकी वर्तमान केयरटेकर की नियुक्ति कैसी हो गयी, यह भी संदिग्ध है और इस पर प्रश्न–चिन्ह लगाया है। अब शासनादेश से इस सोसाइटी को हैरिटेज कल्चर के नाम पर प्रश्नगत बेशकीमती जमीन एलाट कर दी गयी और एक शासनादेश जारी हुआ उसी शासनादेश का एक और बिंदु पढ़ना चाहता हूं। यदि किसी वेलफेयर के लिए कोई जगह दी जाती है और वह संस्था उसका उल्लंघन करती है तो उसे दंडित होना चाहिए। लेकिन यहां पर उसको इनाम दिया जा रहा है। यानी एक चोर रास्ता खोला जा रहा है उसके लिए कि जाओ और हैरिटेज व कल्चरल के नाम पर धन्धा करो। पहली बात तो यहां निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास है, खेल–खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान है और कुछ व्यवसायी लोगों के रोजी–रोटी का विषय है वहां पर हैरिटेज सेन्टर के नाम पर चोट करो। उसके बाद अगर तुम्हें लाभ कमाना हो तो उसका व्यावसायिक उपयोग कर लो। उस शासनादेश का सातवां बिन्दु, यदि आगरा हैरिटेज सेंटर का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जायेगा और इससे कोई लाभ प्राप्त होगा तो प्रश्नगत नजूल को पी0पी0पी0 के आधार पर दे दिया जायेगा राज्य सरकार भागीदारी नजूल भूमि की होगी।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करिये, आपको क्या कहना है उसको स्पष्ट कीजिए।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, संक्षेप कर रहा हूं। इसके माध्यम से उसको पी0पी0पी0 पर दे दिया जायेगा यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जमीन दी जा रही है अगर वह संस्था उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, व्यावसायिक कार्य करती है तो वह संस्था दंडित होनी चाहिए। बल्कि यहां उसको पी0पी0पी0 के आधार पर जमीन दे दी जायेगी ऐसा प्राविधान किया गया है इस शासनादेश में। मान्यवर, इस सरकार के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। वहां के जो निर्धन छात्र हैं वो दुःखी हैं उनके हितों पर चोट हो रही है, खेल–खिलाड़ियों के ऊपर चोट हो रही है, उन 13 दुकानदारों के रोजी–रोटी पर चोट हो रही है और मान्यवर, इसको अगर फौरन रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, गम्भीर मामला है इसे दिखवायेंगे, अवश्य दिखवायेंगे। लेकिन ऐसा न हो कि इधर से बचे और उधर कोई हड़प ले। किसी की निगाहें ऐसी तो नहीं हैं कि इधर से बचा ले और फिर ये हमारी हो जाए, ऐसा भी होता है। कभी–कभी किसी की जायदाद और जमीन पर कब्जा करने के लिए दो फर्जी पार्टियां अदालत चली जाती हैं फिर एक सरेण्डर कर जाता है तो दूसरे फ्राड के हक में फैसला हो जाता है तो यहां दोनों ही चीजें देखी जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तीसरा निशाना लगाये बैठा हो, उसे भी रोकेंगे और इसे दिखवायेंगे।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो शासनादेश जारी हुआ है जिसका उल्लेख माननीय उपाध्याय जी ने अपने वक्तव्य में किया है। वो शासनादेश तब तक निष्प्रभावी हो जाये, अगर वो प्रभावी रहेगा तो नीचे की कार्यवाही जारी रहेगी। उसी के लिए विधान सभा में यह मुद्दा उठाया गया कि शासनादेश के ऊपर रोक लगायी जाये जो शासनादेश जारी किया गया है। मान्यवर, एक निर्धन छात्रावास को कब्जा करने के उद्देश्य से शासनादेश जारी कर दिया गया और उससे आगे यह रास्ता छोड़ दिया गया। मान्यवर, पी0पी0पी0 मॉडल का, अगर यह हैरिटेज सेन्टर दुरुपयोग करेगा तो पी0पी0पी0 मॉडल से हम इसको टेक ओवर कर लेंगे। मान्यवर, एक बैक डोर से इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। इसलिये मान्यवर, यह विधान सभा में आया। मान्यवर, हम केवल इतना चाहते हैं कि वह जो शासनादेश 28–12–2015 को जारी हुआ है उसके ऊपर रोक लगे। उद्देश्य यही है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपने बता दिया, मंत्री जी ने कहा कि दिखवा लिया मैंने। कारण देखेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कान आपकी तरफ हैं सिर्फ हाथ इधर हैं। अगर दो तीन काम एक वक्त पर न करें तो फिर यहां बैठने देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस पर कोई व्यवस्था दे दें कि जिस शासनादेश की वजह से यह यहां पर आया। उद्देश्य यह था कि निर्धन छात्रावास को समाप्त न किया जाय। उस प्ले ग्राउन्ड को समाप्त न किया जाय। वो दसियों साल से है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्योंकि सारे तथ्य सामने नहीं हैं मेरे। मैंने खुद ही आपको आश्वस्त किया कि अगर ऐसा है तो यह बहुत संगीन है। इसको देखेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ छात्रावास ही है या छात्रावास से जुड़ी हुई कितनी जमीन है, क्या है ? तो कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना तो नहीं है। तो सारी चीजें देखकर ही ठीक निर्णय लेंगे।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रवीन्द्र भड़ाना जी का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब कहां तक करेंगे। एक–एक पार्टी के कितने लोग बोलेंगे। आपकी पार्टी से तीन लोग बोल चुके हैं, दूसरी पार्टियों से दो–दो लोगों को बोलने दीजिये। आप लोग बैठिये। भड़ाना जी को बोलने दीजिये। विमला सोलंकी जी आपका अक्सर आता है नियम 51 में आता है, 301 में आता है और भाषण भी करती हैं। भड़ाना जी को बोलने दीजिये, आप बैठिये ना।

'श्री रवीन्द्र भड़ाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र का मामला है। गांव काशी के अर्न्तगत एक नाबालिग लड़की डिम्पी बंसल का दिनांक 23–1–2016 को अपहरण कर लिया गया और कल उसके घर में सोते हुए परिवार के घर पर आग लगा दी गई। मान्यवर, ऐसी विडम्बना है कि आज तक न तो वह लड़की जिसका अपहरण हुआ है वह बरामद हो पाई है और उसके घर को समाप्त करने का काम किया गया। उसके घर के नीचे जो दुकान थी वह जलकर नष्ट हो गई, उसमें रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। ऊपर वह परिवार सोया हुआ था मकान में। मोहल्ले वालों ने रात्रि में हल्ला मचाया तब वह लोग जगे और वह लोगों के द्वारा बड़ा प्रयास करके बचाये गये। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि सरकार एक तो इस मामले में उन लोगों पर कार्रवाई करे जो लोग अपहरण करके उस लड़की को ले गये हैं और दूसरी बात जिन्होंने आग लगाई है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको दंडित किया जाय। मान्यवर, तीसरी बात, जो सामान उनके घर का फुंका है, मान्यवर, सारा सामान नष्ट हो गया। एक गरीब सामान्य परिवार है। उनका जो भी सामान जला है उसके लिये सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि उनको थोड़ी आर्थिक सहायता उस मामले में हो जाय तो बहुत बड़ी सरकार की कृपा होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जितना सुना है, वह तो गम्भीर है। अब यह जांच की जायेगी कि ले गये हैं या गई हैं, इस पर भी जांच करेंगे और यह भी जांच करेंगे कि आग कैसे लगी किसने लगाई। तो यह थोड़ा सा काम्प्लीकेटेड है इसमें जांच जरूरी है। जांच करायेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

'श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक महीने से लड़की बरामद नहीं हो पा रही है, उसके घर में आग लगा दी गई। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको दिखवायेंगे। यह जो आग लगी है इसको तो दिखवा लीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह तो देखना पड़ेगा ना कि ले गये या गई।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह जब इनके पास यूनियन है, यह लड़ लेते हैं वही परिषद्‌ीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिये आपने प्रश्न किया, आप बैठिये। एक लल्लू जी को भी कह लेने दीजिये। सभी पार्टी के लोगों को थोड़ा–थोड़ा कह लेने दीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं कुशीनगर जनपद से सम्बन्धित कुछ मुद्‌दों पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं करायेंगे। दो मिनट में कहिए जो कहना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

हमारे यहां तमकुही विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है आप जानते हैं। वहां तमकुही रोड से लेकर छितौनी तक एक रेल परियोजना.....

श्री अध्यक्ष–

यह तो भारत सरकार का है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

सुन तो लीजिए, दो मिनट सुन लीजिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है। 20 फरवरी, 2007 को तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री श्री लालू यादव जी ने उसका शिलान्यास किया। तमकुही रोड से छितौनी तक रेल परियोजना, उसमें जमीन अधिग्रहण करने का मामला था। बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके किसानों का मुआवजा भी दे दिया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद कुशीनगर में जो भूमि अधिग्रहण करनी थी वह न तो अब तक अधिग्रहण किया न उस पर मुआवजे की कोई कार्यवाही हुई जिसके कारण यह रेल परियोजना अधूरी पड़ी हुई है। मान्यवर, अगर यह रेल परियोजना बन जाएगी तो पिछड़े क्षेत्र का बड़ा विकास होगा और उत्तर प्रदेश से बिहार जाने के लिए..

श्री अध्यक्ष–

तमकुही से सीधे जाती है उधर से छितौनी जाने की क्या जरूरत है ऐसे ही पूर्व जाती है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र आग्रह था कि यह करीब साढ़े बारह मीटर....

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया अब बैठिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की जमीन अधिग्रहीत करनी है उसको कब तक करा लेंगे। इस पर जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

सरकार को जवाब देना होगा तो देगी इसमें कोई जबर्दस्ती नहीं है। हो गया अब आप बैठे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा निवेदन है, विनती है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष–

सुरेश राणा जी, आपकी पार्टी के तीन हो गये। कांग्रेस का हो गया अब एक इनका होगा। गजेन्द्र सिंह जी, आप जो प्रस्ताव लाए हैं वह एक बार आपकी पार्टी ने जाटों के आरक्षण के लिए भारत सरकार को भेजा था। अब भारत सरकार ने जब उसे स्वीकार नहीं किया तो आप दुबारा लाकर क्या करोगे। इसलिए यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जाट आरक्षण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जाट समाज के लोग पूरे प्रदेश के साथ–साथ पूरे देश में जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं और.....

श्री अध्यक्ष–

आप यहां भी जाट आन्दोलन कराना चाहते हैं क्या ?

'श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी तो उन्होंने जाटों को जनरल आरक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा था और उसमें ओ0बी0सी0 का आरक्षण दिलाये जाने का समर्थन किया था और आज भी आरक्षण की लड़ाई चल रही है उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी ने जाटों को आरक्षण देने के लिए अपना समर्थन दिय है तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजे कि जाटों को आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बार पहले भेजा जा चुका है स्वीकार नहीं हुआ। अब आप बैठे।

श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो जाट समाज आज आन्दोलन कर रहा है इस समाज के लोग भुखमरी के कगार पर चले गए उनका भविष्य अंधकार मय हो गया है उन्हें अशिक्षित होने के कारण रोजगार नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आज जो जाट समाज आन्दोलन कर रहा है।....

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया अब बैठिये। आपके क्षेत्र वाले आपका स्वागत....

श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी से जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मंत्री जी जवाब दें या हम ही कह दें। देखिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था माननीय मौर्या जी भी जानते है। आपकी सरकार ने भेजा था, अगर भारत सरकार को करना होता तो वह ओ0बी0सी0 में डाल देती। किसी तरह से उन्होंने ओ0बी0सी0 में डाला लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया।

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें जो वहां आन्दोलन हो रहा है। यहां से आपका प्रस्ताव गया था वह विचाराधीन है निरस्त तो हुआ नहीं है तो अलग से प्रस्ताव भेजने की क्या जरूरत है। अब आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर मामला है और हरियाणा के जाट भाइयों के साथ थोड़ा अन्याय तो हुआ है क्योंकि चुनाव में उनसे वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने उनके मैनीफेस्टो में भी था और सभी सभाओं में कहा था प्रधान मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया था कि वह यह रिजर्वेशन देंगे तो पालिटिकल कमिटमेंट को पूरा किया जाना चाहिए यह तो नैतिक बात है लेकिन एक कानूनी बात भी है कि यहां से रेजोल्युशन हुआ वह गया और कानून को सबसे बड़ी पंचायत सुप्रीमकोर्ट ही है सुप्रीमकोर्ट के फैसले को हम मानते हैं सभी को मानना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी एक पंचायत है वह है देश की पार्लियामेंट जो कानून को बदल सकती है रिजर्वेशन का नया कानून ला सकती है नये मानक तय कर सकती है तो देखिए सब बराबर बैठे हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपको चाहिए कि आप केन्द्रीय सरकार से यह मांग करें कि वह पार्लियामेंट में नया बिल लाए और नया कानून बनाए आपका रिजर्वेशन हो जाए हमें क्या ऐतराज हो सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो बातें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही हैं जो बातें आपके उत्तर में सम्बन्धित न हो उसकी कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

पार्लियामेन्ट ही तो कर सकता है उन्होंने पार्लियामेन्ट ही तो कहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने वायदों का पास नहीं रहा अपने लीडर की कमिटमेंट का पास नहीं रहा और आर्मी से अपने ही देश के बन्धुओं को मरवा दिया अगर यह बात मैंने गलत कही है और मैं पार्लियामेन्ट की सुप्रीमेसी को मान रहा हूं तो मैं आपसे माफी मांगे लेता हूं। आपने आर्मी का इस्तेमाल शुरू ही कर दिया है। मान्यवर, जिन चीजों पर आर्मी के कानों में हवा नहीं जानी चाहिए थी आपने जनता को आर्मी से मरवाया है आप हिन्दुस्तान को सीरिया और बगदाद बनाना चाहते हैं ईरान और ईराक बनाना चाहते हैं आप देश को कहां लिए जा रहे हैं आप देशवासियों को इस तरह से मारेंगे उनकी वह मांग जो आपने मानी जिस पर आपने वायदा किया चुनाव में उसके लिए आप उन पर आर्मी से गोली चलवा रहे हैं यह बात निन्दनीय है फिर भी मैंने आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कह दी है तो मैं आपसे माफी मांगे लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

दलबीर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। दलबीर जी अध्यापकों को आप कहां ले आए उनकी यूनियन है वह आपसे ज्यादा लड़ते है।

'श्री दलबीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है उनका ज्ञापन बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

आप उसे सरकार के पास भेज देते। एसेम्बली में उठाने की क्या जरूरत थी।

श्री दलवीर सिंह–

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लें प्रदेश में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं इस सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई कि अपने होम डिस्ट्रिक में जो भी जाना चाहते हों उन सबके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ट्रांसफर हुए विभिन्न जनपदों में जहां उनकी इच्छा थी उसके हिसाब से सरकार ने यथा उचित ट्रांसफर किये लेकिन उनकी जो सीनियरिटी काउंट की जानी चाहिए जहां से ज्वाइनिंग रिपोर्ट हुई थी वहां से न करके बाद में जिस

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिले में आए वहां से उनकी सीनियारिटी काउंट की जा रही है इससे उनकी हकतलफी हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

वह लड़ने में समर्थ हैं वह सब यूनियन बनाकर कोर्ट में लड़ लेते हैं।

श्री दलबीर सिंह–

उन्होंने हमको दिया है। हम इस पर जवाब चाहते हैं। अध्यापकों की यह मांग जायज है उनकी सीनियारिटी वही से काउंट की जानी चाहिए जहां से वह ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दो शब्द कह दें तो अच्छा लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

आपको दिया है तो आप शासन को मार्क करके भेज देते।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने तो खुद ही आश्वस्त कर दिया कि इसे आप विभाग को भेज दें विभाग इस पर विचार करेगा और जो नियमानुसार उनका अधिकार बनता है उस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

आप उनको जानते हैं उनके पास संघर्ष समिति है आप कहां इस बवाल में फंस गए। आपको माला पहनाए होंगे आप खुश हो गए।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी का मामला है इनका कहना है कि प्रमाण–पत्र नहीं मिल रहा है मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज कैंसर की चपेट में है। सारे उद्योगों का जहरीला पानी सीधा नदियों में जा रहा है, जिसके कारण से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज कैंसर की चपेट में है। एक तरफ तो किसान गन्ना भुगतान न होने के कारण बरबादी के कगार पर है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वह यह है कि जल स्तर ऊपर उठाने के लिये नदियों में चेकडैम बनाये गये थे। वह चेकडैम इसलिये बनाये गये थे कि जल स्तर ऊपर उठे, लेकिन अब नदियों का पानी जहरीला हो गया है और चेकडैम जब जहरीले पानी को ऊपर उठाता है तो वह नीचे–नीचे सारे के सारे जल स्तर में चाहे वह नल हों चाहे अन्य पानी के श्रोत हों, वह जहरीला रासायनिक पदार्थ घुल गया है, जिसके कारण पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गॉव नहीं बचा है जहॉ एक से लेकर दस पेशेन्ट कैंसर के न हों। जब हम सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट हेतु प्रस्ताव की मांग करते हैं तो उस पर भी शून्य जवाब आता है। मा0 अध्यक्ष जी, कृष्णा और हिंडन नदी।

श्री अध्यक्ष–

मा0 राणा जी, आप कोई सुझाव देना चाहें तो दीजिये। कृष्णा और हिंडन पर कल तो बात हो गयी, प्रश्न भी आ गया, अब आप उसको क्यों उठा रहे हैं। आपका मामला जल स्तर का था और आप उसे कैंसर पर ले गये। मा0 राणा जी, कैंसर पश्चिम में जितना है उससे कहीं ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का पानी बहुत प्रदूषित है, जिससे बड़ी दिक्कत होती है। मा0 मौर्या जी भी कुशीनगर से आते हैं, हम लोग भी आते हैं।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, कारखानों के नाम बोल रहा हूं। थाना भवन में शुगर फैक्ट्री है, लगातार पाँच साल से उठा रहा हूं। नरौता में गत्ता फैक्ट्री है, नरौता में शुगर फैक्ट्री है। गाजियाबाद से सटे जितने उद्योग हैं, पूरा मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक जितना क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में उद्योगों द्वारा जहरीला और विषैला पानी डाला जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हीट एण्ड ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जल को शुद्ध कर प्रवाहित किया जाये, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग तड़प रहे हैं, लोग बरबादी की कगार पर हैं, हजारों लोग तड़प–तड़प कर जान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बार–बार क्यों उसी बात को कह रहे हैं ?

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर अगर कुछ कहेंगे तो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जायेगी, कुछ कारखानों के खिलाफ कार्रवाई हो जायेगी जिससे उन्हें सबक मिलेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं जो कहूंगा उसे आप अन्यथा ले जायेंगे। आपने शुगर मिल का नाम लिया, चलिये ठीक है, आपने नाम लिया, शुगर मिल्स पानी को साफ करके अपना प्लांट खुद लगाते हैं, लेकिन जो पानी नदियों में आता है उसके लिये ट्रीटमेंट प्लांट हम तैयार करते हैं और हमने वह सारी योजना भारत सरकार को भेजी है। मैं यह बार–बार कहता हूं कि भारत सरकार से धन नहीं मिला। हमारा फेडरल सिस्टम है, हम टैक्स देते हैं, हर प्रदेश के लोग टैक्स देते हैं जिससे केन्द्र की सरकार का खजाना भरता है और वही पैसा फिर प्रदेशों को बॉटा जाता है, जिसमें हमारे यहां बहुत कमी आई है खुद हमारे विभाग में कमी आई है। जल निगम या हमारी वह संस्थाएं जो इस काम को करती हैं, पांच महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है और तनख्वाह इसलिये नहीं मिली है, क्योंकि जितनी योजनाएं चल रही थीं, भारत सरकार ने वह सभी योजनाएं रोक दीं हैं। सीवर सिस्टम अगर 40 प्रतिशत बन गया था तो वहीं रुक गया, जितने ओवरहैड टैंक्स बन रहे थे वहीं रुक गये, जहां पानी बिछाने की लाइने पड़ रही थीं, पिछले दो साल से लगभग वह सारा

काम रुका हुआ है, क्योंकि भारत सरकार वह स्कीम्स जो पिछली सरकार में अप्रूव्ड थीं, जिन पर धन भी अलॉट हो गया था, एक किश्त आ भी गयी थी, हमारे यहॉ से उसका यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट भी चला गया कि यह पैसा यूटिलाईज हो गया, लेकिन भारत सरकार से पैसा नहीं आया है और हालात यह हैं कि पांच महीने से जल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। इसलिये एक हल तो यह है और दूसरा जो दूसरे कारखाने हैं जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं गोश्त के कारखाने, जिनकी वजह से अगर पानी में कुछ गाढ़े तो वहीं से पानी उबलने लगता है, वह बड़ा जहरीला पानी है। उसके लिये हम बार–बार आपसे कह चुके हैं कि आप एक यूनीफार्म पालिसी ले आइये। पार्लियामेंट में एक बिल ले आईये और उस बिल से पूरे देश में जितने कारखाने हैं, आपके आदेश से वह सारे कारखाने बंद हो जायेंगे। सबसे ज्यादा पाल्यूशन अगर हो रहा है तो वह उन गोश्त के कारखानों से हो रहा है, उन्हें बंद करा दीजिये। ...

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर लिया है। वह लिखकर कागज चला जायेगा। अब चर्चा प्रारम्भ करिए।

श्री सुरेश राणा–

अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपके संरक्षण में हम लोग अपनी बात रखते हैं। मान्यवर, गोश्त के कारखानों की बात आयी, क्या प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? जब संसदीय कार्य मंत्री जी को जानकारी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप जानते हैं कि इन कारखानों को लाइसेंस केन्द्र सरकार देती है। मैंने पहली कैबिनेट में इस इशू को रखा था, इस सरकार की जब पहली कैबिनेट हुई, रखा था कि ये कारखानें बन्द कराने चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह हमारे अधिकार से बाहर है, लाइसेंस भारत सरकार देती है और पलूशन को रोकने की जिम्मेदारी भी आप पर ही है। आपका पलूशन बोर्ड है, वह क्यों नहीं रोकता, केन्द्रीय पलूशन बोर्ड है। अब हमारा दर्द तो यहॉ तक है कि हमारे यहां जो एक शराब का कारखाना है, शहर के बीच में आ गया है, सिविल लाइन्स एरिया में, मान्यवर, मैंने पिछले प्रधानमंत्री जी को लिखा, आपके प्रधानमंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति जी लिखा, चिट्ठी का एकनॉलेजमेंट तक नहीं आया, कहिए तो हम आपको उसकी कापी दे देंगे। तो जब एक सरकार के मंत्री की ही चिट्ठी पर, और मैं क्या चीज हूं, चे पिद्दी, चे पिद्दी का सोरबा, मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखते हैं तो उसकी वसूलयाबी तक की खबर नहीं आती। आप पूरी तरह से सक्षम हैं या तो हमें पैसा दीजिए, अगर उन कारखानों को आप बन्द नहीं करा सकते तो हम इनसे निकले हुए पानी का ट्रीटमेंट इतना अच्छा कर देंगे कि उस पानी को चाहे आप

खेती में इस्तेमाल करें और अगर पीने के पानी की कमी है तो उसे पीने का पानी बना देंगे। 75 प्रतिशत आप केन्द्र से दिलवाइये जो नियम है, फेडरल सिस्टम का, 25 प्रतिशत हम आपको कहीं से दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

रामचन्द्र जी, आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। श्री बब्बन सिंह चौहान की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री संजय कपूर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, चलिए, आपकी सूचना पर भी ध्यान आकृष्ट।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

ख्ा0 24 बजे, वित्तीय वर्ष (2016–17) के आय व्ययक पर साधारण चर्चा[4]

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सब का कर लिया। अब चर्चा शुरू होगी।

श्री अब्दुल मशहूद खां–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह यह साबित करता है कि इसमें समाज के सभी वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। हमारी पार्टी का एक नारा है कि 'रोटी–कपड़ा सस्ती होगी, दवा, पढ़ाई मुफ्ती होगी'। इस बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है। इतनी योजनाएँ हैं, अगर मेट्रो रेल की बात करूं, समाजवादी पेन्शन की बात करूं, कृषक दुर्घटना बीमा योजना की बात करूं, आम आदमी बीमा योजना की बात करूं, समाज के सभी वर्गों के लिए इस सरकार ने जितना किया है और पूरी तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी गंभीर हैं कि किसानों को उनका हक कैसे दिलाया जाए, गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को उनका हक कैसे दिलाया जाए, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, उसके लिए 102, 108 एम्बुलेंस जीता–जागता उदाहरण है। दुग्ध उत्पादन के लिए कामधेनु योजना, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कौशल विकास मिशन अपने आप में एक अभूतपूर्व योजना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, डाक्टरों की कमी उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से चली आ रही थी, जिसे दूर करने के लिए अगर किसी ने सोचा तो हमारे युवा ऊर्जावान मुख्य मंत्री जी ने सोचा और डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए एम0बी0बी0एस0 की सीटें उन्होंने बढ़ाईं। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को 35 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए 7587 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश भी किया गया है। गॉवों की तरक्की के लिए आई सपर्श योजना अपने आप में अभूतपूर्व योजना है।

(इस समय 01 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

---

[4] दिनांक 24 फरवरी, 2016 की कार्यवाही से।

इसके अतिरिक्त ऐसी तमाम योजनायें चलायी जा रही हैं जिसका सीधा लाभ किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को यहॉ पढ़ने वाले छात्रों को, तमाम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यकों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत लाभकारी काम किये हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्रीवाल से लेकर और तमाम योजनायें चलायी हैं। नगरों के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारे नगर विकास मंत्री जी ने अभूतपूर्व काम किया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

श्रीमती रजनी तिवारी।

(श्रीमती रजनी तिवारी जी का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर

श्री अधिष्ठाता जी ने श्री रोशन लाल वर्मा जी का नाम पुकारा।)

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे सत्तापक्ष के मा0 सदस्य ने किसानों की बात की, गरीबों की बात, मजलूमों की बात की। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 2014–15 में मा0 मुख्यमंत्री जी ने एक दिल्ली में बैठक बुलायी थी जिसमें कई देशों से उद्योगपति बुलाये थे जिसमें यह कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाकर हम यहां के गरीब, मजलूमों को काम दिलायेंगे। मान्यवर, कई दशकों से हमारे उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठे क्योंकि वह भी उद्योग माना जाता है। ईंट भट्ठे चलाये जा रहे थे लेकिन इस वर्ष से उत्तर प्रदेश में लगभग 18 हजार ईंट भट्ठों को संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग दो–ढाई करोड़ गरीब मजदूरों की रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है। मान्यवर, मैंने यह बात इससे पूर्व में भी उठायी थी जिस पर मा0 अध्यक्ष जी ने यह भरोसा दिलाया था कि मा0 मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हो चुकी है। यह भट्ठे अब शीघ्र संचालित करा दिये जायेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर जहॉ पर जो शक्तिशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वहां के भट्ठे कुछ जगह चलाये जा रहे हैं। लेकिन हमारे जनपद शाहजहांपुर में लगभग ढाई सौ से तीन सौ ईंट भट्ठे हैं। वहां के हजारों गरीबों की रोजीरोटी का संकट आ गया है। यहां तक कि मान्यवर, कुछ परिवार हमारे उत्तर प्रदेश से पलायन करने को तैयार हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को यह निर्देशित करें कि वहॉ के जिला अधिकारी या अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें जिससे कि वह ईंट भट्ठे अतिशीघ्र चलाये जा सकें जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से ढाई करोड़ तक गरीबों की रोजीरोटी चल सके। और मैं कहना चाहता हूं कि इससे पूर्व में हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी के पिताश्री मा0 नेता जी हमारी तिलहर विधान सभा से चुनकर आये थे लेकिन हमारी विधान सभा में अभी 2011–12 में भीषण बाढ़ आयी थी। भीषण बाढ़ के कारण तिलहर–निगोही मार्ग पर लगभग 300 मी0 की सड़क कटकर वहॉ पर उसने बड़े तालाब का रूप ले लिया और हमारी तिलहर तहसील जाने के लिए एकमात्र वही रास्ता है। अभी इस बजट पुस्तिका में बड़े पैमाने पर बजट की जो

व्यवस्था की गई है, लगभग 03 लाख 50 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बजट पुस्तिका में हमारे तिलहर की जो सड़क कटी हुई है जिससे पचासों हजार लोग वहां पर प्रभावित होते हैं, जबकि हमारा तिलहर विधान सभा क्षेत्र मा0 नेता जी का क्षेत्र रहा है, उसका कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, इसी प्रकार निगोही से खुदागंज की जो पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्मित मार्ग है उसके ऊपर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, किसानों की आये–दिन वहां पर दुर्घटनायें होती रहती हैं, सरकार किसानों की बात कर रही है, किसानों के हित की बात कर रही है, वहां पर भी कोई सड़क बनवाने का काम नहीं किया। इसी प्रकार लिपोलिक–भिण्ड मार्ग, निगोही से बीसलपुर मार्ग पर निगोही से बहुत ही संकरा पुल बनाया गया है, जो सदियों से अंग्रेजों के जमाने से बना है, उस पर आये–दिन बड़ी–बड़ी जामें लगी रहती हैं, कई बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं तो उस पुल पर भी कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जिससे आये–दिन वहां पर दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसी क्रम में हमारे हम्जापुर और निगोही के मध्य कैमुआ नाला पर, जब बरसात के समय बाढ़ आती है, जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाती है और दर्जनों गाँव, सैकड़ों गॉव, बरसात में वहां पर पानी भरने से लोग बेघर हो जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, तो वहां पर भी पुल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे तिलहर विधान सभा क्षेत्र का मा0 नेता जी के ऊपर वहां की जनता का एहसान है क्योंकि वहां से हमारे तिलहर के सम्मानित मतदाताओं ने, सम्मानित जनता ने नेता जी को चुन कर भेजा था, उसके बावजूद भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने वहां पर विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसी क्रम में मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि अभी जनपद शाहजहांपुर में बड़े पैमाने पर जो विधवायें हैं, जो वृद्धा हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी हजारों की संख्या में वहां के सम्मानित अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से उनकी पेन्शन काट दी गई और दलोसा द्वारा फर्जी पेन्शन बनाकर गलत तरीके से उनका करोड़ों रुपया वहां पर निकाल लिया गया, इसी क्रम में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक नथुआपुर और अख्तियारपुर के बीच जहां पर पूरे जनपद शाहजहांपुर में इतना पिछड़ा गाँव कोई नहीं होगा, वहां पर छोटी पुलिया का निर्माण न होने के कारण बरसात में लोग अपने गाँव में गुजारा करते हैं, यहां तक अगर वह वहां से कहीं बाजार सिंधौली के लिए जाना चाहें, तो वहां के लिए भी निकलने में उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने एक शेर सुनाया था, तो मैं गरीबों पर एक बात कहना चाहता हूं कि जो अभी सरकार ने बताया कि मैंने किसानों के हित में कार्य किया, गरीबों के हित में कार्य किया, लेकिन शायद बड़े–बड़े उद्योगपतियों के लिए कार्य किया होगा। मैं कबीर दास जी का दोहा कहना चाहता हूं–

''धनावती कांटा लगा, दौड़े लोग हजार ।
निर्धन गिरा पहाड़ से, कोई न आया पास'' ।।

मान्यवर, ये सरकार की नीति और रीति है, मैंने अभी कहा कि हजारों–हजारों, करोड़ों–करोड़ों हमारे प्रदेश के गरीब निर्धन बेसहारा लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री जाहिद बेग–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अगर आप कहें तो मैं सम्भाल के बोलूँ, धीरे–धीरे बोलूँ ताकि हमको समझ लीजिएगा। आज कोई भी पार्टी चुनाव में जाने से पहले चुनाव घोषणा–पत्र अपना बनाती है। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को, कि जो वायदा उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच किया था, वह सारे वायदे उन्होंने पूरे किए। चाहे वह मुफ्त पढ़ाई हो, चाहे वह मुफ्त दवाई हो, सिंचाई मुफ्त, सड़कों का जाल, जो मूल सुविधा प्रदेश की थी और गाहे–बगाहे यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष में बैठे लोग भी इस बात की तारीफ करते हैं कि आज दवाई, 108, 102, अस्पतालों में दवाई गरीबों को फ्री मिल रही है। सिंचाई के बारे में जो लोग किसान की बात करते हैं, बच्चा–बच्चा जानता है कि क्या पहले की सरकारों ने किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त कभी किया था ? कभी नहीं किया था। आज किसान दुर्घटना बीमा किसने दिया है। इसके पहले सरकारें थीं जो आज दुहाई दे रहे हैं, एक लाख रूपया नेता जी ने किया था, माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश जी ने उसे पांच लाख रूपया कर दिया। आज दवा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया गया है। बहुत जल्दी इसका नतीजा सामना आ जायेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बिजली के लिए घोषणा की है। आज सारी बातें जब व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए पूरा किया और सारी तारीफ करने के बाद विपक्ष कहता है, लॉ एण्ड आर्डर आ जाता है। अधिष्ठाता महोदय, किसी की भी सरकार आ जाए, हत्या हुई है, दुर्घटना हुई है, चोरियां हुई हैं लेकिन इसके बावजूद भी आज आप सरकारी ऑकड़ा निकाल कर देख लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम और हत्या के मामले और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पीछे है। लेकिन हद तब हो जाती है जब पार्टी में बैठे हुए लोग वोट के सवाल पर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। वोट के सवाल पर जब चाहे जिसको मार दें। यह जुल्म की इंतिहा हो जाती है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाभारत में तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, आपकी सरकार के लोगों ने आर0एस0एस0 के लोगों ने, केन्द्र में काबिज सरकार के इशारे पर, आर0एस0एस0 के इशारे पर, रोहित वेमुला हैदराबाद के नौजवान लड़के को काण्ड के तहत, षड्यन्त्र के तहत मारने का काम किया है। जे0एन0यू0 के कन्हैया का मामला आज पूरे देश में एक सवाल खड़ा करता है आज मीडिया के माध्यम से मैं भी देख रहा था, एबीपी न्यूज देख रहा था, उन्होंने दिखाया कि पहले क्या थी आज क्या हुआ शिफ्टिंग के मामले में जो चर्चा हो रही थी। पहले यह दिखा रहे थे कन्हैया ने नारा लगाया था आज वही मीडिया, वही कमीशन के लोग, दिल्ली कमीशन का बयान आता है कि कन्हैया उस वक्त मौके पर खड़ा था। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं जब यहां सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग रक्षक नहीं भक्षक

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन जाएंगे। अदालत के सामने किस तरह लोगों ने अपने चरित्र को पेश किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बीफ के सवाल इकलाख को मार दिया गया यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह दोहरा चरित्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। माननीय अधिष्ठता महोदय, आज जो सवाल करता है उसके ऊपर एफ0आई0आर0 हो जाता है, 120बी के तहत। हमारे भाजपा के अध्यक्ष, बसपा के सदस्य बोल रहे थे कि जाट आंदोलन के सवाल पर आपदा के सवाल पर। जब चुनाव मेनिफेस्टो में आपने वायदा किया था, मस्जिद के सवाल पर सन् 1992 में जिसकी हत्या हुई। उसमें 120बी0 के तहत उन नेताओं को शामिल करना चाहिए था जिन्होंने घोषणा–पत्र में शामिल किया था। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को हत्या के मामले में जेल में डाल देना चाहिए था जिन्होंने चुनाव में घोषणा की थी। वह रिकार्ड, वह वीडियो मौजूद है कि वोट के लिए, गद्दी के लिए देश के अन्दर अराजकता फैलाने का काम कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह बात मैं कहना चाहता हूं कि दोहरा चरित्र कुर्सी के लिए, दोहरा चरित्र हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों ने न कभी किया है और न हम कभी करते हैं। ऐसी कुर्सी को ठोकर मारने का काम अगर कोई करता है तो मा0 नेता जी करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज बसपा के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि ये बेचारे अपने आप कुढ़े जा रहे हैं उन्होंने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी को और आज इसी वजह से इनकी हालत यह हुई है। आज कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उप चुनावों में इन लोगों ने मिलकर काम किया है जनता देख रही है।

श्री अधिष्ठाता–

जाहिद साहब, अब समाप्त करें।

श्री जाहिद बेग–

अधिष्ठाता जी, मैं एक मिनट में अपने क्षेत्र के सवाल पर अपनी बात समाप्त करता हूं मैं जानता था और इसी वजह से मैं लम्बा नहीं खींच पा रहा हूं। उप चुनाव में जनता ने देखा है कि सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हुए नजर आए थे और आने वाले दिनों में इसका जवाब तो जनता देगी, कांग्रेस पार्टी को देगी। मैं अपने भदोही की बात करता हूं चूंकि भदोही हमारा अपना विधान सभा क्षेत्र है, भदोही जिला है। अभी दो दिन पहले बहन जी का बयान आता है लखनऊ से कि हमारी सरकार बनी तो हम भदोही का नाम सन्त रविदास नगर कर देंगे जो भदोही बना दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और पत्रकार बन्धु बैठे हुए हैं। इस जिले का नाम पहले भदोही था। भदोही जी0आई0 के नाम से विदेशों में मशहूर है और जब इन्होंने भदोही का नाम सन्त रविदास नगर कर दिया तो वहां का व्यापार कमजोर हो गया, ठप हो गया। वहां के व्यापारियों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां के गरीबों ने मांग की मा0 मुख्य मंत्री जी से कि हमारे उद्योग के लिए भदोही को पुनः वापस कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, एक मिनट। डा0 साहब एक मिनट। मा0 मुख्य मंत्री जी ने नाम वापस कर दिया। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि कोई सन्त हो, कोई देवता हो और कोई पैगम्बर हो, कभी यह नहीं सोचता कि हमारे नाम से किसी को तकलीफ हो, उद्योग चौपट हो जाए। कभी किसी सन्त ने सपने में नहीं सोचा था, सन्त रविदास जी ने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे नाम पर उद्योग चौपट हो जाए। ये लोग देश को, देवी–देवताओं को पेटेण्टीकरण करके बेचना चाहते हैं। मैं देवी–देवता, महापुरुष का पेटेण्टीकरण करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने यह नहीं सोचा था कि हमारे नाम को करने से वे बहुत खुश होंगे। आप अपने वोट के लिए नाम बदलकर कई बार नाम बदलते हैं वोट लेने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार तो मैंने चुनाव 17 हजार से जीता था इस बार 50 हजार से जीतकर आऊंगा कोई रोक नहीं सकता। नाम बार–बार आपने बदला है। मा0 अध्यक्ष जी, भदोही में 50 करोड़ रुपया कारपेट बाजार के नाम पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्राविधान किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि कारपेट बेल्ट से कई लाख लोगों की रोजी–रोटी जुड़ी हुई है। यह काम समाजवादी पार्टी के नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने किया है। बाकी भाजपा और आप जैसे लोगों का काम है सिर्फ जनता को लड़ाना, हत्या करना, देश के अन्दर अराजकता भरा माहौल पैदा करना और कुर्सी पर कब्जा करना। मा0 अधिष्ठाता जी, धन्यवाद।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता भाजपा के विचारों से अपने का सम्बद्ध करता हुआ मैं बजट की चर्चा पर आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में जब बजट भाषण पढ़ा तो बहुत गर्व के साथ उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र के बाद देश का सबसे बड़ा बजट है और हमने पिछले वर्ष के मुकाबले 14.6 प्रतिशत अतिरिक्त धन की व्यवस्था की है। 3 लाख 46 हजार करोड़ की व्यवस्था की। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप पिछले साल का बजट देखें तो मूल बजट 3 लाख 25 हजार करोड़ था और जो अनुमानित अंतिम आंकड़े आये हैं उसके हिसाब से यह 3 लाख 30 हजार करोड़ का बजट है। वर्ष 2015–16 में 3 लाख 30 हजार करोड़ का बजट और वर्ष 2016–17 में 3 लाख 46 हजार करोड़ का बजट अर्थात् कुल मिलाकर यह सिर्फ 16 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त है अर्थात् यह 14.6 प्रतिशत बढ़ा नहीं है, सिर्फ 5 प्रतिशत बढ़ा है और महंगाई की दर को अगर जोड़ दिया जाये तो मूलतः वर्ष 2016–17 का बजट, वर्ष 2015–16 के बजट से कम है। दूसरी चीज माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगातार हम सदन में चर्चा सुनते हैं कि भारत सरकार ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, यहॉ पैसा काट लिया। सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया और अपना साहित्य दिया तो मैंने उस साहित्य को पलटना शुरू किया और माननीय

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अबतक सरकार लगातार सदन में गलतबयानी करती आ रही है। सरकार ने लिखित रूप से जो साहित्य हम लोगों को दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सरकार को केन्द्र सरकार से सारे अनुदान के रूप में कुल मिलाकर 1 लाख 39 हजार 133 करोड़ रूपये प्राप्त हुये और इस साल वर्ष 2016 में एक लाख उन्तालिस हजार के जगह पर सरकार को 1 लाख 56 हजार 785 करोड़ रुपये मिले हैं अर्थात् पिछले साल के मुकाबले इस साल केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाली मद्द जिसे लिखित रूप से राज्य सरकार ने अपने साहित्य में स्वीकार किया है। वह 17624 करोड़ है और बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार बजट साहित्य में जब देती है तो लिखित रूप से कहती है कि भारत सरकार ने हमको 17624 करोड़ रुपये अधिक दिये और जब रोजमर्रा की बहसें होती हैं, किसी भी चर्चा में हम आते हैं तो विषयान्तर करके यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमको भारत सरकार से धन नहीं मिल रहा है। आखिर सदन में जो गलत बयानी करते हैं और बजट में जो तथ्य लिखते हैं इन दोनों के अन्तर को चिन्हांकित किया जाना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, जो सबसे बड़ी चीज है, सरकार यह कहती है कि हमने बजट बढ़ा कर दिया लेकिन सरकार की सच्चाई क्या है कि सरकार ने जो पूँजीगत परिव्यय किया है, वह पिछले साल से कम कर दिया। पिछले साल सरकार ने 1 हजार 75 करोड़ रूपये का पूंजीगत परिव्यय किया था और इस साल सरकार ने जो आंकड़ें अपने साहित्य में दिये हैं उसके हिसाब से यह सरकार सिर्फ 93 हजार करोड़ का पूंजीगत परिव्यय करने जा रही है अर्थात् पूँजीगत निर्माण में यह सरकार अपने बड़े बजट के बावजूद 8 हजार करोड़ रुपये की कमी करने जा रही है, अर्थात् सरकार जो कुछ भी अतिरिक्त खर्च जो भारत सरकार ने इन्हें 17 हजार करोड़ रुपया दिया है, उसी के आधार पर यह 16 हजार अतिरिक्त खर्चा कर रहे हैं लेकिन उसका उपयोग अनुत्पादक खर्चों में कर रहे हैं, पूंजीगत परिव्यय में नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारा बजट देश का दूसरा सबसे बड़ा बजट है। यह भी एक मिथक है अधिष्ठाता महोदय, देश के बजट का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम अब्सिलयूट एमाउण्ट पर नहीं करते हैं, प्रतिव्यक्ति बजट पर करते हैं और जब हम प्रतिव्यक्ति के आंकड़ों पर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश जो दुनिया का छठवां सबसे बड़ा देश होता, जैसा कि हम बार–बार कहते हैं, हम ग्यारहवें स्थान पर आते हैं। हमसे अधिक प्रतिव्यक्ति पूंजीगत परिव्यय बिहार का छोड़कर सारे बड़े प्रांतों की है। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का इस साल का प्रतिव्यक्ति व्यय 59935 रूपये है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड के जो आंकड़े हम लोगों के पास हैं, उत्तराखण्ड का 1 लाख 15 हजार है, तमिलनाडु का 1 लाख 28 हजार है, हरियाणा का 1 लाख 47 हजार है अर्थात् इस सारी दौड़ में आज भी उत्तर प्रदेश हमारे लिए शर्म का विषय होना चाहिए, जिसे यह गर्व का विषय बना करके असत्य वचन इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से कहलाना चाहते हैं। हम उस विकास के दौड़ में न सिर्फ पीछे हैं बल्कि अभी बहुत लंबे समय तक पीछे रहने वाले हैं। इसका आधार है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है एसोचैम। एसोचैम के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार डबल डिजिट ग्रोथ का एक कॉन्फ्रेन्स करने

जा रही है। अधिष्ठाता महोदय, उस एसोचैम नाम की संस्था का अध्ययन आया है। सब जगह उपलब्ध है जिसमें एसोचैम ने बहुत साफ–साफ इस बात को इंगित किया कि देश के जितने बीमारू प्रान्त हैं उनमे उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्तर पर है। उत्तर प्रदेश की कम्पाउण्ड एनुअल ग्रोथ रेट कुल मिलाकर 6.9 प्रतिशत है जबकि बिहार की कम्पाउण्ड एनुअल ग्रोथ रेट 9.3 है, मध्य प्रदेश की कम्पाउण्ड एनुअल ग्रोथ रेट 8.8 है, राजस्थान की कम्पाउण्ड एनुअल ग्रोथ रेट 8.2 है। देश के विकास मे हमारा हिस्सा जब यह सरकार नही आयी थी तो देश के विकास मे हमारा हिस्सा 8.8 प्रतिशत हुआ करता था और आज जब हम यह बहस कर रहे हैं तो यह हिस्सा 8.8 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत हो चुका है। यह इस सरकार के पांच साल के कार्यकाल का असर है हमारे उत्तर प्रदेश के विकास पर। अधिष्ठाता महोदय, 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और सरकार ने यह वादा किया था हम लोगों से आपको याद होगा बजट साहित्य में उपलब्ध है कि कुल मिलाकर 12 लाख 51 हजार करोड़ रूपये का निवेश इस प्रदेश में कराया जायेगा आप सभी माननीय सदस्यों को याद होगा। आज माननीय मंत्री जी ने जब सरकार की ओर से जवाब दिया है सदन में हमारे माननीय महाना जी ने सवाल पूछा था कि वास्तव में पिछले चार सालों में इस प्रदेश में पूंजी निवेश कितना है तो सरकार के मंत्री ने सदन में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि कुल मिलाकर 24 हजार 368 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश इन चार सालों के अन्दर इस प्रदेश में आ चुका है। सरकार ने वादा किया था 12 लाख 51 हजार करोड़ रुपये के निवेश का और वास्तविक निवेश हुआ 24 हजार 368 करोड़ रुपये का और अधिष्ठाता महोदय स्वाभाविक है आप चाहे तिनके भी कान्क्लेव कर लें, उद्योगपतियों को कितनी भी मीटिंग में बुला लें अगर सदनों में यह कहेंगे कि उद्योगपति बिजली चोर होते हैं, अगर सदनों में आप कहेंगे कि व्यापारी टेढ़ीमार होते हैं और सदनों में आप उस सारे वर्ग को जो इस प्रदेश के विकास की नींव रख सकता है उसको गालियों से सुशोभित करेंगे तो आपके कान्क्लेव के माध्यम से आपके प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं आने वाला। अध्यक्ष महोदय, जब 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना सरकार ने तय की तो कुछ मानीटरेबिल गोल तय किये, कुछ लक्ष्य तय किये आज यह समय आ गया है कि हम इस सरकार से पूछे कि जिन लक्ष्यों को तुमने खुद बताया था उन लक्ष्यों को पाने में तुम कहां तक सफल हुए जैसे इस सरकार ने वादा किया था कि हम एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और अधिष्ठाता महोदय जब आप यहां थे तो आपने स्वयं माननीय मंत्री जी के बयान को सुना होगा सरकार ने आज ही इस सदन में स्वीकार किया है कि हम कुल 15 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार दे पाये हैं। कहां घोषणा पत्र की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं वादा किया था एक करोड़ का और रोजगार दिया सिर्फ 15 लाख लोगों को। सरकार ने वादा किया था कि उसी के क्षेत्र में 05 प्रतिशत दर की कृषि वृद्धि होगी अधिष्ठाता महोदय सरकार ने स्वयं अपने साहित्य में इस बात को स्वीकार किया है कि कृषि की विकास दर हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2.3 प्रतिशत हुई है। सरकार ने यह वादा किया था कि हम प्रदेश के सारे मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ देंगे। हम सभी यहां बैठे है हम सभी जानते हैं कितने हमारे ऐसे जनपद हैं जिन्हे फोर लेन से जोड़ा

गया। सरकार ने यह वादा किया था कि हम अपने श्रोतो से 250 से लेकर 500 की आबादी के समस्त गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे। सरकार ने यह वादा किया था कि प्लान्ट लोड फैक्टर हम 57 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर देंगे और 80 एम0सी0 लास जो बिजली का नुकसान होता है वह हम 33.42 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देंगे। अधिष्ठाता महोदय मैं समाप्त करने की ओर आ रहा हूं। अतिरिक्त उत्पादन सरकार का यह कहना था कि 16 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ा देंगे और कल सरकार ने यह स्वीकार किया है कि जब यह सरकार सत्ता मे आई थी तो 4209 मेगावाट बिजली का उत्पादन था और आज यह घटकर 3356 मेगावाट हो चुका है। सरकार ने यह वादा किया था कि सारे शहरी निकायों को हम सुरक्षित पाइप लाइन से पीने का पानी दे देंगे आप भी शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, हम सभी हैं हम इस तथ्य को जानते हैं कि शायद एक भी नगर को हम सुरक्षित पीने का पानी नहीं दे पाये हैं। सरकार ने यह वादा किया था कि हम सारे नगरों में सालिड वेस्ट और सीवरेज की व्यवस्था कर देंगे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पूरा प्रदेश इस बात का इन्तजार कर रहा है कि यह सरकार किसी एक नगर में एक सफल सालिड वेस्ट और सीवरेज की व्यवस्था चलाकर दिखाये। अधिष्ठाता महोदय मैं उन आकड़ों को जरूर रख देना चाहूंगा जो सरकार के सीधे–सीधे वादा खिलाफी से सम्बन्धित हैं। सरकार ने वायदा किया था कि हम इनफैन्ट मोर्टिलिटी 61 से घटाकर 32 कर देंगे आज यह 50 है इनफैन्ट मैटरनल मौर्टिलिटी हम 359 से घटाकर 200 कर देंगे आज यह 285 है, कुपोषण की दर 47 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत कर देंगे आज यह 47 से बढ़कर 48 है। औरतों में खून की कमीं सरकार का यह वायदा था कि 51.6 प्रतिशत से घटाकर इसे 20 प्रतिशत कर देंगे आज यह बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है। सरकार का यह वायदा था कि हम टोटल फर्टिलिटी को 3.8 प्रतिशत से घटाकर 2.8 प्रतिशत कर देंगे और आज भी अध्यक्ष महोदय यह 3.1 प्रतिशत है। साक्षरता का वायदा 85 प्रतिशत का किया गया था आज हम पूरे देश में साक्षरता में बिहार के बाद सबसे पीछे खड़े हुए हैं। हमने यूनिवर्सल इनरोलमेन्ट रेशियो की बात की थी हमने जेन्डर गैप को घटाने की बात की थी, हमने ड्राप आउट रेट को समाप्त करने की बात की थी, एक बहुत बड़ा अध्ययन प्लानिंग कमीशन के बहुत माननीय सदस्य है प्रफुल्ल भंडारी उनके द्वारा आया है, हेल्थ इंडेक्स रेशियो, एजूकेशन इंडेक्स रेशियो और इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स रेशियो, कई प्रान्तों का यह अध्ययन है उत्तर प्रदेश 21 में नीचे से इक्कीसवें स्थान पर है हेल्थ के मामले में, एजूकेशन के मामले में कई प्रान्तों में हमारा नीचे से इक्कीसवां स्थान है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं इसे स्वीकार करता हूं हम लोगों ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। एक्सप्रेस–वे और न जाने कितनी बाते होती हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमारा स्थान आठवां है लेकिन शर्म की बात क्या है अध्यक्ष महोदय, आज की सच्चाई है उड़ीसा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो जो बीमारू प्रदेश कहे जाते थे आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही आपने जो समय दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री संजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2016–17 के बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो मौजूदा हालात हैं प्रदेश के वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। जिस समय सरकार 2012 में बनी थी तो नौजवानों को बहुत बड़ी उम्मीद और अपेक्षा थी इस सरकार से कि सरकार नौजवानों को रोजगार देगी, शिक्षा के साधन मुहैया करायेगी मगर आज हालात यह है कि बच्चों को शिक्षा अगर ग्रहण करनी पड़ती है तो उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अगर नौकरी की जरूरत पड़ती है तो उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार का साधन नहीं है। वह नौकरी के लिए और प्रदेश में चाहे कर्नाटक जाये, आंध्रा, तमिलनाडू जाये, केरल जाये या मुम्बई जाये तो यह पलायन हो रहा है। जहां तक किसानों का सवाल है किसानों को बहुत अपेक्षायें थी, किसानों को बहुत उम्मीदें थी एक ऐसी सरकार है जो किसानों की हितैषी कही जाने वाली सरकार है किसानों के लिए गन्ने के मूल्य में बहुत बढ़ोत्तरी होगी। गन्ने का मूल्य कम से कम साढ़े तीन सौ चार सौ से कम नहीं होगा । मगर हालात यह है कि पहले से और कम हो गया है और उसके भुगतान में भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है किसान बहुत ज्यादा बुरे हालात में है। उसके हालात यह है कि उसको बिजली मिल नहीं रही है बिजली के लिए बहुत लम्बी–लम्बी बाते करी गयी थी अपने घोषणा–पत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाते करी थीं बहुत ज्यादा 24 घण्टे और 22 घण्टे बिजली देने की बात कही गयी थी मगर आज हालात यह है किसान को 6 घण्टे– 8 घण्टे बिजली मुश्किल से मिल पा रही है किसान बहुत परेशान है। किसान को अगर बिजली सही नहीं मिली तो किसान ही अन्नदाता होता है अगर अन्नदाता ही खुश नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा । इसमें कहीं कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया 4 साल पूरे हो गये। इस सरकार से लोगो को बहुत अपेक्षायें थीं कि यह बहुत अच्छे स्तर पर जायेगी लेकिन उत्तर प्रदेश और प्रदेशों के मामले में आज भी पीछे के पायदान पर है। एक उम्मीद की किरण जगी थी कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा लेकिन आज हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों के मामले में प्रयास जरूर किया गया है कोशिश करी है शिवपाल जी ने सड़कों पर पैसा दिया, मगर हालात यह है कि अगर सड़क पर पैसा चला गया है तो नीचे लेबिल पर जो अधिकारी लोग हैं उनके टेण्डर नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे यहॉ एक साल हो गया है रामपुर में एक बिलासपुर औहिरौसी मार्ग है उस पर पैसा आवंटित हो गया था अब से एक वर्ष पहले 17 मार्च, 2015 को, आज एक वर्ष हो गया है लगभग 10 बार उस पर टेण्डर लगा दिये गये अधिकारियों द्वारा खानापूरी की जा रही है मगर आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर सरकार जागरूक होती, सरकार की कोशिश होती, तो चूंकि यह मुख्य मार्ग है और बरेली को जोड़ने वाला मार्ग है, उसमें अगर टेण्डर के जरिये काम नहीं हो पा रहा था, तो डिपार्टमेण्ट के जरिये काम किया जा सकता था। मैं समझता हूं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सरकार की सोच में कहीं न कहीं कमी है। हमारे यहां इसी प्रकार की एक दूसरी सड़क भी है बिलासपुर मिलक स्वार इसमें धन आवंटित हो चुका है और इसमें लगभग सात महीने हो गये हैं, लेकिन आज तक उसमें भी कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है, आज तक टेण्डर नहीं हो पा रहा है। हालात यह हैं कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार उसे मिल नहीं पा रहा है। शिक्षा का हाल यह है कि अगर डिग्री कालेज खुल रहे हैं, तो डिग्री कालेज में अध्यापकों की कमी है, अगर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं तो उसमें टीचर्स मौजूद नहीं हैं। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में टीचर्स की कमी है। जब तक शिक्षा सर्वसुलभ नहीं होगी और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में उचित कार्यवाही नहीं होगी, तब तक हमारा प्रदेश कैसे तरक्की कर पायेगा। ऐसी दशा में कैसे हम उत्तम प्रदेश की बात कर सकते हैं, कैसे हमारा नौजवान आगे बढ़ सकेगा, यह सोचने का विषय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा उद्देश्य मात्र किसी पर कटाक्ष करने का नहीं है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मगर यह बात चिंतनीय है और हमें सोचना पड़ेगा कि हमें नौजवानों को कैसे रोजगार देना है। नौजवानों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी। शिक्षा का हाल यह है कि अगर प्राइमरी में कहीं टीचर एक है तो जूनियर में बिल्कुल मामला साफ है। डिग्री कालेज में अगर कहीं पर दस टीचर की आवश्यकता है तो उसके अगेन्स में एक टीचर है। इस प्रकार जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। मान्यवर, जमीन उतनी ही है और आबादी बराबर बढ़ती चली जा रही है। अगर किसी परिवार के पास पहले दस बीघे जमीन थी, तो आज उसके पास पांच बीघे जमीन रह गई है, कल को उसके पास चार बीघे जमीन रह जायेगी, आज तेजी से आबादी बढ़ रही है। अगर किसी परिवार में चार बच्चे हैं, चारों ने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो फिर दो लोग नौकरी में चले जायेंगे और दो लोग खेती का काम देख सकते हैं, लेकिन अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, नौजवानों को काम नहीं मिला, तो यकीनन गृह क्लेश की स्थिति आयेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। जहां तक स्वास्थ्य का हाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उपलब्धियां होनी चाहिये थी, उसमें कहीं न कही कोई कमी है। हालत यह है कि मेरे यहां केमरी टाऊन एरिया है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 90 प्रतिशत है, वहां पर पिछले दस सालों से सी0एच0सी0 की मांग चली आ रही है, वहां पर रोज मत्यु होती है, मगर आज तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया है। यह बहुत सोचने की बात है कि सरकार जो वायदे करे उसे पूरा भी किया जाना चाहिये। हमारे परिवहन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, मेरे क्षेत्र बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डे की बात करी, यह उत्तराखण्ड के बार्डर पर है, पर आज तक वहां पर रोडवेज बस अड्डा नहीं बन पाया है। पिछले छह साल से इस संबंध में आश्वासन समिति में आश्वासन भी लम्बित है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा कहना है कि सरकार जो कहे उस पर अमल किया जाना चाहिये। सरकार अगर नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है, तो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिये, सरकार अगर नौजवानों को शिक्षा देने की बात करती है, तो नौजवानों को शिक्षा मिलनी चाहिये। अगर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर

हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकेगा। अगर हमें अपने प्रदेश को बढ़ाना है तो फिर हमें पार्टियों के बंधन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभाये, यह न सोचे कि यह विपक्ष के विधायक हैं और यह सत्तापक्ष के विधायक हैं। जो लोग चुनकर आये हैं, वह सभी सरकार के ही होते हैं। जनता के हित के काम हम लोग भी लाते हैं, जो इधर बैठे लोग हैं, जनता के हित के काम वह लोग भी लाते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ जाते हैं, तो उस समय यह सोचना चाहिये कि जनता के अगर हित का काम है, तो उसे पूरा किया जाना चाहिये। आज हालात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जनेश्वर मिश्र योजना में सभी विधायकों की भागीदारी ली जायेगी। आज तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। लोहिया गांव के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लोहिया गांव में सभी विधायकों से प्रस्ताव लिये जायेंगे, लेकिन मुझसे तो एक भी प्रस्ताव नहीं लिया गया। हो सकता है कि किसी और विधायक से लिया गया हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता। नलों की बात आई थी। आज हालात यह है कि आबादी बढ़ रही है। मैं गांव का रहने वाला हूं आज गांवों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। आज गांव का रहने वाला कोई भी आदमी छोटे नलों से पानी नहीं पीना चाहता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना है कि जो बातें इन्होंने कही है, जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहीं हैं, वह बातें धरातल पर आनी चाहिये तभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ।

श्रीमती रजनी तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आय–व्ययक की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैंने बजट को देखा, उसको समझा। बजट आम जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि चुनावी एजेण्डा नजर आया। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रलोभन का पिटारा नजर आया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस तरीके से चुनावी वायदे करके जनता को प्रलोभन देकर वोट लेने का जाल बुना जाता है। यह लोकतंत्र के बिल्कुल हित में नहीं है। मान्यवर, अभी पंचायत स्तर के चुनावों में यह देखने को मिला यदि इसी तरीके से प्रलोभन की राजनीति होती रही और जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की नीति, जिस तरीके की रीति सरकार की है, मान्यवर, वह दिन दूर नहीं, कि लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ में चला जायेगा। मान्यवर, बजट जनहित में होना चाहिये, देशहित में होना चाहिये, लोकतंत्र के हित में होना चाहिये न कि वोट के हित में। माननीय अधिष्ठाता जी, यह सरकार का पांचवा बजट है जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उसके पहले इतने वायदे कर दिये गये थे उसके पहले इतनी घोषणायें कर दी गयी थीं कि जब 2012 में बजट आया तो सरकार की समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी योजनायें चलाई जायें, कौन सी योजनायें बंद की जायें और किस तरीके से वायदे पूरे करके जनता का मुंह बंद किया जाय। मान्यवर, जब दूसरा वर्ष आया तो चुनावी वायदे मुंह बाये खड़े थे इसलिये सरकार ने योजनाओं को उलझाना शुरू कर दिया कि जनता का दिमाग भटक

जाये। जब तीसरा वर्ष आया तो कोर्ट–कचेहरी शुरू हो गया सरकार भी चलती रही और चौथै वर्ष में मान्यवर, पंचायत स्तर के चुनाव हो गये, सरकार भी चलती रही और अब यह पॉचवा वर्ष है। सरकार कह रही है कि यह किसान वर्ष है। मान्यवर, किसान वर्ष के रूप में सरकार इसे मनाये। हम सबको भी खुशी होती कि किसानों की बात रखी जाय, हम सब खुश होंगे मान्यवर, लेकिन 2016 में ही किसान वर्ष क्यों ? 2012, 13, 14, 15 में किसान वर्ष क्यों नहीं मनाया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार किसानों की राजनीति नहीं कर रही, किसानों के लिये राजनीति नहीं कर रही, अन्नदाता के लिये राजनीति नहीं कर रही, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार अन्नदाता पर ही राजनीति कर रही है, किसानों पर ही राजनीति करने लग गयी है मान्यवर।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारा मूल परिवेश ग्रामीण है हमारे प्रदेश की आम जनता, जो कि कुल आबादी की 60 प्रतिशत है, आज वह गांवों से शहरों में पलायन कर रही है। अगर देखा जाय तो कृषि क्षेत्रों में ही रोजगार के इतने साधन हैं यदि उनको प्रभावी बनाया जाय तो आज कृषक रोजगार के लिये शहरों में नहीं जायेगा। लेकिन किसानों के प्रति यदि सोच ही नहीं होगी तो क्या किया जाय इसलिये हमारा प्रदेश का किसान बहुत परेशान है और सरकार कह रही है कि यह किसान वर्ष है। मान्यवर, यह किसान वर्ष नहीं, सच्चाई तो यह है कि सरकार यह प्रलोभन वर्ष मना रही है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तीन लाख छियालिस हजार करोड़ में मेरी विधान सभा क्षेत्र की जनता का भी अधिकार बनता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा, गर्रा, गंगा आदि नदियां हैं। बरसात के दिनों में पानी बरसे या न बरसे, उससे हमारे यहां बाढ़ नहीं आती है लेकिन जब पहाड़ी इलाके पर जलस्तर बढ़ जाता है, बांधों से पानी छोड़ा जाता है, तब मेरी विधान सभा में लगभग प्रतिवर्ष इन नदियों के किनारे बसे गांवों में कटान हो जाता है मान्यवर, इसका स्थायी समाधान होने की आवश्यकता है और बिल्कुल इसके ठीक विपरीत जो हमारा ऊंचाई का क्षेत्र है वहां पर सिंचाई के साधन निष्क्रिय होने के कारण लगभग हजारों एकड़ भूमि बंजर होने की कगार पर है इसका मुख्य कारण सिंचाई के साधनों का निष्क्रिय होना है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दो माइनर हैं। रूपापुर और बरबन, मान्यवर, वहां पर न जाने कब से पानी नहीं आया, इसका मुख्य कारण हमने पता किया तो पता चला कि वहां पर शाहजहांपुर डिवीजन है मण्डल कर दिया है सीतापुर जबकि शाहजहांपुर डिवीजन में सीतापुर मण्डल नहीं आता अगर उसको बरेली मण्डल कर दिया जाए तो हो सकता है कि वहां पर पानी आ जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को पांचवां वर्ष होने जा रहा है लेकिन जब 2012 में सरकार आई थी उस समय हमको 85 हैण्डपम्प दिये गये थे तब से इतना समय हो गया मेरी विधान सभा में एक भी इंडिया मार्का हैण्डपम्प नहीं दिया गया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, शुद्ध पेयजल हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्पों की बहुत आवश्यकता है और जो हैण्डपम्प खराब पड़े हैं उनके रि–बोर की भी बहुत आवश्यकता है। मेरी विधान सभा में एक मात्र मंडीस्थल पॉली पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा के साथ–साथ शाहजहांपुर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी अति आलू उत्पादक क्षेत्र हैं लेकिन मार्केटिंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को भारी

समस्या का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मेरे यहां सड़कों की भारी दुर्दशा है इसके लिए मैंने कई बार कार्य–सूची में दिया लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैंने देखा मॉडल प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का बजट काफी कम है, प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की काफी कमी है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार यह तो लिख रही है कि यह आधी आबादी है परन्तु इसके सापेक्ष बजट में महिलाओं को उपेक्षित ही रखा गया है जिसका मुझे बहुत खेद है। सरकार कहती है कि बिजली की विश्वस्तरीय अवस्थापना करायेंगे लेकिन सरकार की व्यवस्था यह है कि जिन गांवों के किनारे से या जिन गांवों के बीच से बिजली की लाइन निकली हुई है उन्हें वह कनेक्शन नहीं देंगे और जो गॉव पहले से विद्युतीकृत हैं वहां पर बिजली की अभी तक सप्लाई नहीं है इसलिए मान्यवर, इसमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है अन्यथा जो सरकार कह रही है कि विश्वस्तरीय अवस्थापना करायेंगे यह हकीकत में नहीं हो पायेगी केवल यह कागजी किताबों में ही रह जायेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज के समय में परिवहन और पर्यावरण दोनों को एकसाथ देखने की आवश्यकता है, जितना सार्वजनिक परिवहन का उपभोग बढ़ेगा उतना ही पर्यावरण पर प्रदूषण का दबाव घटेगा। 80 से 90 प्रतिशत ग्रामीण जनता परिवहन हेतु सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा युक्त बसों का संचालन किया जाए इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। मान्यवर, केन्द्र सरकार कह रही है कि स्मार्ट सिटी योजना बनायेंगे लेकिन मैंने देखा कि उसमें मेरे प्रदेश का एक भी शहर नहीं है क्या प्रदेश की सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है जैसे कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टाउन, स्मार्ट विलेज। मान्यवर, देश की सरकार का तो क्या कहना उसने पहले भी कहा था कि हमारे सांसद एक–एक गांव गोद लेंगे लेकिन आज अगर देखा जाए तो वह गांव रो रहे हैं वहां पर सांसद देखने नहीं जाते। हमें तो कहना पड़ रहा है कि देश में बैठी जो बी0जे0पी0 की सरकार है वह हवाई–तवाई बातें करने में प्रदेश की सरकार से भी कई गुना आगे है और इन्हीं सरकारों की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की जनता आज बहुत परेशान हो रही है और वह कह रही है कि धन्य हैं बहन मायावती जी जिनकी योजनाएं इतनी सराहनीय थीं जिनकी कानून–व्यवस्था की आज जनता मिसाल दे रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपको बहुत–बहुत धन्यवाद्।

श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय –

मा0 अधिष्ठाता जी, हमने नेता विरोधी दल से ले करके नेता भाजपा तक के भाषणों को सुना है। जो आदमी काम नहीं करना चाहता है जिन सरकारों ने काम नहीं किया था वह अपना ठीकरा हमारी सरकार पर फोड़ रहे हैं। हमारी सरकार के चलते किसानों को जितना फायदा हुआ, एक–एक किसान जिसने गेहूं बीज का अनुदान पाया उनके खातों में हजारों–हजार रूपया गया है। हमारा किसान जिन्होंने ट्रैक्टर लिया, हमारे किसानों ने जिन्होंने बीज के नाम पर जो अपना काम किया है वो पता नहीं चलता है। प्रतिपक्ष के लोग जानते सब हैं लेकिन कहना नहीं चाहते कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार का अच्छा काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे जो 250 की जनसंख्या की आबादी के गांव थे उन सबका विद्युतीकरण हो गया है। हमारे यहां

एक–एक विधान सभा में बीस–बीस पेयजल योजनायें स्थापित हो गयीं। हमारे टाउनएरिया भारतगंज में दो पेयजल योजना स्थापित हो गयी, हमारी सिरसा टाउनएरिया में पेयजल योजना और सीवर लाइन का काम चालू होने जा रहा है। यह आपको दिखायी नहीं देता। आपके विधान सभा क्षेत्र में जो काम हो रहा है आप उसको बताना नहीं चाहते। आप बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। आपकी सरकार ने क्या किया था ? पैसा लेकरके टिकट दिया था, यही काम था क्या ? पार्क बनवाया, यही काम था क्या ? पहले अगर काम हुआ होता तो आज लोहिया आवास के नाम पर इतना बढ़िया काम न होता। आज लोहिया आवास में साढ़े तीन लाख रुपया जिन गरीबों को मिल रहा है, उनका चेहरा आप देखिये, उनका घर देखिये। बेटी के विवाह के लिए भी धन मिल रहा है, वजीफा के नाम पर उनको मद्द मिल रही है, उसको आप देखिये, उसको आप देखना नहीं चाहते। आप देखना चाहते हैं तो हमारी सरकार की बुराईयां। हमारी सरकार की अच्छाइयां आपको नजर नहीं आती। एक्सप्रेस–वे बन रहा है उसको आप देखना नहीं चाहते, हमारे यहॉ मेट्रो चलने जा रही है, उसको आप देखना नहीं चाहते। आप देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से दंगे हों, उत्तर प्रदेश में किस तरह से हाथी मदमस्त होकर के घूमे और गन्ना खा–खाकर उसका खात्मा कर दे। मित्रों, मैं इन सवालों पर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा क्षेत्र में तमाम काम हुए हैं एक पुल बन रहा है उस पुल का खर्चा 17.5 करोड़ रुपया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 5 साल से खुदी पड़ी हुई है, आज तक उस पर एक रोड़ा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना विफल हो रही है, आने–जाने का रास्ता अवरुद्ध है। हमारे यहां एन0एच0 है उसकी मरम्मत का कोई काम भारतीय जनता पार्टी की राज में नहीं हो रहा है। जब हमारी सरकार काम करना चाहती है तो आप कहते हैं कि हमने बहुत बजट दे दिया अगर आपने बजट दिया होता तो काम होता क्यों नहीं ? प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत सड़क बनती क्यों नहीं? हमारे तमाम कामों को रोकने का काम आप लोगों ने किया। जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना चल रही थी अब आपने उसको बदलकर दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया, पर कामकाज कुछ हो नहीं पा रहा है। आप टेण्डर में पूरे प्रदेश को फंसाये हुए हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकारें काम करें उसकी अच्छाइयों को भी आप लोगों को बताना चाहिए। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां गंगा जी हैं, हमारे यहां बगल में तीन–तीन पॉवर–प्लाण्ट लग रहे हैं मेजा, करछना और बारा पॉवर प्लाण्ट। (ब0स0पा0 की तरफ से आवाज आयी कि यह हमारी स्कीम थी।) स्कीम आपकी हो, मैं यह नहीं जानता हूं। आप हमारे मित्र हैं, इलाहाबाद में रहे हैं, स्कीम्स से आपको फायदा होगा। आप असत्य भाषण न करिये मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने बजट में उसको डाला था, आपको इसका पता करवाना हो तो कागज निकलवाकर देख लीजिए, असत्यता की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोड़हार पेयजल योजना, धनावल पेयजल योजना जो पुरानी है, भारत सरकार में हमारी

स्कीमें पड़ी हुई हैं आज तक उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां गंगा जी का कटान हो रहा है, रेलवे स्टेशन बगल में है, अगर वह कटान नहीं रूकेगा तो कुछ दिन में हमारे ऊंचडीह रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां इण्डिस्ट्रयल बेल्ट में सरस्वती हाईटेक सिटी बनने जा रही है, उसके स्थान पर हमारे विधान सभा क्षेत्र मेजा में ऊँचडीह पर सरस्वती हाईटेक सिटी के स्थान पर जो इण्डिस्ट्रयल एरिया है वहॉ शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारी विधान सभा का विकास हो जायेगा। यह इलाहाबाद के नजदीक भी है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भारतगज टाउन एरिया में कन्या डिग्री कालेज नहीं है। अगर एक कन्या डिग्री कालेज की स्थापना हो जाती तो हमारे विधान सभा में भारतगंज, जो पहाड़ पर है उसकी भी शोभा बढ़ जायेगी और वहाँ भी हमारी बहू बेटियॉ पढ़ सकेंगीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा मिर्जापुर से सटी हुई है। हमारी विधान सभा कोरावां में, रीवा से सटी हुई है, चित्रकूट, बांदा से सटी हुई है। हमारे विधान सभा में बुन्देलखण्ड की सुविधा नहीं है। जबकि हमारी विधान सभा में जितनी व्यवस्थाएं हैं सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत, बुन्देलखण्ड का दर्जा हमारी विधान सभा में मेजा, कोरावं और बारा को मिला हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बुन्देलखंड को सुविधा मिली हुई है उसी तरह इलाहाबाद के जमुनापार को भी बुन्देलखंड की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का फायदा हो सके। हमारे यहां चेक डैम बन रहे हैं, हमारे यहां ब्लास्टिंग कूप बन रहे हैं इसलिये हम बांदा से, चित्रकूट से, रीवां से सटे हुए हैं। हमारी विधान सभा को भी बुन्देलखंड का दर्जा दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सलिल विश्नोई—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2016—17 के बजट अनुमानों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्यों से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, किसी भी सरकार का बजट उसकी साल भर की उपलब्धियों और योजनाओं का लेखा जोखा होता है जो प्रदेश की जनता को उसके सुनहरे भविष्य की तसल्ली देता है, उसको सपने दिखाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे प्रदेश के नौजवानों, महिलाओं और बेरोजगारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद हो सके। माननीय अधिष्ठाता जी, इस प्रदेश के नौजवानों ने सबसे ज्यादा युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी के नेतृत्व में विश्वास करके उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी लेकिन आज वही नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्योंकि आज जिस प्रकार की सरकार की नीतियां चल रही हैं जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उससे लगता है कि सिर्फ एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी सब उदास और निराश हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तक पिछले बजट का 25 परसेन्ट से लेकर 40 परसेन्ट पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारे बजट का जो बचा हुआ

पैसा है वह सिर्फ मार्च के महीने में किस कारण से खर्च किया जाता है इससे कोई अन्जान नहीं है। उस सारे पैसे का दरूपयोग होता है। उस सारे पैसे का सदुपयोग हो और उसको बकाया राशि मान करके उस नये बजट में जोड़ दिया जाय ऐसा कुछ प्राविधान किया जाय। मान्यवर, किसी भी प्रदेश की सम्पन्नता और प्रगति का पैमाना उस प्रदेश का व्यापार और उद्योग होता है। उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों को स्थापित करने का कोई माहौल ही नहीं बन पा रहा। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से न तो आधारभूत सुविधाएं हैं, न बिजली है, न सड़कें हैं, न पानी है और न ही चुस्त दुरूस्त कानून व्यवस्था है, इस कारण से बाहर के उद्योगपति डर के कारण उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। सिर्फ निवेशक सम्मेलनों और बड़े बड़े भारी विज्ञापनों से किसी भी प्रदेश का औद्योगिक वातावरण नहीं बन सकता, कोई निवेश नहीं हो सकता है। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की जो संस्थाएं है चाहे वह यू0पी0एस0आई0डी0सी0 हो, यू0पी0एफ0सी0 हो, चाहे पिकप हो, यह सबके सब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में इतना भारी भ्रष्टाचार है कि उसके कारण उद्यमियों को कोई सहायता तो मिलती नहीं है उल्टे उनके खिलाफ इन लोगों की कार्यवाही इस प्रदेश की उद्योग विरोधी हो रही है। इन संस्थानों में एक नहीं कई यादव सिंह बैठे हैं जिनकी जांच की जरूरत है और उत्तर प्रदेश के औदयोगिक वातावरण को इनके पंजों से मुक्त कराने की जरूरत है। आज यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की लीज की जो कन्डीशन होती है, भू आवंटन की जो प्रक्रिया होती है, दोनों सिस्टम बहुत डिफेक्टिव हैं। इस कारण से ही प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी चल रही है। वो इन्हीं कारणों से, इन्हीं नीतियों के कारण से पहले चरण में ही अपना दम तोड़ चुकी है। इसलिए इन संस्थानों का चाहे यू0पी0एस0आई0डी0सी0 हो, चाहे यू0पी0एफ0सी0 हो चाहे पिकअप हो इनकी कार्यप्रणाली को बदला जाए, और प्रदेश के उद्योगों को एक अच्छा वातावरण दिलाया जाए। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एरिया में जो इन्ड्रस्ट्री चल रही हैं पिछले दस सालों से, जिनके इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रिटर्न बराबर जा रहे हैं जिनमें प्रोडक्शन बराबर हो रहा है उनकी जमीनों को फ्री–होल्ड किया जाए। अधिष्ठाता जी, जब देश में और प्रदेश में एक समान कर प्रणाली वाली जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने वाली हो तो उत्तर प्रदेश में समानान्तर मंडी शुल्क की व्यवस्था को भी समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर एक सूत्रीय जी0एस0टी0 प्रणाली लाना चाहते हैं तो फिर अलग–अलग करों को लगाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो और इन्सपेक्टर राज को समाप्त किया जाए और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और उद्यमियों को भी किसानों, वकीलों और कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा और पेंशन आदि की योजनाओं को भी लागू किया जाए। जिससे प्रदेश में उद्योग लगाने के वातावरण को एक अच्छा माहौल मिल सके।माननीय अधिष्ठाता जी, कानपुर इस प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है और सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है जब तक कानपुर प्रगति नहीं करेगा, इस प्रदेश की सम्पन्नता का सपना अधूरा

ही रहेगा।पहले कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इण्डिया कहा जाता था।लेकिन लगातार कानपुर की उपेक्षा होने के कारण आज कानपुर का औद्योगिक स्वरूप निरन्तर गिरता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि कानपुर में सिर्फ उद्योग ही हैं, कानपुर में और भी असीम सम्भावनायें हैं कानपुर असीम सम्भावनाओं वाला शहर है। कानपुर आज रक्षा सामग्री के उत्पादन का सबसे बड़ा केन्द्र है। हौजरी का बहुत बड़ा केन्द्र है। सब्जी मसाला,पान मसाला और चमड़ा उत्पादन का बहुत बड़ा केन्द्र है। पड़ोस में सुगन्ध की जो नगरी है कन्नौज है सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला फर्रुखाबाद है, अगर कानपुर को सही ढंग से विकसित किया जाए तो कानपुर फिर से अपना पुराना गौरव प्राप्त कर सकता है। मान्यवर, कानपुर के पड़ोस में या कानपुर के अन्दर ही रामायण सक्रिट का जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है बिठूर, वह पर्यटन स्थली के रूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना कानपुर के साथ विडम्बना यह है कि इतना बड़ा औद्योगिक केन्द्र होने के बाद भी, हिदुस्तान के एयर मैप पर नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि कानपुर नगर जब एयर मैप पर आएगा तो बाहर से विदेशों से आने–जाने वाला व्यापारी कानपुर आने जाने में अपनी सहूलियत महसूस कर सकेगा और बिठूर जैसा पर्यटन स्थल भी विकसित हो जावेगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सलिल विश्नोई–

माननीय अधिष्ठाता जी, इतनी ज्यादती न करो अपनों के साथ।अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुए हैं। कानपुर एजूकेशन हब के रूप में विकसित हो सकता है कानपुर में आई0आई0टी0 है कानपुर में सी0एस0ए0 है कानपुर में एच0बी0टी0आई0 है कानपुर में मेडिकल कालेज है विकलांग यूनिवर्सिटी है और कानपुर में दो दर्जन से अधिक इंजीनियरिंग कालेज हैं। कानपुर देश में कोटा के बाद सबसे बड़ी कोचिंग मंडी है जहां पचास हजार से ज्यादा बाहर के बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी अगर कानपुर को एजूकेशन हब के रूप में विकसित किया जाए तो कानपुर का फिर से पुराना स्वरूप बहाल हो सकता है। कानपुर में इंजीनियरिंग कालेजों की अधिकता होने के कारण अगर कानपुर को हम पूणे और बंगलौर की तरह एक साइबर सिटी की तरह डेवलप करें तो रोजगार के नये–नये अवसर प्राप्त होंगे। कानपुर में घाटमपुर और बिल्हौर दो जगह पर केन्द्र सरकार की ओर से नये पावर हाउस स्वीकृत पड़े हुए हैं।लेकिन उन पावर हाउसों को लगाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कोई सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा है। पनकी की यूनिटें बन्द पड़ी हुई हैं। गंगा के किनारे रिवर्स साइट पावर हाउस बन्द पड़ा हुआ है या तो पनकी की बन्द यूनिटों को चलाया जाए अथवा नया प्लान्ट लगाया जावे और रिवर्स साइट पावर हाउस जो गंगा के किनारे हैं उसमें सोलर इनर्जी के विंड प्लान्ट को लगाया जाए तो कानपुर और आसपास की जो बिजली की कमी की समस्या है वह दूर हो सकती है। कानपुर में आज की तारीख में ट्रैफिक जाम गन्दगी और प्रदूषण की पहचान बनता चला जा रहा है इसलिए कानपुर महानगर पर

बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।ए टू जेड नाम की संस्था जो वहां पर काम करती थी वह पूरी तरह से फ्लाप हो गई है बन्द हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष प्रयास करके कानपुर के कूड़े को उठाने की और कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था करनी चाहिए। अतिक्रमण हटाकर कानपुर की सड़कों को व्यवस्थित किया जाय कानपुर पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिष्ठाता महोदय जब कानपुर तरक्की करेगा तभी इस उत्तर प्रदेश की तरक्की का रास्ता बनेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट प्रस्तावों पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

'श्रीमती इन्द्राणी देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमारा क्षेत्र नेपाल सीमा से श्रावस्ती क्षेत्र विधान सभा भिनगा का क्षेत्र है वहां से हम पहली बार विधान सभा में चुनकर आए हैं। जब से विधान सभा शुरू हुई हमारे युवा मुख्य मंत्री समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने बजट पेश किया तो मैं बजट के दिन जब आवास और क्षेत्र में गई तो इस बजट की सराहना हमारा किसान भाई हमारा व्यापारी भाई नौजवान भाई और हमारी बहनें बच्चियां वित्त विहीन शिक्षक इतनी बधाइयां देने के लिए हमारे घर पर एकत्रित हुए कि मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी को अपने किसान परिवारों की ओर से बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। विपक्ष की तरफ से बहुत बातें आईं लेकिन अधिष्ठाता महोदय मैं बताना चाहती हूं कि मैं किसान परिवार से हूं पूर्ववर्ती बसपा सरकार थी लेकिन हमारा किसान भाई जो अपनी मेहनत से गेहूं और मसूर पैदा करता था बसपा सरकार में उसका समय से सही कीमत दिलाने का काम नहीं किया गया। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि वर्ष 2012 में आप जब से उत्तर प्रदेश की कमाल संभाले तब से हमारे किसानों को चाहे गेहूं का दाम हो अरहर का दाम हो मसूर का दाम हो आपने दिलाने का काम किया है आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है और उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता है। उत्तर प्रदेश में बहुत से वित्त विहीन शिक्षक जो मात्र एक हजार दो हजार में तीसों साल से काम कर रहे थे लेकिन युवा मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को वित्त विहीन शिक्षक बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको स्थायी रूप से मानदेय देने का ऐलान किया है। हमारा क्षेत्र भिनगा जनपद श्रावस्ती है वर्ष 2014 में भाजपा ने 75 लोक सभा सीटें जीतीं और दिल्ली में सरकार बनाई लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लोक सभा के जो एम0पी हैं जो बी0जे0पी0 के हैं एम0पी0 पार्लियामेंट का क्षेत्र दो जनपद का है और पांच विधान सभा का है लेकिन एम0पी0 साहब एक गांव को गोद लेते हैं लेकिन उसके सारे काम अधूरे पड़े हैं न उसमें कोई सड़कें बनती हैं न उसमें कोई किसानों का काम होता है न उसमें बालिकाओं का कोई काम होता है मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं माननीय अखिलेश यादव जी को कि जब से सरकार बनी है हमारे एम0एल0ए0 को अपने विधान सभा के गांवों का विकास करने

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र गांव चयन करने के लिए कार्य किया है। हमारा जनपद दो एम0एल0ए0 का क्षेत्र है वहां 10 गांव चयन करने के लिए एक साल का समय मिलता है आज पॉचवां साल है हमने 40 गांव लोहिया समग्र विकास में चयनित किया और 25 गांव जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित किया आज उन गांवों में खुशहाली और विकास चल रहा है डा0राम मनोहर लोहिया गांव में हमारी 36 परियोजनाएं हैं जिसमें हमारे समूह से लेकर गांव की सड़क हो गांव की बिजली का विकास हो गांव में शौचालय हो और 36 परियोजनाएं हैं चाहें विकलांग पेंशन हो। चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे बहनों के लिये, बुजुर्गों और वृद्धों के लिये पेंशन की योजना के बारे में हो, सभी विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा है, इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देती हूं। मा0 नेता जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने डा0 राम मनोहर लोहिया गांव चयन करने का निश्चय किया था, उस योजना को हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया है, जिसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। हमारे क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार बसपा की थी, हमारे श्रावस्ती में अंधेरपुरवा का पुल टूटा पड़ा था, सैकड़ों गांवों के लोगों का चलना मुश्किल था, लेकिन मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो अंधेरपुरवा का पुल, हमारा बलरामपुर कोड़री का पुल और हमारे विधान सभा क्षेत्र में मधवापुर का बहुत बड़ा पुल बनाने का काम किया है, जिससे आज बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बड़े आराम से चलते हैं और ऐसे गरीबों की दुआ हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी को मिलती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, पूर्ववर्ती बसपा की सरकार में हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि आप हमें तहसील दीजिये। आपने विकास के नाम पर विनाश करने का काम किया है। मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने सरकार बनते ही तहसील देने का काम किया है, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आज तहसील शुरू हो गयी है और उस तहसील के बन जाने से 80 किमी0 की दूरी आज कम होकर मात्र 15 किमी0 की दूरी भिनगा मुख्यालय से मल्हीपुर तहसील तक हो जाने से हमारी जनता को राहत मिल गयी है। हमारे क्षेत्र में अभी हाल ही में बहराइच से श्रावस्ती तक फोर लेन, भिनगा से चौधरी जी बार्डर तक टू लेन मा0 मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम किसान परिवार से हैं, हमें खेत में उपज भी करनी होती है। मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया योजना के तहत ट्यूबवेल देने का काम किया है, इसके लिये हम सभी किसान परिवारों की तरफ से मा0 शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे नगर में पानी की बड़ी दिक्कत थी, हम सदर के एम0एल0ए0 हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कत थी। बसपा की सरकार में सारी टंकिया ध्वस्त हो गयी थीं, लेकिन मैं मा0 नगर विकास मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं विशेषकर हमारे नगर वासियों ने हमसे कहा था कि विधायिका जी, आप नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद दीजियेगा। मैंने अपने क्षेत्र की समस्या से मा0 नगर विकास मंत्री जी को अवगत कराया और मा0 नगर विकास

मंत्री जी ने क्षेत्र में तीन–तीन टंकियां बनवाने का कार्य किया है। भाजपा और बसपा और अन्य पाटियों के द्वारा मैंने सुना, मैं इस सदन में अवगत कराना चाहती हूं कि जिस तरह हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने छठे बजट की बात की है तो हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी विधान सभा में छठा बजट जरूर लायेंगे। हमारे किसान परिवार, व्यापारी परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, दलित परिवार और युवा सभी खुशहाल हैं। आज बसपा के हमारे साथी विधायक कानून–व्यवस्था की बात करते हैं। आपने उस समय कानून–व्यवस्था की बात नहीं की, जब आपकी मुखिया ने कालिदास मार्ग पर बैठकर बैरियर लगाने का काम किया था। अगर मुख्य मंत्री के आवास की तरफ किसी की नजर भी पड़ जाये तो आंख निकलवाने का काम आपकी मुखिया ने किया, उस समय आपने कानून–व्यवस्था की बात नहीं की। आज चाहे लाचार हो, चाहे गरीब हो, चाहे विपक्ष का भाई हो, चाहे हमारे सत्ता पक्ष का भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, आज वह हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी से चाहे तो सड़क पर बात कर सकता है, चाहे तो आवास पर बात कर सकता है और चाहे वह विधान सभा में खड़ा होकर अपनी समस्या बता सकता है। देश के नौजवान, देश के बच्चों...

(सदस्य, श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा बीच में टोके जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जय प्रकाश जी, कोई आपत्तिजनक शब्द होगा, उसे निकलवा देंगे। आप बैठ जाइये।

श्रीमती इन्द्राणी देवी–

...देश के बुजुर्गों को मैं आह्वान करती हूं, अधिष्ठाता जी, ऐसा ईमानदार मुख्य मंत्री न हुआ है, हमारे मुख्य मंत्री फिर इस उत्तर प्रदेश की बागडोर जरूर संभालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

सुदेश शर्मा जी, आप बोलिए।

'श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने 2016–17 के इस बजट की सामान्य चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया। हमारे काफी विद्वान सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। चाहे वह इधर के सम्मानित सदस्य हों, चाहे उधर के सम्मानित सदस्य हों और यहाँ तक कि सत्ता पार्टी के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा–चढ़ा कर बजट की तारीफ की है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यह सरकार, सरकार के रूप में काम न करके केवल समाजवादी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पार्टी के रूप में काम कर रही है और केवल उन्हीं सदस्यों के यहां काम कराये जा रहे हैं और जो इधर के सदस्य हैं, वह कुछ ज्यादा ही ...

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

शान्त रहें।

श्री सुदेश शर्मा–

बोलने दीजिए, आप लोग सुनने का भी माद्दा रखिए, सरकार सुनने का भी माद्दा रखे। आप लोग कहते हैं तो सुनने का भी माद्दा रखिए। अधिष्ठाता जी, अभी समाजवादी पार्टी के एक सम्मानित सदस्य थे, वह तो अपने पूरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी लिस्ट गिनवा रहे थे कि मेरे क्षेत्र में यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के टोका–टाकी करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें, बोलने दीजिए।

श्री सुदेश शर्मा–

अधिष्ठाता जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जितना कहेंगे, मुझे और ज्यादा अच्छा ही लगेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है।

अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने घोषित किया है कि वह इस वर्ष को किसान और युवा वर्ष के रूप में मना रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं, वहीं इसी विधान सभा के अन्दर रोज किसानों को लेकर हंगामा होता है, रोज वाकआउट होता है, वेल में धरना और प्रदर्शन होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि

(इस समय 02 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शारदा प्रताप शुक्ल पीठासीन हुए)

हमारे जो आदरणीय सदस्य गुलाम मौहम्मद साहब हैं, उनके क्षेत्र के किसान काफी खुश हैं और मुझे लग रहा है कि मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र शायद उत्तर प्रदेश के अन्दर नहीं आता क्योंकि वहां का किसान हताश और परेशान है। वहां पर आज भी कई सौ करोड़ रूपया किसानों का बकाया है। एक भी पैसा, इस साल की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले साल का भी लगभग 70 करोड़ रूपया बकाया है। लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हम किसान वर्ष मना रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो बजट में प्राविधान रखा गया है तो इस बजट में यह जोड़ा जाना चाहिए था कि जो भी प्राइवेट मिल किसानों का भुगतान नहीं करेंगी, उस भुगतान को सरकार करके उन मिल मालिकों के ऊपर रिकवरी डाली जायेगी। लेकिन यह सरकार की कैसी मजबूरी है कि न तो उनको धन दे पा रही है और न ही उन मिल मालिकों को ही गिरफ्तार किया जा

रहा है, जिन्होंने किसानों का भुगतान नहीं किया। सरकार कह रही है कि फिर भी हम किसान वर्ष मना रहे हैं। अभी जो छूट मिल रही थी, उनके ट्रैक्टर पर, कल्टीवेटर पर और अन्य यन्त्रों पर, वह छूट तक समाप्त कर दी गयी, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हम किसान वर्ष मना रहे हैं, हम युवा वर्ष मना रहे हैं लेकिन हमारे मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी खेलने का स्टेडियम नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, हम यहां से लखनऊ मेल या नौचन्दी एक्सप्रेस से जब बैठ करके जाते हैं, वह गाड़ी सुबह 5.00 बजे हापुड़ पहुंचती है, हमारे और भी सम्मानित सदस्य जाते होंगे, यहां से, लेकिन जब हम उन सड़कों पर जाते हैं जो जी0टी0 रोड है, उस पर आजकल वह युवा सुबह रेस लगाते हुए और जांगिंग करते हुए मिलते हैं। क्योंकि उन्हें भर्ती के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आज तक एक स्टेडियम हमारे उस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बनाया गया है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे लेकिन सरकार बताये कि कितने युवाओं को अब तक रोजगार दिया गया। उसमें भी सरकार फेल रही। लेकिन सरकार कहती है कि हम किसान वर्ष और युवा वर्ष मना रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आम आदमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो व्यक्तियों की सूची है उसमें पटवारी अपने आप 20–30–40 नाम लिख लेता है और उसको यह भी नहीं मालूम होता है कि उसका नाम आम आदमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आता है। न उसको कोई कार्ड दिया जाता है। और यदि दुर्भाग्यवश उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके बेचारे परिवार को भी नहीं पता होता है कि उसके परिवार का जो सदस्य था वह आम आदमी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आता है। मान्यवर, पिछले वर्ष धान की फसल में किसानों को काफी नुकसान हुआ और इस वर्ष गर्मी की मार में गेहूं की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि किसानों के लिए कम से कम बोनस की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जो इस बजट में नहीं की गयी। सरकार सिंचाई को मुफ्त करने की बात कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह आंकड़े निकलवा लिये जायें कि सरकारी नलकूपों से कुल कितनी सिंचाई होती है। बहुत कम सिंचाई सरकारी नलकूपों से होती है। यदि वास्तव में सरकार किसानों की शुभचिंतक है तो उसे चाहिए कि जो किसानों के प्राइवेट नलकूप हैं उनके बिल माफ किये जाने चाहिए और हमारे यहॉ तो अनेकों ब्लाक डार्क जोन के अन्तर्गत हैं। जब डार्क जोन से उनके ब्लाक ही बाहर नहीं आ रहे हैं और न कोई सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि वह डार्क जोन से बाहर आ सकें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुदेश शर्मा–

मान्यवर, अभी दो मिनट भी नहीं हुये हैं। कम से कम 5–6 मिनट तो बोलने के लिए मिले। यह तो ज्यादती है मेरे साथ। ऐसा न कीजिए मान्यवर। तो उनको डार्क जोन से निकालने के लिए सरकार की कोई योजना होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के अंदर जाम की सबसे बड़ी समस्या है। अनेकों बार सरकार को चेताने पर भी वहां के समाधान के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। न कोई बाईपास की योजना है न ही जो एलीवेटेड पुलों की बात की गयी थी वह भी नहीं है। मोदी नगर के अन्दर मैं मांग करता हूं कि इस बजट में कन्या डिग्री कालेज एवं इण्टर कालेज की स्थापना की जानी चाहिए थी जो इस बजट में नहीं की गयी है। मोदी नगर के अंदर एक ई0एस0आई0 अस्पताल जो कि सैकड़ों बीघा में है लेकिन उसमें सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है मैं चाहूंगा कि इस बजट के अंदर उसमें कुछ आधुनिक सुविधायें और बेड बढ़ाये जायें और मोदी नगर विधान सभा के अंदर भी कम से कम एक राजकीय मेडिकल कालेज खोला जाना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि मोदी नगर में राज चौपला और हापुड़ रोड व सीकरी रोड पर आर0ओ0बी0 का शीघ्र निर्माण करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिल सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मोदी नगर में श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा श्रमिकों के लिए लगभग 40 वर्ष पूर्व मकान आवंटित किये गये थे। 40 वर्षों से वह लोग उन मकानों में रह रहे हैं। लेकिन उसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है। पिछले शासन काल में जब मा0 नेता जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उन्हीं मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा वह मकान बुक वेल्यू पर दे दिये जायेंगे तो कम से कम इस बजट में यह प्राविधान होना चाहिए था कि जितनी भी श्रम विभाग की कालोनियां हैं उन्हीं मजदूरों को वह मकान बुक वेल्यु पर मिलने चाहिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के अंदर जर्जर हो चुके तारों को बदलने का भी प्राविधान इस बजट में होना चाहिए और हमारा जो मोदी नगर शहर है वह दिल्ली से मात्र 50 किमी0 की दूरी पर है और गाजियाबाद से 20 किमी0 की दूरी पर है। तो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र वह है जो कि पहले औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहां मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आज मोदीनगर के लिए इस बजट में कोई प्राविधान वहां उद्योग स्थापित करने के लिए नहीं रखा गया है। मैं चाहूंगा और मैं मांग करता हूं कि इस बजट में मोदीनगर को दोबारा से औद्योगिक नगरी बनाने का प्राविधान इस बजट में रखा जाना चाहिए और मोदीनगर चूंकि दिल्ली के काफी नजदीक है, इसलिए जो मैट्रो गाजियाबाद तक आ रही है, मोदीनगर तक भी मैट्रो जाय तो कम से कम वह एन0सी0आर0 पूरे क्षेत्र से उसका एक जुड़ाव हो जायेगा और वहां के लोगों को भी काफी सुविधा मिल जायेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं थोड़ी सी बात शिक्षा पर भी करना चाहता हूं, जहां तक शिक्षा की बात है, तो उस पर तो सरकार का रवैया और सरकार का नजरिया बिल्कुल साफ है। हमने एक बार यहां पर इस विधान सभा के अन्दर एक सवाल लगाया था, उसमें जब मा0 रामगोविन्द चौधरी जी मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाय, तो उसमें बोलने का मौका मिला और हमने कहा था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी सरकारी अधिकारी हैं, उनके बच्चों का या वहां पर जो टीचर हैं उनके बच्चों का भी दाखिला उस स्कूल में अनिवार्य हो और उसके बाद फिर वही फैसला मा0 हाई

कोर्ट ने भी दिया चार महीने बाद और मैंने उस सवाल को डाला यहां पर तो यह कहा गया, मैंने पूछा था कि क्या सरकार मा0 हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन करायेगी, लेकिन सरकार का नजरिया साफ आया और मेरे पास जवाब आया कि नहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ मा0 सुप्रीम कोर्ट में जायेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की नीति और नीयत साफ है और सरकार चाहती है कि बेसिक शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा के स्तर में सुधार आये, ऐसा क्या कारण है कि जो प्राईवेट पब्लिक स्कूल हैं, उनमें मात्र दस–दस हजार रूपये एक टीचर को वेतन मिलता है, लेकिन वहां के स्कूलों का स्तर इतना ऊंचा है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों से दूर भागते हैं, जबकि वहां के शिक्षक को 40–40 हजार रुपये वेतन मिलता है। मैं कहना चाहता हूं मा0 अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के बजट में इस पर ध्यान दिया जाय, यदि वास्तव में हम शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राईमरी शिक्षा है, वहीं पर हमारे देश का नौनिहाल और इस देश का भविष्य उसमें शिक्षा ग्रहण करता है, यदि वहां पर सांसदों के, विधायकों के और उसी जिले में रहने वाले कलेक्टर, कोतवाल और वहां के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चे भी उसमे पढ़ेंगे, वहां के टीचर्स के बच्चे, वहां के शिक्षकों के बच्चे भी यदि उन स्कूलों में पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं यह निश्चित है कि उन स्कूलों का स्तर शुरू के 03 महीने में ही सुधर जायेगा और फिर उन अभिभावकों को पब्लिक स्कूलों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्दर राम मनोहर लोहिया समग्र के अन्दर जो कार्य हो रहे हैं, मेरे क्षेत्र के बहुत कम गांव चयनित किये गये हैं, जनेश्वर मिश्र योजना में भी बहुत कम गांव चयनित किये गये हैं, मैं चाहूंगा कि कम से कम अब ये आखिरी वर्ष है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा गांव उन विपक्ष के हमारे साथियों के भी चयनित होने चाहिए और उसका प्राविधान भी इस बजट में हो और इसकी जो धनराशि है, इससे निश्चित रूप से जिन भी गांवों के अन्दर यह योजना गई है, वह अच्छे कार्य वहां पर हुए हैं, लेकिन इसका जो बजट है वह 20 लाख या 25 लाख, वह वहां की आबादी के अनुसार है, लेकिन यह बजट बहुत कम है, इस बजट को भी बढ़ाये जाने का प्राविधान इस बजट के अन्दर होना चाहिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर परिचर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद्।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में बैठे मा0 सदस्यों की संख्या को भी देख लिया जाय। इस समय सदन में सदस्य संख्या बहुत कम है।

'श्री आरिफ अनवर हाशमी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी के 2016–17 के रखे गये बजट के समर्थन में

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं मान्यवर, मैं विपक्ष के साथियों की बात को बड़े गौर से सुना रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार 2012 में मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी और इससे पहले जो सरकार बैठी थी, उसने इस सूबे का क्या किया था लेकिन 2012 के बाद आज 2016 तक चार साल में किसान, मजदूर, नौजवान, खिलाड़ी, कवि, शायर, पत्रकार, समाज का कोई भी तबका, चाहे वह रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वह मिट्टी खोदने वाला हो, चाहे वह गिट्टी तोड़ने वाला हो, चाहे वह सड़क बनाने वाला हो, चाहे वह मंजिल बनाने वाला हो, इमारत बनाने वाला हो उसको भी रजिस्ट्रेशन करके साइकिल देने का काम अगर किसी ने किया है, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों की बात पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साथी कह रहे थे, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया ? 2014 में एक सरकार आयी, 2014 के चुनाव का दृश्य सबने देखा। प्रधानमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश से ही हैं, गृहमंत्री भी यहीं से हैं, रक्षामंत्री भी यहीं से हैं और मैं तो इस गरिमामय सदन में यह कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सांसद न दिए होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में न बनती। 2014 से लेकर के 2016 बीत गया, वह वायदे कहां गए जो होने वाले प्रधानमंत्री जी ने किए थे। मुझे तो इस पर एक शेर याद आता है कि 'होठों पर हंसी, अधरों पर शिकन, इकरार भी है, इनकार भी है, उस वायदे का क्या मतलब समझूं, आसान भी है, दुश्वार भी है'। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण जब शुगर मिल इंडस्ट्री के मालिकों ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा हम गन्ना मिल नहीं चलायेंगे, हम किसानों का गन्ना नहीं खरीदेंगे, हम बहादुर सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रि–मण्डल के सहयोगियों और समाजवादी पार्टी के अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश खजाने में व्यवस्था करके और किसानों को पैसा दे करके पुनः मिल चलवायी। हम उन्हें बार–बार मुबारकबाद देना चाहते हैं। दिल्ली सरकार गंगा सफाई योजना पर काम कर रही है 'राम तेरी गंगा मैली हो गयी, पापियों के पाप धोते–धोते' मान्यवर, हम आपसे कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने कहा था कि गांव में बिजली आती है कि नहीं आती है, गांव में सड़कें हैं कि नहीं हैं। एक योजना मॉडल स्कूल की चल रही थी। मॉडल स्कूल गरीब बस्तियों में बनाए जा रहे थे, अभी हमारे साथी स्कूल की बात कर रहे थे उसमें कुछ पैसा केन्द्र सरकार का था, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार का था। बहुत–से मॉडल स्कूल बन गए लेकिन भारत सरकार ने उसको डिलिंक कर दिया। अब जो बिल्डिंग बन गयी है, वह सफेद हाथी हो गयी है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जी से और साथियों से कहना चाहते हैं, दादा हमारे बैठे हैं, यह प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के हैं, प्रधानमंत्री जी को लिखें कि जो उत्तर प्रदेश के साथ उपेक्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश को जो वायदा किया जा रहा था, उतनी बिजली नहीं दी जा रही है, उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिससे उत्तर प्रदेश का विकास स्लो चल रहा है। मान्यवर, हम मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे कि उन्होंने किसानों के साथ–साथ वित्त विहीन विद्यालय के अध्यापकों को खजाने से मान दे देने का काम किया है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में

माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग में जितने पुल नदियों पर बनाए गए हैं, वह एक इतिहास है। जितनी सड़क बनायी गयी हैं उत्तर प्रदेश के खजाने से, उतनी अद्वितीय है। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा प्रतिशत में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के टोका–टाकी करने पर)

सुनिए, सुनिए थोड़ा तसल्ली से सुनिए। अभी तो आपकी तरफ हम आ रहे हैं। वह पत्थर की हाथी की तरफ अभी आ रहे हैं। रुकिए, सुन लीजिए, तकरार न करिए। अभी चलने दीजिए, सुनिए न तसल्ली से। विकास की बातें कर रहा हूं तो अच्छा नहीं लग रहा है ? प्रदेश के, सूबे के विकास की बातें कर रहा हूं, गरीब की बेटियों को कन्या विद्या धन मिल रहा है तो क्या अच्छा नहीं है।

(बसपा के सदस्यों की ओर से 'कहां मिल रहा है')

मिल रहा है, मिलेगा। गरीब के बेटों को लैपटाप मिल रहा है, क्या ये अच्छा नहीं है। 67 साल की आजादी में, झोपड़ी में, छप्पर में रहने वाले लोगों को लोहिया समग्र गांव में पक्की छत बना करके, आवास दे करके, उनको रोशनी का इन्तजाम करके अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि उन गरीबों के घर में मशाल लाने, रोशनी लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 साल की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में घोटाला, घोटालों पर घोटाला। आपको अगर इण्टरमीडिएट की मान्यता लेना है तो 5 लाख, आपको उच्च शिक्षा में कालेज की मान्यता लेना है तो 10 लाख, बी0एड0 कालेज की मान्यता लेना है तो 10 लाख रुपया चलता था। एक तरफ से पूरा मंत्रि–मण्डल, इनके सारे मंत्री घोटाले में पकड़े गए हैं। कुछ तो जेल के अन्दर हैं, कुछ जाने वाले हैं। कुछ जेल के अन्दर हैं, सलाखों के पीछे हैं। इनके राज में एन0आर0एच0एम0 का सारा पैसा लूट लिया गया। एन0आर0एच0एम0 का सारा पैसा खा लिया गया।

(बसपा के कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

शान्त रहो, शान्त रहो। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश की सरकार, मा0 अखिलेश यादव की सरकार अच्छा काम रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है और इनके मंत्री, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश का दस्तावेज बता रहा है कि बसपा के सारे मंत्री घोटालों में फंस गए, विजिलेंस ने पकड़ लिया, एण्टी–करप्शन ने पकड़ लिया। सब जेल में हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ फरार हैं।

इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक़–ए–जुर्म हैं,

कुछ ज़मानत पर रिहा हैं और हैं बाकी फ़रार।

मान्यवर, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, मजलूमों और व्यापारियों का राज है, कहीं भी इंस्पेक्टर राज नहीं है। इस सरकार ने सबका सम्मान

किया है और सबके विकास की बात की है, सबके विकास का काम किया है। मैं एक बार पुनः मा0 मुख्य मंत्री, श्री अखिलेश यादव जी द्वारा रखे गए बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत–बहुत शुक्रिया।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने आय–व्ययक वर्ष 2016–17 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा के अन्तर्गत मेरी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, बहुत–बहुत आभारी हूं लेकिन इस आय–व्ययक 2016–17 के अन्तर्गत कानून–व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग में बेरोजगारी मुक्त किए जाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है बल्कि इन सारे विषयों की भारी उपेक्षा की गई है। इसलिए मान्यवर, मैं कतिपय बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो वह पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, शोषण और उत्पीड़न है। इसके कारण आज पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसे गम्भीर अपराधों की पराकाष्ठा हो गई है। मान्यवर, आज फर्जी अपराध पंजीकृत करके विरोधियों को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है और सही अपराध पंजीकृत नहीं किए जा रहे हैं। मान्यवर, जनपद पीलीभीत के नगर में दिनांक 5 फरवरी, 2016 को एक अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ एक सम्प्रदाय के व्यक्ति ने छेड़–छाड़ की जिसका अभियोग पंजीकृत तक नहीं हुआ। परिणामतः दूसरे दिन अनुसूचित जाति के लोगों ने प्राथमिकी पंजीकरण हेतु मांग की लेकिन 11 नामजद और 150 अज्ञात पीड़ित पक्ष के लोगों के ही खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया। मान्यवर, अभी जो त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हुए हैं, इसमें ब्लाक प्रमुख के चुनाव में वटखेड़ा विकास खण्ड में फर्जी प्राथमिकी पंजीकृत कराकर इतना आतंक पैदा किया गया कि एकतरफा मतदान करा लिया गया। मान्यवर, विकास खण्ड बीसलपुर में भी 84 निर्वाचकों में से 22 मतदान सहयोगी प्रदान किये गए और इस प्रकार से जबरदस्ती सफलता प्राप्त कर ली गयी। मान्यवर, जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश के मानचित्र में एक ऐसा जनपद है, जहां का उत्पादन पूरे प्रदेश में प्राथमिक और श्रेष्ठ होता है लेकिन इस जनपद में शिक्षा की विकृत व्यवस्था है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनपद पीलीभीत में 200 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो की शिक्षक विहीन हैं अथवा एकल शिक्षक विद्यालय हैं और इस प्रकार से 200 विद्यालयों का बंद पड़ा होना एक चिंता का विषय है। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में 15000 के लगभग शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए रिक्तियों का प्रकाशन किया गया और उसकी काउन्सिलिंग भी की गई, न नियुक्ति पत्र दिये जाने की फरवरी, 2015 की तारीख निश्चित की गयी लेकिन अब तक वह नियुक्तियां नहीं की गईं हैं, इस प्रकार से आज जनपद पीलीभीत ही नहीं पूरे प्रदेश में शिक्षकों का अभाव है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बहुत–सारे विभाग हैं, जिनमें लाखों की संख्या में रिक्तियां हैं, लेकिन वह भरी नहीं जा रही हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का विकास आज रुका हुआ है। मान्यवर, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के भी

शिक्षकों की नियुक्तियां की जानी हैं, जिनका साथ–साथ में ही साक्षात्कार हुआ है लेकिन अब तक अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं, जबकि उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां बार–बार की जा रही हैं।

बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)–

अंग्रेजी और मैथमेटिक में 29000 में से 27000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। ये बातें झूठ हैं, गलत न बोलिये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में विकास खण्ड बीसलपुर एक ऐसा विकास खण्ड है, जिसमें अब तक आजादी के 66 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है यह कितना दुःखद विषय है। मान्यवर, हमारे यहॉ एक बिलसंडा नगर है, जहॉ एक राजकीय कन्या इंटर कालेज है जिसमें ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति को प्रिंसिपल बनाया गया है, जो अयोग्य है, उसको आपत्ति किये जाने पर हटा दिया गया और आगे बढ़कर उसे चार और विद्यालयों का प्रधानाचार्य बना दिया गया है। मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि जो सदन में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने सड़कें दिये जाने का, नल दिये जाने का, विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि में वृद्धि किये जाने की बात की है, मैं सहमत हूं लेकिन मान्यवर, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां कहना चाह रहा हूं कि जो विधायकों का वेतन है उसमें वृद्धि न करके उसमें कमी की जाए। मैं समझता हूं कि जैसे मंहगाई 10 प्रतिशत कम हुई है, विधायकों के वेतन में कम से कम उसी प्रतिशत में कटौती की जाए।

'श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मै आपको धन्यवाद कहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं छोटी काशी, अनूप शहर जनपद बुलन्दशहर से चुनकर आता हूं। छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि अनूप शहर के बीच से होकर गंगा निकलती है और वह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां पर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर गंगा किनारे घाटों का निर्माण कराया था और जैसे ही 2012 में सरकार गयी तो जो प्रोजेक्ट हमारे यहां घाटो के निर्माण के चल रहे थे वह वर्तमान सरकार ने रोक दिया जिससे वहां पर सारे के सारे निर्माण कार्य ठप हो गये। ऐसे में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो वर्तमान बजट है उसमे अनूप शहर का विशेष ध्यान रखकर वहां पर घाटों का निर्माण, सड़कों का निर्माण कराया जाये इसी के साथ–साथ जो वर्तमान मे बजट आया है उसमे कहीं भी अभी आप देखें पूरे प्रदेश मे किसान, मजदूर और नौजवान, यह हाहाकार कर रहे हैं और वर्तमान मे चाहे यू0पी0 की सरकार हो चाहे केन्द्र की

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार हो इन सबने किसानों का नौजवानों का अधिकार देने का काम नही किया। आज किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। किसान जो अपनी फसलों को सींचने के लिए खून पसीना लगाकर फसल उगाता है आज उन फसलों का हाल यह हो गया है कि गन्नों का पेमेन्ट का हाल यह है कि वर्तमान का तो छोड़ दे पिछले 2–2 सालों का पेमेन्ट हमारे क्षेत्र मे गन्ने का अभी नही हुआ है। मेरा यहां सहकारी चीनी मिल अनूप शहर लगता है और एक शुगर मिल अगौता लगता है, उन दोनो चीनी मिलों पर किसानों का पेमेन्ट अभी रूका हुआ है और किसान चक्कर काट रहे हैं हम लोग सरकार को अवगत करा रहे हैं लेकिन किसान का पेमेन्ट नही हो पा रहा है। जिससे वहां पर किसानों की स्थिति यह आ गयी है कि वह अपने रोजमर्रा के काम तो छोड़ो, अगर बीमारी से उनके बच्चे भी बीमार हैं उसके लिए भी उन्हें अपनी चीज गिरवी रख, जमीन गिरवी रखकर इलाज कराने पड़ रहे हैं ये आज उत्तर प्रदेश के हालात किसान के हो गये हैं। खास कर नौजवान की बात करें तो नौजवान शिक्षा लेने के बावजूद आज धक्के खाने को मजबूर हैं चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार मे नौकरियां निकल रही हों उन्हें रोजगार नही मिल रहे और केन्द्र सरकार तो कहीं कुछ सुनने को तैयार नही है और तो और जो केन्द्र सरकार ने वादे किये थे आज सिर्फ छल करने का प्रयास कर रही है। खास कर मै अपनी विधान सभा के गांव का जिक्र करूं जिनमे कोई विकास कार्य न तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कराये गये और न ही केन्द्र के द्वारा कराये गये। मेरे यहां अगौता ब्लाक का गांव लगता है, खेड़ी, बौन्दरा, बीहरा, तौमडी, पिपाला, सैगली, महेशपुर, पसौली, अलावा, नसीरावाद पूठी इन गांव मे सड़कों की हालत जर्जर हो गयी है वहां पर आवागमन की स्थिति यह हो गयी है किसान वहां पर पैदल नही चल सकता। जो चीनी मिल के लिए रास्ता आता है चाहे शेखपुर गढ़वा हो, दौलतावाद हो, रामगढ़ हो, लखावटी हो, मूढ़ी बकापुर हो, गंगाहरी हो, भंडौरिया हो, ख्वाजपुर अशरफपुर हो, नगला जीत उर्फ जिताका हो, खनोदा हो, पवसरा हो, बिसुन्दरा हो, लौहरका हो, पाली बेगपुर हो, भावसी हो, औरंगाबाद हो और इसी के साथ चरौरा मुस्तफाबाद हो, नगला करन, मैथना जगतपुर, जहरा, सैमली, जीवत, सराय छबीला, ईस्माइला, सैदपुरा, भीकनपुर, पोथ, जनौरा, नौबतपुर, बालका, सुरजावली, औरंगपुर मोहसन, बकौरा, मीरपुर, अकबराबाद कूडा, जमनाठेर, जौठ, आलमगीरपुर नैनसुख, मिर्जापुर अगरपुर जो गांव अगौड़ा चीनी मिल का गन्ना लेकर आते हैं उन गांव के रास्ते की स्थिति यह है कि अपने गन्ने को लेकर चीनी मिल तक जाने के लिए जो मेन रास्ता है औरंगाबाद से बिहड़ा तक होकर चीनी मिल तक जाता है उस मार्ग की स्थिति यह हो गयी है, चाहे लखातपुर से कसौली होते हुए पिपाला तक का मार्ग हो उसकी स्थिति यह है कि वहां ट्रैक्टर, ट्राली तो छोड़ो, पैदल चलना दूभर है। आये दिन वहां पर ट्रैक्टर, ट्राली पलटने से मौते होती हैं। भैंसा बुग्गी जो लेकर आते हैं उनके भैंसो की टांग टूट जाती है इसी के साथ साथ अड़ौली, बंगला पूठरी, मानकपुर, उटरावली, मिल्क मौहसनगढ़, हजरतपुर समसपुर, कलौली, दोहली, पौण्डरी, जुलेपुरा, कुछेजा नगर में सहकारी जो सूत मिल है वह लम्बे समय से बन्द है अगर सरकार इस सहकारी सूत मिल को चला दे तो आसपास के पूरे इलाके को लाभ मिल जाय। इसी के साथ साथ मुरसाना, किशनपुर, शिवाली, आलमगीरपुर धनौरा, फरहादपुर, सीकरी, शाहपुर, रशीदपुर, सदरपुर, सन्नौट, सलैमगढ़, बुढ़ाना, रसूलपुर तेलिया उर्फ मैथना, आंजनी खनपुरा, जुगसाना खुर्द, जुगसाना कलां, नवीनगर, डबकौरा,

मानकरौरा, रौडात्र बदरखा, शेखूपुर रोरा, जटवाई, गहना गोवर्धनपुर, खिजराबाद, गुंचावली यह सारे के सारे गांव इनके रास्तों की स्थिति यह है कि किसान अपनी फसल लेकर मण्डी नहीं जा सकते, आवागमन के साधन बिलकुल बन्द है। जब भी हम कोई क्वैश्चन लगाते हैं तो सरकार का जवाब आता है कि वित्तीय संशाधन की उपलब्धता पर निर्भर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अनूप शहर विधान सभा की तरफ कि वहां पर सड़कों का हाल यह हो गया है कि वहां पर आज पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है इसी के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा नगर जहांगीराबाद लगता हैं। वहां पर जब पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 18 से 20 घन्टे बिजली आती थी आज अनूपशहर नगर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है वहां पर अनूपशहर, जहांगीराबाद और औरंगाबाद।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस तरह से कैसे मैं अपने क्षेत्र की बात को उठाऊंगा यह तो बेइमानी है हमारे साथ।

श्री अधिष्ठाता–

7 मिनट की बात हुई है।

श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें। इसी के साथ हमारे यहां रोड की व्यवस्था कराई जाय। हमारे यहां भइयापुर, चचरई, प्रेमनगर, जमराऊ, टिटौटा उर्फ वीरगांव, भौपुर, विधिपुर, जसर, जयरामपुर उर्फ कुदैना, माधौगढ़, साहिबाबाद उर्फ ककरई, मुबारिकपुर, पूठा, कारौजी, खदाना, गोधना, रूठा, जलीलपुर, सांखनी मान्यवर, सांखनी वह गांव है जो सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला गांव है जहां सरकार बनने के बाद न वहां कोई विकास कार्य हुआ न कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का कोई काम हुआ। बड़े–बड़े वायदे और नारे दिये गये, सरकार कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनाने का कार्य कर रही है हमारे क्षेत्र में एक भी मुस्लिम गांव में कोई भी चहारदीवारी करने का काम मुस्लिम आबादी में नहीं हुआ। इसी के साथ साथ डूंगराजाट, गंगावास पहाड़ा, लछोई, चरौरा, जटपुरा, डरौरा, नूरपुर उर्फ करनपुर, विचौला, खलौर, तौली, सलगवां, देवकरन उर्फ बझेड़ा, बिरौली शेरामपुर, जिनाई, रौरा, मलकपुर, जारजपुर मजरा मलकपुर, राजपुर, बेगमपुर उर्फ जयरामपुर, शाहजहांपुर,सुनाना, सुनाई, हिसावटी, डूगरा जौगी, पारली, अमरपुर, खनौदा, नगलानलू, पोटा बादशाहपुर, बढपुरा, बनवारीपुर, सिहाली नागर, दरावर, रजापुर, अहार बांगरी, मुबारिकपुर बांगर, मौहरसा, बामनपुर, खालकपुर, हसनपुर बांगर, सिरौरा बांगर, पचदेवरा, शिकोई, मौजपुर, पहाड़पुर, आजमपुर तौरई, बच्ची खेड़ा, नेतानगर, सलामतपुर, अमेठा, गरहरा, अनीवास, दुगरऊ, पगौना, करनपुर, लच्छमपुर,

अचलपुर, शेरपुर बांगर, फतहपुर रूढ़ वांगर इन गांवों में जो मेन रोड है उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हिन्दू परेशान है, मुसलमान परेशान है हमारे क्षेत्र के किसानों का, नौजवानों का, हिन्दू का मुसलमानों का ध्यान रखा जाय और वहां विकास के कार्य कराये जायें।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर हमको चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। कोई भी सरकार चलाने के लिए कोई भी मुख्य मंत्री जो वर्तमान में कुर्सी पर रहते हैं वह अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। घर को चलाने के लिए भी घर में भी आदमी अपना बजट पेश करता है, परिवार के अन्दर भी तर्क–कुतर्क होता है, यह तो सदन है। यहां पर शिक्षा, चिकित्सा, किसान और व्यापारी की बातें चली। शिक्षा का हाल यह रहा कि जो लोग भी डिग्री कालेज चलाते होंगे उनको विगत सरकारों में मान्यतायें कैसे मिलती थी उसका दर्द वह डिग्री कालेज चलाने वाला प्रबन्धक ही जानता होगा और चिकित्सा का हाल यह रहा कि गरीब का बेटा पांच रुपये की दवा पा जाता है, तो रास्ते चलते आदमी को धन्यवाद देता है। अस्पतालों के अन्दर टोकन मनी लेकर दवा की जाती थी और हालात इतने बदतर रहे कि एन0आर0एच0एम0 के घोटाले में क्या–क्या हुआ उसको पूरा प्रदेश जानता है। हालात यह भी रहे कि जहां यह कहा जाता है कि किसानों के हित की बात की जाती है और अभी परसों एक विवाद यहां पर डन्डीमार के नाम पर स्टार्ट हो गया था। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में उस समय में समाजवादी पार्टी से राजनीति करता था तो मुलायम सिंह जी ने व्यापारियों को चुंगी कर को समाप्त करने का काम किया, 3/7 को समाप्त करने का काम इतना ही नहीं किया, बहुत कुछ किया। आज की तारीख में मैं एक बात कहना चाहता हूं और खासकर सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार व्यापारियों को जो धान मिल मालिक हैं इनको डीजल पर सब्सिडी देने का काम कर रही है, तो हम चाहते हैं और सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं इन किसानों के लिए भी जितना जिसका खेत है उसके अनुपात में उसको डीजल दिया जाये और उस डीजल की व्यवस्था में जिस प्रकार से व्यापारी को वैट प्रणाली से छूट दी गई है, उसी तरह से हमारे किसानों को भी छूट दी जाये। सरकार पयर्टन स्थल घोषित कर रही है और हम महराजगंज जिले से आते हैं। हमारा जिला महाराजगंज वन आच्छादित का मानक पूरा करता है वहां अंग्रेजों के जमाने से बनाई हुई ट्राम्बे लाइन है, अगर उस लाइन को सुसज्जित किया जाये और जो सोहगी बरवा वन क्षेत्र प्रणाली है उसको सुसज्जित किया जाये तो निश्चित तौर पर नेपाल और भारत के बीच में व्यवस्थित बार्डर का यह इलाका पयर्टक स्थल घोषित हो सकता है। हमारे यहां बनरसिंहा में जहां महात्मा बुद्ध ने अपना वस्त्र उतारा था, हम चाहते हैं कि उसको पयर्टक स्थल घोषित करके सरकार हमारे पयर्टकों को आकर्षित करने का काम करे। जहां तक बजट का सवाल है, सरकार ने जो बजट पेश किया है वहीं बजट गांव सभावों को भी जाता है और वही बजट जिला पंचायतों को भी जाता है। अभी चुनाव हुआ, हालात बड़े बदतर थे। आपने एक चीज देखी होगी कि गांव सभाओं का चुनाव

हुआ, हालात बड़े बदतर थे। आपने एक चीज देखी होगी कि गांव सभाओं के चुनाव में लोग कैसे चुनाव लड़े और ब्लाक प्रमुखों का चुनाव कैसे हुआ, इसमें किस चीज का आदान–प्रदान हुआ। हल्ला होता कि ताकत का प्रयोग किया गया, मैं इसको नहीं मानता। अगर प्रयोग हुआ है तो धन का प्रयोग हुआ और जो भी आदमी इतना धन खर्च करके जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठेगा और जो भी आदमी इतना धन खर्चा करके ब्लाक प्रमुख की कुर्सी पर बैठेगा वह निश्चित तौर पर न अपने गांव को विकास दे सकता है और न अपने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को विकास दे सकता है। मैं सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अगर चुनाव में इस पैसे की व्यवस्था को तोड़ना है तो हमको, आपको सारे लोगों को संगठित होकर यह चुनाव जनता से करवाना होगा, जनता से चुनाव करवाने के बाद निश्चित तौर पर यह ताकतरूपी व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जायेगी। हालात इतने ही नहीं हैं, यह नई चीज नहीं है, सरकार इनकी बनी तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है जब इनकी सरकार रहती है और यह चुनते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। उसका उदाहरण सिद्धार्थनगर का जिला है। उस समय बहुजन समाज पार्टी से भालचन्द्र यादव चुनाव लड़े थे और हालात इतने बदतर थे कि मतदाताओं को घर में से उठा लाये थे। किसी ने किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। सड़कों पर हत्या होती है, आप ढिढोरे पीटते हो, मंत्री जी लोगों ने बलात्कार किया था और मंत्री जी लोगों ने आप ही की सरकार में रहकर के बलात्कार करने का काम किया था। बात इसकी होनी चाहिये। हर आदमी एक दूसरे पर लांछन लगाने का काम कर रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपने दामन में झांको कि पैसे पर टिकट लेकर के समाज को कोई सिंचित नहीं कर सकता। आर्थिक सोच का आदमी कभी सामाजिक हो ही नहीं सकता। जिसके अन्दर धन देकर धन लेने की लालच होगी, वह समाज को कभी नई दिशा नहीं दे सकता, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य प्लीज शान्त रहिये इनको बोलने दीजिये। जब आपकी बारी आये, तब आप भी कहियेगा।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

अब बुरा किस बात का लग रहा है, इसमें आप लोगों को बुरा लगने की बात नहीं होनी चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, सच्ची बात बड़ी बुरी होती है और कड़वी लगती है। इन लोगों को कडुवा लग रहा है, जितना भाषण इन्होंने दिया, बजट पर नहीं दिया और मैंने ग्राम पंचायत को, जिला पंचायत को बजट पर ले जाने का काम किया। तो इन्होंने उसमें लकड़ी लगाने का काम किया। एक चीज जरूर अधिष्ठाता महोदय कहूंगा कि जहां तक बजट का सवाल है हम मानते है कि सरकार ने अपना बजट पेश किया है लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जैसे कोई भी मुख्य मंत्री कभी भी किसी प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं और वह अगर किसी चीज का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं

और किसी काम की अगर सरकार घोषणा कर देती है तो उन कामों पर सरकार को बजट अवश्य देना चाहिये, उन कामों को रोकना नहीं चाहिये क्योंकि इससे समाज की गति रूकती है। इसलिय हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी विधान सभा के अन्दर जो रोहिणी हेड प्रणाली जो 15 साल से टूटी हुयी थी, जिसके लिये मैंने इसी सदन के अन्दर शिकायत की, सरकार ने जांच कराई और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की, सरकार ने लिखित तौर पर आश्वासन भी दिया है लेकिन मेरा यह कहना है कि मेरे क्षेत्र को और मेरी विधान सभा को सिंचित करने का काम रोहिणी नहर प्रणाली करती है, मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि उसको भी हमारे बजट में स्वीकार किया जाय। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सदस्या ने अभी एक सवाल उठाया था कि जहां सपा के विधायक हैं वहीं पर काम हुआ है। अभी माननीय सदस्य ने छोटी काशी का बहुत जिक्र किया। पिछले 50 सालों से अनूपशहर की मांग थी कि अनूपशहर में गंगा का पुल बना दिया जाय। वह यह बताना भूल गये कि वह पुल रिकार्ड समय में नेताजी जब मुख्य मंत्री थे, 2006 में केवल 07 महीने में बनकर तैयार हुआ था और अनूपशहर को मुरादाबाद से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने छोटी काशी के लिये किया था। आप बताना भूल गये, आपने भूल गये, आपने तो सिर्फ उस पुल पर पत्थर लगाने का काम किया था, जिसे जनता ने उखाड़कर फेंक दिया। अभी एक सदस्य ने मांग उठाई कि सपा के जो विधायक हैं उन्हीं के प्रस्ताव होते हैं। मनीष असीजा जी हैं, बी0जे0पी0 के मेम्बर हैं, अभी यहां नहीं है पिछले 50 वर्षों से फिरोजाबाद जनपद में मीठे पानी की मांग को लेकर आन्दोलन होते रहे। लगभग 1500 करोड़ रुपया एक्जेक्ट नहीं मालूम है, फिरोजाबाद को गंगा का पानी देने के लिये बी0जे0पी0 विधायक के क्षेत्र में देने का काम सरकार ने किया है। यहां अग्रवाल साहब नहीं हैं, गोरखपुर में उनकी मांग पर हमारे बहुत ही विशाल हृदय के परिचायक मुख्य मंत्री जी ने जो भी विधायक उस पक्ष का मिला होगा, उसको जरूर कुछ न कुछ देने का काम किया, जो मिला उसको देने का काम किया, क्षेत्र में विकास दिया और कहो तो मैं गिनवा दूं। अग्रवाल साहब मिले उनके क्षेत्र में ओवरब्रिज दे दिया, आगरा में आपके दुबेश जी विधायक हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया उनके क्षेत्र में दिया बनारस में दिया दादा जी के क्षेत्र में, विधायिका जी बैठी हैं उनके क्षेत्र में दिया, ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसको नहीं दिया हो। अब आपको मिलने में डर लगता है कि बहन जी जान लेंगी तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम तो आप मा0 सदस्य से यह जानना चाहते हैं कि जो देवी देवताओं में हम लोग आस्था रखते हैं, वैष्णों देवी, विन्ध्यवासिनी देवी, अब आस्था का केन्द्र आपने दूसरा बना दिया तो उन मन्दिरों में भीड़ कम हो जायेगी इसका भी कुछ इन्तजाम होना चाहिए।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीनों लोकों में खोज करके उन्होंने सर्वमान्य देवी घोषित कर दिया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भाई परलोक कब गये थे खोज करने के लिए और वहां से वापस कब आये। तीनों लोकों में कब घूमने वह गये और कब वह लौट करके आये। अधिष्ठाता महोदय, पुलिस की भर्ती हुई थी और इन लोगों ने सदन नहीं चलने दिया था, यहां पर खड़े हो गये थे और कहा था कि मैनपुरी के हजारों लड़के भर्ती हो गये। 312 लड़के मैनपुरी के भर्ती हुए हैं आप निकलवा लेना और आपने दो दिन इस सदन को नहीं चलने दिया था, आपने कहा था कि मैनपुरी, इटावा और कन्नौज के लड़के भरे गये। कन्नौज के लगभग साढ़े तीन सौ लड़के हुए हैं, सबसे ज्यादा लड़के हुए हैं तो बागपत, सहारनपुर और मुरादाबाद के हुए हैं। यह सदन दो दिन बाधित रहा था, हमारे मुख्य मंत्री जी ने हर क्षेत्र में पूरे विजन के साथ काम किया है और जो बजट लाये हैं वह किसान हित में, देश हित में, प्रदेश हित में है और वह अपने आप में परिपूर्ण बजट है इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं और बजट के समर्थन में बल देता हूं।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लाये गये वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैं बजट के सांख्यकीय आंकड़ों पर नहीं जाऊंजा उस पर काफी देर से चर्चा हो रही है। मैं कुछ बहुत ही जरूरी, आवश्यक और व्यावहारिक पहलुओं की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित कराना चाहता हूं। मान्यवर, इसी सदन में जब वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट मा0 मुख्य मंत्री जी ने रखा था उस समय भी यह बात सामने आयी थी कि यदि एक दो विभाग को छोड़ दिया जाये तो लगभग–लगभग सारे विभागों के द्वारा 12 महीने से 10 10 महीने में मात्र 30 से लेकर 40 फीसदी धन खर्च करने का काम किया गया था। आज भी वही हालात हैं वित्तीय वर्ष 2016–17 का जब बजट आता है तब भी वही बात सामने आती है कि बजट में जो प्रावधान किया गया था एक दो विभाग को अगर छोड़ दिया जाए, मैं मा0 सहकारिता मंत्री, दुग्ध विकास मंत्री और मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके विभागों में 70 से 80 फीसदी धन खर्च हुआ है बाकी जो कृषि और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं उनमें 25 से 30 फीसदी धन खर्च हुआ है। मान्यवर, इससे साफ संकेत मिलता है कि दो महीने के वक्त में अगर 60 से 70 फीसदी धन खर्च करने का अवसर ब्यूरोक्रेट्स को या विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा तो निश्चित रूप से उस धन का इस्तेमाल जनता के फायदे के लिए नहीं होगा बल्कि वह धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। इससे संकेत मिलता है कि यह सरकार किसानों का भला करना नहीं चाहती है। यह सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पैदा करके यादव सिंह जैसे अधिकारियों एक नर्सरी तैयार करने का काम कर रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यादव सिंह जैसे अधिकारी यहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेतागण भी बैठे हैं और सरकार के लोग भी बैठे हैं क्या वजह है कि यादव सिंह जैसा अधिकारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार का भी चहेता होता है

और वहीं भ्रष्टतम अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार का भी चहेता होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों सरकारों की मंशा जनता के भले के लिए नहीं रही है, किसानों के भले के लिए नहीं रही है नौजवानों के भले के लिए नहीं रही है, बेरोजगारों के भले के लिए नहीं रही है अगर यह भले के लिए है और भलाई करने का माद्दा इनमें है तो सिर्फ पूंजीपतियों का भला करने का काम कर रहे हैं और ये सरकार भ्रष्ट अधिकारियों का भला करने का काम कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से किसानों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष और युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज किसानों की हालत क्या हैं अलग–अलग क्षेत्रों में ? मैं थोड़ी सी चर्चा समर्थन मूल्य पर करना चाहता हूं, अगर धान की उपज किसान पैदा करता है तो हर क्षेत्र में उसकी अलग–अलग परिस्थितियां होती हैं, कहीं पर नहरों से सिंचाई होती है, मुफ्त में सिंचाई करके धान पैदा करने का किसान करता है वहीं दूसरे क्षेत्रों में जहां नहर के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, किसान ट्यूबवेल के माध्यम से, डीजल, पम्पिंग सेट के माध्यम से अपने खून–पसीने से फसलों की सिंचाई करके धान पैदा करता है। दोनों की लागत में जमीन आसमान का फर्क होता है। नहर से मुफ्त सिंचाई करके किसान सस्ते लागत से फसल पैदा करने का काम करता है लेकिन जहां का किसान अपने डीजल पम्पिंग सेट के माध्यम से धान पैदा करने का काम करता है उसकी लागत उससे कई गुना ज्यादा होती है लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए मैं सदन से मांग करता हूं कि सरकार एक आयोग का गठन कर और ऐसे सभी क्षेत्रों में जो फसलों की लागत है उसको देखते हुए किसानों की लागत का 50 फीसदी लाभांश जोड़ करके किसानों को फायदा दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। मान्यवर, किसान वर्ष के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंचाई का ढिंढोरा पीटने का काम सरकार ने किया। सरकार ने कहा कि हमारी सरकार ने नहरों से मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था करके किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का सरकारी आंकड़ा है कि मात्र 18 फीसदी किसान नहरों से सिंचाई करने का काम करता है और 82 फीसदी किसान अपने निजी संसाधनों से फसलों की सिंचाई करने का काम करता है। जो निजी संसाधनों से किसान सिंचाई करने का काम करता है उसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था देने का काम नहीं किया है। आज नहरों की हालत क्या है ? मैं अपने जनपद प्रतापगढ़ के नहरों की हालत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रतापगढ़ के किसानों को प्रतापगढ़ मुख्य जल शाखा शीर्ष से 1150 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है और सरकार ने उस शाखा से प्रतापगढ़ को 850 क्यूसेक पानी देने की व्यवस्था किया। लेकिन उस शाखा में बड़े पैमाने पर शिल्ट अभी भी जमा हुआ है और प्रतापगढ़ को मात्र 550 क्यूसेक लीटर पानी मिलता है जिसकी वजह से रजबहों में पानी नहीं जा पाता है, रजबहों के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है, तो माइनर में और छोटी नहरों में कहां तक पानी पहुंचता होगा ? बहुत गम्भीर समस्या है किसान परेशान है, किसान निराश है, किसान आत्महत्या की कगार पर खड़ा है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, नहरों में पानी नहीं है और झूठी सिंचाई का ढिंढोरा पीटने का काम यह सरकार कर रही है। मान्यवर, कोई भी तथ्य

इसमें झूठा नहीं है। आप मेरे जनपद से आंकड़ा ले सकते हैं। भू–गर्भ जल लगातार नीचे गिरता जा रहा है, सरकार ने 2014–15 से जितने चेक डैम बनाने का वायदा किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ की धरती पर 2014–15 में जितने चेक डैम स्वीकृत हुए थे आज तक उसमें एक भी चेक डैम निर्मित नहीं हो सका है। मान्यवर, अगर चेक डैम निर्मित नहीं होगा तो वाटर रिचार्जिंग स्कीमों का परिणाम निश्चित रूप से शून्य रहेगा। एक गम्भीर समस्या की ओर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जा रहा है। (श्री अधिष्ठाता द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, मैं घड़ी देख रहा हूं, अभी तीन मिनट का समय रह गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रतापगढ़ की पहचान आंवला के रूप में की जाती है, सभी किसानों की चर्चा होती है और प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है लेकिन इस सरकार की बजट व्यवस्था में प्रतापगढ़ के आंवला किसानों की चर्चा नहीं हुई है, न ही उनके किसी योजना की बात कही गयी है। मान्यवर, हम सब लोग पूर्वान्चल से चुन करके आते हैं, पूर्वांन्चल इस सदन में 162 विधायक चुन करके भेजता है, लेकिन पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुए इस सरकार ने पूर्वान्चल को विशेष पैकेज देने की व्यवस्था नहीं की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वान्चल को विशेष पैकेज दे करके, पूर्वान्चल को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिस तरीके से नहरों से सिंचाई मुफ्त होती है, उसी तरह से किसानों के लिए मुफ्त डीजल की और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए तब आप किसानों का आंसू पोछने का काम कर सकेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद प्रतापगढ़ में 90 फीसदी ग्रामीण अंचल की जितनी सड़कें हैं, जितने सम्पर्क मार्ग है टोटल ध्वस्त हो गये हैं। इलाहाबाद, फैजाबाद मार्ग पर गजैहडा का पुल हुआ करता था जिसके टूटने से भारी वाहन मेरी विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनके प्रवेश करने से सम्पक्र मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गये। मैंने कितनी बार सदन की कार्यवाही में लाया लेकिन एक भी सड़क पर कार्यवाही करने का काम अभी तक नहीं हुआ है। मान्यवर, अगर आप जानकारी करें कि किसी भी जनपद से एक आध की जानकारी दे दें कि ग्रामीण अंचल में सड़क की कुल लम्बाई कितनी है और कितनी उसमें निर्मित हुई है, कितनी टूटी हुई है, कितनी निर्माणाधीन है तो सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं होता है। मान्यवर, अभी सरकार जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अपना ढिंढोरा पीटने का काम कर रही थी। मान्यवर, केन्द्र सरकार के द्वारा एक योजना चल रही थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिससे गरीब स्मार्ट कार्डधारकों को जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक होते हैं उनके लिये सुविधा थी लेकिन आपने स्मार्ट कार्ड धारकों के लिये कोई योजना चलाने का काम नहीं किया है। बीमा कम्पनी प्रीमियम लेकर मालामाल हो रही है और गरीब इलाज के लिए तरस रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

गुलाम मोहम्मद साहब अब आप कहें।

डा0 आर0के0 वर्मा–

मान्यवर, अभी मेरा समय नहीं हुआ है। दो मिनट मेरा शेष है मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। मैं थोड़ी सी बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रतापगढ़ के विकास के लिये मैंने हमेशा नियम–300, नियम–56, नियम–51 में दिया और याचिकाओं के माध्यम से प्रतापगढ़ की समस्याओं को उठाने का काम किया लेकिन उसका परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा है। मान्यवर, मैंने धूरीपुर से लेकर हन्डौर तक लोनी नदी का पुल उठाया था, चाहे सिंगनी से लेकर लढ़वत का पुल का मामला रहा है। मान्यवर, विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का मामला उठाया था, मान्यवर, (ए0टी0एल0) फैक्टरी को पुनर्जीवित करके बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का मामला रहा है। मान्यवर, मैंने मेडिकल कालेज, ट्रामा सेन्टर का मामला रहा हो, प्रतापगढ़ को फोर लेन से जोड़ने का मामला उठाया लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक गम्भीरता से कार्यवाही कराने का काम नहीं किया है। मैंने मान्धाता विकास खण्ड, लक्ष्मण विकास खण्ड में आई0टी0आई0 लगाने की मांग कई बार सदन के माध्यम से की है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही करने का काम नहीं किया। मैंने मान्धाता विकास खण्ड में उपमण्डी बनाने की बात कहीं थी, उस पर भी कार्यवाही अभी नहीं हुई। सरकार इस वर्ष को युवावर्ष मनाने की बात कह रही है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे प्रतापगढ़ की धरती पर एक भी मिनी खेल स्टेडियम नहीं है। एक भी स्टेडियम नहीं है और आप युवा वर्ष मनाने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार युवा वर्ष मनाने ढिंढोरा पीट रही है लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामाजिक न्याय मोर्चा के छात्र, आरक्षण में विसंगति को लेकर आन्दोलन कर रहे थे तब सरकार ने उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। उनके ऊपर फर्जी मुकदमें डालने का काम किया और सरकार यहां सदन में ढिंढोरा पीट रही है कि हम लोग युवा वर्ष मनाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे बजट में यह व्यवस्था होना चाहिए कि किसानों, मजदूरों, मजलूमों और नौजवानों के कल्याण के लिये जब तक विशेष पैकेज नहीं दिया जायेगा उनके लिये विशेष योजनाएं नहीं बनाई जायेगी तब तक प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण अंचल के सम्पर्क मार्ग टूट चुके हैं। अगर सरकार प्रदेश में खुशहाली चाहती है तो अगर गांव में हम ही नहीं सरकार के लोग भी जाने का काम करेंगे, सरकार के नेता भी घूमने का काम करेंगे अगर जनता की खुशहाली चाहते हैं तो यह व्यवस्था दी जानी चाहिए। मैंने कहा है कि 90 फीसदी सड़कें जो टूटी है को कम से कम 50 फीसदी सड़कों का पुनर्निर्माण कराने का काम, मरम्मतीकरण कराने का काम सरकार को आश्वासन देना चाहिए। मान्यवर, मैं आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

श्री गुलाम मोहम्मद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका बहुत–बहुत शुक्रिया कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट के समर्थन पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से अपनी बात इस शेर के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं :–

मैं कहां रूकता हूं अर्शों फर्श की आवाज से,

मैं कहां रूकता हूं अर्शों फर्श की आवाज से,

मुझको उड़ना है बहुत ऊंचा हद ए परवाज़ से।

यह जो बजट पेश किया गया है मान्यवर, यह बंदिशों वाला बजट नहीं है। यह ये देख करके बजट पेश नहीं किया गया कि हमारी पार्टी को कौन वोट देता है कौन नहीं देता है। यह गलत आरोप है कई लोगों ने यह बात कही, हमारा यह बजट उन महापुरुषों के ख्वाब वाला बजट है, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। जिन्होंने एक ख्वाब देखा कि यहां का सर्वहारा, यहां की अनेकता में एकता जिन्दा रहे। यहां के सर्वहारा, यहां के दीन दुखियों के चेहरों पे मुस्कुराहट आये। यहां अगर कोई कन्स्टेशन रहा कोई सोच रही तो इस बजट के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही सोच है कि हम न हिन्दू की बात करते हैं, न मुसलमान की बात करते हैं न अगड़े की बात करते हैं न पिछड़े की बात करते है सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जो जरूरत में है जो मजलूम हैं, जिनके चेहरों पर उदासी छा गई है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का विजन उनकी विचारधारा उन महापुरुषों के विचारों का प्रतिविम्ब है जो उन्होंने ख्वाब देखा था और इस प्रदेश के सच्चे हितैषी होने के नाते यह बजट पेश किया गया। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बजट पर अगर निगाह डालें तो एक–एक मद उन गरीबों तक पहुंचती है उन गरीबों की मुस्कराहट तक पहुंचती है चाहे 102, 108 एम्बूलेंस की बात हो, आप उन लोगों से पूछिए जो साधनहीन हैं, 20 मिनट में बस उनके यहां पहुंच जाती है जो साधन नहीं रखते हैं उनका इलाज फ्री में होता है जो साधनहीन हैं उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष का मुंह खुला हुआ है। विधायक निधि में भी 25 लाख का प्राविजन मरीजों को जो सख्त मरीज है जो बुरी और खराब बीमारी से ग्रसित हैं उनको आप अपने विवेक से दे सकते हैं यह भी अपने आप में एक बड़ा काम है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, अब किसानों को समस्या है आप देखिए पांच लाख रुपये का बीमा सहायता दी जाती है। कोई अगर घायल हो जाता है अंग भंग हो जाता है, अंग विहीन हो जाता है उसके कृत्रिम अंग लगाने के लिए एक लाख रुपया, पांच लाख रुपया अगर कोई गम्भीर रूप से घायल हो जाता है उसके लिए भी है इसी तरह से जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनके लिए साइकिल हो, चाहे उनके बच्चे की मदद हो, उनके बच्चों की किताबें, उनके बच्चों की फीस, कौन सा ऐसा काम है जो सरकार नहीं कर रही है, इसी तरह से 45 लाख लोगों के लिए समाजवादी पेंशन की व्यवस्था की गई। अब 45 लाख लोगों से बढ़ाकर अब 55 लाख उसकी संख्या कर दी

गई है। यह सच्चे मायने में एक समाजवादी बजट है और मैं बार–बार कह रहा हूं इस तरह के नेतृत्व की क्षमता जो हमारे मुख्य मंत्री जी में है यह प्रदेश ही नहीं हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व का प्रदेश ही नहीं देश भी इंतजार करेगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बहुत साफ रहना चाहिए आडियालॉजी के हिसाब से बहुत साफ रहना चाहिए। जो हमारे देश का संविधान कहता है उस तरह का आचरण रहना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय यहां कुछ लोग अपने को सेक्यूलर कहना चाहते है। मैं बार–बार कहता हूं एक साफ किरदार वाले लोग अगर अपनी जगह बना पायेंगे तो एक न एक दिन लोग उन्हें पहचान जाएंगे और लोग पहचान रहे हैं कि यह सामने कुछ बात करते हैं और बाद में कुछ बात करते हैं। मेरे पास वह वीडियो सुरक्षित है जिसमें कहा गया कि मुसलमान को हराने के लिए बी0जे0पी0 को वोट करा दिया, तो उस पर मेरे एक–दो भाई बोले, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जब आप बिल्कुल साफ सुथरी विचारधारा और साफ आयडियालॉजी रखोगे तो फिर आपकी तरफ कोई ऊंगली नहीं उठा सकता है लेकिन आज बहुत दिन हो गए इस देश को आजाद हुए। लोग समझ जाते हैं आप कहां जा रहे हैं आपकी विचारधारा किधर जा रही है, आप किन लोगों से ताल्लुकात रखना चाहते हैं यह सब पहचान गए हैं। चुनाव में टिकट दे देना, वोट काटना, लोगों को हरा देना सिर्फ यही आप लोगों का काम है। इसके अलावा आप माइनारिटी और अल्पसंख्यकों के लिए जो बहुत कमजोर हो चले हैं उनका आपने कभी कोई ख्याल नहीं रखा। एक तरफ हमारे साथी लोग बैठे हैं बी0जे0पी0 के लोग, एक शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूं–

बादशाह को अधर्मी कह दिया,

मोहतरम की बात को ठुकरायें क्या ।।

बहुत बड़े नेता ने कहा इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, इंसानियत बड़ा धर्म है, मानवता ही बड़ा धर्म है उसको सताओ मत, अगर सताओगे तो आपके ही बड़े लोग इस तरह की बात आपके लिए कहेंगे। वह अधर्मिता कल भी थी आज भी है और मरने के बाद भी रहेगी। चूंकि यह देश सहिष्णुता वाला देश है इस देश में इस तरह की बातें क्षणिक रहेंगी यह इतिहास हमेशा याद रखेगा कि इस तरह की छोटी बातें जब एक तरफ देश निर्माण की बातें चल रही थीं कुछ लोग इस छोटी मेंटलटी की छोटी आइडियोलोजी की भी बात कर रहे थे। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं मैं सबके लिए यह बात कहना चाहता हूं कांग्रेस ने भी खूब ड्रामा किया दोनों हाथों में लड्डू रखे कुछ नहीं किया हम लोग तो सच्चे आदमी हैं जिनको हम भी मानते हैं वह बेचारे छोटी तादात में बैठे हुए हैं मैं तो सिर्फ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है यह सर्वहारा का बजट है यह सच्चे मायने में समाजवादी सोच वाला बजट है यह सच्चे मायने में सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक स्टेट का बजट है मैं सराहना करता हूं मैं समर्थन करता हूं और उसके साथ–साथ मैं आपसे अपने क्षेत्र की भी कुछ बातें बता देना चाहता हूं। हमारे सामने मेरठ करनाल रोड है हमारे बी0एस0पी0

साथियों की जब सरकार थी तो वह रोड बनना शुरू हुआ किसी को ठेका दे दिया गया ठेकेदार कहीं साउथ का था दीक्षित जी को मालूम होगा उससे इतनी मिठाई मांग ली कि वह छोड़कर भाग गया शायद हीरालाल नाम था। यह रोड मेरे क्षेत्र के बीचों बीच होकर गुजरती है। लोग परेशान हो गये उसके बाद 410 करोड़ की लागत से वह हमने बनवाई दो पुल हमारे यहां बन रहे हैं अपर गंगा कैनाल का पुल और हमारी हिंडन नदी का पुल। मेरा कहना है कि जिसकी जो विचारधारा है वह बताए इधर उधर मत भटकें हमारी विचारधारा साफ है एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक हमारी विचारधारा है उसी तरह का हमारा बजट है। आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

श्री जयप्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं मैं अपने नेता विरोधी दल आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नेता भाजपा से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस प्रदेश का बजट, जो उन्होंने बहुत सी बातों से प्रदेश की जनता को आइना दिखाया था उनको विश्वास दिलाया था। मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में घूम–घूमकर गरीबों को विश्वास दिलाया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी बात करेंगे लेकिन आज इनके बजट भाषण में वह चीजें दिखती हुई नजर नहीं आ रही हैं आज युवा मुख्य मंत्री होने के बावजूद इस पूरे प्रदेश के युवाओं ने बहुत भारी पैमाने पर इनको मत देने का काम किया इन्होंने युवाओं को लुभाया गरीबों को लुभाया तमाम लोक लुभावन बातें इन्होंने कहीं इनकी बातों में आकर लोग अपने को आज ठगा महसूस कर रहे हैं अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि उस बजट भाषण में उसका जिक्र आया नहीं लेकिन आना चाहिए था पूरी प्रदेश की जनता चार साल हो गए आश लगाए बैठी थी कि अब मुख्य मंत्री जी उस बात पर विचार करेंगे जिस बात को उन्होंने पूरे प्रदेश में ढिढोरा पीटा था। गरीब के बच्चों को जो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज तक उन गरीबों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। उस आस में वह जी रहे हैं और गरीब किसान जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, उन्होंने कहा था कि हम उनका कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कर्जा माफ करने का काम नहीं किया है और उन्होंने कहा था कि गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चौरीचौरा शहीदों की धरती है, जहां पर शहीदों ने इस देश को आजाद कराने में जो अहम् भूमिका निभाई है, मैं उस क्षेत्र से आता हूं। वहां की तहसील में अभी जो गेहूं की फसल नष्ट हुयी थी और जो आपदा राहत बटनी थी, आप जांच कमेटी से जांच करा लें, उस तहसील के अन्तर्गत आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है जिनको मुआवजा मिलना चाहिये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिये इस तरह की तमाम बातें कही थीं, उन गरीब परिवार के लोगों के लिये कहा था और एक समुदाय के लोगों को 17 धड़ों में बांटकर इन्होंने कहा था कि 17 जातियों को मैं अनुसूचित जाति में शामिल कराऊंगा। शामिल कराने की बात इन्होंने कही थी। चार

साल बीत गये, लेकिन अभी तक इन जातियों को अनूसूचित जाति में शामिल कराने का काम नहीं किया है। पिछली सरकारों ने जो व्यवस्था इन 17 जातियों के लिये बनाई थी उसको भी इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बालू का खनन, तालाब के पट्टे वरीयता क्रम में निषाद समुदाय को देने का काम किया था, उसको इन्होंने समाप्त करने का काम किया है और जब आपदाएं आती हैं तो मछुआ समुदाय के लोगों को पूरे प्रदेश में उस आपातकाल में लोगों के बचाव हेतु बुलाया जाता है, इन्होंने उनको भी ठगने का काम किया है और मछुआ समुदाय के आवास विहीन लोगों को जो आवास मिलते थे, उसको भी इन्होंने समाप्त करने का काम किया है और इन्होंने कहा कि अब मैं प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावित क्या करते हैं, इन्होंने बताया कि प्रदेश को केंद्र की राशि नहीं मिलती है इसलिये मैं इन्हें आवास नहीं दे पा रहा हूं। आज प्रदेश की जनता और इस समुदाय के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम क्षेत्रों में हालात बहुत खराब हैं। इन क्षेत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने पुल और ओवरब्रिज बनाने की बात कही। चौरी–चौरा शहीदों की धरती है, वहां पर भी मैंने चार साल तक लगातार निविआवा ढाला के पास रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की मांग की, देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया जो रोड जाती है, हमारे तमाम साथी बलिया से, गोरखपुर से और पूरे पूर्वांचल के लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, मैंने नियमों के अन्तर्गत उस ओवर ब्रिज की मांग की, लेकिन आज तक उस पर ध्यान देने का काम नहीं किया गया है। चौरी–चौरा में जो शहीद स्मारक बना है, वहां की सभी मूर्तियां जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, वहां पर आने वाले पर्यटकों के लिये एक भी गेस्टहाउस नहीं बना है और दूरदराज से जो लोग उस स्मारक को देखने के लिये आते हैं, उनको किसी तरह की सुविधाएं वहां पर नहीं उपलब्ध हैं। पूरी तहसील के अन्तर्गत एक भी राज्य सरकार का अतिथिगृह नहीं है, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में कानून–व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। चौरी–चौरा थाने का थानाध्यक्ष अपने गुंडों को बुलाकर सुबह से शाम उन्हें अपने साथ बैठाकर शराब पिलाने का काम करता है। वहां पर ऐसे कुछ सिपाही तैनात हैं जो गरीबों को बेफिजूल में परेशान करते हैं और उनसे धन उगाही करने का काम करते हैं, लोगों को सताने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसने का काम सरकार नहीं कर रही है। आज बड़े भारी पैमाने पर यह सारी व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे क्षेत्र में तमाम सारी सड़कें ऐसी हैं, मैंने तमाम सड़कों के बारे में याचिका लगा करके और कई नियमों में भी लिख करके दिया, लेकिन उन सड़कों का भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ। हमने घटुली घाट, फरेंद नाले पर एक पुल के लिए जो बहुत बड़ी ग्राम सभा है, जहां की लगभग 20 हजार से ऊपर की आबादी है। ऐसे ग्राम सभा के लोगों को बाजार तक आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने कई बार लिख करके दिया कि घटुली घाट पर अगर एक पुल बन जाता तो वहां के लोगों को आने–जाने की व्यवस्था हो जाती लेकिन आज तक यह बातें मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में नहीं रखी गयीं। अधिष्ठाता

महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, तमाम इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने का काम सरकार कर रही है। गुण्डे, माफियाओं को खुलेआम घूमने के लिए खुली छूट दे रखी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 19–11–2015 को मेरे आवास पर कुछ गुण्डों ने हमला किया। गुण्डों ने जब हमला किया, पहले तो उन लोगों ने फोन पर धमकियॉ दीं, यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैंने कई बार सरकार को लिख करके कई बार इस बात से अवगत कराया, गृह विभाग को मैंने अवगत कराया, उन्होंने फोन पर भी धमकियॉ दीं, लेकिन हमारी उस बात को नहीं सुना गया और हमारे घर पर चढ़ कर के 19–11–2015 को समय 1.00 बजे तोड़–फोड़ की और 06 मोटर साइकिलें कूंच दी। वह लोग कम से कम 70–75 की संख्या में आए थे। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनको तमाम धाराओं में निरूद्ध किया गया लेकिन आज तक सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हुआ। मुकदमा संख्या–466/2015 के अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 452, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आज तक न तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और न ही किसी प्रकार की कार्यवाई हुई। आज भी ये गुण्डे–माफिया बेलगाम घूमने का काम कर रहे हैं। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश की जनता में इस बात की चर्चा है कि यह सरकार कानून–व्यवस्था में फेल हो गयी है, कानून–व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गयी है, आम आदमी किसी तरह से अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। आज पूरे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है और सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है और समय आने पर इस प्रदेश की जनता जवाब भी देगी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको इस बात से अवगत कराते हुए अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री जय प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। बजट तो हमेशा अच्छा ही होता है, विकासशील होता है और गतिशील होता है। कोई भी बजट जो इस सदन में प्रस्तुत होता है वह अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज मुख्य मंत्री जी ने अपना पांचवा बजट प्रस्तुत किया और लखनऊ के आसपास के बहुत सारे काम हुए। हम 250 कि0मी0 दूर नेपाल सीमा पर रहते हैं, जनपद सिद्धार्थनगर में। हम दो–तीन सुझाव देना चाहते हैं। लखनऊ से आगरा 06 लेन का एक्सप्रेस–वे जो अपने संसाधनों से सरकार बना रही है, बहुत सराहनीय काम कर रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसमें कोई दोराय नहीं है। उस लम्बाई में जितने भी गांव आते हैं, वह सब विकसित हो जायेंगे। परन्तु हम तो ढाई सौ कि0मी0 दूर रहते हैं। हम इतनी बड़ी आशा भी नहीं करते हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं वह मरम्मत हो जायें। जिनके लिए हम चार साल से प्रयासरत हैं। परन्तु आज तक एक पैसा भी उस पर नहीं दिया गया है। बार–बार

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंजीनियर से पूछने पर, शासन से पूछने पर यही बताया जाता है कि इस क्षेत्र के लिए उतनी धनराशि फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

आप इधर आ जाइये।

श्री जय प्रताप सिंह–

आपकी कृपा होगी तो उधर ही से बोल लेंगे। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में मण्डी परिषद द्वारा बहुत सारी सड़कें बनी हुयी हैं और अभी बहुत सारी तारीफ हमने मा0 मुख्य मंत्री जी की भी सुनी। मैं चार साल में एक ही बार उनके यहां गया था और मण्डी परिषद् से सड़कों की मरम्मत के लिए मैंने उनको दर्खास्त दी थी। एक साल हो गया परंतु उस पर आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया। तो हम तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि इतने सारे काम आप लोग कर पायेंगे परंतु ग्रामीण क्षेत्र की यह सड़कें मरम्मत हो जायें तो बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा काम सरकार ने किया है। लोहिया अस्पताल, सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल में बहुत सारी सुविधा दी है। मेडिकल जांचें फ्री कर दी हैं परंतु सिद्धार्थनगर जनपद में जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें करीब 70 डाक्टरों की कमी है। अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद पड़े हुए हैं या एक–आध कम्पाउंडर के द्वारा चल रहे हैं। उसी तरह हमारा जिला संयुक्त चिकित्सालय है। वहां भी पूरी तरह से डाक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, सफाई कर्मचारी की कमी है। इसलिए लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। विद्युत उत्पादन के बारे में अभी दो दिन पहले ही यहां एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की उपलब्धियों पर बात हुयी थी। 4500 मेगावाट का उत्पादन 2012 में और 3556 मेगावाट का उत्पादन आज के दिन जो यहां पर बताया गया था। हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। 08–10 घण्टे का हम अपना बर्दाश्त कर लेते हैं। हम 08–10 घण्टे के आदी हो गये हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहां माघ मेला जो प्रतिवर्ष चलता है उसके कारण से और हमारे मा0 अध्यक्ष जी के कारण से वह 08–10 घण्टा को बढ़ाकर 12 घण्टा कर दिया जाये जो बड़ी बात है। हम तो उससे बड़े संतुष्ट थे कि हमको कम से कम 12 घण्टे बिजली मिले। अक्टूबर में जो आप लोगों ने कहा है कि 18–20 घण्टा या 24 घण्टा देंगे, अलग–अलग श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र में और नगर में, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कितना आप उसमें दे पायेंगे। प्राथमिक शिक्षा में आज भी वही स्थिति है जो लगभग सभी क्षेत्रों में होगी। बहुत सारे स्कूल आज भी बंद हैं। न्यायालय की वजह से तमाम नियुक्तियां हुयीं तमाम नियुक्तियों पर रोक लगी। और आज भी वह पूरा मामला उलझन में पड़ा हुआ है। आज बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय वहां भी बंद हैं। लखनऊ में गोमती नदी के तट का सुंदरीकरण, यह बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद यह अहमदाबाद में साबरमती के तट पर जिस तरह से वहां के घाटों का सुन्दरीकरण हुआ था। शायद वहां पर जाकर लोग उसको देखे होंगे और उसी का एक डिजाइन लेकर यहां पर बनाना शुरू कर दिये हैं। अच्छी बात है। लखनऊ के लिए एक

अच्छा मनोरंजक पाक्र भी वहीं पर बन जाएगा। परंतु हम बाढ़ से प्रभावित लोग हैं। हमारे यहां बंधे बहुत हैं। अपूर्ण स्थिति में भी है। बने हैं तो जीर्णशीर्ण है और वहां पर मरम्मत के काम के लिए एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। यह पूरा क्षेत्र नेपाल से निकली हुयी नदी का दोआबा के अंदर हम लोग रहते हैं। और पिछले पांच सालों में आज तक उसमें कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। कानून व्यवस्था पर तो मान्यवर, यहां पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और बहुत सारी बातें आई हैं, मेरा मानना है कि कानून–व्यवस्था पर मात्र एक काम अगर सरकार करे कि अपनी पुलिस की ट्रेनिंग में कुछ बदलाव लाये, आपने 1090 की स्थापना की, आपने 100 नम्बर डायल का किया, उसका जो रिसपान्स आता है, वह उतनी तेजी से नहीं हो पाता और ग्रामीण क्षेत्र में जो सिपाही आपके यहां पर हैं वह आज भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं जनता से, जैसे पहले भी करते थे, तो कहीं न कहीं उनकी ट्रेनिंग में तमाम कमियां हैं, सरकार उसको आगे देखे और उन कमियों को ठीक करे। मान्यवर, यह सब बिन्दु को लेकर मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, उसमें इन बिन्दुओं पर थोड़ा गौर करे और उनका जो आंकड़ा है, क्योंकि मूलतः बजट को बहुत आकर्षक बनाया जाता है, आंकड़ों के खेल से बनाया जाता है। अभी हमारे मा0 सदस्य डा0 अग्रवाल साहब ने बताया भी था कि किस तरह आंकड़ा जो दिख रहा है अभी 14 परसेण्ट जो अधिक दिख रहा है पिछले साल से, वह वास्तव में मात्र 5–7 परसेण्ट की ही बढ़ोत्तरी है और मंहगाई को लेकर अगर देखा जाय, तो उससे भी कम आता है, सही मायने में सरकार अगर वित्तीय प्रबन्धन करें तो वह आगे चलकर आपके ही फायदे के लिए होगा। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इन बातों पर ध्यान देगी, तो मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा अगला बजट जो पेश करने की बात हो रही है, शायद वह अगला बजट भी पेश कर पायेंगे, अगर इन सभी बातों पर भी गौर करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद्।

'श्री रघुराज सिंह शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2016–17 का जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सरकारें तो बहुत आईं, लेकिन जब–जब समाजवादी सरकारें आई हैं, आम जनता के हित में किसानों के हित में जो फैसले लेने का काम किया, वह किसी भी सरकार ने नहीं लेने का काम किया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा, लोगों की धारणायें तमाम थीं कि नौजवान मुख्य मंत्री जी हैं, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो फैसले लेने का काम किया है, वह इतिहास में दर्ज होने का काम होगा। तमाम हमारे साथियों ने सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बताने का काम किया है, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में लिया जाय, हिन्दुस्तान में कोई सरकार नहीं है जिसने सिंचाई मुफ्त करने का काम किया हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मा0 मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई चाहे नहरें हों, चाहे बम्बे हों, सरकारी ट्यूब्वेल की सिंचाई मुफ्त

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का काम किया है। इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों को हुआ है, उनसे पूछिये जिनके सामने दिक्कतें थीं, परेशानी थीं। जब किसानों के सामने ओलावृष्टि हुई, तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने बिना देरी किये हुए पूरे प्रदेश में किसानों को राहत देने का काम किया और इसके लिए किसान बधाई भी देने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भी मौके पर चेक बांटने का काम किया है, तो लोगों ने बधाई देने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, सबसे बड़ा लाभ किसान बीमा जो चालू की गई है, उसका है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ट्रैक्टर–ट्राली पलट गई, उसमें 13 लोग खतम हो गये। उसमें सबसे ज्यादा दलित परिवार के लोग थे, मैं खुद उनके परिवार के लोगों को चेक देने के लिए गया, उसमें तीन महिलाएं ऐसी थीं, जिनके पति पहले खतम हो चुके थे दुर्घटना में, महिलाओं के नाम जमीन आ चुकी थी, किसान बीमा का उनको लाभ मिला, उनके परिवार में तीन–तीन बच्चियां थीं, कोई उनके परिवार को आगे चलाने वाला नहीं था, उस गांव में जब हमने चेक दिया, उनके परिवार को जब हमने पांच–पांच लाख रुपये का चेक देने का काम किया, तो हमें भी खुशी हुई और मैं समझता हूं कि पूरा गॉव दलित परिवार का था ।....

(इस समय 04 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पूरे गांव ने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देने का काम किया। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया है। आज जो 5–5 लाख रूपये मिले हैं, कम से कम उनसे बच्चियों की शादी कराने का काम किया है। यह काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। एक के लिए नहीं किया है। यह उदाहरण दिया है और मैं समझता हूं कि यह लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने काम करने का काम किया है। सिंचाई के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में सोलर ट्यूबवेल देने के लिए घोषणा की है। बिजली की समस्या है, माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं, उन्होंने सोलर पैनल दे कर ट्यूबवेल चलाने की घोषणा की है। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर ट्यूबवेल देने की बजट में घोषणा कर दी है। हर वर्ग को लाभ देने का काम किया है, हर धर्म के लोगों को लाभ देने का काम किया है। यह सरकार किसानों की सरकार है। आपको 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस में, जो हमारे विधायकगण हैं, उनके द्वारा प्रशंसा सुनता हूं। रास्ते में जब जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है कोई सदस्य नहीं होता है लेकिन 108, 102 पर फोन कर देते हैं तो, एम्बुलेंस अस्पताल ले कर जाती है और भर्ती करवा देती है। तो वह बधाई देते हैं। दवाई फ्री देने का काम किया है। खून की जांचें, जितनी तरह की जांचे होती है, वह निःशुल्क करने का काम किया है। अल्ट्रासाउंड निःशुल्क करने का काम किया है। पिछली सरकार में देखिए, पहले सरकारी अस्पताल में लोग जाते नहीं थे, आज वहां भीड़ लगी रहती है। वह हकीकत में बधाई देने का काम कर रहे हैं। यह आने वाला समय बतायेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः आएगी। जनता सब देख रही है। अभी मैं आ रहा था, आप ट्रेन में बैठिए तब लोग उसकी प्रतिक्रिया देने का काम करते हैं, बधाई देने का काम करते हैं। हमारी सरकार के माननीय हमारे नेता श्री आजम खां को आपने देखा, किस तरह के तमाम भाजपा के लोगों ने आरोप लगाने का काम

किया। बेगुनाह है साथियों, आप उनकी छवि को जानते हैं, पूरा हिन्दुस्तान जानता है, लेकिन आप अंदर झांक कर देखेंगे तो हर व्यक्ति उनको प्रशंसा देने का काम करता है, उनको बधाई देने का काम करता है। चाहे सत्तापक्ष का हो, या विपक्ष का, उनके पास जो व्यक्ति जाने का काम करते हैं, वह सबका काम करने का काम करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी के पास हमारे विपक्षी जो विधायक लोग हैं, जब उनसे मिलने को जाते हैं, तो एक बार हमारी बात नहीं सुनते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी आप लोगों को ज्यादा तवज्जों देने का काम करते हैं। आपकी बात को सम्मान देने का काम करते हैं। आपकी मुख्य मंत्री भी रही हैं। कोई मिल नहीं सकता था, आप लोग नहीं जा पाते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे, पंचम तल पर लोग जा नहीं पाते थे। यह हमारे नेता हैं। हमारे माननीय नेता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप जानते हैं उन्होंने कभी भी भेदभाव से काम नहीं किया है। हर वर्ग को लाभ देने का काम किया है। एक्सप्रेस–वे देने का काम कर रहे हैं, लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे, लखनऊ–आजमगढ़–बलिया समाजवादी एक्सप्रेस–वे तमाम योजनाएं चलाने का काम किया है। पूरे प्रदेश की सड़कें बनाने का काम हो रहा है। कामधेनु डेरी योजना, मिनी कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना, यह योजनाएं चलाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। मुख्य मंत्री जी को बधाई इस वजह से दूंगा, अगर यह डेरी योजना नहीं चलाते तो शायद आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता। इस योजना की वजह से आपको शुद्ध दूध मिलने लगा है। कितनी मिलावट हो रही थी। आज दूध का उत्पादन बढ़ा है केवल इसी डेरी की वजह से बढ़ा है। कम से कम आपके बच्चों को शुद्ध दूध देने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। मेट्रो लाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो लोग आज मुख्य मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। किस क्षेत्र में बधाई देने का काम न किया जाये लेकिन साथियों, हमारे साथ जब अलग से बैठ कर आप बधाई देने का काम करते हैं लेकिन सदन में आप किस तरह की चर्चा करते हैं, वह सब ऊपर वाला देखने का काम करता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा। इतने सीधे, इतने सरल कभी भी कोई मिल लेता है। हाउस के अंदर लोग उनको मिल लेते हैं। अपनी बात कह लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सरल स्वभाव के हैं, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि ऐसा बजट पेश करने का काम किया है किसानों के हित में है, अल्पसंख्यकों के हित में है, छात्रों के, नौजवानों के हित में बजट पेश करने का काम किया है और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हुआ और बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

डा0 मो0 अयूब–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट पर हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष जी, बजट का मुख्य मकसद प्रदेश की जनता का विकास है और सरकार का कार्य बिना भेद–भाव के समाज के सभी वर्गों का विकास करना है। यह

बजट करीब 3 लाख 47 हजार करोड़ का बजट है और समाज के उन वर्गों का जो सबसे कमजोर हैं, उसका इस बजट में पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। बहुसंख्यक समाज का अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग जिसकी आबादी 38 परसेण्ट के करीब है और मुस्लिम वर्ग जिसकी आबादी 20–22 परसेण्ट के करीब है, उसके विकास के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और जब तक बजट में व्यवस्था नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। इन वर्गों को जो कमजोर हैं, जो अपनी आवाज उठा नहीं सकते, अगर वे समाज में अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। अगर वे अपने प्रतिनिधि को इस विधान सभा में भेजते हैं तो मुझें नहीं पता कि वह मुख्य मुद्दों को छोड़ करके जिसके लिए समाज ने उनको चुनकर के भेजा है उनके विकास के बारे में बात न करके सिर्फ अपनी पार्टी के बखान की बातें करते हैं जिससे उनका विकास नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूं कि पिछले बजट में मुसलमानों के लिए विकास में 15 परसेण्ट मात्रांकित किया गया था और निषाद समाज के लिए 7.5 परसेण्ट मात्रांकित किया गया था। उससे न तो मुस्लिम समाज को और न ही निषाद समाज को 01 परसेण्ट का फायदा नहीं हुआ है। चाहे तो आप जांच करा लें, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट में उस मात्रांकित का भी नाम नहीं है। पता नहीं वह बजट में है, उसके लिए अभी वह नियम है कि नहीं है। मगर 2016–17 के बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर ये समाज में अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी मॉग रखते हैं तो कसरवल काण्ड मैं आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं। कसरवल काण्ड में निषाद समाज के कमजोर वर्ग ने सिर्फ 4 परसेण्ट जिनकी आबादी है 8 परसेण्ट, उस समाज ने सिर्फ 4 परसेण्ट के लिए अपनी आवाज उठाई, कोई रेल नहीं रोकी, कहीं कुछ जलाया नहीं। हमारी विधान सभा के पास में उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पर गोलियां बरसाई गईं। आरक्षण की मॉग कर रहे हैं तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पर गोलियॉ चलाई जा रही हैं। उसमें अखिलेश निषाद गोलियों से मार दिया गया, सरकार ने एनाउन्स किया कि उसके आश्रित को 10 लाख रुपया मिलेगा लेकिन अभी तक उसमें एक पैसा भी उस समाज को, उसके परिवार के लोगों को नहीं मिला है। हमारे सन्तकबीर नगर जिले के एस0पी0 के गनर ने लोगों पर गोलियॉ चलाईं। उसके बारे में सरकार ने आश्वासन दिया कि उसके खिलाफ जांच होगी। निषाद समाज के जितने लोग थे, चाहे मोटर साइकिल से थे, चाहे गाड़ियों से थे सारी जला दी गईं। सरकार ने आश्वासन दिया कि उसकी जांच करा करके उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी पर इसके बदले में उनको मिला क्या। इसके बदले में सिर्फ यह मिला कि कम से कम 4 महीने तक निषाद समाज का कोई मर्द हमारे सन्तकबीर नगर जिले में, गोरखपुर जिले में अपने घरों में नहीं जा सका। पुलिस के छापे के डर से और सबके खिलाफ मुकदमे हो गए, 302 के मामले में अनगिनत लोगों के खिलाफ मुदकमे हो गए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जितने वादे किए थे विकास के लिए, वे तो पूरे नहीं किए। अति पिछड़े समाज की 17 जातियों से इन्होंने वादा किया कि हम उनको दलित में डाल देंगे, मगर आपकी जानकारी के लिए और

सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये 4 अतिपिछड़ी जातियॉ हैं जिसमें मांझी, धनगर समेत 4 जातियां हैं, उनको अभी तक नहीं किया जबकि केन्द्र सरकार से उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र देने के लिए निर्देश हैं। मगर इन जातियों को अभी तक प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने मुसलमानों के बारे में बात करना चाहता हूं। मुसलमानों के बारे में कहना है कि सरकार वोट लेने के वादे करते हैं। यहां पर धार्मिक उन्माद भड़काने वाले चाहे विपक्ष के लोग हो वह चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद भड़के मगर विकास के लिए जो भी एजेण्डे हैं, उसको सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर सरकार गंभीर रहती तो वर्ष 2007 में सच्चर कमेटी ने यह बताया कि मुसलमान, दलितों से भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से पिछड़ गया है। अध्यक्ष जी, मैं वो बात रखूंगा जो किसी के द्वारा सदन में नहीं रखी गई है और समाज के उन वर्गों की बात रखूंगा जिसकी आवाज सुनना और उस पर अमल करना, समाज के लिए सबसे जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

वह तो आप बाहर सुनाते ही हैं। समय का ध्यान रखें।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट पर ही आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय आबादी के हिसाब से आरक्षण करने का वादा इस सरकार ने किया था चाहे वह सरकारी नौकरी हो, चाहे वह तालीम हो, कहीं पर भी आजतक आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं किया है। मैंने सवाल भी लगाये सरकार ने जवाब दिया कि इसके बारे में सरकार का कोई विचार नहीं है, केवल वोट लेने के बात करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है 40 प्रतिशत बच्चे भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं और ये सभी बच्चे या तो ये मुसलमान के हैं और या तो वह अति पिछड़े और दलित समाज के हैं। सरकार यह घोषणा करती है कि 1 साल से 14 साल के बच्चों को मिड–डे–मील देगी, मुफ्त शिक्षा देगी, मगर जो सबसे गरीब बच्चा है मुसलमान का वह मदरसे में पढ़ता है और अति पिछड़े और अति दलित समाज का जो सबसे गरीब बच्चा है वह सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। मुसलमानों को, मैं बार–बार यह कह रहा हूं कि जो सबसे कमजोर है, जहां बच्चे का विकास होना है, तो उस बच्चे के विकास के लिए तालीम के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जवाब दिया कि केन्द्र सरकार से जो निर्देश आता है, उसके हिसाब से वह मिड–डे–मील देती है, बस्ते देती है, किताब–कॉपी देती है, घर बनवाने के लिए पैसा देती है। अगर केन्द्र सरकार यह विकल्प नहीं रखती तो प्रदेश सरकार के पास अख्तियार है कि जो कमजोर लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, उनके लिए सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

अब समय का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा समय हो गया है।

डा0 मो0 अयूब–

बिल्कुल मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का बच्चा जो सबसे गरीब है। इस प्रदेश के विकास में वह सहयोग देना चाहता है और वह कुपोषण का शिकार है, वह कैसे सहयोग दे सकता है फिर मुसलमान का विकास कैसे हो सकता है इसलिए विकास के लिए जरूरी है कि कुपोषण दूर किया जाए, उसको तालीम बेहतर की जाए और जहां सबसे गरीब बच्चा है, उस पर फोकस सबसे ज्यादा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत–सारे विधायकगण, बहुत सारे माननीय विधायक हमारी बात पर बहुत हंसते हैं। 80 प्रतिशत मुसलमान गोश्त खाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिए। 80 नहीं 100 प्रतिशत खाते हैं, अब उससे क्या मतलब।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुन लें उसके बाद आप निर्णय दें, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप तो यह पिछले सत्र में भी बोल चुके हैं।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि 80 प्रतिशत मुसलमान गोश्त खाता है। वह दो सौ रूपया और डेढ़ सौ रुपया किलो दाल नहीं खरीद सकता। वह 10–20–40 रुपये किलो सब्जी नहीं खरीद सकता। वह एक किलो गोश्त लेता है मैं सही बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक किलो गोश्त वह 120 रुपये किलो में लेता है तो सुबह भी खाता है, दिन में भी खाता है और रात में उसी को खाता है पूरा परिवार खाता है, मगर वह दाल से नहीं खा सकता। मगर यह गोश्त ही है जो कुपोषण दूर करता है, तो जो कुपोषण दूर करने का है, जो मुसलमान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज तक कभी इस पर चर्चा नहीं होती। यहां पर जितने हमारे माननीय विधायकगण हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग मांसाहारी होंगे, मांस खाते होंगे तो अगर स्लाटरहाउस बेहतर नहीं हैं तो इनको शुद्ध मांस कैसे मिलेगा, स्वच्छ मॉस कैसे मिलेगा अध्यक्ष जी, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कैसे मिलेगा, इस बजट मे स्लाटर हाउस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से शुगर इण्डस्ट्री में लेवी से शुगर ली जाती है, गोश्त इण्डस्ट्री मे लेवी लेकर और सस्ते दाम पर गरीब मुसलमानों को देना मै समझता हूं यह जनहित में है, यह सबसे जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपने कह दिया आपकी बात आ गयी।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट की आम चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का 2016–17 वित्त वर्ष का बजट 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अशासकीय विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय देना माननीय मुख्य मंत्री जी का एक क्रान्तिकारी कदम है और जैसा हमारी सरकार कहती है वैसा हमारी सरकार ने कर के दिखाया इसके लिए मै समाजवादी सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, यह किसान वर्ष है और साथ ही युवा वर्ष भी है, समाजवादी युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी और खास तौर से 12वीं पास जो हमारे छात्र होते हैं उनके लिए कैरियर काउन्सलिंग की व्यवस्था सरकार ने की है यह भी एक बहुत ही दूरगामी कदम है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विधान सभा सोरांव मे तथा गंगा पार में एक भी आई0टी0आई0 नही थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 करोड़ रुपये की लागत की एक आई0टी0आई0 स्वीकृत की है, उसके लिए भी मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र विधानसभा सोरांव में लगभग 4 से 5 करोड़ रूपये की लागत से माडल स्कूल बनकर तैयार हो गया अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सरकार को यह माडल स्कूल हमारी सरकार पी0पी0पी0 माडल पर चलाना चाहती है, जो अद्यतन जानकारी है कि कोर्ट ने भी उसकी अनुमति प्रदान कर दी है अतः आग्रह है कि शीघ्र ही वह पी0पी0पी0 माडल पर चलाई जाये ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसमें बहुत गुणात्मक सुधार हो सके। अध्यक्ष जी लगभग 2–2 सब स्टेशन 33/11 के चार–चार, पांच–पांच करोड़ की लागत के हमारे क्षेत्र मे बनाये जा रहे हैं। एक सोरांव में बन चुका है, दूसरा मऊआइमा टाउन एरिया के लिए प्रथक सब–स्टेशन बन रहा है और अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात यह है कि टाउन एरिया मऊआइमा में जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है वहां के लिए स्वतंत्र फ्रीडर के प्रस्ताव दिये गये हैं। मै आपके माध्यम से आगृह करूंगा कि वह प्रस्ताव शासन मे लम्बित है शीघ्र ही वह स्वतंत्र फ्रीडर स्वीकृत हो जाये तो उस क्षेत्र का समग्र औद्योगिक विकास हो सकेगा। हमारे नेता माननीय आजम साहब बैठे हुए हैं, आज मैं इस सदन की तरफ से अपने सोरांव विधान सभा के एक–एक व्यक्ति की तरफ से अपने मऊआइमा टाउन एरिया के एक–एक बाशिन्दों की तरफ से मै उनका हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारे टाउन एरिया मऊआइमा का जिस तरह से उसका समग्र विकास हुआ है कोई भी सड़क नही बची है जो चमक नहीं रही है, कोई भी गली नहीं बची है जिसका विकास न हुआ हो। गलियां ढूंढ़ी जा रही हैं कि अगर कोई बची हो तो उसका भी विकास कर दिया जाये। दो–दो पेय जल की टंकिया स्वीकृत होकर बाका जलालपुर और मऊआइमा में लगभग टंकी निर्माण भी शुरू हो गया है। जिस तरह से उन्होंने टाउन एरिया का समग्र विकास किया है मैं हृदय से

आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। यह चीजें इसलिए भी बता रहा हूं कि हमारे विपक्ष के साथी एक सिरे से बात कह देते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है हम तो अपनी एक विधान सभा की बात कर रहे हैं। प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी मेट्रो को न सिर्फ कहते बल्कि साकार रूप दे रहे हैं और अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि शीघ्र ही अक्टूबर नवम्बर में मेट्रो रेल शुरू होने से लखनऊ के यातायात में और उत्तर प्रदेश के यातायात व्यवस्था मे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मे क्रान्तिकारी सुधार हो सकेगा। मान्यवर, डायल 100 की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हमारे इलाहाबाद में चाहे ट्राफिक सिस्टम हो, चाहे पुलिसिंग सिस्टम हो उसमें भी क्रान्तिकारी सुधार किया गया है। हर चौराहे पर स्कार्पियों और इनोवा जैसी अत्याधुनिक गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जैसे ही कोई घटना ईश्वर न करे, होती है तत्काल वह पहुंचती हैं और तत्काल उनका निदान होता है। 1090 से अब तक 3 लाख 43 हजार महिलाओं की शिकायतों का निवारण हो चुका है। क्या यह हमारी माताओं बहनों की अस्मिता को बचाने का कार्य नहीं किया गया है क्या यह कार्य बेहतर नहीं है। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी और अपनी सरकार को ऐसे संवेदनशील कार्य के लिए मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इलाहाबाद में गंगा नदी पर एलीवेटेड पुल के लिए ढ़ाई सौ करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था की गयी है मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इलाहाबाद के लिए एक इंडिपेन्डेन्ट स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है साथ ही इलाहाबाद को मेट्रो रेल निर्माण हेतु के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट की भी व्यवस्था की गयी है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं मान्यवर, मुझ जैसे नये सदस्यों के लिए पूरा 10 मिनट समय मिल जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उमरन ताल ड्रेन की समस्या जिस कारण जल प्लावन हजारों एकड़ क्षेत्र में हमारे यहां होता था इसको लेकर के पिछले 15 साल से सैकड़ों गांव के किसान प्रभावित थे। उमरन ताल ड्रेन की न केवल एक करोड़ 22 लाख की लागत से व्यापक सफाई हुई है बल्कि इधर एक दो वर्ष से बहुत अतिवृष्टि नहीं हुई मगर जब अतिवृष्टि होती है तो अब एक भी बिस्वां जमीन पर कहीं पर भी पानी नहीं रुकता है और पूरी तरह से वह बहकर गंगा में प्रवाहित हो जाता है। मैं अपने सिंचाई मंत्री जी को और सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में दो दो स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं एक होलागढ़ ब्लाक के सांगीपुर में और एक बसदेइया के मऊ–आइमा ब्लाक में इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में जो धनराशि का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है किसान भाइयों को चाहे वह कृषक बीमा का चेक हो, चाहे वह ओलावृष्टि का चेक हो, चाहे वह कृषि यन्त्रों पर जो भी 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है यह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर योजना बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। हमारे क्षेत्र में सहित सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को सदन में रख देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में कब्रिस्तान की ब्यापक पैमाने पर चहारदीवारी बनाई जा रही है और अभी मऊ आइमा टाउन एरिया में शमशान घाट के लिए 11 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं आग्रह करूंगा कि उसमें कुछ बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करें। इसके अलावा हमारी सरकार 77 और साथ ही 25 और सांस्कृतिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर ले रही है मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से अधिक मदरसों को भी अनुदान सूची में लिया गया है। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, अल्पसंख्यकों का योजनाओं में मात्राकरण चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे लोहिया ग्राम हो, चाहे हैण्डपम्प हो, चाहे कोई भी योजना हो उसमें पूरी तरह से स्पष्टतः 20 प्रतिशत मात्राकरण हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए हो रहा है यह मै नहीं कह रहा हूं जाकर के आप प्रशासनिक स्तर पर कागजों में आप देख सकते हैं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में उतरौलिया–फैजाबाद–इलाहाबाद मार्ग है जो एनएच है वह बहुत ही खराब है। हम अपने एन0एच0 के चीफ से आग्रह कर चुके हैं कृपया वह बनाया जाय। साथ ही स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत पिछली सरकार में किरांव, सिसई एवं चकअफजलपुर उर्फ पूरे लीला में इन तीन गांव में बड़ी–बड़ी पेयजल टंकियां आधी अधूरी निर्मित हैं, कृपया उनको बनवाने का काम किया जाय। हमारा क्षेत्र मऊ–आइमा और बहरिया को डार्क जोन घोषित किया गया है। अतः जल स्तर बढ़ाने के लिये मनसइता नदी पर 13 चेकडैम के प्रस्ताव भी शीघ्रताशीघ्र स्वीकृत किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिवगढ़ में लघु मण्डी की मांग की है, वो भी शासन स्तर पर लम्बित है, अगर वह स्वीकृत हो जाती है तो गंगापार जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा लखरावां में जो पालीटेक्निक कालेज प्रस्तावित किया है, वह भी शासन स्तर पर लम्बित है। यदि यह स्वीकृत हो जाये, तो क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर श्री आजम खां साहब यहां पर बैठे हुये हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारी सुना करिये और हमें अपनी सुनाया करिये, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और यह बी0एस0पी0 के लोग तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यापारी हैं अब वो तो राजसत्तात्मक संस्थाओं में यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा, लोकदल और समाजवादी पार्टी का जनसेवा से वास्ता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का यह आखिरी बजट है और 16वीं विधान सभा का पांचवा बजट है। कानून–व्यवस्था, बिजली, पानी पर हमेशा शोर होता रहा, लेकिन सरकार उसमें कोई आमूल–चूल परिवर्तन नहीं कर सकी। अभी किसान वर्ष की बात कही गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का पैसा उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन की लापरवाही से किसानों को पैसा नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि हमारी बातों को सुझाव के तौर पर ही मान लें। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण प्रतिभाओं को युवाओं का वर्ष कहा गया है। किसी भी ग्राम पंचायत लेवेल पर, न्याय पंचायत लेवेल पर या ब्लाक लेवेल पर कोई स्टेडियम की बात इस बजट में नहीं कही गई है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दस वर्ष से इण्टर कालेजों में बीस फीसदी भी अध्यापक नहीं हैं और राजकीय इण्टर कालेजों में तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी प्रिन्सिपल नहीं है और इस बजट में उसकी बात नहीं कही गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पेंशन में दोगुनी वृद्धि करने का काम सरकार ने किया है। मान लीजिये कि चालीस हजार पेंशन थी तो उसे बढ़ाकर लाखों कर दी गई है, पर कुछ पात्र लोग जो पुरानी सरकारों के टाइम से बीसों साल से पेंशन ले रहे थे, सूचना के अभाव में वह फार्म नहीं भर पाये, उन पात्र लोगों के लिये आप काम करिये। माना कि उसकी व्यवस्था के लिए सरकार ने धन बढ़ाया है, 300 को 400 और 500 किया है, लेकिन जो लोग छूट गये हैं, उनके लिए पुनः फार्म भरने की बात इसमें नहीं की गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिजली में सुधार हुआ है। 26 साल में हमारी सरकार के जाने के बाद किसी भी सरकार ने एक भी मेगावाट बिजली बनाने का काम नहीं किया है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने कई हजार मेगावाट बिजली के प्रोडक्शन की शुरूआत की है अथवा इसमें काम चालू हुआ है, लेकिन सप्लाई में और कहने में बहुत अंतर आ गया है। सप्लाई की व्यवस्था में लालफीताशाही हावी है, कहते कुछ हैं और होता कुछ और है। बिजली कितनी पहुंच रही है, उसके बारे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, टूटी सड़कों के बारे में अभी हमारे विधायक, बस्ती कुछ भेदभावपूर्ण रवैये के बारे में कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का तो पूरा प्रदेश है। ग्रामीण सड़कों के टूटे होने के बारे में ई0एन0सी0 और प्रमुख सचिव का रुझान सकारात्मक नहीं है। विशेष तौर पर विपक्ष के विधायकों के साथ। माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के लफड़े और कभी दूसरी बातें आज प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, काफी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। साथ में आज गधे, सुअर, पशु स्कूलों में घूम रहे हैं, बाउण्ड्रीवाल की व्यवस्था की बात या उनके भराव की बात बजट में नहीं कही गई है। अध्यक्ष जी, आज पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश की है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ी जनसंख्या है। उत्तराखण्ड में साढ़े तीन करोड़ रूपये क्षेत्र विकास निधि का हो सकता है, एक लाख और अस्सी हजार इसमें विधायक निधि को बढ़ाने की बात नहीं की गयी है। उत्तर प्रदेश में डार्क जोन घोषित कर दिये गये लेकिन वहां ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं ले सकते, वहां कोई नहरें

निकालने की बात या पानी पीने के लिये हैण्डपम्प की बात या विधायकों को हैण्डपम्प देने की बात नहीं कही गयी है। अध्यक्ष जी, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश भवन का किराया एक्स एम0एल0ए0 के लिये एक हजार रुपया कर दिया गया है और उसकी पेंशन 10 हजार है यदि वह बीमारी की हालत में भवन में रूकना भी चाहे तो उसकी तनख्वाह, उसकी पेंशन 10 दिन में खत्म हो जायेगी, इसमें भूतपूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आज रोडवेज की बसों में अध्यक्ष जी आप तो नहीं चलते होंगे, आपको विशेष अधिकार है, गाड़ी–घोड़े हैं लेकिन मेरे जैसा एम0एल0ए0 आज भी बस में चलता है और टूटी बसें, अनुबंधित बसें लगा रखी हैं, इस बजट में रोडवेज की बसों की बात नहीं कही गयी है। आज स्थिति यह है कि जेवर जैसे छोटे कस्बे में 6–6 घन्टे जाम लग जाता है, वहां कोई बाईपास बनाने की बात, जो बहुत जरूरी है, इसमें नहीं कही गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सरकार ने पानी किसानों को फ्री दिया, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन नहर व लम्बे नालों की सफाई, उन पर रास्तों के लिये पुलों की बात इसमें नहीं की गयी है। अध्यक्ष जी, कानून–व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं, आजम साहब बैठे हैं अभी दो–तीन दिन पहले मेरठ के थाना टी0पी0 नगर में दो–तीन लड़के घर जा रहे थे और वहां यह बात एस0पी0 ने कबूल की, यह बात एस0एच0ओ0 ने कबूल की कि वहां 5–6 सिपाही और दरोगा शराब पिये हुये थे, उन्होंने लड़कों को मारा। मेरी एस0एस0पी0 से बात हुयी और एस0एस0पी0 बड़े तैश में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कानूनी कार्यवाही बड़े पारदर्शी तरीके से होगी। इन लड़कों को जेल भेजने का काम किया गया और जिन सिपाहियों ने और जिस दरोगा ने उत्पात मचाया, लड़कों को पीटा, औरतों को पीटा, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुयी और वह खुले घूम रहे हैं और वह लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गये हैं और कुछ लोग अपना घर छोड़कर भागे हुये हैं। अध्यक्ष जी, उस एस0पी0 ने इतनी बड़ी बात ऐसे कही जैसे पूरा प्रदेश वह चला रहे हो, उस एस0पी0 के खिलाफ जांच होनी चाहिये कि वह क्यों घूम रहे हैं और उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बांते ऐसी भी हैं जो स्वागत योग्य हैं। कृषि के क्षेत्र में, आगरा–लखनऊ हाई–वे के क्षेत्र में, लायन सफारी के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, किसान दुर्घटना बीमा जिसे एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया, उस क्षेत्र में, मेट्रो के क्षेत्र में और जनेश्वर मिश्र और लोहिया का तो कोई जवाब ही नहीं, यह सब अच्छे काम हुये हैं। बिजली उत्पादन पर काम हुआ है लेकिन सप्लाई के मामले में और पेंशन के मामले में सरकार कुछ पीछे हैं। जहां तक बीमारों की बात है तो मेरे यहां मुख्य मंत्री जी ने 100 लाख कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ लोगों को दिया है। ऐसे बीमार, जिनका कोई इलाज नहीं करा सकता, उनको दिया है, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है गन्ना भुगतान के बारे में यह सरकार पिछड़ गयी है। आज गोमती नदी को जिस तरह साफ और विस्तार किया जा रहा है यह सिंचाई मंत्री जी की बड़ी कृपा है। लखनऊ को अच्छा बनाया जा रहा है, मेट्रो का काम और भी महानगरों में हो

रहा है और परसों सिंचाई मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि गाजियाबाद, मोहन नगर, मुरादनगर से और देहरादून तक नहर के किनारे बनाने का काम दोनों सरकारों ने जो किया है, वह स्वागत योग्य है।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोका–टाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, वह मुख्य मंत्री जी की कृपा नहीं, वह गलत तरीके से विधायकों को गाड़ी देने जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, मेरी आखिरी बात, कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि बसपा वाले और बीजेपी वाले तो दंगाई हैं, कारोबारी हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन जो कमियां हैं, उनको सुधारने का काम भी सरकार करे, यह हमारा आग्रह है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद् देना चाहता हूं कि आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, चाहता हूं कि एक सेर के माध्यम से अपनी बात की शुरूआत करूं।

आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर यह आंकड़े झूठे हैं यह दावा किताबी है।
उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं आप,
इधर परदे के पीछे बर्बरियत है और नवाबी है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या कर रहे हैं आप इसके आखिरी हिस्से में तो दो शब्द फारसी के हैं, ये क्या कर रहे हैं, निकाले जाओगे पार्टी से।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

कोई बात नहीं, जो हकीकत होगा उसे बोलने की आदत है और यही अपनी पहचान है। इसीलिए पिछली बार भी बजट के दौरान मैंने कहा था कि इस किताब के अन्दर जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत हैं और चाहे वह भारत सरकार की योजनाएं हों, इन योजनाओं का यदि ठीक ढंग से क्रियान्वयन धरातल पर हो जाए तो निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनते हुए नजर आयेगा यदि 25 प्रतिशत भी इसका क्रियान्वयन हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पिछले साल और इस साल को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। अगर

बजट में कृषि की चर्चा की जाए तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल 2015–16 में 2435 करोड़ रुपए का प्रावधान था कृषि में जबकि उसके सापेक्ष मात्र 32.27ः धनराशि ही जनवरी, 2016 तक खर्च हुई, बाकी धनराशि भगवान जाने। 2014–15 में 117 करोड़ रुपए के सापेक्ष 25.2 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसी तरीके से अगर पंचायती राज में देखा जाए तो 2533 करोड़ रुपए के सापेक्ष 50.47ः धनराशि ही खर्च की गई, पशुधन विभाग में पिछली बार 31.96 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हो पाई। इसी तरह से अगर मत्स्य पालन विभाग की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए तो 15.46 प्रतिशत धनराशि ही खर्च हो पाई। इसी तरह से अन्य तमाम विभागों की ओर देखा जाए तो आंकड़ा इसी प्रकार का आयेगा। यह सरकार इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। हम लोग बलिया जनपद से आते हैं और बलिया जनपद उत्तर प्रदेश के अन्तिम छोर पर है, हम कह सकते हैं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है बाढ़ की विभीषिका बलिया जनपद और उत्तर प्रदेश ने झेला, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की भी मार हम लोगों ने झेला और सूखा की मार भी झेला, बलिया जनपद को सूखाग्रस्त भी घोषित किया गया था लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं आप संज्ञान ले लीजिएगा कि फेफना विधान सभा क्षेत्र में 10 से 15 प्रतिशत से अधिक न तो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि का लाभ किसानों को मिल पाया है और न ही सूखा प्रभावित किसानों को लाभ मिल पाया है इसलिए सदन से मैं मांग करना चाहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाए और जो इसके लिए उपयुक्त किसान हैं जिनका हक, हिस्सा बनता है उन्हें पारदर्शिता के साथ अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखा का मुआवजा दिलाया जाए। इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले मैंने बलिया जनपद में विश्वविद्यालय खोलने की मांग की थी, बलिया जिला मंगल पाण्डे की धरती है, चित्तू पाण्डे की धरती है, लोकनायक जय प्रकाश नारायण की धरती है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान के बेटे चन्द्रशेखर जी की धरती है और छोटे लोहिया के नाम से जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उन छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी की भी धरती है लेकिन बलिया जनपद में विश्वविद्यालय की लागत अगर 10 करोड़ रुपए घोषित की जाए तो निश्चित रूप से वह बहुत कम है और इसलिए मैं इस सदन से मांग करना चाहता हूं कि बलिया वीरों और क्रान्तिकारियों की धरती है तो बलिया की धरती के अनुरूप कम से कम यह धनराशि 10 करोड़ की जगह पर बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपए कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

जब यूनिवर्सिटी बनती है तो यह अनुदान कोष बजट की व्यवस्था की जाती है, यह प्रारम्भिक होता है और इसके बाद फिर यह बढ़ता है। हमारी यूनिवर्सिटी बन रही थी तो पहले 10 करोड़ हुआ, फिर और काम हुआ फिर और बढ़ा। उपेन्द्र जी, इसमें 1000 करोड़ रुपया एक साथ नहीं मिलता है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैंने इसलिये कहा कि 1984 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी बलिया में आयी हुई थीं और स्वर्गीय चित्तू पाण्डेय जी जिन्होंने 1942 की आजादी की लड़ाई में तिरंगा झण्डा फहराकर वहां के जिलाधिकारी को भगाने का काम किया था उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की और उन्होंने शिलान्यास भी किया, वह शिलापट आज भी दिख रहा है। इसलिए मैं इस विधान सभा से मांग करना चाहता हूं कि बलिया की धरती ने चन्द्रशेखर जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री को पैदा किया, वो एक किसान परिवार से थे। इसलिए जो विश्वविद्यालय बनाने की बात है वह स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी के नाम पर बलिया में विश्वविद्यालय बनाया जाए यह मैं इस सदन से मांग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब जल्दी समाप्त करिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर लखनऊ में नाइट सफारी, बहुत बड़े पार्क और अन्य योजनाओं की घोषणा की गयी। हमने मांग किया था कि बलिया में भी उनके नाम पर कुछ किया जाए, उनके नाम से किया भी गया लेकिन उसमें मैं आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। बलिया में एक वन विहार पार्क हुआ करता था वह स्वर्गीय वंशराज सिंह जी जो मुखा ग्राम के निवासी थे और 1971 की लड़ाई में शहीद हो चुके थे उन्हीं के नाम पर वो सड़क थी और उसका नाम बदल करके लोहिया पथ करके जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर वह पार्क घोषित कर दिया गया। स्व0 जनेश्वर मिश्र जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा रहा है, वह छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे, अगर वहां पार्क खोलना था तो बलिया जनपद में हमारे समझ से सैकड़ों, हजारों एकड़ भूमि ऐसी पड़ी हुई थी जहां पर पाक्र का निर्माण कराया जा सकता था लेकिन यहां पर कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। इसको अगर सदन सुधार ले तो बेहतर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार को संदेश देने के लिए तीन–चार चीजें हैं जिससे वहां से संदेश जाता है, शासन–प्रशासन हनक से चलता है। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे हास्पिटल हो, चाहे बिजली, सड़क, पानी हो लेकिन मैं कह सकता हूं कि कानून–व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं ठीक उसी तरीके से बलिया जनपद के अन्दर जो दो साल से लगातार कानून–व्यवस्था की स्थिति टूटी हुई थी जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, चरम सीमा पर था राजूबाबू सिंह के जमाने में। उनको हटाकर आपने अनीस अहमद अंसारी जी जैसे कप्तान की पोस्टिंग बलिया में की थी। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि चार महीने के अन्दर ढाई–तीन साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम अगर किसी ने किया था तो बलिया के कप्तान अनीस अहमद अंसारी ने किया था लेकिन उनको बलिया से हटाकर पी0ए0सी0 में भेज दिया गया। जब उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून का राज स्थापित कराने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होगी तो वही होगा जो अभी मा0 मुख्य मंत्री जी के आवास के बगल में हुआ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, दो मिनट और आपका संरक्षण चाहूंगा। इसी तरीके से अगर हॉस्पिटल की स्थिति देखी जाए, तो मा0 अध्यक्ष जी, मैं बलिया का जिक्र करना चाहूंगा, बलिया जिला अस्पताल, कल मेरा प्रश्न लगा हुआ था। सांप काटने के इलाज के इंजेक्शन के अभाव में सुदामा वर्मा की मौत हो गयी। कल मेरा प्रश्न था लेकिन टेकअप नहीं हो पाया। इंजेक्शन के अभाव में सुदामा वर्मा की मौत तड़प–तड़प कर हो गयी। वह 12.00 बजे रात में जिला अस्पताल में पहुंचा था सुदामा वर्मा को 11.45 बजे रात में सर्प ने काटा, वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतसर पहुंचा था वहां पर कोई डाक्टर नहीं मिला केवल हेल्पर मिला। फिर वह जिला अस्पताल आया रात में 01 बजे फोन आया, वहां के डॉक्टरों ने उसे बनारस के लिए रेफर कर दिया। फिर हम लोग अस्पताल पहुंचे लेकिन इंजेक्शन न होने की वजह से सी0एम0एस0 को बुलाया गया सारे डॉक्टर आये लेकिन इंजेक्शन के अभाव में चार बजे से दो घण्टा लगातार हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा वह तड़प–तड़प कर मर गया। उसमें मुकदमा कायम हुआ, हम लोग धरने पर बैठे। माननीय पूर्व मंत्री जी भी पहुंचे थे, पहला ऐसा मौका था कि 15 साल के अन्दर गये थे क्योंकि वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था सुदामा वर्मा। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो पायी।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

आज भी सी0एम0ओ0 बलिया ने हास्पिटल में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अखाड़ा बना करके बैठा हुआ है और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करते समय एक बात और कहकर समाप्त करना चाहता हूं। सरकार ने इस वर्ष को युवा वर्ष और किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण भी चाहूंगा और आपको आईना भी दिखाना चाहूंगा, मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला है, आजादी के 68 साल के इतिहास में कभी भी पी0सी0एस0 का पेपर लीक नहीं हुआ था लेकिन अनिल यादव के जमाने में, जो उसके चेयरमैन थे, हुआ है। जरूर इस सदन से मांग करना चाहता हूं कि उनकी पोस्टिंग किसकी वजह से की गई थी इसकी भी जांच होनी चाहिए और अनिल द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

और पारदर्शिता के तौर पर उस संस्था को पवित्र रखना चाहिए।...

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। बैठ जायं। उमेश पाण्डेय जी आप शुरू करिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा ....

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2016–2017 के बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल मौर्या जी द्वारा सामान्य बजट पर रखे विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को आगे रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश का माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत भारी भरकम 3 लाख, 46 हजार 935 करोड़ रुपये का बजट लाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब यह सरकार चुनकर आई थी तो हमारे बेरोजगार नौजवानों ने, किसानों ने, बेबस लाचार लोगों ने एक नौजवान युवा को देख करके बड़े पैमाने पर बहुमत की सरकार देने का काम जब किया तो उनको ऐसे–ऐसे लालीपॉप दिये गये। लैपटाप की बात की गई, टैबलेट की बात की गई, उनको बेरोजगारी भत्ते की बात की गई। किसानों को मुफ्त पानी देने की बात की गई, किसानों का कर्जा माफ करने की बात की गई, किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस बजट को पढ़ा और पढ़ने से पता चला अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी बड़े इतरा रहे थे कि हमारे क्षेत्र में इतनी सड़कें बन गईं, हमारे क्षेत्र में इतने पुल बन गये, इतनी टंकियां पास हो गईं, इतने हैंडपम्प लग गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस शहीदी धरती से आता हूं मधुबन की शहीदी धरती से। वहां पर 2012–13 में मात्र 3 गांव लोहिया गांव लिये गये। उसके बाद न वर्ष 2014–15 में लिये गये न वर्ष 2015–16 में लिये गये और न वर्ष 2016–17 में हमको लगता है कि लिया जायेगा और विकास कोसों दूर। स्वास्थ्य के मामले में मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ काम किया है। 108 और 102 एम्बुलेंस चला करके लेकिन क्या हास्पिटल की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत हैं। अस्पतालों में मान्यवर, दवा नहीं है। कुत्ता काटता

(इस समय 05 बजकर 04 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शारदा प्रताप शुक्ला पीठासीन हुए)

है तो लोग 40 किलोमीटर दूर जिला हेड क्वार्टर पर जाते हैं। पी0एस0सी0, सी0एच0सी0 में कुत्ता काटने का इन्जेक्शन नहीं है और यह सरकार दावा ठोंक रही है कि बड़े आराम से लोगों को निःशुल्क चिकित्सा मिल रही है। वहां एक्स–रे मशीन खराब पड़ी है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। क्या यही है चिकित्सा ? क्या यही स्वास्थ्य आप देना चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता को। क्या इसी तरीके से यह प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा ? इतने बड़े पैमाने पर बजट लाये हैं और बजट में हमारे गरीब, बेबस, लाचार लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं। आज मान्यवर, पूरे प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। हाई स्कूल, इन्टर की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अब मेरे मधुबन की धरती पर, मेरे मऊ जनपद की धरती पर और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर मात्र 2–3 घंटे बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जो बिजली व्यवस्था बिगड़ी हुई है इस समय बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए उसमें

तत्काल दो शिफ्टों में वहां 8 से 5, 8 से 5 बिजली देने की व्यवस्था की जाय ताकि परीक्षा देने वाले बच्चे अपनी परीक्षा सुचारु रूप से दे सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बड़े पैमाने पर हमारे साथियों ने कहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में दिनांक 17–1–2016 की रात्रि गजियापुर बंधे पर ओम प्रकाश पुत्र राम आशीष ब्लाक पोस्ट गजियापुर, थाना मधुवन जनपद मऊ की किराना दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। घटना के समय ओम प्रकाश अपनी किराना की दुकान के अन्दर सो रहा था। माननीय अधिष्ठाता महोदय उसे भी जलाकर मारने का प्रयास किया गया जब उक्त घटना की जानकारी मुझे मिली, मैं मौके पर पहुंचा उस किराना व्यापारी की दुकान का सारा सामान में कुछ बचा नहीं था। दुकान को तोड़कर जो किराना व्यापारी था उसको भी जलाकर मारने की व्यवस्था की गई थी। माननीय अधिष्ठता महोदय, उस पीड़ित परिवार के पास न कोई भूमि है और किराना की दुकान से ही उसके पूरे परिवार का जीविकोपार्जन चलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं मान्यवर, दिनांक 17–1–2016 की रिपोर्ट 18–1–16 को देर रात में चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा संख्या–98/16 अपराध संख्या–12436, 427, 504, 506 भारतीय दण्ड संविधान की धारा–ए–1–3/3 (दो) एस0सी0एस0टी0 के तहत दर्ज की गई। सभी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज तक वह अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उस व्यापारी को धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम अपने मुकदमें की पैरवी करोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसका मुआवजा दे, उसका 18 लाख का सामान जला है। वहां पर लेखपाल और एस0डी0एम द्वारा मूल्यांकन किया गया कि कितने मूल्य का सामान जला, तो मान्यवर, 18 लाख का सामान जला है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार उस परिवार को 20 लाख का मुआवजा देने की घोषणा करे। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं दूसरी घटना के बारे में कहना चाहता हूं 3–1–16 को मेरे क्षेत्र के थाना मधुवन के अन्तर्गत ग्राम द्वारी के दिलीप मौर्या की कम्प्यूटर की दुकान है, स्थानीय दबंगों ने घुसकर उसके सारे कम्प्यूटर उपकरण को तोड़कर नष्ट कर दिया और इसे बुरी तरह से मारापीटा गया। जिससे दिलीप मौर्या को गम्भीर चोटें आईं और आज तक पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज तक नहीं की। अपराधी खुलेआम घूम करके उत्पीड़ित परिवार को धमकाने का काम कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे मधुवन क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की वजह से क्षेत्रीय किसानों की पूरी फसलें नष्ट और बरबाद हो गईं। आज सरकार जो पिछला वर्ष बीता है उसे किसान वर्ष के रूप में लेने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब सरकार ने वायदा किया था किसानों को मुफ्त पानी देने का काम करेंगे तो जब आज किसान हमारा परेशान है, बदहाल है, तो उसके लिए हमारे पूर्वांचल और मधुवन के किसानों का, जो प्राइवेट ट्यूबवेल से उन्होंने सिंचाई का काम किया है उसकी बिजली का बिल माफ करने का काम सरकार करे, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता जिसमें

किसान, नौजवान, बुनकर, बिजली की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आज बिजली दो–तीन घंटे मिलने की वजह से आज हमारा बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में जो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है हमारे विधान सभा क्षेत्र मधुवन में 33 के0बी0ए0 33 के0वी0ए0 मोलनापुर, मिसरौली, 33 के0वी0ए0 सूरजपुर, 33 के0वी0ए0 पाण्डेयपार सभी पावर स्टेशनों पर ओवरलोड होने से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरे क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश के 33 के0वी0ए0 के सब–स्टेशनों की ओवरलोडिंग की समस्या को समाप्त नहीं करते तब तक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगी माननीय अधिष्ठाता महोदय 33 के0वी0ए0 की विद्युत लाइनों में उच्च क्षमता का कंडक्टर लगाया जाय अन्यथा 33 हजार की अलग लाइनें बनाई जाएं तब जाकर इसमें सुधार किया जा सकता है। विद्युत स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाया जाय। 440 वोल्ट और 11000 बोल्ट की जर्जर लाइनों को बदला जाए और विद्युत पावर स्टेशनों पर फीडर की संख्या बढ़ाई जाए। किसी भी लाइन में खराबी आने पर पूरे पावर हाउस को शट डाउन कर देना पड़ता है शट डाउन करने के बाद पूरी जनता सब–स्टेशन का घेराव करने लगती है माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी तो मैं दो तीन मिनट बोला हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री उमेश पाण्डेय–

अधिष्ठाता महोदय क्षेत्र की समस्या है सरकार से मेरी समस्याओं का समाधान करा दीजिए मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई आपके सामने लाना चाह रहा हूं। इसके निदान के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के दोहरी घाट गोहटा 132 के0वी0ए0 की क्षमता बढ़ाई जाए एवं अन्य विद्युत पावर स्टेशन की स्थापना कराई जाए। मधुबन क्षेत्र में घनी आबादी में लो–बोल्टेज की समस्या व्याप्त है वहां पर 11000 की केबिल के माध्यम से नए विपणन परिवर्तक लगाए जाएं जिससे लो–बोल्टेज की समस्या का निदान हो सके। अधिष्ठाता महोदय जो सड़कें ऊंची हो जाती हैं तो जो पोल हैं वह नीचे आ जाते हैं और तार जमीन से टकराने लगते हैं इससे बड़े पैमाने पर हादसा हो रहे हैं। गांव में देहातों में रोडें बन रही हैं उसमें तार और जमीन के बीच की दूरी घट जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके इसके लिए सड़कों के दोनों तरफ पोल लगाकर ऊंचाई बढ़ाई जाए जिससे आम जनता के साथ रोज होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अधिष्ठाता महोदय पीक आवर में बिजली सप्लाई देने से फीडर ट्रिप कर जाता है और ट्रिपिंग की समस्या आती है मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मधुबन घोसी विधान सभा क्षेत्र में पीक आवर के बाद बिजली दी जाए जिससे जनाक्रोश को रोका जा सके। मान्यवर, आज हमारे क्षेत्र की एक समस्या है चकबन्दी की ग्राम मर्यादपुर, परगना नत्थूपुर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ ग्राम दुबारी, परगना नत्थूपुर, तहसील मधुबन जनपद मऊ में पुनः चकबन्दी के आदेश के विरोध में हमारे मर्यादपुर और आस–पास के लोगों ने पूरे ग्राम सभा के लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है वहां की जमीन

वाणिज्य स्थिति में आ गई शहर नुमा हो गई है जमीन की कमी है कुछ भू–माफिया चकबन्दी कराकर बड़े पैमाने पर वहां पर वहां पर काफी सरकारी जमीनें बची हैं चकबन्दी में उसको हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मर्यादपुर, डुमरी की चकबन्दी पूर्व में हो चुकी है जिसका धारा–52 1979–80 में हो चुका है यह कि पूर्व में चकबन्दी 15 प्रतिशत भूमि की कटौती किसान की कृषि योग्य भूमि से हो चुकी है जिससे काफी क्षेत्र का नुकसान किसानों को सहन करना पड़ा है। यही नहीं इसके पहले जब चकबन्दी जब हुई थी तो पी0ए0सी0 लगाई गई थी हमारे किसानों पर लाठियां चार्ज की गईं थीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं तो तत्काल वहां की चकबन्दी को रुकवाने का काम करें ताकि भूमाफियाओं का जो भूमि हड़पने का काम चल रहा है वह रुकने का काम हो और कानून–व्यवस्था कायम हो सके। अधिष्ठाता महोदय अभी–अभी मुझे जानकारी मिली है मेरा व्यक्तिगत है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सन् 2005 में 16–10–2005 को मेरे बड़े भाई अखिलेश पाण्डेय जो ब्लाक प्रमुख थे एवं उनके साथी रामबचन राम तथा पूर्व प्रधान गंगा राम, इन तीन लोगों की ब्लाक परिसर में दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी। जब दिनदहाड़े क्रूरतम हत्या हुई, वह सजायाफ्ता मुजरिम जिसको सजा मिली है, जिसको जेल मैनुअल के हिसाब से सेन्ट्रल जेल में होना चाहिये था, लेकिन सरकार बदलते ही उसको सेन्ट्रल जेल से उठाकर जिला जेल में रखकर इस सरकार द्वारा अय्याशी करने की पूरी खुली छूट दे दी गयी है, इससे प्रदेश में अगर अराजकता का माहौल नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा ? मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, इसके बाद और क्या हो रहा है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार उन अपराधियों को माफीनामा देने का प्रयास कर रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन अपराधियों को माफी न दी जाये, अन्यथा इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। मा0 अधिष्ठता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे परिवार के लोग और मेरे सहयोगी लोग आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। ऐसे अपराधी को आज छोड़ा जा रहा है जिसने क्रूरतम हत्या की और दिनदहाड़े बेकसूर लोगों की हत्या की और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का काम किया, ऐसे अपराधी को सरकार आज छोड़ने जा रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2016–17 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट है और बहुत जोरशोर से यह चर्चा हो रही है कि बहुत बड़ा बजट है। पिछली बार भी जो बजट आया था उसमें भी यही चर्चा थी, लेकिन उस बजट की हकीकत जब हम देखेंगे तो लगता है कि यह पैसा आखिर कहां जा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपया त्वरित विकास निधि से मेरे क्षेत्र की सड़कों के लिये दिये थे, उस सड़क का इस्टीमेट बन गया, यहां आ गया, लेकिन पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। बजट कहां गया ? जब मैं सचिव से मिला तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, कहां गया बजट ? मा0 आजम खां

साहब, शहरी विकास मंत्री जी अभी यहां नहीं बैठे हैं, मैंने कुछ मुस्लिम क्षेत्रों के विकास के प्रस्ताव वर्ष 2014 में नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से दिये थे, 2015 में भी दिये, पांच करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, लेकिन पैसा नहीं मिला। मैंने मा0 आजम खां साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि क्या करें, पैसा नहीं है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने अनुपूरक में भी पैसा नहीं दिया। इतना बड़ा बजट और महत्वपूर्ण विभाग, डूडा में पैसा नहीं, त्वरित विकास निधि में पैसा नहीं। मेरा एक पुल किलोमीटर 89 पर पास हुआ, पुलिया नहर की है चार करोड़ रुपये की पास हो गयी, इस्टीमेट बन गया, टेण्डर हो गया, लेकिन पैसा नहीं। इसलिये कैसा बजट, जब बजट में पैसा ही नहीं है तो वह पैसे कहां गये ? मुझे निश्चित रूप से एक कहावत याद आती है कि 'बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागै अति दूर'। यह बजट लोकलुभावन है, बजट कहीं होता है और काम कहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां कर्मचारियों की कमी न हो। सभी जगह कमी है, काम नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निकायों में कमी, अध्यापकों की कमी, पुलिस सिपाहियों की कमी, यहां पर भी कमी है सचिवालय में भी कर्मचारियों की कमी है, लेकिन भर्ती नहीं हो पाई। यह कैसी सरकार है जो काम ही नहीं कर पा रही है ? जब अधिकारी नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे तो योजनाओं के लिये फाईलों को आगे बढ़ाने के कार्य कैसे होंगे ? काम नहीं हो पा रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूं, मान्यवर, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना शहर में पेयजल संकट के समाधान के लिए आई, यह 2007 में आई। हमारे बगल में हमारे काबिल मित्र बैठे हुए हैं, उनकी सरकार के समय में आई और 2016 तक अभी कहीं एक बूंद पानी किसी शहर को नहीं मिला। टंकियां खड़ी हैं, हमारे यहां वाटर लाइनें टेस्ट की जा रही हैं तो जगह–जगह पानी की लीकेज है यानी सारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का पैसा, हजारों करोड़ रुपया, जिसमें केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार का भी पैसा था, बर्बाद हो गया। हमने कई बार आजम खां साहब से कहा कि उसकी जांच करा दीजिए, उन्होंने शुरुआत में दो बार तो कमेटी की बैठक बुलाई, उसके बाद बैठक भी नहीं बुलाई क्योंकि चर्चा होगी और अधिकारियों की पोल खुलेगी। ऐसे अधिकारियों को संरक्षण क्यों, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको सजा क्यों नहीं ? आप सरकार चलाना चाहते हैं, पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं और यह भी दावा करते हैं कि जो हमने विकास की घोषणाएं की थीं, जो वायदे किए थे, वह वायदे पूरे हो गए। क्या वह हवा में हो गए या जमीन पर हो गए ? धरातल पर तो नहीं हुए। धरातल पर क्या आप हरिजनों को मकान दे पाए, क्या नौजवानों को रोजगार दे पाए, क्या कोई फैक्ट्रियां या मिल चला पाए, जिसमें मजदूर काम कर सकें, क्या उत्तर प्रदेश की सड़कों की दशा ठीक कर पाए, क्या विद्युत व्यवस्था में आप सुधार कर पाए ? आपने हमारे कानपुर में 03 विद्युत केन्द्र बनाने की घोषणा की थी, पनकी पॉवर हाउस में 600 मेगावॉट की, एक सरसौल में 1200 मेगावॉट की और एक घाटमपुर में। 03 साल हो गए हैं, मुख्य मंत्री जी को, 2012 से यह घोषणाएं हो रही हैं लेकिन आज तक एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी। कैसी आपकी योजनाएं हैं कि 04 साल में अपनी योजनाएं नहीं पूरी कर

पायें ? 04 साल में कोई काम न कर पाये और कहें कि वायदे तो मेरे सब पूरे हो गए। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। सदन ने पास कर दिया, यहां आ गया, 06 महीने हो गए और उत्तर प्रदेश की सरकार एक कदम से निर्णय ले सकती है कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम इस कम्पनी को दे दिया जाए। लेकिन किसको दिया जाए, यह निर्णय भी सरकार नहीं कर पा रही है। कैसी सरकार है, कैसे काम करने वाली सरकार है ? यह बात समझ में नहीं आती। आज सफाई कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के सारे नगर निगमों में कमी है। हमारे यहां 07 हजार सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन चाहिए 14 हजार। मैंने एक प्रश्न पूछा था, मंत्री जी का जवाब आया कि हमारे यहां पर्याप्त हैं, संविदा पर रख लिए हैं। लेकिन सफाई नहीं हो रही है, नालियां नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर चोक हैं। सीवरों की हालत यह है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में जो सीवर का प्रोजेक्ट प्रारम्भ हुआ, अभी पहला फेज भी कम्प्लीट नहीं हो पाया, जबकि 2017 तक दोनों फेज कम्प्लीट करने थे। तो काम की गति सरकार की यह है और सरकार काम कर रही है और सरकार सारे वायदे पूरे कर रही है। कानून–व्यवस्था के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, तमाम लोगों ने कह दिया, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि कहीं न कहीं किसी महिला के साथ कोई घटना न घटती हो, चाहे वह बलात्कार की हो, चाहे वह सोसाइट की हो, चाहे वह अपहरण की हो। मान्यवर, प्रदेश के सभी जिलों में घटनाएँ होती हैं, कैसी आपकी कानून–व्यवस्था है ? आप उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, आपके अधिकारी, आपके अनुसार काम नहीं करते, फाइलें लटकी हुई हैं, जिस फाइल पर एक हफ्ते में स्वीकृति मिलनी चाहिए, महीनों में स्वीकृति नहीं मिलती, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है देखने की कि हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है, हमारी मंशा के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ? सरकार का आंकलन तो उसकी कार्य–पद्धति से होता है। सरकार की मंशा का आंकलन तो उसकी काम करने की तेजी से होता है। एक–दो योजनाएं आपने जरूर चला दी हैं। चाहे वह मेट्रो की योजना हो और चाहे वह यमुना एक्सप्रेस–वे हो। क्या दो योजनाओं के आधार पर गरीब का पेट भर जाएगा। क्या दो योजनाओं के आधार पर उन गरीब नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। क्या दो योजनाओं के आधार पर उन मरीजों का इलाज हो जाएगा जो भूखे और बेहाल और फटे नंगे हैं। आज यह सरकार यह भी वायदा करती है कि हम मुस्लिमों के हिमायती हैं। वोट भी लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम के अंदर गरीबी नहीं है। मुस्लिम आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गरीब है, बेहाल है। क्या उनके लिए आपने कुछ मकान की व्यवस्था की है। क्या उनके लिये कोई योजनायें चलायीं। आप कब्रिस्तान तो बना सकते हैं भावनात्मक रूप से भड़काने के लिए, लेकिन उनको आप दवाई, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करते। रोजगार की व्यवस्था नहीं करते। इस प्रकार की सरकार की नीतियां हैं। जो नीचे का तबका है उनके लिए सरकार काम करे। तो सरकार ने पांच वर्ष में ऐसा कोई काम नहीं

किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट लोकलुभावन और दिखावे का बजट है। धन्यवाद।

'श्री महावीर सिंह राणा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया और अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की एक नम्बर सीट, बेहट, जनपद सहारनपुर से चुनकर आया हूं। मेरी विधान सभा के तीन ओर उत्तराखण्ड, हरियाणा और हिमांचल प्रदेश है। अत्यंत विषम परिस्थितियों का क्षेत्र है। यहां पर 2012–13 में जो बाढ़ आयी थी इसमें 42 व्यक्ति बह गये थे। सात पुल, तालापुर हिण्डन सोलानी और रपटे बह गये थे जिनका 70 करोड़ का इस्टीमेट आपके विभाग का आया था। कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि वह बजट अवमुक्त नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ क्षेत्र से जो आपदा में इस्टीमेट आया है नदियों का, पुलों का और सड़कों का जो सत्तर ग्राम को जोड़ती है वह पैसा रिलीज किया जाये। अधिष्ठाता महोदय, सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश का दूसरे नम्बर का औद्योगिक क्षेत्र था। देहरादून और हरिद्वार इसी जनपद के अंदर आते थे। परंतु वहां का उद्योग स्थानांतरित होकर उत्तरांचल में चला गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में सहारनपुर जनपद में कोई उद्योग नहीं लग पा रहा है। वहां पर सहारनपुर मण्डल में पापुलर की लकड़ी पैदा होती है। लिप्टस की लकड़ी पैदा होती है। पापुलर की लकड़ी से इतना उत्पादन हुआ कि पिछले सालों में 12–13 सौ रुपये प्रति कुं0 लकड़ी बिकती थी जो हरियाणा यमुनानगर में जाती थी। प्लाई की फैक्ट्रियां लगती थी। दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि हरियाणा में यूनियन बन गयी और रॉ–मेटीरियल 80 प्रतिशत सहारनपुर से जाता है। उसका रेट साढ़े चार सौ–पांच सौ रुपया प्रति कुं0 हो गया है। किसान, मजदूर परेशान है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्लाई फैक्ट्री की जो रोक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आंकड़े गये हैं वह तथ्यहीन भेजे गये। उसको सुधार की आवश्यकता है। सी0आई0सी0 ने नया सक्रिल रेट भेजा है। किसान की पापुलर की फसल और लिप्टिस की फसल को वन उपज न मानकर हरियाणा, उत्तराखण्ड ने उसको कृषि उपज माना है। किसान के यहां उत्पादन होता है और इससे करीब पचास हजार लोग सहारनपुर व बरेली मण्डल में रोजगार में लगे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लाई फैक्ट्रियां लगाने का जो अभियान चल रहा है। उसमें सरकार अनुदान दे और उस अभियान को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमीशन कराकर उसको कराया जाये। इससे सहारनपुर का विकास होगा। सहारनपुर में नौजवान लोगों को युवा वर्ष में रोजगार मिलेगा। मेरा सरकार से तीसरा अनुरोध है कि सहारनपुर जनपद में बेहट तहसील को आम पट्टी घोषित किया है। वहां पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लग सकती। उच्च कोटि का आम–अमरूद वहां पर पैदा होता है व सब्जी का उत्पादन वहां पर होता है। पूरी तहसील पूरे जनपद में एक भी कोल्ड स्टोरेज आज की तारीख में नहीं है। फूड प्रोसेसिंग

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए केंद्र सरकार ने योजनायें, यू0पी0 सरकार ने दी है। जिसका लाभ उत्तराखण्ड सरकार ले रही है। सहारनपुर को उसमें अभी समुचित भागीदारी नहीं मिली है। वहां पर उत्तराखण्ड में उनको 72 प्रतिशत सब्सिडी है। तो सहारनपुर के जो इंडस्ट्री वाले थे वे वहां चले गये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सहारनपुर में भी सब्सिडी का प्राविधान किया जाये। ताकि वहां जो फैक्ट्रियां लग सकती हैं वह लगें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सहारनपुर को दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग से जोड़ा गया था। जिसकी लागत उस समय साढ़े सत्रह सौ करोड़ थी। 800 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद वहां प्राइवेट कम्पनी को परमीशन नहीं मिल पाई पेड़ काटने की, अब वह पेड़ कट गये हैं, परन्तु वह कम्पनी यहां से पलायन कर गई। मेरी सरकार से मांग है कि जो बैंक उस कम्पनी को लोनिंग कर रहे थे, उनसे दोबारा मीटिंग कर के इसको बनाया जाय, यह पश्चिमी उत्तर की भाग्य रेखा है, इससे सहारनपुर, बागपत, शामली इत्यादि जनपदों का सीधा दिल्ली का रास्ता ढाई घण्टे का हो जाता है, इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, पंचकुला से रुड़की, पंचकुला से छुटकनपुर होते हुए चार लाईन का राज मार्ग बन रहा है, 32 करोड़ रूपये सरकार ने उसकी जमीन के मुआवजे के लिए दिया है, अभी तक यमुनानगर तक जमीन का मुआवजा मिल चुका है, चण्डीगढ़ से रोड बननी शुरू हो गई है, परन्तु हमारे जनपद में अभी उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, यह परसों ही पैसा रिलीज हुआ है, सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से स्टेट को, सहारनपुर जनपद में पहुंच गया है, मेरी सरकार से मांग है कि इसकी जमीन को अधिग्रहण कर अतिशीघ्र इस कार्य को कराया जाय, ताकि हरिद्धार आने वाले जो जम्मू–काश्मीर, हरियाणा, पंजाब से तीर्थ यात्री आते हैं, डेथ होने के बाद फूल लेकर आते हैं और जाम में फंस जाते हैं, सहारनपुर का बाई पास अगर बन जायेगा, इससे सहारनपुर जनपद को अत्यधिक लाभ होगा। मान्यवर, मेरी तीसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि सहारनपुर में जो मेडिकल कालेज है, वह बनकर तैयार है, सवा पांच सौ करोड़ रुपया उसमें लग चुका है, इस बार बजट में 40 करोड़ का प्राविधान किया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर सिटीस्कैन मा0 मंत्री जी मेडिकल कालेज में नहीं है, किसी प्रकार की मशीनें नहीं हैं, टेक्नीशियन नहीं हैं, प्रिंसिपल हैं और चार डाक्टर हैं, सरकार का इतना रुपया खर्च होने के बाद जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। सहारनपुर के कई सौ मरीज पर डे चण्डीगढ़ पी0जी0आई0 को जाते हैं, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेडिकल कालेज को लगभग 90 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है, सभी मशीनों के लिए और सभी व्यवस्था के लिए तो सरकार इसको अतिशीघ्र शुरुआत कराने का काम करे, ताकि जनता को लाभ मिल सके। एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बहुत बड़ा संस्थान है, मा0 अधिष्ठाता महोदय, सहारनपुर जनपद में हरिद्वार और देहरादून आते थे, पर्यटन का बहुत अच्छा था, सब अपने क्षेत्र में घूमने के लिए जाते थे, हरिद्वार जब सहारनपुर में था, यह अलग हो जाने के बाद सहारनपुर में कोई स्थान नहीं रहा कि जहां व्यक्ति अपने बच्चों को ले जाय, एक मात्र शिवपीठ है, मा0 मंत्री जी भी वहां पर गये थे, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में पानी पीने की विकट स्थिति है, वहां पर पानी

की टंकी का इन्तजाम कराया जाय और वन की जमीन है, महोन से लेकर सहारनपुर जनपद में बेहट तहसील में वन विभाग की जमीन है, वहां पर पर्यटन को घोषित कर उसका विकास किया जाय, क्योंकि यमुना नदी और गंगा नदी दोनों नदियों का पानी एक जगह संगम मिल रहा है कुंआखेड़ा गांव में, वहां पर पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं, मैं इसकी भी सरकार से मांग करता हूं और चौथा मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों का शुगर मिल एक सहारनपुर जनपद में था टोडरपुर, बेहट विधान सभा क्षेत्र तहसील बेहट में एक ही शुगर मिल था, पिछले दो साल से यह शुगर मिल बन्द हो गया, बहुत अच्छी रिकवरी थी, परन्तु मिल मालिक उसको चलाना नहीं चाहता, तो सरकार उसका अधिग्रहण कर किसानों के हित में, मजदूरों के हित में उसको चलाने का प्रबन्ध कराये। इसके साथ ही मेरा आपसे अनुरोध है कि बोर्ड के एक्जाम चल रहे हैं, सहारनपुर जनपद में महानगर में 07 से 11 तक है बिजली मा0 मंत्री जी, बच्चों को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, देहात में बिजली की स्थिति भी असंतोषजनक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिजली की स्थिति का जो कट है, वह रात का न होकर दिन में कट हो, इस समय किसान को भी पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है, बच्चों को रोशनी की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है रात को, बोर्ड के एक्जाम हैं, इसलिए वहां पर बिजली की व्यवस्था सुधारी जाय। मान्यवर, सहारनपुर नगर में सड़कों का बहुत अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की जो 17 सड़कों का स्टीमेट यहां पर आये हुए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटित करने का कष्ट करें, मान्यवर इन्हीं शब्दों के साथ हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे, धन्यवाद।

श्री मौ0 इरफान–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सम्मान के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, यह बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। अब तक का ऐतिहासिक, सबसे बड़ा बजट और अब तक के इतिहास में इतनी योजनाएं हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट में बतायी गयी हैं, जो अपनी मिसाल आप हैं। सरकार का चार साल का कार्यकाल जो लगभग पूरा होने जा रहा है, अब तक का जितना भी इस विधान सभा का इतिहास रहा है, जितनी सरकारें रही हैं इन सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा बेहतर कार्यकदगी का और सबसे ज्यादा तरक्की का और सबसे ज्यादा विकास का समय रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे यह कहना चाहूंगा कि कितनी नई योजनाएं इन चार साल में जनता के सामने लायी गयी हैं। कितने पुराने कामों को जो डेड पड़े थे, उनको चालू कराया गया, उनको संशोधित कराया गया और उन पर काम कराया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतनी–इतनी बड़ी योजनाएं जो कभी उत्तर प्रदेश के लिए ख्वाब हुआ करती थीं, मेट्रो एक उपहार है, जो कभी ख्वाब था, जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा किया है। मैं उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वह जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने पूरी तौर पर दयानतदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे प्रदेश

की सेवाभाव से जितनी योजनाएं चलायी हैं उन सबका श्रेय उनको जाता है। हमारे नौजवान मुख्य मंत्री जी, जो अपनी मिसाल आपके साथ, इतनी बड़ी योजनाएं लेकर जो हमारे बीच में रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बने जो एक बहुत बड़ा इतिहास है। दुर्घटना बीमा योजना जो पहले कभी 1 लाख हुआ करती थी, वह 5 लाख करना, एक बहुत बड़ा कारनामा है। बीज–खाद की कोई समस्या इस बार मौके पर किसी किसान को नहीं आने दी गयी। जो इससे पुराने जमाने में किस कदर दिक्कतें फसल बोने के वक्त हुआ करती थीं। 'कामधेनु योजना', 'मिनी कामधेनु योजना' जो सरकार ने दूध के लिए चालू की है। एक ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश जब पूरी जरूरत ही पूरी नहीं करेगा, अगर यह पूरी तरह से लागू हो गयी तो यह इतनी अच्छी योजनायें हैं जिनको प्रेरित करने के लिए सरकार के द्वारा उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही की गयी है वह एक सराहनीय काम है। नगर विकास के क्षेत्र में गरीबों के लिए 'आसरा योजना'। तमाम नगरों में इतने–इतने मकान बनाए गए हैं जो गरीबों को दिए जा रहे हैं, कुछ दिए गए हैं। एक ऐसा उदाहरण है, जो गरीब को सिर छुपाने के लिए नगर विकास मंत्रालय से दिया गया है। रफीकुल मुल्क ट्रेनिंग सेंटर, जो नेता जी के नाम से लखनऊ में चलाया जा रहा है जिसमें उन गरीब बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को आगे बढ़ने के लिए स्टडी सेंटर बनाया गया है, ताकि वह विकास में, ताकि वह तरक्की में, ताकि वह शिक्षा में, उस सब में शामिल हो सकें जहां कि और वर्गों के लोग और सारे वह लोग शामिल हैं, जिन्हें सहूलियात मुहैया हैं। सारा इंतजाम सरकार उठाती है। 'राम सरन दास सड़क योजना' जो अनजुड़े गांव थे, जो अनजुड़े मजरे थे इसके तहत हजारों मजरों को जोड़ने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्य मंत्री जी की योजना के तहत बजट में प्रस्तावित किया गया। सबसे बड़ा काम अमल में लाया जा चुका है 'वुमेन पावर लाइन' 1090, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी कारगर साबित हुई है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब महिलायें पूरी तौर पर अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। सड़कें, पुल इनका पूरे प्रदेश में जाल बिछाया गया है। किसान वर्ष मनाये जाने का हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, वह यकीनन स्वागतयोग्य कदम है। कब्रिस्तान की बाउंड्री, कोई गांव, कोई क्षेत्र जब निकल जाये तो जंगल में जहां आबादी से दूर या आबादी के बीच में जो लोगों ने कब्जे कर रखे थे, जो लोगों ने इन्क्रोचमेण्ट कर रखे थे, उनको कब्जामुक्त करा कर कब्रिस्तान की बाउंड्री करायी गयी है। जो इस तरह का एक बड़ा काम है, जो बिल्कुल स्पष्ट दिखायी दे रहा है जो विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए और वह तमाम क्रियाघर, जो सभी उन सारी जगहों पर जहां–जहां जरूरी थी। बजट में प्रस्तावित किया गया, उन क्रियाघरों का काम कराया गया है। लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्र ग्राम और समाजवादी पेंशन जो 45 लाख लोगों से बढ़ाकर 55 लाख की जा रही है। सीधे–सीधे गरीब को 500 रुपये महीने का सहारा इतना बड़ा काम है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। मेरा क्षेत्र बिलारी जो दो जिलों में पड़ता है, सम्भल और मुरादाबाद। वहां अग्निशमन केन्द्र की स्थापना इसी बजट में की गई है। हमारे जिले में दूसरा अग्निशमन केन्द्र कांठ में प्रस्तावित किया गया

है। मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो इस तरह की घटनाएं होती थीं तो हमारे प्रस्ताव पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने पैसा मंजूर किया है और वह बहुत जल्दी बनना शुरु हो जाएगा लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हैं। जो हमारे सामने वाले लोग हैं उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। केवल एतराज नहीं करना चाहिए।

कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं किन्तु नहीं शरमाते लोग,
कैसे सुनाएं गीत ये दिल का, सत्य नहीं सुन पाते लोग।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो एतराज करना है, जो ऑबजेक्शन करना है, उसमें कोई लॉजिक तो होना चाहिए। केवल अपनी तरफ से विरोध करना, केवल गलत बताना, उसकी कोई वजह नजर नहीं आती है। हर चीज इस बात के साथ होनी चाहिए कि कोई सुझाव होना चाहिए, मुख्य मंत्री जी हमेशा सुझावों का स्वागत करते हैं लेकिन अगर केवल बुराई ही ढूंढनी है तो फिर यह अच्छा नहीं लगता। हम उस सपने को नहीं कहते जो किस तरह से दिखाए गए थे। एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं।

दिखाओ मत हमें अच्छे दिनों के ख्वाब भाई जी
मिठाई देखने से मुंह की कड़वाहट नहीं जाती।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में जो चीजें, जो प्रस्ताव, जो तमाम योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, वे स्वागत योग्य हैं और हमारे साथी जो सामने बैठे हैं, ये इस तरह के हालात हैं कि हमेशा तनकीद न की जाए बल्कि जो अच्छी चीज है, उसको बताया जाए और अपने सुझाव दिए जाएं। हमारी सरकार हमेशा इस बात का स्वागत करती है। मा0 मुख्य मंत्री जी जो निहायत काबिल, निहायत ही जिम्मेदार मुख्य मंत्री हैं उन्होंने हमेशा स्वागत किया है, विपक्षी दलों का स्वागत किया है। हमारे मा0 नगर विकास मंत्री जी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने महकमे में किस कदर काम किए हैं कि अब बनाने के लिए सड़कें शहरों में ढूंढने से नहीं मिल रही हैं। विकास के इतने काम हुए, पानी के इतने काम हुए, इतने प्रस्ताव दिए हैं। यकीनी तौर पर वे काबिल–ए–तारीफ हैं, सराहनीय हैं और मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का फिर इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बजट प्रस्ताव दिया है, वह स्वागत योग्य है। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, सामने वालों को एक संदेश भी देना चाहता हूं, अपने साथियों को संदेश देना चाहता हूं।

फूल के रंग को तितली के हवाले कर दें,
अब हम अहंकार को तुलसी के हवाले कर दें।

धन्यवाद।

श्री राधे श्याम–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें लोकतंत्र में चुनी गई हैं। सभी सरकारों ने बजट रखा है और बजट इसीलिए रखा जाता

है कि प्रदेश का विकास हो। यह बात सही है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और सरकार के द्वारा बहुत जगहों पर भेदभाव भी किया गया है। यह भी सही है। मैं जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद अमेठी से आता हूं। मैं सीधे–सीधे कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे जनपद अमेठी को बने हुए अभी लगभग 6 साल हुए हैं, नया जनपद है। वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार के द्वारा मेरे जनपद को गोमती नदी पर 3 पुल दिए गए हैं और यह भी सही बात है कि समय रहते लगभग 90 परसेन्ट पुल कम्प्लीट भी हो गए हैं लेकिन 10 परसेन्ट में एप्रोच का काम जिसके लिए धन की मांग की गयी उसमें किसान का मुआवजा भी है, सम्पर्क मार्ग से पुल तक जोड़ने का काम भी है उसके लिए धन नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूं कि एप्रोच का धन विभाग को रिलीज कर दिया जाए ताकि जनता में उसका उपयोग होने लगे। हमारे यहां राजकीय बालिका इण्टर कालेज है। पिछले कई वर्षों से उसका निर्माण कार्य चल रहा है, बाजार शुक्ल में है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उसको पूर्ण कराया जाए। संजय गांधी पॉलिटेक्निक इंडस्ट्रियल एरिया में है, छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य चल रहा है, वह भी काफी समय पहले से चालू हो गया लेकिन छात्रावास का भवन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। इसके साथ–साथ विद्युत उपकेन्द्र कौरी हमारा है, वहां पर 5 मेगावाट का ट्रान्सफार्मर और लगभग 5 किलोमीटर की एक लाईन बनने का प्रस्ताव पॉवर कारपोरेशन का आया है जिस पर यदि उसका धन रिलीज कर दिया जाए तो जैसा सरकार की घोषणा है कि हम जिले को, शहर को, मण्डल मुख्यालय को इतने–इतने घंटे बिजली देने का काम करेंगे तो शायद उससे जनता को सुविधा मिलेगी। एक अहम बात है जिस पर मैं पिछले कई बार से कह रहा हूं, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति होता है, मेरी समझ से आज के दौर में वही करोसिन का उपयोग करता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 6–6 महीने तेल नहीं मिलता है और मैं यह भी कह रहा हूं सदन में कि तेल नहीं मिल रहा है उसमें सत्ता के लोग शामिल हैं। तेल के बदले में जो कोटेदार होते हैं, उनको 2000 रुपये प्रति ड्रम दिया जाता है, तेल नहीं दिया जाता है। अगर कोटेदार एक बार से दो बार जहां पर उसका डिपो है, अगर वह अपनी आवाज उठाये कि मुझे तेल क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसको बंद करके मारा भी जाता है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी लाख कहे कि हम जनता की भलाई के लिए, जनता की अच्छाई के लिए बेहतर काम कर रहे हैं जैसे कभी–कभी संसदीय कार्य मंत्री जी अभी नहीं है, वह ये कहते हैं कि मेरी लाख अच्छाई, कोई न कोई एक वजह होती है, कोई कारण होता है उसमें घुल जाती है। इसके साथ–साथ कहना चाहूंगा कि जगदीशपुर कस्बा है, लगभग 15–16 हजार की आबादी है, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए कई बार चिट्ठी लिखी गई। डी0एम0 अमेठी के द्वारा डी0ओ0 आर्डर भी आया, भरोसा था कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो जायेगी, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हुआ। अभी एक साथ विपक्ष के कह रहे थे कि कोई काम नहीं करना होता है तो एक चिट्ठी चली जाती है कि वित्तीय संसाधन नहीं होने के कारण यह कार्य नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह कहता हूं अभी मेरे बगल में

सत्ता के विधायक हैं एक तहसील की घोषणा कर दी गई। तहसील बन जायेगी, जनता को सुविधा मिलेगी उसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं, मैं सरकार को बधाई देता हूं। माननीय गोप साहब बैठे हुए हैं, मेरा क्षेत्र दो जिलों में आता है। सरकार ने कैबिनेट की अपनी बैठक में फैसला लिया कि कानूनगो हलियापुर को अमेठी जनपद में जोड़ दिया जायेगा। कम से कम 9 महीने हो गए तथा हलियापुर को वि0 खण्ड का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई मै माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि उसको अमेठी में शामिल कर दिया जाये बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको ब्लाक का भी दर्जा दे दिया जाये ताकि वहां की जो हमारी 28 ग्राम सभा हैं, जगदीशपुर ब्लाक की 71 ग्राम सभा हैं, मुसाफिर खाना ब्लाक की 54 ग्राम सभा हैं अगर इसमें से एक–एक न्याय पंचायत को हम काट भी देंगे (तो एक बेहतर मीडियम क्लास का हलियापुर ब्लाक हो जायेगा) और पूरी जनता–जनार्दन को उससे सुविधा मिलेगी और सरकार का यश होगा और उसके लिए मै अनुरोध करता हूं कि शायद माननीय मंत्री जी हमारी बात को सुने है जरूर कुछ न कुछ हो जायेगा इसके साथ–साथ एक गांव हमारा लोहिया मे चयन किया गया था। चूकि सत्ता के जो हैं वो ज्यादा ले लेते हैं, हमारे जनपद के माननीय मंत्री जी हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यह लोग कहते हैं कि हम किसी के साथ भेद–भाव नहीं करेंगे। अफसोस इसी बात का है, मेरे जनपद का 29 का कोटा था कि मेरे जिले मे 29 लोहिया गांव जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने अपनी विधान सभा में 16 गांव लिया, सत्ता के दूसरे विधायक ने अपनी विधान सभा मे 10 गांव लिया मेरी विधान सभा मे सिर्फ 3 गांव मेरे कहने पर मिला। इसके लिए भी मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने दो ही दे दिया। बगल की विधान सभा को 2 मिला। आप सही कह रहे हैं किसी को एक भी नहीं मिला, आपकी बात सही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि कथनी और करनी में जो फक्र है आप सम्मानित माननीय मंत्री जी है, सरकार है शपथ लेते समय यह कहती है कि हम किसी के साथ भेद–भाव नहीं करेंगे लेकिन शपथ के बाद जब हाउस में आते हैं तो पहले वहीं से शुरू हो जाता है कि हम भेद–भाव जरूर करेंगे और गिन–गिन कर करेंगे और वो आप लोग करते भी हैं, दोनो चीजें करते हैं। एक तो लोहिया का हमारा बिल्कुल हाई–वे से डेढ किलोमीटर दूर मगरौरा है, जगदीशपुर ब्लाक का। मेरी विधान सभा में मैं मानता हूं कि लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का रिन्यूअल करवाया है इस सरकार ने मैं उसके लिए अपनी विधान सभा की तरफ से धन्यवाद देता हूं लेकिन इस लोहिया गांव की सड़क को ठीक कराने के लिए बराबर इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से, सारे लोगों से लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है कि यह गांव की सड़क को नहीं ले रहे हैं उसके बदले दूसरे गांव की सड़क ले लेते हैं। मैं एक मिनट मे अपनी बात खत्म कर रहा हूं इसके साथ–साथ जहां सरकार कह रही है ब्लाक मुख्यालय से हम फोर लेन की सड़क जिला मुख्यालय को टच करेंगे, बनवायेंगे कहीं–कहीं बन भी रही है यह भी बात सही है लेकिन मेरे ब्लाक से दो सड़कें आती हैं जो जिला मुख्यालय को टच करती हैं, सुकुल बाजार से जगदीश पुर, सुकुल बाजार से रानीगंज होते हुए हाई–वे तक आती हैं। यह दो सड़कें अत्यन्त खराब

हैं, इन सड़कों का स्टीमेट भी आया हुआ है यहां पर उसका धन रिलीज करा दें तो जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री लोकेश दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, मैं अपने विपक्ष के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने आप में सम्बद्ध करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार हम अपने आप से भी प्रश्न करते हैं और सोच–विचार करते हैं कि हमारे बागपत ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारा जिला बागपत है। कोई भी योजना हमारे बागपत के लिए नहीं है, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि आज तक वहां पर बस अड्डा भी नही है। उस बस अड्डे के लिए कई बार हमने कहा पर उस पर कोई विचार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे हम पहली बार विधायक चुनकर आये हैं हमे बताया गया था कि इतना भेद–भाव होगा तुम्हारे साथ जितना भेद–भाव तो सौतेली मां भी नही करती बच्चे के साथ। यह सुनकर देखकर बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत मे हम लोग आयें हैं हमे बोलने का मौका तो जरूर मिलता है, हम बोलते भी हैं पर हमे एहसास यह होता है कि किसी ने हमसे कहा था कि आपकी बातों पर विचार भी यह लोग नही कहेंगे, आज कुछ बात को देखकर लगता है कि वह सत्य था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत, गन्ना जिला प्रदेश का सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मिठास बागपत देता है चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है वह, जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया वहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप किसान गन्ने की बात करते हैं। कोई ज्यादा कह दो माननीय मंत्री आजम साहब बिगड़ जाते हैं, मील बेच दी फलाना कर दिया, भाई हमने जो किया तुम क्या कर रहे हो तुम तो बताओ। भाई, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतनी घृणा क्यों ? बागपत से इतनी घृणा क्यों ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गन्ने का किसान घर में नहीं रो सकता क्योंकि घर में महिलाएं रहती हैं वह जब खेतों में जाता है तो खून के आंसू रोता है। उसको एहसास होता है उधर तो केन्द्र में बैठी हुई मोदी सरकार और मोदी जी का 56 इंच का सीना कहां चला गया। एक दो लाख से नहीं पांच–पांच लाख से सांसद जिता दिये और मोदी जी तो भइया आ नहीं रहे इधर। इस सरकार में कहते थे कि नेता जी किसान के हैं, धरती पुत्र कहते हैं। भाई, हमें तो यह नहीं पता लगा सके कि पुत्र है किसका धरती का है मां का है, किसका है। किसान वहीं रो रहा है, परेशान है उसकी आत्मा रोती है वह कहता है वोट दिया सपोट दिया, लड़े मरे फिर दुर्गति हो गयी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, तीन लाख सैंतालिस हजार करोड़ के आस–पास का बजट। भला सा आदमी लगावे जीरो तो लगाना भूल जाय और हुआ क्या, हमारी बड़ौत सीएचसी में कल 4–5 लोग चले गये फिर उन्होंने फोन किया सुबह मुझे कि विधायक जी, कुत्ते काटने के इंजेक्शन भी नहीं हैं। मैंने कहा मेरी डाक्टर से बात कराओ, डाक्टर साहब

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोले, बागपत से नहीं आये वहां पर भी नहीं है और इतना मोटा बजट। भाई कुत्ते के काटने के कम से कम इंजेक्शन ही भिजवा दो, सड़क तुम बनवाओगे नहीं, लड़के हमारे तुम लगाओगे नहीं, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है माननीय अधिष्ठाता महोदय, सुना था पहले कि राजा बहुत क्रूर होता है पर यह राजा तो बहुत नरम आदमी है सीधा आदमी तो इतना जो अपराध किया जा रहा है और कटघरे में किसान खड़ा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं 4 साल से मैं विधायक हूं पांचवी साल चल रहा है और पांचवा बजट है। बड़ौत में तहसील के सामने, माननीय मंत्री जी सो नहीं सुन लो मेरी बात, तहसील के सामने, माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कहें किससे, तहसील के सामने एक कब्रिस्तान है जो खाते में दर्ज है, खतौनी में दर्ज है, सब लेटेस्ट और एक बहुत बड़ा जेहोड़ जिसको तालाब कहा जाता है। खाते में है, खतौनी में है, लेटेस्ट फर्द भी है यह क्या है माता के भांग यानि माता का मन्दिर। मैं चार साल से इस पंचायत में, सांसद का चुनाव लड़े, चार साल से मैं बराबर इस हाउस में उसको चर्चा में ला रहा हूं, 51 में लगा रहा हूँ, 56 में लगा रहा हूं। भाई, सरकार की सम्पत्ति है इसको बचा लो, 100 करोड़ से ऊपर की जमीन है जो खाता खतौनी में है, सिजरे में है, फर्द में है, हुआ क्या ? जब हमने ज्यादा उसकी सख्ती करी, कमिश्नर ने कहा कि हां इसके अन्दर तो कब्रिस्तान है। हुआ क्या बड़े बड़े माफिया भी आ गये, कई सौ करोड़ का मामला है जब कमिश्नर ने सख्ती की छापा पड़ा तमाम राइफलें बन्दूक और बारूद पकड़ा गया। माननीय एसडीएम साहब ने 151 में 5 मिनट में जमानत करके भू–माफियाओं को छोड़ दिया। हुआ क्या, उन लोगों ने मेरे ऊपर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करा दिया। जो व्यक्ति चार साल से लड़ाई लड़ रहा है कब्रिस्तान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बराबर में हाईकोर्ट तक चला गया रिट डालने के लिए, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा पर्सनल मामला है, मुकदमा एक नहीं चाहे दस करा दो कोई दिक्कत नहीं, झेलेंगे। झेलेंगे। बता दिया था मगर मजबूर हूं। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप अधिकारियों से संज्ञान ले लें। मैंने वर्ष 2005 में राजनीति शुरू की थी, 2005 में मैं जिला पंचायत मेम्बर बना और आज मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं। कोई एस0पी0, सी0ओ0, कोतवाल किसी भी थाने का दरोगा अगर यह कह दे कि लोकेश दीक्षित ने किसी अपराधी के लिए फोन भी किया हो, तो मैं इस सदन से ही नहीं, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश से ही चला जाऊंगा। मैंने कभी किसी अपराधी के लिए फोन नहीं किया, मैंने जीवन में कभी किसी अपराधी को बचाने के लिए कप्तान, सी0ओ0, कोतवाल को कभी फोन नहीं किया। इसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार और सरकार के मंत्री कहते हैं कि कब्रिस्तान हम बचायेंगे, मुसलमानों को हम बचायेंगे। वह हिन्दुओं का ठेका लिये बैठे हैं, यह मुसलमानों का ठेका लिये बैठे हैं। लगता है कि यह मिले–जुले लोग इस प्रदेश का नुकसान करके रहेंगे, इसको बर्बाद करके रहेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा पूरा जिला डार्क जोन में है। यह गन्ना उत्पादक जिला है और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके बावजूद भी इसे डार्क जोन में कर दिया गया है। यहां पर लोग नया कनेक्शन लगा नहीं सकते हैं, नया

ट्यूबवेल लगा नहीं सकते हैं, यहां पर गन्ना किसान बर्बाद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको डार्क जोन से हटाया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री लोकेश दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर किसी का मोटर या सबमर्सिबल पांच हार्स पावर का है, तो उसको पन्द्रह का देना पड़ता है, उसको साढ़े बारह का देना पड़ता है। यह कैसी किसानों की सरकार है मैं कहना चाहता हूं। अरे बड़ी–बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना बर्बाद हो जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार प्रकट कर रही हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2016–17 का बजट पेश किया है। बहुत बृहद बजट है, आशा भरा बजट है, लेकिन आशा पूरी होगी, ऐसा लगता नहीं है। इस बजट में पूंजी निवेश 4394 करोड़ का है और इसमें 349229 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आश्चर्य कि कोई बड़ा उद्योग नहीं खोला जा रहा है। न तो पिछले चार सालों में कोई उद्योग खोला गया है और न पांचवे साल बजट में लिया गया है। सारे रोजगार जो मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग देंगे, उसके आधार पर यह आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। इसलिये बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें रोजगार मिलेगा, यह सोचा नहीं जा रहा है। इस बजट में सीवर लाईन की सफाई की बात कही गई है, सफाई कर्मचारी सीवर लाइन की सफाई करते वक्त अगर मत्यु को प्राप्त हो जाये, तो उसके परिवार को राहत सहायता दी जायेगी। आश्चर्य है कि यह सीवर लाइन बहुत गहरी होती है। जनपद वाराणसी के गौधुलिया, जो शहर का केन्द्र बिन्दु है, वहां की सीवर लाइन 40 से 45 फिट नीचे है, इसीलिये कभी कोई जमादार सफाई करने नहीं जाता, अगर किसी कारण से कोई उतरा तो रस्सा पकड़कर नीचे उतरता है और अगर ऊपर रस्सा पकड़ने वाले का हाथ ढ़ीला हो जाये, तो मत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिये कोई जमादार जल्दी तैयार नहीं होता है। तीन–चार साल पहले गौधुलिया की मेन सड़क पर सीवर का पानी बह रहा था। हमारे बहुत चिल्लाने के बाद धरना–प्रदर्शन करने के बाद सीवर की सफाई शुरू हुई। मैं भी गौधुलिया रात एक बजे देखने को पहुंच गई कि क्या होता है, तो हमारा दिल एकदम दहल उठा कि जाड़े का मौसम आधी रात आदमी नीचे उतर रहा है और अगर कुछ हो जाये तो उस बेचारे का जीवन खत्म हो जायेगा। मैंने वहां के जिलाधिकारी को उसी समय रात को फोन किया। इस समय वह शासन में विशेष सचिव हैं श्री प्रान्जल यादव, उस समय वहां डी0एम0 थे उन्होंने फोन उठाया और कहा कि मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। वास्तव में बजट में इस प्रकार के कल्याणकारी काम होने

चाहिये। अगर वास्तव में कार्य करना है तो सीवर सफाई के लिये बड़ी मशीन की व्यवस्था करनी चाहिये। यह मशीन वाराणसी में नहीं है। हो सकता है कि बहुत से शहरों में भी न हो लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे। इसमें जो कहा गया है कि कार्य करते वक्त सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार को राहत दी जायेगी। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि कर्मचारी शब्द हटा दिया जाय क्योंकि जो भी व्यक्ति ठेके पर, कान्ट्रेक्ट पर या संविदा पर सीवर सफाई करने नीचे उतर रहा है और उसके जीवन को खतरा हो गया तो उसको राहत देना चाहिये, उस समय यह कर्मचारी है कि नहीं है, यह देखना नहीं चाहिये।

मान्यवर, सरकार ने 60 करोड़ रुपया आवास हेतु रखा है और मेरा अपना कहना है कि आवास सब लोग किश्त पर नहीं ले सकते। जो कैन्ट स्टेशन पर पड़े हैं जो पुलों के नीचे रात काट रहे हैं, नहरों के किनारे पड़े हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं, कि वह सरकारी किश्त जमा करें और सरकार के सस्ते आवास लें। एक प्रतिशत, दो प्रतिशत कुछ ऐसे मकान ऐसे लोगों को फ्री दे देना चाहिये जो इस प्रकार सड़कों के किनारे जिन्दगी काट रहे हैं। जिनके बच्चे कपड़े के तम्बू में रहते हैं जो सामने बिल्डिंग पर पंखा चलते हुये बच्चों को ऐश करते देखते हैं, उनका मन विद्रोह कर जाता होगा, इस प्रकार से कैन्ट स्टेशन पर जो खुला परिवार पड़ा रहता है, उसकी औरतें गलत रास्ते जा सकती हैं इसलिये जरूरी है कि कुछ एक प्रतिशत लोक कल्याण के नाम पर इन गरीबों को मकान आवंटित किया जाय। इसी बीच बनारस में एक बहुत खराब स्थिति पैदा हो गयी है। सन् 1990–91 में विकास प्राधिकरण ने अल्प आय वालों को कुछ मकान कर्जे पर दिया था जो 2 हजार रूपया तनख्वाह पाते हैं, कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, या किसी के यहां क्लर्क हैं, 4 हजार पाते हैं, 8 हजार पाते हैं, इससे ज्यादा आय वालों को वह मकान नहीं मिले हैं। लेकिन 1990–91 में जो मकान दिये गये थे, उन्होंने आज उसका सारा किश्त जितना उसका मूल्य था, मूल्य प्लस उसका सारा ब्याज पे कर दिया है, जितने का मकान था उसका डबल पे कर दिया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके मकान निरस्त किये जा रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक चिठ्ठी प्रमुख सचिव को लिखी थी कि इस प्रकार लोग जो दुगना सूद पेमेंट कर चुके हैं, टैक्स पर सूद में छूट दिया जाय एक निश्चित राशि भले उनसे ले लिया जाय, उसकी निश्चित अवधि तय हो जाय तो सरकार ने इतना ध्यान दिया कि चिठ्ठी का यह जवाब दिया कि 16 मार्च तक सारा पैसा वह अदा कर दें तो उनका ऋण माफ हो जायेगा। अब वह 16 मार्च तक कैसे अदा करें, यह एक बहुत कठिन विषय है। एक आदमी जो 70 हजार के फ्लैट पर 4 लाख का कर्जदार है, वह बहुत से बैकों में 4 लाख या कुछ धन के लिये कर्ज लेने के लिये दौड़ा, किसी बैंक ने उसको कर्ज नहीं दिया और कहा कि हम 8 हजार तनख्वाह पाने वाले को कर्ज नहीं देंगे क्योंकि तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे। अब सरकार को सोचना चाहिये कि इतना रूपया जो जमा कर चुका है अब आप उसका मकान निरस्त करेंगें जो इतने दिन अपने बच्चों का दूध–दही का पैसा काटकर आपको रुपये पर रुपया देता गया है तो फिर वह क्या सड़क का भिखारी बन

जायेगा, इसलिये सरकार कोई रास्ता निकाले और इस प्रकार से कम आय वालों को जब मकान दिया जाता है तो उसकी सुविधा और राहत की बात भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

मान्यवर, सरकार कहती है कि हम लोक कल्याण कर रहे हैं आपके प्रति वर्ष के बजट में समाज कल्याण पर होने वाला खर्च का प्रतिशत खर्च निरन्तर घटता जा रहा है। सन् 2012–13 में सरकार ने सम्पूर्ण बजट का 7.9 परसेंट समाज कल्याण पर खर्च किया था आज 2016–17 के बजट में यह घटकर 2.98 प्रतिशत हो गया है। समाज कल्याण पर जो सरकार जितना खर्च करती है वह लोक कल्याण का हित कर रही है, यह समझा जाता है। लेकिन जिस सरकार के बजट में समाज कल्याण पर लगातार खर्च प्रतिशत घटता जा रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं। इसी प्रकार से बेसिक शिक्षा पर सरकार के सम्पूर्ण शिक्षा बजट का केवल 2 परसेंट खर्च हो रहा है आप समझिये कि बेसिक शिक्षा समाज की रीढ़ होती है बेसिक शिक्षा पर सारे सम्पूर्ण जीवन की उन्नति की नींव पड़ती है आज जब अनिवार्य सर्वशिक्षा अभियान चल रहा है। बेसिक शिक्षा पर पूरे बजट का मात्र 2 परसेंट खर्च हो रहा है तो निश्चित यह लक्षण भी अच्छा नहीं है। सरकार कहती है कि हम बड़े–बड़े डिग्री कालेज खोल रहे हैं। बनारस में राम नगर एक जगह है। वहां न तो कोई निजी डिग्री कालेज है और न वहॉ कोई सरकारी डिग्री कालेज है। वहां के बच्चों को जब स्नातक पढ़ाई करनी होती है तो गंगा पार करना पड़ता है और गंगा पार करने के लिये डेढ़ से दो घन्टे का समय लग जाता है। जो पुल बन रहा है वह तो बीरबल की खिचड़ी पक रही है। लड़के तो स्कूटर और मोटरसाइकिल पर आ भी जाते हैं बी0एच0यू0 में प्रवेश की कोशिश करते हैं जो बड़ा कठिन है वह दूसरे कालेजों से स्नातक कर लेते हैं। लेकिन बेचारी लड़कियों की पढ़ाई रूक जाती है इसलिये सरकार जो डिग्री कालेज खोल रही है उसके अन्तर्गत राम नगर में भी डिग्री कालेज खोल दिया जाय, ऐसी हम दोनों हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना करते हैं, इस पर ध्यान दें और एक डिग्री कॉलेज खासकर रामनगर में लड़कियों के लिए खोल दिया जाए। मान्यवर, मैंने तो अभी दो मिनट भी नहीं बोला है। यू0पी0 में जो ऑलरेडी पहले से कॉलेजेज हैं उन कॉलेजों के मेंटीनेंस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राम नगर में इंटरमीडिएट सरकारी कॉलेज हैं न तो वहां पर पंखा है और न दरवाजे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं लड़कियों के सरकारी इण्टर कालेज ने यहां तक कि कोई बाथरूम तक नहीं है बाथरूम लड़कियों के कॉलेज में भी नहीं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी से सिफारिश की गई थी तो लड़कियों के कॉलेज में लैट्रीन बाथरूम बना दिया है लेकिन राम नगर के लड़कों का जो डिग्री कॉलेज है वहां अभी तक यह व्यवस्था नहीं हुई है यह पकड़ में तब आया जब बाढ़ आई थी और लोग उस कॉलेज में भर गये थे। अन्त में यह शिक्षा की जो व्यवस्था है वह भी बैलेन्स्ड नहीं है, हम देख रहे हैं कि उसमें भी बेसिक शिक्षा में जो खर्च हो रहा है उसमें भी पक्षपात है। सरकार हर प्रकार की शिक्षा पर खर्च कर रही है तो संस्कृत कॉलेजों को क्यों भूल गई किसी भी संस्कृत पाठशाला में एक पैसा भी सरकार सहायता के लिए नहीं दे रही है। बनारस में इस प्रकार के वैदिक कॉलेज और संस्कृत पाठशालाएं

भरी हुई हैं जहां अभी भी वैदिक साहित्य का अध्ययन हो रहा है विभिन्न इन आश्रमों को लोग उन्हें अपने पास से पैसा दे करके चला रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया है कि उनको भी कुछ सरकारी सहायता दे दी जाए। इसके अलावा सरकार ने बुनकरों के बिजली में राहत देने की बात कही है, बुनकर करीब–करीब हर जिले में हैं लेकिन बनारस में बहुत बड़ी संख्या में लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर भी हैं। उन कारीगरों की पुरानी मांग है कि हमें भी बिजली के रेट में सब्सिडी दी जाए, फिरोजाबाद में चूड़ी के कारखाने हैं, हर जिले में कोई न कोई कारीगरी है तो मान्यवर, इन कारीगरों पर भी सरकार ध्यान दे। कारीगर कारीगर होते हैं वह सभी दलाल का शिकार होते हैं उनको अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता इसलिए यदि बिजली में वह सब्सिडी की मांग कर रहे हैं और सरकार बुनकरों को दे रही है तो मेरी प्रार्थना है कि जो लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर हैं जो कि बनारस की प्रसिद्ध कारीगरी है उन कारीगरों को भी बिजली में सब्सिडी दी जाए। अन्त में इतना जरूर कहेंगे कि पॉवरलूम के विकास के लिए सरकार ने ध्यान दिया है, पॉवरलूम कुछ भी हो एक छोटी मशीन होती है लेकिन बनारस में हथकरघा उद्योग बहुत अच्छा है जो वास्तव में एक प्रकार से कलात्मक उद्योग है जहां कारीगर अपनी कला दिखाता है, हथकरघा उद्योग को कोई सहायता नहीं दी जा रही है पॉवरलूम को सहायता दी जा रही है यह भी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है हथकरघा उद्योग पर भी ध्यान दिया जाए। मान्यवर, अन्त में एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि 7 करोड़ रुपया सरकार ने आवास के लिए निर्धारित किया है कितना आवास होगा इसकी कोई गणना नहीं है हमारे कितने लोग बिना आवास के हैं कितने आवासों की आवश्यकता है, एक साल में कितने होने चाहिए, हम कितना दें कि सभी लोगों को आवास मिल जाए इसका कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है। मैं आपके आदेश को मान रही हूं और अपनी बात को यही समाप्त करती हूं, मेरा आपसे अनुरोध है कि विकास प्राधिकरण की जो बात मैंने कही है उसे सरकार के पास पहुंचा दीजिए कि किसी आदमी को उसके मकान से निरस्त न किया जाए।

'श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट भाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो 2016–2017 का बजट प्रस्तुत किया है इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे वह दिन भी याद है इसमें से बहुत से हमारे साथी उस समय थे और पूरे साल का बजट मात्र तीन मिनट में पास हो चुका है। आज मैं अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी मा0 सदस्यों की बातों को सुना है और बहुत से हमारे साथी जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी बातों को भी धैर्य से सुनकर काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया होगा। पिछली बार की सरकार में आपने देखा कि खाद के लिए, किसानों को खाद तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं मिलती थी लाठियां मिलती थी, उनकी साइकिलें भी चोरी चली जाती थी। आज हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई किसान नहीं कह सकता है कि उसको खाद, बीज नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, उस ऐतिहासिक काम में आप चाहे 102, 108 नम्बर देख लीजिए और तो और गांव–गांव के अंदर ग्रामीणों को दवायें मिल रही हैं, इंजेक्शन मिल रहे हैं और यहां तक अल्ट्रासाउण्ड और एक्स–रे की सुविधा निःशुल्क कर दी गयी है। पिछली बार की सरकारों में कुत्ते काटने तक की दवा, इंजेक्शन नहीं मिलते थे, लोगों को बाहर से जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे।

श्री लोकेश दीक्षित–

आज भी कुत्ते की दवा नहीं मिल रही है।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

आप बता दीजिए इसी सदन में, कहां नहीं है, आप बता दीजिए। कुत्ते काटने की, बंदर काटने की बहुत सारी दवायें हैं, जहां न मिले आप बता देना। जहां नहीं होगा वहां के सी0एम0ओ0 सस्पैंड हो जायेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये दवायें न हो।

श्री लोकेश दीक्षित–

कहीं नही है।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

आपको काटा हो, आप बता दीजिए या आपने जिसको भेजा हो उसको दवा न मिली हो। आपके यहां अगर किसी को काटा हो तो बता दीजिए।

श्री लोकेश दीक्षित–

हमें कैसे काट सकता है, वह कुत्ता ही मर जायेगा।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

पहचानता है कि साथ में हैं इसलिए नहीं काटता है।

श्री अधिष्ठाता–

अनूप गुप्ता जी आपस में बात न कीजिए। आप बजट पर अपनी बात रखिये।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, इसी प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ है यह आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने चाहे नहरों का पानी हो चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, किसानों को सिंचाई मुफ्त कर दी है। दवाई मुफ्त मिल रही है, पढ़ाई मुफ्त हो रही है, और क्या चाहते हो ? (ब0स0पा0 के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) बता दो गुण्डागर्दी कहां होती है ? हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने गरीब लोगों को बैटरी चालित रिक्शा देने का काम किया है। जो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए शहरों में आते थे उनको किराये के ऊपर रिक्शा लेना पड़ता था, आज उनको बैटरी रिक्शा निःशुल्क दिया जा रहा है जिससे उनकी आजीविका चल पा रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों ने आज तक कभी भी अपने क्षेत्र या कहीं दूसरी जगह के गरीब लोगों के इलाज के लिए चिट्ठी लिखी हो और उसको अनुदान/सहायता न मिली हो। (ब0स0पा0 के

सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर) डरते हो इसलिए नहीं लिखते हो चिट्ठी कि बहन जी नाराज न हो जांए, बहन जी जान जायेंगी इसलिए नहीं लिखते हो। लिख दो और न मिले तो आप बता देना। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इलाज के लिए उन बेसहारा लोगों को जो गम्भीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, बहुत अनुदान दिया है। मैंने खुद अपनी विधान सभा क्षेत्र के अंदर कई लोगों को इलाज के लिए चाहे पी0जी0आई0 से आया हो, चाहे डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आया हो, चाहे कैन्सर के अस्पताल का आया हो, चाहे जितना बड़ा उसका बजट हो, चाहे 8 लाख या 10 लाख का हो जो व्यक्ति अपना खेत बेचकर भी इलाज नहीं करा पाता था उन सब को भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने असहाय रोग के लिये पैसा देने का काम किया है। इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अंत में यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपने आप को माननीय नेता विरोधी दल आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी के भाषण के साथ सम्बद्ध करता हूं। हमारे बड़े भाई और सीनियर नेता भाई अनूप जी अभी बता रहे थे कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में खाद मांगने पर लाठी चली। लेकिन यह भूल गये कि बुन्देलखण्ड में कितना भयानक सूखा पड़ा और सूखे से किसानों की फसलें बर्बाद हुईं और उनकी कुछ पैदावार नहीं हुई। वह लोग अपनी बात को रखने के लिये इकट्ठा हुए थे और उन पर लाठी चार्ज किया गया इसी सरकार में। इसी सरकार में उन पर भयानक लाठी चार्ज हुआ जिसमें कई किसान घायल हुए। हमारे काबिल दोस्त अभी उधर से बता रहे थे कि किसानों के लिये, किसानों को बहुत ज्यादा सुविधाएं और सहूलियतें दी गई लेकिन जिस तरीके से गेहूं का किसान, धान का किसान, आलू का किसान आज ठगा महसूस कर रहा है। सरकारी क्रय केन्द्रों पर उसके गेहूं और धान औने पौने दामों पर बिचौलियों के द्वारा खरीदा जाता है और उसको मंडी में जा करके वह बिचौलिये उसको बेचते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर वास्तविक किसान है तो वह अपनी फसल बहुत अप्रोच लगाने के बाद, बहुत सिफारिश कराने के बाद भी अपनी फसल उन क्रय केन्द्रों पर नहीं बेच पाया। जहां तक गन्ना किसानों की जब बात आती है तो सदन में वही पुरानी रटी रटाई बातें बताई जाती हैं कि यह चीनी मिल बेच दी गई, वह चीनी मिल बेच दी गई। मैं आज अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि मैं गन्ने का किसान हूं, गन्ने के किसान की पीड़ा जानता हूं। यह गन्ने का रेट 125 रुपये से 250 रूपये बढ़ाने का काम हमारी नेता बहिन सुश्री मायावती जी ने किया और उत्तर प्रदेश में पहली बार गन्ना किसानों को उनके बकाये पर ब्याज दिलाने का काम उत्तर प्रदेश में बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया। आप लोग इस सरकार की बात करते हैं। सरकार अपनी हनक और इकबाल खो चुकी है। गन्ना की

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिजर्वेशन मीटिंग में चीनी मिल मालिकों को बुलाया जाता है, हम जनप्रतिनिधि भी आज गन्ना रिजर्वेशन मीटिंगों में जाते हैं, चीनी मिल मालिकों ने साफ इंकार कर दिया कि मैं इस रिजर्वेशन मीटिंग में नहीं जाऊंगा। क्या वजह है, क्या कारण है कि चीनी मिल मालिक आज इतना बेबाक हो गये हैं और घटतौली जानकर वह कर रहे हैं और घटतौली करने के साथ साथ सरकार को अपनी मॉगे मनवाने के लिये बाध्य कर रहे हैं। 240 रुपये का रेट पिछली बार दो किश्तों में दिया। 240 और 230 रुपये का रेट चीनी मिल मालिकों ने दिया और 40 रुपये का रेट उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुदान के रूप में उन चीनी मिल मालिकों को दिया और तब भी पूरा बकाया पिछले वर्ष का अब भी हजारों करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। पिछले वर्ष 240 हर चीज चीनी की कीमत बढ़ी तब चीनी 2400 रुपये 2500 रुपये क्विंटल थी और आज 3100 सौ रुपये और 3200 रुपये क्विंटल है। और तब चीनी का परता अगर साढ़े आठ और नौ परसेन्ट रिकवरी थी तो आज चीनी की रिकवरी 10 और 11 परसेन्ट है। रिकवरी बढ़ गई, रेट बढ़ गये लेकिन चीनी के मूल्य में उन्होंने 40 रुपये से घटाकर 230 रुपये सरकार से मनवाने का काम किया। 50 रुपये इस वर्ष सरकार अनुदान के रूप में दे रही है। कौन सी ऐसी मजबूरी है कि चीनी मिल मालिकों को अनुदान दिया जा रहा है रॉ–मैटीरियल पर। चीनी मिल मालिको को अनुदान दिया जा रहा है डीजल की खरीद पर। अरे किसानों की सरकार, किसान वर्ष मना रहे हैं। हम भी अचंभित होते हैं जब यहां पर घोषणा की जाती है कि यह पयर्टन वर्ष मनाया जायेगा, यह युवा वर्ष मनाया जायेगा और यह किसान वर्ष मनाया जायेगा। समझ में नहीं आता है कि यह सरकार कौन सा वर्ष मनाना चाहती है। किसानों के बीच में जाती है तो किसान वर्ष। युवाओं के बीच में जाती है तो युवा वर्ष। पर्यटन के बीच जाती है तो पर्यटन वर्ष। सिर्फ कोई वर्ष नहीं मनाना चाह रही है यह अपना अंतिम वर्ष मनाना चाह रही है जो इस सरकार के कार्य–काल का अंतिम वर्ष है, यह मना रही है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 50 रुपये क्विंटल सब्सीडी चीनी मिल मालिकों को बीस रुपये प्रति लीटर डीजल पर सब्सिडी लेकिन गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब, लाचार, व्यक्ति आज गांव में रहता है आज दो साल से दाल की कीमत दो सौ रुपये डेढ़ सौ के ऊपर है। चालीस रुपये, पचास रुपये, साठ रुपये कुंतल दाल तब मिलती थी जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तब गरीबों की थाली में दाल नसीब होती थी, आज दाल गायब है क्या प्रदेश सरकार ने कभी यह प्रयास किया कि गरीबों को मिलने वाली दाल के लिए पचास रुपये और साठ रुपये अनुदान दिया जाए। क्या प्रदेश सरकार ने, केन्द्र सरकार ने, प्रयास किया कि गरीब आदमी जो गांव में रहता है उनको दाल दी जाए। आज जब अनाज तैयार होता है तब उस अनाज को, खरीदने के लिए वह कहां जाता है जब उसका अनाज आलू,प्याज, लहसुन, तिलहन, दलहन, जब उसके हाथ से निकलकर बाजार में बिचौलियों के हाथ में जाता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। वजह क्या है अधिष्ठाता महोदय, वजह साफ है मान्यवर, कि हम किसानों के पास उसको स्टॉक करने की, उसको रखने की कोई जगह नहीं है हम अपना अगर पचास कुन्टल, सौ कुन्तल गेहूं

पैदा करें, तिलहन पैदा करें, हल्दी पैदा करें, मिर्चा, आलू, अदरक, धनिया, लहसुन पैदा करें तो उसको हम कहां रखें, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। रहने की जगह तो छोड़िये आज गांव में हमारे पास रहने की जगह नहीं है। मोदी जी, जो झूठ बोलकर सरकार बनायी जो भ्रामक प्रचार किया कि हम 15–15 लाख रुपये देंगे देश की सीमायें सुरक्षित रहेंगी । काला धन हम वापस लेकर आएंगे, उन्होंने भी कहा कि हम हर गरीब के सिर पर छत देने का काम करेंगे। लेकिन आज गरीबों के पास घर नहीं है, गरीब बेघर है, देख रहा है सरकार उनकी है 2019 तक, और बात करते हैं कि 2022 तक हम घर देंगे, तीन–चार साल बाद की बात करते हैं जबकि उनका सूपड़ा 2019 में साफ हो जाएगा और जनता उनकी झूठी बातों का संज्ञान लेते हुए सत्ता से बेदखल करेगी। आज कहा जाता है कि बिजली की उपलब्धता है। हम गांव में रहते हैं अधिष्ठाता महोदय, बिजली गांव में दवाई की तरह आती है जैसे हमारे वृद्ध लोग दवाई सुबह दोपहर शाम लेते हैं, ऐसे ही बिजली, सुबह नाश्ते के समय कुछ मिनटों के लिए, दोपहर खाने के समय कुछ मिनटों के लिए, और रात में खाने के वक्त कुछ मिनटों के लिए आती है।यह बिजली की त्रासदी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नौकरियों की बात की थी इस प्रदेश सरकार ने भी, वायदा किया था कि हम नौकरियां देंगे, हम तुमको नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए। मोदी जी ने वायदा किया था कि हम नौकरी देंगे लेकिन उन लोगों ने भी नौकरी देने का काम नहीं किया। बल्कि नौकरी के नाम पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने एक लाख सफाई कर्मियों को और चालीस हजार पुलिस कर्मियों को भर्ती करके नौकरी देने का काम किया। आज हमारे जनपद में नेपाल का पानी आता है।अचानक बन्धे का पानी छोड़ दिया जाता है यहां आने के बाद वह पानी तबाह कर देता है। गांव के गांव कट जाते हैं गांव के गांव बह जाते हैं। चार वर्षो से इसी सदन में नियम–51, नियम–56, नियम–301 कोई भी नियम नहीं बचे होंगे जिसमें उनके पुनर्वास की बात न की गई हो। अधिकारियों से बराबर सम्पक्र किया। यहां तक कि मंत्री जी से कहा मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पैसा उपलब्ध है वहां से आप प्रपोजल भिजवाओ, जमीन खरीदकर, अगर सरकारी जमीन नहीं है, तो जमीन खरीदकर उनको बसाया जाएगा। इतने अधिकारी निरंकुश हैं कि कहने के बाद भी उन्होंने कोई प्रपोजल यहां से नहीं भेजा। अधिष्ठाता महोदय, आज बीसों हजार लोग नदी के कटान से बेबस होकर के खानाबदोश की तरह अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। चाहे वह राज्यपाल जी का अभिभाषण हो,चाहे बजट भाषण हो हर भाषण में उनकी वेदना और उनके कष्ट को बयान करता हूं लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है जबकि जमीन देने का और उनका घर बनाने का भरोसा इतना होना चाहिए कि उनको घर मिल जाए। पक्षपात की बात हो रही है लोहिया ग्राम दिए गए, जनेश्वर मिश्र ग्राम दिए गए इसी सदन में आप कार्यवाही देखें अधिष्ठाता महोदय, इसी सदन में मुख्य मंत्री जी द्वारा सौ–सौ हैण्डपम्पों को देने की घोषणा की जाती है लेकिन वह सर्वे कराने तक का काम होता है। लोग कहते हैं हमसे लिस्ट मांगी जाती है हम लिस्ट देते हैं लिस्ट देने के बाद सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद, वह खुशी खुशी कहते हैं भइया, वो सर्वे करने

आए थे नल लग जाएगा लेकिन उसके बाद कोई नल नहीं लगता है और इसलिए नल नहीं लगता है कि हम लोगों की बदनामी हो। वही नल कहीं उप चुनाव हो रहा है। अधिकारी अपनी मर्जी से करते हैं। अतिवृष्टि ओलावृष्टि की बात आई सूखा की बात आई। प्रत्येक गांव में पक्षपातपूर्ण ढंग से धनराशि वितरित की गई। यहां पर मामला उठाया गया यहां पर बात की गई लेकिन उससे बात नहीं बनी। उन लोगों को जिनका सही मायने में फसलों का नुकसान हुआ था उनको कोई मुआवजा नहीं मिला यहां पर सुबह एक प्रश्न के उत्तर में भी यह बात आई थी एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि बैंकों से जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं उनका तो बीमा श्योर होता है। मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे तो मैंने सुना जनपद लखीमपुर खीरी में 68 लाख रुपए मात्र का बंटवारा हुआ हैं। अधिष्ठाता महोदय किसानों की बात कर रहा हूं किसानों के दुखदर्द से जुड़ा हूं आप भी संघर्षशील रहे हैं आपने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया है इसलिए आप हमारी थोड़ी सी बात है उसे पूरी आ जाने दीजिए। आज सत्ता सरकार की हनक का आलम यह है सारे जनपद लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पाक्र है मुख्य मंत्री जी अक्सर दुधवा नेशनल पाक्र में जाते हैं और इस बजट में भी 10 करोड़ रुपए दिया है इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। वह 10 करोड़ रुपया कैसे खर्च होगा इसको लेकर लड़ाई चल रही है। 15 नवम्बर को दुधवा नेशनल पाक्र खुलता है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के लोग अपनी बुकिंग कराते हैं लेकिन वहां पर फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी फील्ड डायरेक्टर और जिलाधिकारी महोदय का एक विवाद चलता है समाचार–पत्रों की बीसों दिन से सुर्खियां बनी हुई हैं। उन सुर्खियों के बाद यहां मुख्य मंत्री जी के संज्ञान तक बात आती है मुख्य सचिव को आदेश होता है कि इन दोनों लोगों को बुलाकर इनसे बात की जाए फिर यहां से समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम होता है कि समझौता करा दिया गया है जिलाधिकारी और फील्ड डायरेक्टर दुधवा का समझौता हो गया है यहां से जाने के बाद फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वन्यकर्मी अपना हथियार सौंप देते हैं वहां के हाथी चलाने वाले जिप्सी चालक स्ट्राइक पर चले गए हद तो अब हो गई है कि थारू क्षेत्र की महिलाएं आज सड़क पर उतरकर आई हैं आवागमन बन्द है। महीनों से जनपद खीरी में यह दोनों अधिकारी लड़ाई कर रहे हैं शासन का खुले आम मखौल उड़ रहा है सरकार का खुलेआम मखौल उड़ रहा है सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

अधिष्ठाता महोदय बस मैं खत्म कर रहा हूं यह हमारा मामला नहीं है न मैं सड़क पुल पुलिया मांग रहा हूं मैं थोड़ी बातें संज्ञान में ला रहा हूं। यह दोनों लोग सही रास्ते पर आएं क्योंकि

(इसी मध्य 06 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पर्यटन के रूप में दुधवा नेशनल पाक्र डेड़ दो महीने से बन्द चल रहा है इससे हमारे खीरी जनपद की बहुत बदनामी हो रही है। 30 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन होना था यह किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पा रहा है उनका तुरन्त समायोजन होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जितनी पानी की टंकियां बनी हैं उनमें से 90–95 प्रतिशत पानी की टंकियां चल नहीं रही हैं घटिया सामग्री होने की वजह से घटिया निर्माण होने की वजह से करोड़ों रुपए सरकार का खर्च होने के बावजूद आज तक उनका संचालन नहीं हो सका। अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कितनी देर आप बोलेंगे।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

अध्यक्ष जी आपकी तो कृपा रहती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे चर्चा लेते ही आप आए हैं इसका थोड़ा लाभ हमें मिले। शादी अनुदान खत्म कर दिया गया है जो अल्पसंख्यकों को हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को शादी में अनुदान मिलता था आज पिछले तीन चार सालों से उसको बन्द कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बन्द कर दिया गया है। इसलिए आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत देर से बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आपकी बात आ गई है।

श्री शमशेर बहादुर शेरू भैय्या–

अध्यक्ष जी आपकी कृपा है बस अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन बैठे रहना भागना मत। जो बोलता है वह खिसक लेता है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

हम आपको भेजकर तब घर जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हालत हमारे यहां बहुत खराब है। हमने कई प्रश्नों के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाये हैं। कि वहां एक रोजगार के तरीके से चल रहा है। कोटा सस्पेंड करके, उसको अटैच करके, अधिकारियों की मिलीभगत से उसमें लाखों–लाख रूपये हड़पे जाते हैं, लाखों रुपये लेकर कोटे का अटैच और सस्पेंड और बहाल करने का काम किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, पूरी तहसील में 200 कोटे होंगे और उन 200 कोटों में पौने दो सौ कोटों को निरस्त और निलंबित करके बहाल करने का काम किया गया है, यह चिन्ता का विषय है, इस पर अंकुश लगना चाहिये जिससे गरीबों को मिलने वाला अनाज, गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल, गरीबों को मिलने वाली चीनी उनको सुलभता से उपलब्ध हो सके। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने मा0 नेता से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजीव गुम्बर–

मान्यवर, इस सरकार द्वारा अपने अंतिम वर्ष का यह बजट पेश किया गया है, परन्तु इस बजट के अन्दर जहां सरकार बड़े–बड़े वायदे करने का काम किया है वहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत उपेक्षित किया है। सरकार के द्वारा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां उपेक्षा है वहीं बजट के अंदर सहारनपुर के लिये कोई भी प्राविधान नहीं है। पूरा सहारनपुर जिला अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इस बजट के अंदर जहां बड़े–बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है, आज सहारनपुर के अंदर पूरा उद्योग ठप्प पड़ा है। सहारनपुर के उद्योगधंधे बिल्कुल चौपट हो गये हैं, क्योंकि वहां पर न तो बिजली की आपूर्ति है और कानून–व्यवस्था का यह आलम है कि उद्योगपतियों के साथ लगातार डकैतियां हो रही है और उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। बिजली की कमी का हाल यह है कि सहारनपुर से पूरा का पूरा उद्योग आज उत्तरांचल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, लोग यहां से अपना उद्योग छोड़कर जा रहे हैं। मान्यवर, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह उन लोगों की मदद करे जो उस मदद के हकदार हों, चाहे विधवा हों, चाहे वृद्धावस्था के लोग हों, चाहे बेरोजगार युवक हों, परन्तु सरकार द्वारा आज इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है कि एक विधवा औरत जिसका कोई सहारा नहीं होता है, वह 300 रुपये के लिये भटक रही है। हमारे सहारनपुर के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जो आज विधवा पेंशन के लिये दर–दर ठोकरें खा रही हैं और ऐसी ही स्थिति वृद्धावस्था पेंशन वाले उन बुजुर्गों की है जो 300 रुपये की पेंशन के हकदार हैं, परन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार ने बड़े–बड़े वायदे किये थे। सरकार ने युवा वर्ष घोषित किया। सरकार ने कहा कि हम रोजगार के साधन बनायेंगे और यदि रोजगार के साधन नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज उत्तर प्रदेश का पूरा युवा वर्ग इस बेरोजगारी की चपेट में है और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर वह केवल सरकार की ओर मुंह देखने का काम कर रहा है ओर उन्हें कोई भी भत्ता नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मैनीफेस्टो में घोषणा भी की थी कि हम शहरों को 22 घंटे की विद्युत आपूर्ति देंगे और गांवों को 14 से 16 घंटे की विद्युत आपूर्ति देंगे, परन्तु पूरे उत्तर प्रदेश में यह हाल है और हमारे सहारनपुर नगर में भी यह हाल है कि जहां 20 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की यह सरकार बात करती है। आंकड़े गवाह हैं, रोस्टर निकलवा लें, वहां 14 से 15 घंटे से ऊपर बिजली की आपूर्ति नहीं मिल रही है। आज जो शहर के अंदर पढ़ने वाला युवक है, जो छात्राएं हैं, सुबह जब उनका पढ़ने का समय होता है तब 4 बजे 5 बजे बिजली गोल हो जाती है, इस वजह से उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मान्यवर, हमारे सहारनपुर के अंदर नगर निगम का गठन हुये 8 वर्ष हो गये, परन्तु आज तक नगर निगम के चुनाव सरकार के द्वारा नहीं कराये जा पाये हैं और नगर निगम के अंदर इतनी अव्यवस्था है कि अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं और उनकी निरंकुशता का यह हाल है कि जो सड़कें आज से 6 महीने पहले बनीं थीं, सरकार उन सड़कों की जांच करवाये कि पिछले एक वर्ष के अन्दर जो सड़के बनी थीं उनका क्या हाल है। मैं दावा कर सकता हूं कि उनमें से आधी सड़कें एक वर्ष के अंदर बिल्कुल टूट चुकी हैं और

सरकारी पैसे की पूरी बंदरबांट हो रही है। मान्यवर, सरकार ने यह वर्ष युवा वर्ष घोषित किया है, परन्तु युवाओं के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। खेलों को बढ़ावा देने के लिये जब युवा खेलेगा, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था सहारनपुर के अंदर नहीं की गयी है। मेरे द्वारा पहले भी मांग की गयी है कि सहारनपुर के अंदर स्टेडियम का उच्चीकरण किया जाये, वहां पर स्टेडियम को और सुविधायें दी जायें, परन्तु कोई भी ऐसी सुविधा का सरकार ने प्रावधान नहीं किया है। सरकार को स्वास्थ्य के प्रति अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी एक ऐसी चीज है जिसकी कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। हमारे यहां एक मेडिकल कालेज बना था जो कि आज सफेद हाथी बनकर खड़ा है, शेखाकुल हिंद मेडिकल कालेज, उसमें डाक्टर नहीं हैं, टेक्नीशियन नहीं हैं, इलाज के उपकरण नहीं हैं और वह मेडिकल कालेज एक सफेद हाथी की तरह कुछ लोगों के हाथ में चल रहा है, कोई भी सुविधा सरकार के द्वारा नहीं दी गई है और शायद इस बजट के अन्दर भी उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, कानून–व्यवस्था की हालत पूरे सहारनपुर में बहुत खराब है। पिछले दिनों बहुत बड़े–बड़े काण्ड हुए। हमारे यहां का सर्राफा व्यापारी इस कदर पीड़ित है कि रोज उसके साथ कोई न कोई घटना होती है। पिछले दिनों तनिष्क के शोरूम पर लूट हुई, राघव ज्वैलर्स पर लूट हुई, उसके अलावा न जाने कितने छोटे–बड़े सर्राफों को बदमाशों द्वारा अपना निशाना बनाया गया। अभी प्रियलक्ष्मी के अन्दर एक छोटे से सर्राफ को बदमाशों ने निशाना बनाया और उसकी जान ले ली, आज तक उस केस का खुलासा नहीं हुआ है। मान्यवर, सरकार मेडिकल फैसिलिटी की बात करती है, सरकार को लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। हमारे यहां कम्पनी बाग के नाम से एक मात्र ऐसा पार्क है, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। परन्तु वहां पर भी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं कि वहां जो बुजुर्ग और महिलाएं घूमने के लिए जाती हैं, वहां शौचालयों तक की व्यवस्था नहीं है, वहां पर सड़कें टूटी–फूटी पड़ी हैं, वहां शाम के समय लाइट नहीं रहती है कि लोग वहां जाकर घूम पायें। मान्यवर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या है, पिछली सरकारों द्वारा एक राष्ट्रीयकरण की योजना 29–05–1993 लाई गई थी, जिसमें पूरी की पूरी बसों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज गांव का व्यक्ति, शहर को जाने वाला व्यक्ति साधनों के अभाव से जूझ रहा है। मैं कल ही परिवहन मंत्री जी से मिला था और मैंने अनुरोध किया था कि सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 39 रूट इस जद में हैं, जहां पर रोडवेज की बसों का परिचालन बन्द कर दिया गया है, परन्तु उसके पश्चात् वहां पर किसी नयी बसों का प्राविधान नहीं है। गांव के लोग बड़े चिन्तित हैं, डग्गामार वाहनों में लोग अपनी जान पर खेलकर सफर करते हैं, उन गांवों के अन्दर, उन सड़कों पर, उन शहरों के अन्दर बसों को चलाने का प्राविधान किया जाए। मान्यवर, हमारे सहारनपुर की एक प्रमुख समस्या है, पेपर मिल फाटक और टपरी फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाए क्योंकि वहां पर हर समय जाम लगा रहता है। मैंने पिछले सत्र में भी अनुरोध किया था, उसके पश्चात् भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर दिया

कि सहारनपुर वासियों को इस जाम से निजात दिलायी जाए। आज शायद रेल बजट के अन्दर उस के बीच के हिस्से को जिसे रेलवे को बनाना है, उसको बनाने की घोषणा कर दी है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन ओवरब्रिज को बनवाया जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

कोरम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सब को शादी में भी जाना है और दूसरा कोरम भी नहीं पूरा है, क्योंकि कोरम पूरा नहीं है इसलिए आप कल पूरी चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

आपको तो कोरम का सवाल नहीं उठाना चाहिए। सत्ताधारी दल का कोई सदस्य तो कोरम का सवाल नहीं उठाता है। लेकिन उठा दिया तो घण्टी बजायें। अगर कोरम पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बन्द कर देंगे।

(कोरम के लिए घण्टी बजायी गई)

(सदस्य श्री काली चरन सुमन के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

लिस्ट में आपका नाम है। अब कल बुलवा देंगे। आप लिखकर दे दो। हम सब जुड़वा देंगे। अब कोरम हो गया। घण्टी बंद करा दो। अगर कोरम नहीं होगा तो यह नियम–51 भी नहीं पढ़ा जाएगा। देखो कोरम पूरा है ?

ख्श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर।,

श्री अध्यक्ष–

आपका भी नाम है।

(कोरम पूरा होने पर)

ख्6.44 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

1–श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

2–श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के मलौनी बांध से ग्राम सभा सनहा के पास चौरी होते हुये रायगंज सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

3–ठा0 दलवीर सिंह की उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की अनदेखी करते हुये मुख्य अभियन्ता अलीगढ़ द्वारा कास्ट डाटा बुक से निर्धारित दर से अधिक पैसा जमा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

4–श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद बांदा की तह0 नरैनी के ग्राम रीगा के मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

5–श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

1–पं0 सुदेश शर्मा की नगर पालिका परिषद् मोदीनगर, गाजियाबाद की अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2–श्री राज नारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में जिला कारागार के नवीन भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

3–श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के अन्तर्गत सिढ़पुड़ा में ग्राम पिलखुनी से अखतउमंगदपुर स्थित गंजडुंडवारा मार्ग पर कला बम्बा की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

4–श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत दोहरीघाट खटिक टोला स्थित देशी शराब की दुकान की बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में है।

5–श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम पिछौती से धुवई होते हुये सिकन्दराराऊ हसायन तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

6–श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में पानी की टंकी से निकलने वाली समस्त पाइप लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

7–श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा अन्तर्गत मथुरा एवं वृन्दावन में केन्द्र की तत्कालीन सरकार की जेनर्म एवं यू0डी0आई0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत बिछाई गयी सीवर लाइन को एस0टी0पी0 से जोड़ने के सम्बन्ध में है तथा

8–श्री प्रभु दयाल की जनपद मेरठ के अन्तर्गत मवाना शुगर मिल द्वारा हजारों किसानों के गन्ने का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0सं0	नाम
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना,

2	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
3	श्री रविन्द्र भड़ाना,
4	श्री सुरेश बंसल,
5	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
6	श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
7	श्री योगेन्द्र उपाध्याय,
8	श्री मुकुल बिहारी वर्मा,
9	श्री आरिफ अनवर हाशमी,
10	श्रीमती कृष्णा पासवान,
11	श्री अगयश रामसरन वर्मा,
12	श्री रामचन्द्र यादव,
13	श्री सलिल विश्नोई,
14	श्री मनीष असीजा,
15	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
16	श्री रविन्द्र जायसवाल,
17	श्री जगन प्रसाद गर्ग,
18	श्री मो0 इरफान,
19	श्री बृजेश कुमार,
20	श्री राजकुमार रावत,
21	श्री सिबगतुल्ला अंसारी,
22	श्री मुकेश श्रीवास्तव,
23	डॉ0 अरुण कुमार,
24	श्री गजराज सिंह,
25	श्री शहजिल इस्लाम,
26	श्री पंकज गुप्ता,
27	श्री रोशन लाल वर्मा,
28	श्री राधेलाल रावत,
29	श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
30	श्री जाकिर अली,
31	श्री बब्बन सिंह चौहान,
32	श्री चौधरी गजेन्द्र सिंह,

33	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
34	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
35	श्री जय प्रकाश निषाद,
36	श्रीमती आराधना मिश्रा,
37	श्री बाला प्रसाद अवस्थी,
38	श्री गुलाब सिंह सरोज,
39	श्री रवि शर्मा,
40	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या,
41	डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द,
42	श्री नदीम जावेद,
43	श्री दलजीत सिंह,
44	श्री दीपक पटेल,
45	श्री राम सिंह,
46	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
47	श्री राधेश्याम,
48	डॉ0 मो0 मुस्लिम, तथा
49	श्री राजेश त्रिपाठी।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 25 फरवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ–7 पर)

कामधेनु डेयरी योजना के स्थापित इकाइयों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	श्री पोप सिंह यादव	श्री हर प्रसाद	निवासी जमाल नगर भैस पो0 चमरोला	9412722515
2	आगरा	श्रीमती शैलजा जैन	स्व0 श्री एस0पी0 जैसवाल	114 पुरानी विजय नगर कालोनी	9997365222
3	आगरा	श्री ताराचंद बंसल	श्री आर0सी0 बंसल	रूनकता आगरा।	9557735535
4	आगरा	श्री मनोज कुमार यादव	श्री सोमवीर सिंह यादव	गढ़ी नवलियां, कुआखेड़ा, पो0 कलाल खेडिया, वि0खं0 ब0अहीर	9410252211
5	आगरा	श्री दाऊदयाल	श्री जगजीत सिंह	ग्राम हौंद बरोली गूर्जर	9761011753
6	आगरा	श्री अशोक कुमार सिंह	स्व0 श्री महाराज सिंह	इनायतपुर, पो0 फूलपुर, फतेहाबाद	9759902315
7	आगरा	श्री ऐदल सिंह रविन्द्र सिंह	श्री मोहनलाल	खरगपुर, पो0 चौकडा, खन्दोल	9917649198
8	आगरा	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	श्री देवेन्द्र सिंह	तोर, पो0 इरादत नगर, वि0 खं0 शमशाबाद, आगरा	9719094195 9837230694
9	मथुरा	श्री राकेश यादव	स्व0 श्रीवेदराम यादव	ग्रामकरनावल पो0 बरारी मथुरा।	9412280576
10	मथुरा	श्री अतुलमंगला	श्री मुरारीलाल	ए–1 श्रीजीधाम कालौनीगोवर्धन रोड	9927000877
11	मथुरा	श्री तेजपाल सिंह	श्री दुलीचन्द	ग्राम इनायतगढ़ पो0 छिनपारई वि0ख0 नौहझील	9411257422
12	मैनपुरी	श्री शिववीर सिंह	श्री शंकर सिंह	ग्रा0 व पो0 ओड़न्य मण्डल ब्लाक व तह0 मैनपुरी	9457627569
13	मैनपुरी	श्रीमती नीता पाण्डेय	प्रदीप कुमार	बैंक कालोनी स्टेशन रोड मैनपुरी	9410635699
14	मैनपुरी	श्रीमती विमला	श्री रविन्द्र सिंह	मो0 रामबाग कचहरी	9627017511

		यादव	यादव	रोड मैनपुरी	
15	फिरोजाबाद	श्री ओमप्रकाश	श्री रक्षपाल सिंह	ग्राम–अहिवरनपुर, पो0–झाल गोपालपुर, फिरो0	9412590286 8923176018
1	2	3	4	5	6
16	फिरोजाबाद	श्री जयप्रकाश यादव	श्री विद्धराम	नगला सदासुख गुदाऊ, फिरोजाबाद	9927034001
17	फिरोजाबाद	श्री अवधेश प्रताप	श्री सुन्दर सिंह बघेल	कठफोरी, पो0–बछेला–बछेली, फिरोजाबाद	9927085303
18	फिरोजाबाद	श्री कृष्ण	श्री धनीराम	ग्रा0 व पो0–जहांगीरपुर,	9412575463
19	फिरोजाबाद	श्री कमलेश सिंह	श्री निहाल सिंह	नगला अमर सिंह, पो0–सलेमपुर, फिरोजाबाद	9758298693
20	फिरोजाबाद	श्रीमती रजनी यादव	श्री राधेश्याम यादव	मो0 खेड़ा, शान्ति नगर, शिकोहाबाद	9412332339
21	अलीगढ़	श्री नबाव सिंह	हरी सिंह	ग्रा0 सलेमपुर पो0 सादाबाद ब्लॉक सादाबाद तह0 सादाबाद	9720193251
22	अलीगढ़	श्री प्रताप चौधरी	श्री परसादी लाल	लेनिन डेयरी फार्म सादाबाद हाथरस	9412728740
23	अलीगढ़	श्री राजपाल सिंह	श्री सुम्मेर सिंह	ग्राम अजरोई पो0 सासनी जिला हाथरस	9412563264
24	अलीगढ़	श्री नैपाल सिंह	सैतान सिंह	जलेसर रोड मानिकपुर हाथरस	9411966843
25	अलीगढ़	श्री अर्जुन सिंह	खजान सिंह	ग्रा0 बिलखौरा खुर्द पो0 सासनी हाथरस	9759538131
26	कासगंज	श्री बिजेन्द्र सिंह	श्री विष्णु सिंह	ग्राम–नगरिया हसनपुर सोरों	9927976321
27	कासगंज	श्री अनिल अग्रवाल	श्री राम कुमार	अमॉपुर रोड, निकट सब्जी मण्डी, कासगंज	94122282568
28	एटा	श्री गंगा प्रसाद	श्री श्रीराम	ग्राम–नयॉवास, पो0–टिकाथर, वि0ख0–अवागढ़, एटा	9412377718
29	एटा	डा0 शिव नन्दन सिंह	श्री दीनानाथ	शिव नगर, अलीगंज रोड, एटा, निवासी–13 महाराणा प्रताप नगर, विकास खण्ड–शीतलपुर,	9412430737

				एटा	
30	एटा	डा0 राजेश कुमार	श्री मोहर सिंह	शिढपुरा रोड कुठला लायकपुर, एटा, निवासी–517/25 संजय नगर, आगरा रोड एटा, विकास खण्ड–शीतलपुर, एटा	9837028757, 9412095242
31	एटा	श्री वरूण वार्ष्णेय	श्री राकेश कुमार वार्ष्णेय	बदरिया रोड, निवासी–66– इन्द्रपुरी, विकास खण्ड– शीतलपुर, एटा	9528299998
1	2	3	4	5	6
32	हाथरस	श्री नबाव सिंह	हरी सिंह	ग्रा0 सलेमपुर पो0 सादाबाद ब्लाक सादाबाद, तह0 सादाबाद	9720193251
33	हाथरस	श्री प्रताप चौधरी	श्री परसादी लाल	लेनिन डेयरी फार्म, सादाबाद, हाथरस	9412728740
34	हाथरस	श्री राजपाल सिंह	श्री सुम्मेर सिंह	ग्रा0 अजरोई, पो0 सासनी, जिला हाथरस	9412563264
35	हाथरस	श्री नैपाल सिंह	सैतान सिंह	जलेसर रोड मानिकपुर हाथरस	9411966843
36	हाथरस	श्री अर्जुन सिंह	खजान सिंह	ग्रा0 बिखौरा पो0 सासनी हाथरस	9759538131
37	इलाहाबाद	श्री प्रदीप सिंह	श्री राम अचल सिंह	ग्राम–पतेवरा, पो0–पुरुताखास ब्लाक–करछना, तह0– इलाहाबाद	9839753036
38	इलाहाबाद	श्री शिवपूजन केसरवानी	श्री लालचन्द्र केसरवानी	ग्राम–कसेरूवाकला, पो0– सहसों, ब्लाक–बहादुरपुर, तह0–फूलपुर	9794920000
39	इलाहाबाद	श्रीमती सुमन सिंह यादव	श्री कुंवर सिंह	407ए/171सी0, अशोक नगर, इलाहाबाद	9454559317
40	इलाहाबाद	श्री उस्मान अली	श्री मुस्तफा	ग्राम–41 दामुपर, पो0–करेली तह0–सदर, इलाहाबाद	9956165877
41	इलाहाबाद	श्री अजित त्रिपाठी एवं श्रीमती मंजूबाला त्रिपाठी	पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी	ग्राम पाण्डर, पो0 जसरा, इलाहाबाद	9454171182
42	इलाहाबा	श्रीमती कुमुदलता	पत्नी श्री राजेश	ग्राम पाण्डर, पो0 जसरा,	9935985418

	द	त्रिपाठी	त्रिपाठी	इलाहाबाद	
43	इलाहाबाद	श्री विनीत कुमार पाण्डेय	श्री हर्ष नारायण पाण्डेय	ग्रा0 उल्दा, पो0 अटरामपुर, इलाहाबाद	9839635571
44	कौशाम्बी	श्री फैसल अजीज	श्री अजीजुद्दीन	नगर पंचायत भरवारी, जनपद कौशाम्बी	7571828998
45	कौशाम्बी	श्री रामचन्द्र	स्व0 श्री धर्मराज	ग्रा0 व पोस्ट तिल्हापुर, वि0ख0 नेवादा	9559922524
46	फतेहपुर	श्रीमती दुर्गा गुप्ता	श्री रजनीकान्त	67 बैलाही बाजार दक्षिणी बिन्दकी, फतेहपुर	9838819600
47	फतेहपुर	श्री जितेन्द्र सिंह गौतम	श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम	मोहार, ब्लाक मलवां, फतेहपुर	9235698670
48	फतेहपुर	श्री शिवांश दीक्षित	श्रीकान्त दीक्षित	जाफरगंज, ब्लाक–खजुहा, फतेहपुर	9389947801
1	2	3	4	5	6
49	प्रतापगढ़	श्री आनन्द भूषण सिंह	श्री बालेन्दु भूषण सिंह	प्रताप बहादुर पार्क, प्रतापगढ़	9532319100
50	प्रतापगढ़	श्री प्रमोद कुमार मौर्य	श्री सालिगराम मौर्य	ग्राम व पो0 चकवड विहार, प्रतापगढ़	9451126300
51	प्रतापगढ़	श्री मनीष शुक्ला	श्री इन्द्रनाथ	ग्राम शहाबपुर, पो0 बेती, प्रतापगढ़	
52	प्रतापगढ़	श्री संगमलाल गुप्ता	स्व0 कड़ेदीन गुप्ता	ग्राम–कटरामेदनीगंज, प्रतापगढ़	9415350831
53	आजमगढ़	श्री चन्द्रशेखर राय	स्व0 श्री विश्वनाथ राय	ग्राम–असईमोलनापुर, पोस्ट– सिकरौर सहबरी, वि0ख0– मार्टीनगंज, तह0–फूलपुर	7376244919
54	मऊ	श्री हरीशचन्द्र सिंह	स्व0 सुबेदार सिंह	ग्रा0 बस्ती, पो0 खिरिया, मऊ	9415305386
55	मऊ	श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	ग्रा0 व पो0 सिधवल, मऊ	9415246794
56	बलिया	श्री अजय यादव	श्री मंगल यादव	ग्राम–राघोपुर पो0 अठिलापुरा रसड़ा, बलिया	9559462500
57	बलिया	श्री रामेश्वर पाण्डेय	श्री सनातन पाण्डेय	ग्राम पाण्डेयपुर, पो0–ताखा, बलिया	9918622264
58	बलिया	श्री गुलाबचन्द्र यादव	स्व0 रामकिशुन यादव	ग्राम–ब्रम्हाइन, पो0 व वि0ख0 हनुमानगंज, बलिया	9415254664
59	बरेली	श्री अवधेश कुमार	श्री नाथू राम	10 जमुना विहार नार्थ	9760478015

		गौला	गोला	सिटी स्टेशन के सामने पीलीभीत वाई पास बरेली	
60	बरेली	श्री मो0 नदीम	श्री अजीमुउद्दीन	ग्राम गुलड़िया अता हुसैन, पो0 फरीदपुर बहेड़ी, बरेली	9412296786
61	बरेली	श्री सोमपाल शर्मा	श्री पूरन लाल	ग्राम नवदिया डा0 लंगूरा, तहसील आंवला, बरेली	9412737161
62	बरेली	श्री सत्यपाल सिंह	श्री नौबत सिंह	ग्राम मनकरा, पो0 मानपुर, तहसील बहेड़ी, बरेली	9837912294
63	बदायूं	श्री हितेन्द्र शंखधार	श्री तोताराम शंखधार	नि0 मो0 साहूकारा कस्बा इस्लामनगर, जिला–बदायूं	9758248604
64	बदायूं	श्री वैभव माहेश्वरी	श्री रामेन्द्र चन्द्र	नि0 श्याम सदन नियर एस्कोर्ट एजेन्सी कसबा बिसौली, जिला–बदायूं	9897383659
65	बदायूं	श्री उदयवीर सिंह	श्री केवलराम	नि0 ग्राम रायपुर मजरा, पो0 रिसौली तह0 बिल्सी, जिला–बदायूं	8859012800
1	2	3	4	5	6
66	शाहजहांपुर	श्री ज्ञानेश तिवारी	श्री जानकी प्रसाद तिवारी	ग्रा0–नवीपुर, शाहजहांपुर	945333265
67	शाहजहांपुर	श्री राजीव कुमार सिंह	श्री अभिलाख सिंह	ग्राम पहोडा अल्लागंज	9839351836
68	शाहजहांपुर	श्री सुनील कुमार यादव	श्री रघुवीर यादव	फौजी डेरी–चिनौर	9450091501
69	शाहजहांपुर	श्री अजय कुमार सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह	राजमहल परौर	9198037600
70	शाहजहांपुर	श्रीमती किशवरी बेगम	श्री शब्बीर अली	ग्राम व पो0–कोरो कुइयां, सिंधौली	9321014451
71	पीलीभीत	श्री गौरव चौधरी	श्री वीरपाल सिंह	टाडा विजेसी	9675763709
72	पीलीभीत	श्री सुखवीर सिंह	श्री उजागर सिंह	ग्राम कुलहारा फार्म अमरिया	7409213000
73	पीलीभीत	श्री जगमोहन राय अग्रवाल	श्री कर्मचन्द अग्रवाल	जसवन्ती राइस मिल पूरनपुर रोड पीलीभीत	
74	पीलीभीत	श्री सुरेश गंगवार	श्री तुलसीराम	ग्राम सैजना	9837081089
75	बस्ती	श्री अमरेन्द्र प्रताप	स्व0 अवधेश	ग्रा0–कवलपुर,	9935950138

		सिंह	सिंह	पो0–बेलवा बाधानाला ब्लाक–विक्रमजोत, तहसील–हर्रैया, जनपद–बस्ती	
76	बस्ती	राजा ऐश्वर्य राज सिंह	स्व0 राजा लक्ष्मेश्वर सिंह	राजभवन राजा मैदान पुरानी बस्ती, ब्लाक–बस्ती सदर, तहसील–बस्ती सदर, जनपद–बस्ती	9415014203
77	बस्ती	डा0 सी0पी0 चौधरी	स्व0 श्री रामलौट चौधरी	ग्राम–बनकसही, पो0–ओड़वारा, ब्लाक–सॉऊघाट, तह0–बस्ती सदर, जनपद–बस्ती	9415579117
78	संतकबीर नगर	श्री भाल चन्द्र यादव	श्री राम सहाय यादव	ग्राम व पो0–भगता, वि0ख0 व तह0–खलीलाबाद, संत कबीरनगर	9415080024
79	संतकबीर नगर	श्रीमती शशि सिंह	श्री विजय बहादुर सिंह	ग्राम व पो0–बडगो वि0ख0– व तह0–मेंहदावल, संतकबीरनगर	9918800135
80	सिद्धार्थन गर	श्रीमती संध्या यादव	श्री प्रमोद कुमार यादव	ग्राम व पो0 दुर्जनपुर, वि0ख0 नौगढ़, तह0–नौगढ़ सदर, सिद्धार्थनगर	9695932986
81	सिद्धार्थन गर	श्री तिलक राम यादव	श्री बाढू यादव	ग्राम कम्हरिया बु0 पो0 पथरा बाजार, वि0ख0–मिठवल, तह0–बांसी, सिद्धार्थनगर	9918260016
1	2	3	4	5	6
82	सिद्धार्थन गर	श्री गोविन्द यादव	श्री धर्मराज यादव	ग्रा0 व पो0–भडेहर ग्रान्ट वि0ख0 नौगढ़, तह0–नौगढ़ सदर, सिद्धार्थनगर	9415669579
83	बांदा	श्री हरपाल सिंह	श्री पूरन सिंह	ग्राम कैमहा, पो0 अतरार माफ, ब्लाक कबरई, जि0 महोबा	9415145101
84	चित्रकूट	श्री योगेश जैन	श्री रमनलाल जैन	चकला राजरानी, विकास खण्ड कर्वी	9450223165
85	चित्रकूट	श्री नत्थू प्रसाद	श्री महावीर	बाबूपुर, पहाडी	9984071401
86	चित्रकूट	श्री मलय द्विवेदी	श्री जनार्दन	एस0डी0एम0 कालोनी,	9839118873

			द्विवेदी	कर्वी	
87	चित्रकूट	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	श्री रुद्र नाथ पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट छीबो, रामनगर चित्रकूट	9793011501
88	महोबा	श्री हरपाल सिंह	श्री पूरन सिंह	ग्राम कैमहा पो0 अतरार माफ ब्लाक कबरई, जि0 महोबा	9415145101
89	फैजाबाद	श्री राम सजीवन मिश्रा	श्री रामनरेश मिश्रा	ग्राम सिरसिण्ड, पूरेसिरवार, चिरौली ब्लाक मिल्कीपुर, फैजाबाद	9415720615
90	अम्बेडकर नगर	श्री अरविन्द यादव	श्री राम दौर यादव	ग्राम बसिरहा, पो0 रामपुर सकरवारी	9918118243
91	अमेठी	श्री राम गोपाल	श्री भगवानदीन	ग्राम व पोस्ट जामो अमेठी	9451048967
92	सुल्तानपुर	श्री कुंवर विष्णु कुमार सिंह	श्री रामबिहारी सिंह	ग्रा0 व पो0 हलियापुर, सुलतानपुर	9648945173
93	बाराबंकी	श्री जगदीश प्रसाद	स्व0 सियाराम वैश्य	मो0 घघवारा, पोस्ट टिकैत नगरा, विकास खण्ड पूरेडलइया, बाराबंकी	9919113284
94	बाराबंकी	श्री रजन कुमार	श्री भगौती प्रसाद	ग्राम बड़ागांव, पोस्ट एवं विकास मसौली, बाराबंकी	9415014555
95	बाराबंकी	श्री जय प्रकाश	श्री सीताराम	ग्राम अटहरी, हेतमापुर, विकास खण्ड सूरतगंज, बाराबंकी	8127222888
96	गोण्डा	श्री विवेक भार्गव	श्री उमाकान्त भार्गव	मो0 पड़ाव, नवाबगंज, गोण्डा	9919533533 9839775755
97	गोरखपुर	श्री राजाराम यादव	श्री श्रीराम यादव	ग्राम–नकहा नं0–2, पो0–बरगदवां, ब्लाक–चरगांवा, तह0–सदर, गोरखपुर	9415314497
1	2	3	4	5	6
98	महराजगंज	डा0 उमाशंकर मिश्र	स्व0 रघुवंश मिश्र	ग्राम–परागपुर पां0 निचलौल, ब्लाक, निचलौल, महराजगंज	9792875172 9005385499
99	देवरिया	डा0 जय प्रकाश मिश्रा पी0एच0डी0	श्री तिलकधारी मिश्रा	489/18 उमानगर दक्षिणी देवरिया।	8874966000
100	कुशीनगर	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह	श्री राजकिशोर सिंह	ग्राम व पोस्ट खोटही, ब्लाक–रामकोला, तह0	9793190237

				कप्तानगंज रामकोला, कुशीनगर	
101	झांसी	श्री संजय सिंह निरंजन	श्री अयोध्या सिंह	ग्रा0 व पो0 सुटटा, ब्लाक बामौर, जिला झांसी	9415590216
102	झांसी	श्री रहीश सिंह यादव	स्व0 मूंगाराम यादव	ग्राम सेवारा, ब्लाक, जिला झांसी	9450041708
103	ललितपुर	श्री जी0एस0 परिहार	श्री महेन्द्र सिंह	गंज, तालबेहट	9415030541
104	जालौन	श्री वंशनारायण दीक्षित	श्री प्रभुदयाल	ग्राम व पोस्ट रामहेतपुरा माधौगढ़	9453703702
105	जालौन	श्री चन्द्रप्रकाश	श्री बालाप्रसाद यादव	मु0 कछोरन जालौन	9415114406
106	जालौन	श्री करन सिंह	श्री हरनारायण सिंह	ग्रा0 बम्होरी कलां	9415032077
107	जालौन	श्री सुरेश राव डेगरे	स्व0 श्री नरसिंह राव	मु0 बालमभट्ट जालौन	9415113405
108	कानपुर नगर	श्री सतीश कुमार सचान	श्री राम कुमार सचान	127/378, डब्लू 1 साकेत नगर, कानपुर	9839211802
109	कानपुर नगर	श्री नारायण महेश्वरी	श्री केशवचन्द्र महेश्वरी	केशवम 355, विकास नगर	9559000222
110	कानपुर नगर	भानू सिंह	मान सिंह	139 ग्राम व पो0—कुलगांव	9984818200
111	कानपुर देहात	शिवमहिमा इन्ड्रस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	स्व0 नन्हे लाल गुप्ता	रनियां	7617010680
112	कानपुर देहात	श्री रामजी गुप्ता	स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद	भटौली, रूरा	9415159091
113	कानपुर देहात	श्री मो0 सईद	पु0 मो0 अहमद	अकबरपुर	9838667605
114	फर्रुखाबाद	श्री असगर अली	श्री मुख्तयार अली	कतरौली पट्टी खुदागंज	9839800233
115	इटावा	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री विशम्भर सिंह यादव	ग्राम व पो00 खर्दूली, सैफई इटावा	9897893071
1	2	3	4	5	6
116	इटावा	श्री अखिलेश यादव	श्री रामस्वरूप यादव	ग्राम व बिहारी पो0 कुइया, सैफई इटावा	9412283716
117	इटावा	श्री राम औतार	श्री राम नाथ	ग्राम केवाला पो0 मलाजनी जसवन्तनगर,	9412182165

				इटावा	
118	कन्नौज	श्रीमती गीता आर्या	श्री राम प्रकाश आर्य	गुरसहायगंज	9415124004
119	कन्नौज	श्री नरेन्द्र कुमार	श्री सूरजभान सिंह	कटरी बैसाहार	9839943544
120	कन्नौज	श्रीमती पूजा बाजपेई	श्री आशुतोष	कन्नौज,	9369977977
121	औरैया	श्री विनय शाक्य	श्री बाबूराम शाक्य	ग्रा0 भटौरा पो0 गूरा	9415902768
122	लखनऊ	श्रीमती सरोज चौधरी	पुत्र स्व0 श्री कुबेर सिंह यादव	सी0–2/136, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	9450776514
123	लखनऊ	श्री मो0 अय्यूब	श्री रऊफ अहमद	227/82–क, अस्तबल यहियागंज, लखनऊ	9935026153
124	उन्नाव	श्री कुबेर तिवारी,	श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी	ग्राम–सन्नी सरांय, उन्नाव	9415040266
125	उन्नाव	श्री एतिशाम अहमद	स्व0 श्री रसूल बक्स	पता–260 वाजिद नगर, उन्नाव	9839118989
126	उन्नाव	सुश्री अंकिता बांगर	श्री तरूण कुमार बांगर	पता–122/513 सिंधी कालोनी फ्लैट नं0–7 प्रभू छाया शास्त्रीनगर कानपुर	9792002474
127	रायबरेली	श्री धर्मेन्द्र सिंह	श्री रामनरेश	ग्राम देवपुर पो0 जोगापुर लालगंज, रायबरेली	9984607321
128	हरदोई	श्री विवेक कुमार सिंह	श्री रामपाल सिंह	दौलतयारपुर माधौगंज, हरदोई	9415149519
129	हरदोई	श्री रामप्रकाश अग्निहोत्री	बडेलल्ला अग्निहोत्री	बिल्सर हरसेन पो0 बिल्सरी हरदोई	8858855588
130	सीतापुर	श्री आशीष कुमार गुप्ता	स्व0 श्री ओम प्रकाश गुप्ता	46–जेल रोड, सीतापुर	9415047109
131	सीतापुर	श्रीमती पुष्पा त्रिवेदी	श्री ललित किशोर त्रिवेदी	ग्राम बहादुर मछरेहटा	980715568
132	सीतापुर	श्री प्रदीप सिंह चौहान	श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम देवीपुर सिधौली	9415062151
133	सीतापुर	श्रीमती रमेश्वरी देवी	श्री महेश कुमार गुप्ता	102, कृष्णानगर हरदोई रोड चंकी चौकी, सीतापुर	9453857253
134	खीरी	श्री रामसनेही सिंह	श्री हरनाम सिंह	ग्रा0 व पो0 रायपुर, ईसानगर, खीरी	9919503170

1	2	3	4	5	6
135	खीरी	श्री सलिल अग्रवाल	श्री श्रीराम अग्रवाल	कृष्णानगर, परिहन रोड, पलियाकलां, खीरी	9415186170
136	खीरी	श्रीमती ममता यादव	पत्नी श्री विनोद कुमार यादव	ग्राम धर्माखेड़ा मैगलगंज, खीरी	9415146409
137	मेरठ	श्री भूले सिंह	श्री होशियार सिंह	ग्राम कूड़ी, ब्लाक खरखौदा मेरठ	9719947714
138	मेरठ	श्री कपिल कुमार शर्मा	श्री महेन्द्र शर्मा	पता 256/5 थापर नगर, मेरठ	9927066361
139	मेरठ	श्री सतीश कुमार	श्री हरदन सिंह	नगर पंचायत करनावल, मेरठ	9719404953
140	मेरठ	श्री असलम	श्री जागर	ग्राम नरहेडा डा0 जाहिदपुर, मेरठ	9917488372
141	मेरठ	श्री नीरज कुमार	श्री रणवीर सिंह	ग्राम सादुल्लापुर उर्फ चन्दपुरा ब्लाक खरखौदा	9837375106
142	मेरठ	श्री जियाउररहमान आरिफ	श्री हकीम मोहम्मद उमर	पता मौ0 सराय अफगानान सरधना, मेरठ	9412321550
143	मेरठ	श्री अर्जुन गौतम	श्री एस0 के0 गौतम	पता सी0—1 प्रमप्रयाग कालोनी समीप मेडिकल कालेज गढ़ रोड, मेरठ	9810375288
144	मेरठ	श्री सुरेश कुमार व प्रीति शुक्ला एवं सोनम सिंह	अमन सिंह व श्री मोहनलाल शुक्ला	पता 34 मोहल्ला मुन्नालाल मवाना मेरठ	9313491229
145	मेरठ	श्री प्रेम सिंह	श्री लालसिंह	ग्राम मैथना इन्दर सिंह ब्लाक दौराला मेरठ	9720422488
146	मेरठ	मौ0 अबरार एवं उमर मौ0	श्री उमर मौ0 एवं सददीक	ग्राम व पो0 हर्रा मेरठ	8865942000
147	बागपत	श्री धीर सिंह यादव	श्री दान सिंह यादव	ग्राम गौना पो0 स्टौल	9582404626
148	बागपत	श्री कोकब हमीद	श्री नवाब शौकत व हमीद खां	ग्राम एवं पो0 बागपत	9412209779
149	बागपत	श्री करण सिंह	श्री पीतम सिंह	ग्राम एव पो0 बडौली	9756637676
150	गाजियाबाद	श्री हरेन्द्र त्यागी	श्री शैराज सिंह त्यागी	असालतपुर मुरादनगर	9811339908
151	गाजियबाद	श्री अजयवीर सिंह	श्री दरघाई सिंह	चिरौडी लोनी	9311525267
152	गाजियाबा	श्री मकेश त्यागी	श्री बलराज	दुहाई, गाजियाबाद	8800970780

	द		सिंह		
153	गाजियाबाद	श्री चरण सिंह	श्री तेजराम	शाहपुर बम्हेटा	9910544571
1	2	3	4	5	6
154	हापुड़	श्री योगेन्द्र प्रधान	श्री गजेन्द्र प्रधान	पीरनगर दतियाना हापुड़	9690867796
155	हापुड़	श्री आदेश कुमार	श्री सत्यपाल सिंह	ग्राम लालपुर डा0 ततारपुर हापुड़	9837104704
156	हापुड़	श्री हरिराज सिंह रावत	श्री किशन सिंह रावत	ग्राम मीरपुर मजरा भटियाना धौलाना हापुड़	9411243354
157	हापुड़	श्री नरेन्द्र सिंह राणा	श्री सूबेदार सिंह	ग्राम सिरोधन पोस्ट मतनावली हापुड़	9837284853
158	जी0बी0 नगर	श्री फतेह चन्द /	श्री मिश्री लाल	खुर्जा रोड जेवर ब्लाक जेवर तहसील जेवर–गौतमबुद्धनगर ब्लाक जेवरतहसील जेवर	9412641199
159	जी0बी0 नगर	श्री हरीराम / स्व0	श्री रामचन्द्र सिंह	ग्राम–चिटहैरा, ब्लाक–दादरी	9310948944
160	बुलन्दशहर	श्रीमती सुषमा गोयल	श्री गोपालराम गोयल	ग्राम–इब्राहिमपुर जुनेदपुर उर्फ मौजपुर खुर्जा जंक्शन, बुलन्दशहर	9761145234
161	बुलन्दशहर	श्री कमलजीत सिंह	श्री रतन सिंह	ग्राम–बुटैना, विकास खण्ड–सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर	9837429850
162	बुलन्दशहर	श्री नरेन्द्र सिंह	स्व0 श्री खानचन्द सिंह	ग्राम–अकरबास कनैनी, पो0–अहमदगढ़, जनपद–बुलन्दशहर	9818871705
163	बुलन्दशहर	श्री कुंवर ऋषभदेव सिंह	श्री सुनील कुमार सिंह	म0नं0–241 भदौरी ऑसफपुर प्याना खुर्द वि0ख0–ऊंचागांव	9410000009
164	बुलन्दशहर	श्री सुगड़ सिंह	श्री दीपचन्द सिंह	ग्राम–लोहरारा विकास खण्ड–अगौता, बुलन्दशहर	9758742823
165	मिर्जापुर	श्री गणेश शंकर यादव	श्री बचनूराम यादव	ग्राम–धारा, पोस्ट–हरिहरपुर, वि0ख0–जमालपुर, मीरजापुर	9838971362
166	मिर्जापुर	श्री अखिलेश्वर सिंह	स्व0 श्री उदित नारायण सिंह	ग्राम–धनसिरियां, पोस्ट–राजगढ़, मीरजापुर	9838383272

167	मिर्जापुर	श्री वंशनारायण उपाध्याय	स्व0 श्री चन्द्रबली उपाध्याय	ग्रा0–बंधवा, पो0–जमुआ, मीरजापुर	9415830604
168	मिर्जापुर	श्री तिलकराज सिंह	श्री कमला शंकर सिंह	ग्राम–भोवरूपुर अजगना, पोस्ट–हरगढ़ बाजार, मीरजापुर	9415251511
169	मिर्जापुर	श्री शरद कुमार सिंह	स्व0 श्री ज्ञान सिंह	ग्राम–हकानीपुर खुर्द पोस्ट अचितपुर नरानपुर, मीरजापुर	9935145883
1	2	3	4	5	6
170	सोनभद्र	श्री चन्द्रकेशर मौर्य	स्व0 श्री फुलगेन	ग्रा0 नागनारहरैया, पो0 मधुपुर, सोनभद्र	9554960133
171	सोनभद्र	श्री राकेश कुमार चौबे	श्री सुरेश प्रसाद चौबे	ग्रा0 मझिगांव चौबे, पो0 राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	9889782899
172	संतरविदास नगर	श्री नागेन्द्र बहादुर सिंह	श्री कड़ेदीन सिंह	ग्राम–महासिंहपट्टी, सदौपुर, भदोही	9415870498
173	संतरविदास नगर	श्री इन्द्र पाल सिंह	श्री देव नरायन	ग्राम–धनीपुर भदोही	9415443654
174	मुरादाबाद	श्री चन्द्रपाल सिंह यादव	श्री हेतराम सिंह यादव	ई 255 गली नं0 66 ला0पा0 मुरादाबाद	9757947737
175	मुरादाबाद	श्री कुशल कुमार	श्री हरगोविन्द सिंह	ग्राम व पोस्ट मौढा तैया, कोठ, मुरादाबाद	9760014700
176	मुरादाबाद	श्री अनीस चौधरी	श्री अहमद जान	चमरउवा, अक्का डिलारी मूंढापान्डे मुरादाबाद	9758551245
177	मुरादाबाद	श्रीमती भूरी बैगम	श्री नजाकत हुसैन	निकट आर0टी0ओ0 आफिस आजाद नगर मुरादाबाद	9927539786
178	अमरोहा	प्राइमो होल डेरी	–	खाद गुर्जर गजरौला, अमरोहा	9456832415
179	अमरोहा	श्रीमती कान्ता पालीपाल	डा0 सुनील कुमार	लक्ष्मीनगर गजरौला अमरोहा	9412139037
180	सम्भल	श्री कल्याण सिंह	श्री परमेश्वरी	कमालपुर	975879266
181	सम्भल	श्री वीरेन्द्र कुमार	श्री ओमप्रकाश	बहजोई	9412244352
182	रामपुर	श्री सैय्यद बखितयार अली	श्री सैय्यद ताहिर अली	ग्राम–जूननागर, मिलक	9837016444
183	रामपुर	श्री हरपाल सिंह	श्री मान सिंह	बजरंग राइस मिल, बिलासपुर	9897447834
184	बिजनौर	श्रीमती प्रीति ठाकुर	पत्नी श्री नीरज कुमार	ग्राम व पो0–गौहावर हल्लू, ब्लाक–नरूपुर।।	9760534867

185	बिजनौर	श्री लाल बहादुर सिंह	श्री भगवत सिंह	ग्राम–जगूपुरा, पो0–मोजमपुर सूरज, ब्लाक–धामपुर।	9917412401
186	बिजनौर	श्री महाराज सिंह	स्व0 श्री नत्थू सिंह	ग्राम–मिर्जापुर बकैना, पो0–बकैना, ब्लाक–जलीलपुर	9411270705
187	बिजनौर	श्री जियाउल्ला फिरोज	श्री बकाउल्ला फिरोज	मौ0–शेखान शेरकोट, पो0–शेरकोट, ब्लाक–धामपुर	9412326565
188	सहारनपुर	श्री पिताम्बर सिंह	सेहला सिंह	ग्रा0 व पो0–साल्हापुर, ब्लाक–नकुड	9719410711 9759571853
1	2	3	4	5	6
189	सहारनपुर	श्री दिग्वेन्द्र सिंह	श्री महिपाल सिंह	इस्माईलपुर माजरा, ब्लाक–नकुड	9758545854
190	सहारनपुर	श्री जोगेन्द्र सिंह	श्री रफल सिंह	गंगोत्री गुर्जर ब्लाक–नागल	9719424807
191	सहारनपुर	श्री अरूण कु0 जैन	श्री पुष्पेन्द्र कु0 जैन	सरावज्ञान नानौता ब्लाक–नानौता	9412234459
192	सहारनपुर	श्रीमती सुमनलता	पत्नी स्व0 अनिल कुमार	मुजफ्फराबाद, फतेहपुर	9719542003
193	सहारनपुर	श्री हरजेन्द्र सिंह	श्री अवतार सिंह	आसेवाला पो0–चौरादेव	9359547010
194	मुजफ्फर नगर	श्री निशान्त मलिक	श्री हरेन्द्र मलिक	गांव व डा0–काजीखेड़ा, बघरा, मु0नगर	9219577777
195	मुजफ्फर नगर	श्री धर्मेन्द्र सिंह पंवार	श्री चन्द्रपाल सिंह	509/2, मुनीम कालोनी, नई मण्डी, मु0नगर	9412210281
196	मुजफ्फर नगर	श्री अंकुर मलिक	श्री सतेन्द्र कुमार	गांव व डा0–काजीखेड़ा, बघरा, मु0नगर	9927076836
197	मुजफ्फरन गर	श्रीमती मंजू	श्री मुकेश कुमार	रामपुर तिराहा, रामपुर, मु0नगर	7078898477
198	शामली	श्री नारायण सिंह	श्री बदलू सिंह	ग्रा0–गढ़ीरक्खा, पो0–गंगेरू, ब्लाक–कांधला, शामली	9012668086
199	शामली	श्री देवेन्द्र	श्री राम सिंह	ग्रा0 व पो0–किवाना, ब्लाक–कांधला, शामली	9758755000
200	वाराणसी	श्री अखिलेश मिश्रा	स्व0 प्रेम भिखारी मिश्रा	डी0 21 इमलाक कालोनी नदेसर वाराणसी	9415331111
201	वाराणसी	मनीष राज यादव	स्व0 सुदामा	सीर गोवर्धन वाराणसी	9415619485

			प्रसाद यादव		
202	वाराणसी	श्री हर्ष मधोक	श्री दीपक मधोक	ग्राम–करसड़ा पोस्ट–बच्छाव, वाराणसी	9421452004
203	जौनपुर	श्री तनुज पाण्डेय	श्री श्याम मूर्ति पाण्डेय	ग्राम–मधुपुर, पो0–मीरापुर, ब्लाक–महराजगंज, तह0–बदलापुर, जौनपुर	9919307557
204	जौनपुर	श्री नासिर खां	श्री शमीम अहमद	ग्रा0–उत्तरपट्टी, पो0–हिन्दी बघेला, जौनपुर	9415234383
205	जौनपुर	श्री प्रदीप जायसवाल	स्व0 जगदीश जायसवाल	ग्रा0–मेहदीतला, पो0–केराकत, वि0ख0–केराकत, तह0–केराकत, जौनपुर	8948904409
1	2	3	4	5	6
206	गाजीपुर	श्री रामश्रय सिंह यादव	श्री मुख राम सिंह यादव	ग्रा0 व पो0–सलेमपुर बधाई, सादात, गाजीपुर वि0ख0–सादात, तह0–जखनियां	9452546046
207	गाजीपुर	श्री राधेश्याम सिंह	श्री राजनारायन सिंह	ग्रा0 मुगलपुरा, पो0–मारकीनगंज, ब्लाक–रेवतीपुर गाजीपुर, वि0ख0–रेवतीपुर तह0–जखनियां	9616864143
208	गाजीपुर	श्री अजीत कुमार राय	श्री रविन्द्र नाथ राय	ग्रा0 व पो0–भानमलराय, ढढ़नी–जमानियां, वि0ख0–रेवतीपुर, तह0–जमानियां	9839407000
209	गाजीपुर	श्री सत्येन्द्र सिंह यादव	श्री धर्मदेव सिंह यादव	ग्रा0 व पो0 रसूलपुर सूजनीपुर, वि0ख0–मनिहारी, तह0–जखनियां	9450024664
210	गाजीपुर	श्री राधेमोहन सिंह	स्व0 मेघबरन सिंह	ग्रा0 व पो0–करमकपुर गाजीपुर, वि0ख0–सैदपुर, तह0–सैदपुर	7706000400
211	गाजीपुर	श्री कामेश्वर सिंह	स्व0 त्रिवेणी सिंह	ग्रा0 पो0 गहमर पट्टी मैगरराय वि0ख0–भदौरा, तह0–जमानियां	9984013157

212	गाजीपुर	श्री अखिलेश कुमार सिंह	श्री नरायण सिंह	ग्राम–मानिकपुर, पोस्ट–नौबतपुर, विकास खण्ड–सैयदराजा, तहसील–सदर चन्दौली	9838966161

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0–06 का उत्तर पीछे पृष्ठ–32 पर ?)

वर्ष 2014–15 में पाठ्यक्रमवार अनुसूचित जाति छात्रों की संख्या

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	छात्र संख्या
1	2	3
1	ए0पी0जी0डी0सी0ए0	1
2	ए0डी0एफ0डी0टी0	2
3	ए0एन0एम0/हेल्थ वर्कर फीमेल	1015
4	आचार्य	98
5	बी0ए0	309033
6	बी0ए0 (एफ0डी0टी0)	4
7	बी0ए0(एम0सी0 एण्ड जे0)	32
8	बी0ए0 (एम0एस0)	6
9	बी0ए0 (टूरिज्म)	2
10	बी0ए0 एण्ड बी0एड0	43
11	बी0ए0 एण्ड एल0एल0बी0 (आनर्स)	598
12	बी0ए0 एण्ड एल0एल0बी0 (इन्टीग्रेटेड)	386
13	बी0ए0 इकोनामिक्स	16
14	बी0ए0 इंग्लिस	7
15	बी0ए0 आनर्स	786
16	बी0ए0 आनर्स अपलाईड साइकोलाजी	6
17	बी0ए0 एम0सी0	3
18	बी0ए0एम0सी0	120
19	बी0आर्क0	337
20	बी0आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट	9
21	बी0बी0ए0	10099
22	बी0बी0ए0 एण्ड एम0बी0ए0 इन्टिग्रेटेड	77
23	बी0बी0ए0 एण्ड एल0एल0बी0 इन्टिग्रेटेड	8
24	बी0बी0ए0 प्लस एम0बी0ए0 इन्टिग्रेटेड	2
1	2	3

25	बी0बी0ए0 टूरिज्म	11
26	बी0सी0ए0	5147
27	बी0काम0	16803
28	बी0काम0 एण्ड एल0एल0बी0 इन्टिग्रेटेड	3
29	बी0काम0 आनर्स	342
30	बी0काम0 प्रोफेशनल इन्टिग्रेटेड सी0ए0 एण्ड सी0एस0	25
31	बी0डी0एस0	290
32	बी0 डिजाइन	6
33	बी0ई0	75
34	बी0एड0	24402
35	बी0 एलीमेंटरी एड	321
36	बी0एफ0ए0	383
37	बी0एफ0ए0डी0	717
38	बी0एफ0एस0सी0 नाटिकल साइंस	21
39	बी0एच0एम0एस0	76
40	बी0एच0एम0सी0टी0	374
41	बी0जे0एम0सी0	206
42	बी0एल0आई0एल0सी0	242
43	बी0 लिब0	135
44	बी0 म्यूजिक	15
45	बी0आप्टोमेट्री	35
46	बी0पी0ए0 पार्ट–1 एण्ड 2	1
47	बी0पी0ई0	8
48	बी0पी0एड0	1433
49	बी0पी0टी0	306
50	बी0फार्मा0	3789
51	बी0एस0सी0	63224
52	बी0एस0सी0 बायोटेक	716
53	बी0एस0सी0 (बी0आर0डी0आई0टी0)	22
1	2	3

54	बी0एस0सी0 फूड साइंस टेक्नालाजी	11
55	बी0एस0सी0 जियोलाजी	15
56	बी0एस0सी0 हेल्थ इनफार्मेशन एडमिस्ट्रेशन	9
57	बी0एस0सी0 होम साइंस	826
58	बी0एस0सी0 हास्पिटलिटी एण्ड एडमिस्ट्रेशन	48
59	बी0एस0सी0 ह्यूमन न्यूट्रिशन	14
60	बी0एस0सी0 मेडिकल माईक्रो बायोलाजी	47
61	बी0एस0सी0 बायो केमेस्ट्री	9
62	बी0एस0सी0 बायो मेडिकल साइंस	39
63	बी0एस0सी0 आनर्स	83
64	बी0एस0सी0 इन लैब टेक्नालाजी	110
65	बी0एस0सी0 आक्युपेशनल थेरेपी	3
66	बी0एस0सी0 कृषि	3673
67	बी0एस0सी0 कला ड्राइंग संगीत	3
68	बी0एस0सी0 ई0एम0	15
69	बी0एस0सी0 फोरेंसिक साइंस	22
70	बी0एस0सी0 होटल मैनेजमेंट	7
71	बी0एस0सी0 आई0टी0	8
72	बी0एस0सी0 माईक्रो बायोलाजी	164
73	बी0एस0सी0 नर्सिंग	486
74	बी0एस0सी0 सी0एस0	45
75	बी0एस0सी0 हार्टीकल्चर	67
76	बी0टी0सी0	5444
77	बी0टेक0 प्लस एम0बी0ए0 इन्टिग्रेटेड	82
78	बी0टेक0 बायोटेक इंजीनियरिंग	28
79	बी0 टेक0	25491
80	बी0टेक0 इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल	11
81	बी0टेक0 आई0टी0	40
82	बी0टेक0 कृषि	327
1	2	3

83	बी0टेक0 बायो इंजीनियरिंग	8
84	बी0टेक0 बायो मेडिकल इंजीनियरिंग	3
85	बी0टेक0 सिविल इंजीनियरिंग	1465
86	बी0टेक0 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	267
87	बी0टेक0 कम्प्यूटर साइंस	406
88	बी0टेक0 इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्युनिकेशन	408
89	बी0टे0 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	436
90	बी0टेक0 इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्टेशन	7
91	बी0टेक0 फूड टेक्नालाजी	35
92	बी0टेक0 मैकेनिकल इंजीनियरिंग	1484
93	बी0टेक0 प्लस एम0एस0सी0 इन्टिग्रेटेड	1
94	बी0टेक0 केमिकल इंजीनियरिंग	9
95	बी0टेक0 कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	14
96	बी0यू0एम0एस0	8
97	बी0बी0ए0	24
98	बी0वी0 साइंस एण्ड एनीमल हस्बेंडरी वेट्रीनरी	50
99	सी0एम0पी0एच0	12
100	कक्षा–11	155496
101	कक्षा–12	106525
102	डी0ए0टी0 एण्ड सी0आर0एस0	24
103	डी0ए0एफ0ई0	8
104	डी0सी0ए0	315
105	डी0ई0सी0	1349
106	डी0एच0एम0सी0टी0	15
107	डी0एम0	1
108	डी0पी0ए0	2
109	डी0पी0एड0	8
110	डी0पी0एम0टी0	34
111	डी0पी0टी0	28
1	2	3

112	डी0एस0	6
113	डी0टी0डी0	43
114	डी0टी0टी0	48
115	डी0डब्लू0ई0डी0	1
116	डेन्टल हाईजीनिस्ट	8
117	डेन्टल मैकेनिक्स	5
118	डिप्लोमा इन आक्जिलरी नर्स एण्ड मिडवाईफरी	25
119	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांस0 टेक्ना0	3
120	डिप्लोमा इन सी0टी0स्कैन टेक्ना0	15
121	डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्ना0	15
122	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्ना0	65
123	डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल	2513
124	डिप्लोमा इन इमरजेंसी एण्ड ट्रामा केयर टेक्ना0	53
125	डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी	2495
126	डिप्लोमा इन लैब टेक्ना0	128
127	डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्ना0	11
128	डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्ना0	296
129	डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री	539
130	डिप्लोमा इन आर्थोटिक्स	1
131	डिप्लोमा इन पैरामेडिकल	3
132	डिप्लोमा इन फार्मेसी	530
133	डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी	592
134	डिप्लोमा इन सेनिटेशन	662
135	डिप्लोमा इन टेक्नीशियन	1
136	डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन	69
137	डिप्लोमा इन परिचय	3
138	डिप्लोमा इन प्रवेशिका पार्ट–1 व 2	3
139	डिप्लोमा इन आई0टी0	59
140	डिप्लोमा इन कृषि इंजीनियरिंग	12
1	2	3

141	डिप्लोमा इन आर्कीटेक्चरल असिसटेंशिप	6
142	डिप्लोमा इन केमिकल इंजी0	42
143	डिप्लोमा इन सिविल इंजी0	3558
144	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग	436
145	डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन एण्ड गारमेण्ट टेक्ना0	2
146	डिप्लोमा इन हियरिंग लैग्वेज स्पीच	2
147	डिप्लोमा इन होम्यापैथिक फार्मेसी	48
148	डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फो साइंस	45
149	डिप्लोमा इन मैकेनिकल आटो	7
150	डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन	3897
151	डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मैनेजमेंट	36
152	डिप्लोमा इन पेन्ट टेक्ना0	9
153	डिप्लोमा इन स्पेशल एजूकेशन	22
154	डिप्लोमा इन स्पेशल एजूकेशन एम0आर0	28
155	फैशन डिजायन एण्ड गारमेंट टेक्ना0	45
156	इंडियन डेयरी डिप्लोमा	7
157	इंडियन एण्ड कन्ट्रौल इंजीनियरिंग	14
158	इन्ट्रोडक्टरी पार्ट–1 एण्ड 2	2
159	आई0टी0आई0	6974
160	एल0एल0बी0	5772
161	एल0एल0बी0 आनर्स	182
162	एल0एल0एम0	204
163	एलएल0एम0 एक वर्ष	2
164	एम0 लाईब्रेरी एण्ड इन्फो साइंस	48
165	एम0फार्मा0 ड्रग रेग्यूलेटरी अफेयर	2
166	एम0फिल0 इंग्लिश	1
167	एम0फिल0 समाज शास्त्र	27
168	एम0फिल0 समाज कार्य	8
169	एम0एस0सी0 जीव विज्ञान	7
1	2	3

170	एम0ए0 ग्रामीण विकास प्रबन्धन	11
171	एम0ए0 डिफेंस एण्ड स्ट्रेटजिक अध्ययन	3
172	एम0ए0 भूगोल	139
173	एम0ए0 गृह विज्ञान	103
174	एम0ए0 मध्य एवं आधुनिक इतिहास	4
175	एम0ए0 सैन्य अध्ययन	1
176	एम0ए0 दर्शन शास्त्र	1
177	एम0ए0 राजनीति विज्ञान	183
178	एम0ए0 उर्दू	3
179	एम0ए0	15254
180	एम0ए0 प्राचीन भारतीय इतिहास	220
181	एम0ए0 अपलाइड अर्थशास्त्र	3
182	एम0ए0 अपलाइड मनोविज्ञान	7
183	एम0ए0 सी0सी0जे0ए0	12
184	एम0ए0 अर्थशास्त्र	630
185	एम0ए0 हिन्दी भाषा	1610
186	एम0ए0 इतिहास	404
187	एम0ए0 भौतिक शास्त्र	99
188	एम0ए0 आर0डी0	12
189	एम0ए0 संस्कृत	430
190	एम0ए0 समाज शास्त्र	2001
191	एम0ए0 मानव शास्त्र	2
192	एम0ए0 संस्कृति	11
193	एम0ए0 आपदा प्रबन्धन	3
194	एम0ए0 ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग	135
195	एम0ए0 शिक्षा शास्त्र	645
196	एम0ए0 अंग्रेजी	730
197	एम0ए0 हास्पिटल व स्वास्थ्य प्रशासन	16
198	एम0ए0 संगीत	30
1	2	3

199	एम0ए0 पी0ए0	4
200	एम0ए0 ए0ई0	6
201	एम0ए0 सहकारिता एवं	30
202	एम0ए0 पी0ए0	15
203	एम0ए0 पी0एड0	23
204	एम0ए0 बी0जे0	9
205	एम0ए0 एम0सी0	6
206	एम0ए0 वास्तुकार	7
207	एम0बी0ए0	14886
208	एम0बी0ए0 अन्तर्राष्ट्रीय बिजनेस	4
209	एम0बी0ए0 व्यापार प्रबन्धन	22
210	एम0बी0ए0 मीडिया व्यापार प्रबन्धन	2
211	एम0बी0ए0 वित्त प्रबन्धन	23
212	एम0बी0ए0 मानव संसाधन प्रबन्धन	29
213	एम0बी0ए0 आई0बी0	29
214	एम0बी0ए0 पर्यटन प्रबन्धन	2
215	एम0बी0ए0 पर्यटन	3
216	एम0बी0बी0एस0	781
217	एम0बी0ई0	13
218	एम0सी0ए0	732
219	एम0सी0(ए0)	9
220	एम0सी0जे0	14
221	एम0काम0	1133
222	एम0डी0एस0	4
223	एम0एड0	477
224	एम0एफ0ए0	5
225	एम0एफ0एम0	2
226	एम0जे0	5
227	एम0एल0एल0	1
1	2	3

228	एम0 लाइब्रेरी	16
229	एम0पी0एड0	75
230	एम0पी0एच0	6
231	एम0पी0टी0	16
232	एम0फार्मा0	255
233	एम0फिल0 पत्रकारिता एवं मास कम्यूनिकेशन	11
234	एम0फिल0 राजनीति विज्ञान	3
235	एम0फिल0	93
236	एम0फिल0 वनस्पति विज्ञान	2
237	एम0फिल0 रसायन विज्ञान	2
238	एम0फिल0 अर्थशास्त्र	8
239	एम0फिल0 शिक्षा शास्त्र	18
240	एम0फिल0 पर्यावरण विज्ञान	5
241	एम0फिल0 लाइब्रेरी साइंस	14
242	एम0फिल0 प्रबन्धन	7
243	एम0फिल0 भौतिक शास्त्र	5
244	एम0फिल0 स्टेटिस्टिक्स	1
245	एम0फिल0 जन्तु विज्ञान	3
246	एम0 सोशल वक्र	336
247	एम0एस0सी0 रसायन विज्ञान	44
248	एम0एस0सी0 गणित	57
249	एम0एस0सी0	1887
250	एम0एस0सी0 कृषि बायोटेक	2
251	एम0एस0सी0 कृषि	481
252	एम0एस0सी0 बेसिक साइंस इन्टीग्रेटेड	2
253	एम0एस0सी0 मेडिकल बायो केमेस्ट्रि	3
254	एम0एस0सी0 मेडिकल माइक्रो बायोलाजी	13
255	एम0एस0सी0 फार्मोकोलोजी	3
256	एम0एस0सी0 मेडिकल फिजियोलाजी	4
1	2	3

257	एम0एस0सी0 वनस्पति विज्ञान	76
258	एम0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान	66
259	एम0एस0सी0 भू–गर्भ विज्ञान	12
260	एम0एस0सी0 हास्पिटलिटी प्रशासन	1
261	एम0एस0सी0 माइक्रो बायोलाजी	12
262	एम0एस0सी0 भौतिक विज्ञान	12
263	एम0एस0सी0 जीव विज्ञान	28
264	एम0एस0सी0 एपलाइड रसायन विज्ञान	82
265	एम0एस0सी0 एपलाइड गणित	112
266	एम0एस0सी0 एपलाइड भौतिक विज्ञान	49
267	एम0एस0सी0 एपलाइड स्टेटिस्टिक्स	3
268	एम0एस0सी0 गृह विज्ञान	230
269	एम0एस0सी0 उद्यान	30
270	एम0एस0सी0 औद्योगिक माईक्रो बायो0	10
271	एम0एस0सी0 सूचना प्रौद्योगिकी	5
272	एम0एस0सी0 अपलाइड पशु विज्ञान	13
273	एम0एस0सी0 बायो केमेस्ट्री	37
274	एम0एस0सी0 (बायोटेक, बायो इन्फो, न्यूट्रीशन पत्रकारिता)	185
275	एम0एस0सी0 बायोमेडिकल विज्ञान	15
276	एम0एस0सी0 इलेक्ट्रानिक्स	2
277	एम0एस0सी0 फूड माइक्रो बायोलाजी एण्ड टैक्सी	4
278	एम0एस0सी0 फूड साइंस एवं टेक्नालाजी	23
279	एम0एस0सी0 फारेन्सिक विज्ञान एण्ड अपराध शास्त्र	5
280	एम0एस0सी0 नैनो साइंस एण्ड नैनो टेक्ना0	1
281	एम0एस0सी0 नर्सिंग	1
282	एम0एस0सी0 पालीमर केमेस्ट्री	4
283	एम0एस0सी0 सिस्टम बायो एण्ड बायो इन्फो0	1
284	एम0टी0ए0	31
285	एम0टेक0 नैनो टेक्ना0 एण्ड नैनो साइंस	4
1	2	3

286	एम0टेक0	564
287	एम0टेक0 बायोटेक्नालाजी	2
288	एम0टेक0 ऊर्जा एण्ड पर्यावरण	6
289	एम0टेक0 कम्प्यूटर विज्ञान टेक्ना0	10
290	एम0टेक0 मेकेनिकल इंजीनियरिंग	3
291	एम0वी0ए0	46
292	एम0वी0साइंस	4
293	मास्टर आफ स्टेटिस्टिक्स	4
294	मास्टर इन फिल्म एण्ड थियेटर	12
295	मास्टर आफ एपलाइड प्रबन्धन	314
296	एन0टी0टी0	9
297	पी0जी0डी0 इन मार्केटिंग	12
298	पी0बी0बी0एस0सी0 नर्सिंग	10
299	पी0जी0 मेडिकल डिप्लोमा	6
300	पी0जी0डी0 प्रोफेशनल बायोटेक्नालाजी	5
301	पी0जी0 डिप्लोमा	180
302	पी0जी0ए0एफ0वी0टी0	5
303	पी0जी0सी0एम0	9
304	पी0जी0डी0सी0ए0	201
305	पी0जी0डी0सी0एच0एन0	40
306	पी0जी0डी0एफ0डी0	1
307	पी0जी0डी0एफ0एम0आर0एम0	1
308	पी0जी0डी0जे0	38
309	पी0जी0डी0एम0	11690
310	पी0जी0डी0पी0पी0टी0	9
311	पी0जी0डी0टी0	2
312	पी0जी0जे0एम0सी0	13
313	पी0एच0डी0 कृषि	73
314	पी0जी0डी0 / डी0फिल0	116
1	2	3
315	पालीटेक्निक डिप्लोमा	25048

316	पालीटेक्निक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा	533
317	पालीटेक्निक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक वर्ष	23
318	शास्त्री	244
319	शिक्षाचार्य	5
320	शिक्षा शास्त्री	13
321	टी0डी0 एण्ड एम0एम0	7
322	बी0फार्मा0	22
323	विद्यावारिधि	1
281	यूनानी मेडिकल नर्सिंग	15
	योग	861474

2–वर्ष 2014–15 में पाठ्यक्रमवार अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	छात्र संख्या
1	डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल	3
2	डिप्लोमा पालीटेक्निक	45
3	डिप्लोमा सिविल	2
4	बी0एस0सी0 कृषि	1
5	बी0एस0सी0	2
6	बी0काम0	2
7	बी0ए0	8
8	कक्षा–12	1
9	डिप्लोमा मैकेनिकल	3
10	बी0एफ0ए0डी0	1
11	डी0पी0एम0टी0	1
12	एम0बी0ए0	1
13	बी0टेक0	14
14	बी0एच0एम0एस0	2
15	एम0एस0सी0	1
16	एम0बी0बी0एस0	16
	योग	103

दिनांक 27–1–2016 तक

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर पीछे पृष्ठ–34 पर) (परिशिष्ठ 'क')

फरवरी/मार्च, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान मद में स्वीकृत धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में

धनराशि लाख रु0 में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपद द्वारा प्रेषित कृषि क्षति की धनराशि	अब तक जनपदों को कुल आवंटित धनराशि	किसानों की संख्या जिन्हें कृषि निवेश अनुदान किया गया	वितरित धनराशि का विवरण	धनराशि वितरण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	बांदा	33619.89	22988.07	394083	21488.11	93.48
2	मीरजापुर	5833.92	3700.76	253284	3472.26	93.83
3	ललितपुर	35510.96	17270.60	152802	17270.59	100.00
4	महोबा	25323.00	20114.11	208725	19778.28	98.33
5	मुजफ्फरनगर	2490.23	2490.23	70049	2490.23	100.00
6	सहारनपुर	3089.76	3089.76	92279	3035.54	98.25
7	आगरा	15924.89	8443.90	200441	8333.28	98.69
8	जालौन	26683.92	20115.95	215277	14115.95	70.17
9	चित्रकूट	17186.91	13690.94	183150	12393.39	90.52
10	इटावा	6036.43	6036.43	205659	6036.43	100.00
11	आजमगढ़	5901.59	5901.59	196741	4500.00	76.25
12	कानपुर देहात	19458.65	11402.75	417927	10932.78	95.88
13	हमीरपुर	26203.98	18469.04	202963	18469.04	100.00
14	मुरादाबाद	17332.76	8093.54	134682	6118.78	75.60
15	बदायूं	5957.55	5957.55	223571	5957.55	100.00
16	सोनभद्र	19.43	25.11	382	25.11	100.00
17	इलाहाबाद	16578.82	7242.88	280276	7042.88	97.24
18	पीलीभीत	1552.80	1552.80	50582	1552.80	100.00
19	अमेठी	5766.30	3756.64	160656	3560.00	91.84
20	कन्नौज	6826.76	6826.76	149417	6270.00	91.84
21	कानपुर नगर	9301.52	8956.57	290456	8206.00	91.62
1	2	3	4	5	6	7

22	खीरी	4087.30	3136.90	159562	2535.96	80.84
23	फर्रुखाबाद	819.00	819.00	26492	801.00	97.80
24	फतेहपुर	26633.65	10395.80	186872	9597.80	92.32
25	उन्नाव	4420.59	4420.59	104359	4399.59	99.52
26	बरेली	8867.86	6752.95	260107	6483.51	96.01
27	फिरोजाबाद	11880.85	8369.82	154242	7012.82	83.79
28	औरैया	1525.96	1525.96	70052	1525.96	100.00
29	प्रतापगढ़	15444.07	7030.94	233254	4952.09	70.43
30	झांसी	35650.14	27840.97	224981	26943.08	96.77
31	फैजाबाद	2247.56	2247.56	123882	2165..84	96.36
32	रामपुर	12099.09	6847.66	143963	4366.90	63.77
33	शाहजहांपुर	13191.77	7670.21	210108	6070.21	79.14
34	मथुरा	31551.03	24857.78	281219	20785.30	83.62
35	कुशीनगर	5353.12	2807.52	169583	2783.45	99.14
36	एटा	7251.20	7251.20	145856	6505.52	89.72
37	बुलन्दशहर	15100.73	8889.44	159009	7105.20	79.93
38	बलिया	4588.59	3302.82	122082	2602.82	78.81
39	गोरखपुर	5906.39	3869.60	77185	3167.11	81.85
40	सम्भल	13467.87	10900.00	188126	10054.58	92.24
41	हापुड़	2996.54	2996.54	59580	2996.54	100.00
42	गौतमबुद्धनगर	5651.60	3347.04	41202	2547.00	76.10
43	हाथरस	12104.77	5293.69	73342	3983.24	75.25
44	शामली	668.31	891.08	17933	896.24	100.58
45	मैनपुरी	14064.44	8450.00	149789	6750.00	79.88
46	अलीगढ़	7206.44	3885.00	180019	3385.00	100.00
47	कासगंज	1554.40	1554.00	47478	1554.40	100.00
48	कौशाम्बी	7160.22	3385.00	102544	3182.07	94.00
49	बहराइच	201.23	248.49	9572	248.49	100.00
50	बाराबंकी	10131.38	4135.00	231859	4134.98	100.00
51	सुल्तानपुर	2833.95	2725.51	142160	2425.48	88.99
52	बागपत	489.76	489.76	16705	489.76	100.00
53	अमरोहा	5745.80	3285.00	99584	3275.24	99.70
54	गाजीपुर	27055.95	7962.67	173552	7695.00	96.64
1	2	3	4	5	6	7
55	लखनऊ	11188.00	4435.00	88715	3035.00	68.43

56	गाजियाबाद	583.96	583.96	17866	583.96	100.00
57	रायबरेली	19153.05	6085.00	205653	6084.93	100.00
58	हरदोई	22768.29	6635.00	284849	6416.38	96.70
59	मऊ	510.00	510.00	32252	510.00	100.00
60	अम्बेडकरनगर	4539.14	3185.00	122467	2185.00	68.60
61	सीतापुर	27812.63	7135.00	259472	6485.00	90.89
62	मेरठ	754.01	754.01	21143	754.01	100.00
63	संतरविदासनगर	2867.19	2867.19	85502	2365.51	82.50
64	वाराणसी	5489.64	3435.00	121785	2838.99	82.65
65	जौनपुर	10972.68	3885.00	141236	2401.66	61.82
66	चन्दौली	12893.04	4485.00	91660	4481.41	99.92
67	देवरिया	7455.78	3235.00	63761	2385.00	73.72
68	सिद्धार्थनगर	1259.43	1259.43	26597	1259.43	100.00
69	बस्ती	16264.38	4135.00	104697	3935.00	95.16
70	गोण्डा	15.12	15.12	479	15.12	100.00
71	श्रावस्ती	1.68	1.68	43	1.68	100.00
72	महराजगंज	590.76	590.76	19665	590.76	100.00
73	संतकबीरनगर	4224.56	2885.00	49444	2053.29	71.17
		753894.91	**449829.03**	**10206941**	**403353.28**	

नान मानसून सत्र में सूखे से हुई क्षति हेतु दी गयी धनराशि

दिनांक 27–01–2016 तक

लाख रु0 में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	SMF	Non SMF	कुल SMF+Non SMF	दी गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	ALLAHABAD	1258.79	843.33	2102.12	450.00
2	AMBEDKAR NAGAR	3913.52	244.08	4157.60	450.00
3	BALRAMPUR	1287.23	81.60	1368.83	450.00
4	BANDA	5675.21	1790.95	7466.17	450.00
5	CHITRAKOOT	3229.05	1786.33	5015.37	450.00
1	2	3	4	5	6
6	DEORIA	15973.07	1217.57	17190.63	450.00

7	FATEHPUR	2516.68	477.09	2993.77	450.00
8	GORAKHPUR	13632.41	952.95	14585.36	450.00
9	HAMIRPUR	925.41	498.44	1423.85	450.00
10	JALUN	198.97	151.63	350.60	150.00
11	JHANSI	3955.42	2631.33	6586.74	450.00
12	KANPUR NAGAR	110.86	30.07	140.93	100.00
13	KUSHINAGAR	4179.96	168.94	4348.90	450.00
14	LALITPUR	11129.48	6918.86	18048.35	450.00
15	MAHARAJGANJ	140.42	17.68	158.10	100.00
16	MAHOBA	5223.56	2217.21	7440.76	450.00
17	MAU	8230.82	583.61	8814.42	450.00
18	MIRZAPUR	3371.91	2944.40	6316.30	450.00
19	SANTKABIR NAGAR	6034.69	308.46	6343.15	450.00
20	SONBHADRA	5844.74	1362.61	7207.35	450.00
21	UNNAO	18840.77	1817.57	20657.67	450.00
		115672.28	**27044.69**	**142716.97**	**8450.00**

खरीफ 2015 में प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं की समेकित प्रगति

परिशिष्ट–ख

क्र0 सं0	जनपद	योनजा का नाम	क्रियान्नयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी	बीमित कृषकों की संख्या	बीमित क्षेत्र (हे0 में)	बीमित राशि (लाख रु0 में)	प्रीमियम (लाख रु0 में)				भुगतान की स्थिति लाख रु0 में
							कृषक अंश	केन्द्र द्वारा अनुदान	राज्य द्वारा अनुदान	कुल प्रीमियम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहारनपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	5691	3839	3639.91	73.22	5.21	5.21	83.64	आंकलन प्रगति पर
2	मुजफ्फरनगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	2634	2186	2517.71	42.16	0.12	0.12	42.40	आंकलन प्रगति पर
3	गौतमबुद्ध नगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	2974	2573	1558.23	35.53	11.84	11.84	59.21	आंकलन प्रगति पर
4	हाथरस	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	11908	12623	3737.33	106.69	35.56	35.56	177.81	आंकलन प्रगति पर
5	फिरोजाबाद	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	29390	28656	8096.83	168.17	47.20	47.20	262.57	आंकलन प्रगति पर
6	बदायूं	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	9791	9139	3213.67	92.19	30.53	30.53	153.25	आंकलन प्रगति पर
7	बिजनौर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	1966	1389	982.55	18.75	1.26	1.26	21.27	आंकलन प्रगति पर
8	अमरोहा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ	10698	8768	4115.48	84.21	24.96	24.96	134.13	आंकलन प्रगति पर

		बीमा	इण्डिया लि0								
9	रामपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	53628	63102	23225.16	486.03	159.84	159.84	805.71	आंकलन प्रगति पर
10	कानपुर देहात	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	22192	19744	8143.23	217.98	77.59	77.59	373.16	आंकलन प्रगति पर
11	प्रतापगढ़	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0	15484	10535	5009.68	137.97	45.99	45.99	229.95	आंकलन प्रगति पर
		एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 योग		**166356**	**162554**	**64239.78**	**1462.90**	**440.10**	**440.10**	**2343.10**	**आंकलन प्रगति पर**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	जौनपुर	मौसम व संशोधित बीमा	बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	26574	16056	2034.83	122.09	273.91	273.91	669.91	628.50 भुगतान हुआ
13	सुल्तानपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	10673	8486	3511.68	105.35	51.80	51.80	208.95	आंकलन प्रगति पर
		बजाज एलायंज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0		**37247**	**24542**	**5546.51**	**227.44**	**325.71**	**325.71**	**878.86**	
14	मथुरा	मौसम व संशोधित बीमा	चोलामण्डल एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	60848	74983	10273.62	616.42	1175.53	1175.53	2967.48	285.00 भुगतान हुआ
		चोलामण्डल एम0एस0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 योग		**60848**	**74983**	**10273.62**	**616.42**	**1175.53**	**1175.53**	**2967.48**	
15	मैनपुरी	मौसम व संशोधित बीमा	फ्यूचर जनराली जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	19178	15227	2844.00	170.64	274.61	274.61	719.86	800.00 भुगतान हुआ
16	मिर्जापुर	मौसम व संशोधित बीमा	फ्यूचर जनराली जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	45263	54733	7734.53	464.08	866.00	866.00	2196.08	1800.00 भुगतान हुआ
		फ्यूचर जनराली जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 योग		**64441**	**69960**	**10578.63**	**634.72**	**1140.61**	**1140.61**	**2915..94**	

17	शामली	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	78	80	134.41	2.78	0.93	0.93	4.64	आंकलन प्रगति पर
18	मेरठ	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	310	330	49.32	1.06	0.35	0.35	1.76	आंकलन प्रगति पर
19	बागपत	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	61	12	5.95	0.12	0.03	0.03	0.18	आंकलन प्रगति पर
20	गाजियाबाद	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	147	115	86.92	1.34	0.21	0.21	1.76	आंकलन प्रगति पर
21	हापुड़	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	303	240	268.10	7.00	2.75	2.75	12.50	आंकलन प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	एटा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	5338	4457	1807.03	58.77	22.84	22.84	104.45	आंकलन प्रगति पर
23	शाहजहांपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	11925	7819	1718.30	103.09	141.76	141..76	386.61	743.93 भुगतान हुआ
24	सम्भल	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	10964	8198	3578.61	70.97	12.92	12.92	96.81	आंकलन प्रगति पर
25	फर्रुखाबाद	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	9956	7999	2650.36	126.64	78.81	78.81	283.26	भुगतान प्रारम्भ
26	इटावा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	10481	10615	2149.74	70.17	27.97	27.97	126.11	भुगतान प्रारम्भ
27	कानपुर नगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस	24697	18516	6624.81	221.12	121.96	121.96	465.04	भुगतान प्रारम्भ

		बीमा	कम्पनी लि0								
28	कौशाम्बी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	30	22	11.57	0.40	0.20	0.20	0.80	भुगतान प्रारम्भ
29	ललितपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	60914	52102	9653.07	464.90	321.97	321.97	1108.84	531.18 भुगतान हुआ
30	बांदा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	36469	55972	6057.20	330.90	275.02	275.02	880.94	233.99 भुगतान हुआ
31	गोण्डा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	1861	2956	2692.21	80.33	30.85	30.85	142.03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	बहराइच	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	19191	16898	5879.74	222.62	111.31	111.31	445.24	भुगतान प्रारम्भ
33	श्रावस्ती	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	7274	7147	2667.04	85.58	41.03	41.03	167.64	भुगतान प्रारम्भ
		एच0डी0एफ0सी0 एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 योग		**199999**	**193478**	**46034.38**	**1846.79**	**1190.91**	**1190.91**	**4228.61**	
34	अलीगढ़	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	31847	34974	18166.73	556.30	233.68	233.68	1023.66	भुगतान प्रारम्भ
35	पीलीभीत	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	41108	50972	18126.68	519.34	209.06	209.06	937.46	भुगतान प्रारम्भ
36	औरैया	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	23781	21600	8577.87	273.29	107.35	107.35	487.99	भुगतान प्रारम्भ
37	जालौन	संशोधित राष्ट्रीय कृषि	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल	55578	162414	20139.78	1212.76	1616.06	1616.06	4444.88	भुगतान प्रारम्भ

		बीमा	इन्श्योरेंस कम्पनी लि0								
38	वाराणसी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	6302	3834	2017.66	65.87	32.89	32.89	131.65	भुगतान प्रारम्भ
39	गाजीपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	22215	15929	6855.13	321.79	160.90	160.90	643.59	भुगतान प्रारम्भ
40	गोरखपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	13367	9363	4484.08	157.17	78.58	78.58	314.33	आंकलन प्रगति पर
41	कुशीनगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	12349	9816	4988.00	131.73	39.00	39.00	209.73	आंकलन प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	रायबरेली	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	58526	41275	13612.97	816.78	511.95	511.95	1840.68	5563.12 भुगतान हुआ
43	सीतापुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	68368	35402	23587.26	722.37	333.15	333.15	1388.67	भुगतान हुआ
44	खीरी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	39505	24386	20945.09	510.28	155.48	155.48	821.24	15.38 भुगतान हुआ
45	फैजाबाद	मौसम व संशोधित बीमा	आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	21118	14831	3254.70	195.28	250.61	250.61	696.50	1222.01 भुगतान हुआ
		आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 योग		**394064**	**424796**	**144755.95**	**5482.96**	**3728.71**	**3728.71**	**12940.33**	
46	बुलन्दशहर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	4750	10850	3300	66	0	0	66	भुगतान प्रारम्भ

47	बरेली	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	24400	23070	16087.62	482.6	206.2	206.2	895	आंकलन प्रगति पर
48	हमीरपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	22180	37077	5995.53	260.74	144.57	144.57	549.88	आंकलन प्रगति पर
49	महोबा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	19710	39415	2738.93	165.48	194.31	194.31	554.1	240.00 भुगतान हुआ
50	बलिया	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	8633	8648	2000	120	94.5	94.5	309	भुगतान प्रारम्भ
51	महराजगंज	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	17810	21360	6229.77	154	51.33	51.33	256.66	भुगतान प्रारम्भ
52	बस्ती	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	15950	14450	4370	131.1	64.24	64.24	259.58	भुगतान प्रारम्भ
53	सिद्धार्थनगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	14960	13610	5754.15	152.6	50.87	50.87	254.34	भुगतान प्रारम्भ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	संतकबीर नगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	8810	9550	3716.67	111.50	39.21	39.21	189.92	आंकलन प्रगति पर
55	लखनऊ	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	4250	5065	2833.33	85.00	41.08	41.08	167.16	भुगतान प्रारम्भ
56	अमेठी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	27700	20500	9000.00	450.00	270.00	270.00	990.00	आंकलन प्रगति पर
		इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 योग		**169153**	**203595**	**62026**	**2179.02**	**1156.31**	**1156.31**	**4491.64**	

57	कासगंज	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	529	471	264.44	6.91	2.38	2.38	11.67	आंकलन प्रगति पर
58	आगरा	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	11917	11436	3297.32	100.53	47.60	47.60	195.73	आंकलन प्रगति पर
59	मुरादाबाद	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	15491	17429	5220.92	207.50	236.41	236.41	680.32	1138.00 भुगतान हुआ
60	इलाहाबाद	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	9918	11158	5036.36	173.54	86.79	86.79	347.12	आंकलन प्रगति पर
61	चित्रकूट	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	31538	30998	6229.07	272.42	136.31	136.31	545.04	343.00 भुगतान हुअ
62	चंदौली	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	6589	8233	3883.56	97.25	32.45	32.45	162.15	आंकलन प्रगति पर
63	भदोही	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	1129	730	336.66	14.98	7.49	7.49	29.96	आंकलन प्रगति पर
64	मऊ	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	9184	6482	3160.60	94.82	43.93	43.93	182.68	आंकलन प्रगति पर
65	देवरिया	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	1665	1563	592.27	17.80	8.57	8.57	34.94	आंकलन प्रगति पर
66	उन्नाव	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	33716	27519	12635.56	469.72	239.59	239.59	948.90	आंकलन प्रगति पर
67	हरदोई	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	33520	26989	13364.91	509.44	253.22	253.22	1015.88	आंकलन प्रगति पर

68	अम्बेडकर नगर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	20611	9216	4376.93	149.21	74.59	74.59	298.39	आंकलन प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	बाराबंकी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	36994	22302	9590.57	365.32	182.64	182.64	730.60	आंकलन प्रगति पर
70	बलरामपुर	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	2054	1492	912.98	25.24	11.16	11.16	47.56	आंकलन प्रगति पर
		रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 योग		**214855**	**176018**	**68902.15**	**2504.68**	**1363.128**	**1363.128**	**5230.94**	
71	कन्नौज	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	22524	22313	5812.13	241.00	120.50	120.50	482.00	भुगतान प्रारम्भ
		रिलायन्स जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0		**22524**	**22313**	**5812.13**	**241.00**	**120.50**	**120.50**	**482.00**	
72	फतेहपुर	मौसम व संशोधित बीमा	टाटा ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	54479	53159	7424.20	445.45	969.60	969.60	2384.65	1800.00 भुगतान हुआ
		टाटा ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0		**54479**	**53159**	**7424.20**	**445.45**	**969.60**	**969.60**	**2384.65**	
73	झांसी	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	160609	353001	23683.99	1410.55	1708.15	1708.15	4826.55	42.61 भुगतान हुआ
74	सोनभद्र	मौसम व संशोधित बीमा	यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	25259	40179	4268.83	256.13	542.16	542.16	1340.45	भुगतान प्रारम्भ
75	आजमगढ़	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा	यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0	15453	9762	5953.70	247.67	123.84	123.84	495.35	2.42 भुगतान हुआ
		यूनीवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0		**201321**	**402942**	**33906.52**	**1914.35**	**2374.15**	**2374.15**	**6662..35**	

		योग	**1585287**	**1808340**	**459499.82**	**17555.73**	**13985.26**	**13985.26**	**15525.95**	16119.14 का भुगतान हुआ

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

नत्थी 'ध'

जनपद फिरोजाबाद की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों की मदवार आय

(धनराशि लाख रु0 में)

आय के मद	वित्तीय वर्ष 2014–15				
	फिरोजाबाद	टुण्डला	सिरसागंज	शिकोहाबाद	योग जनपद फिरोजाबाद
मण्डी शुक्ला	214.15	509.44	564.16	432.82	1720.57
विकास सेस	53.54	127.37	141.04	108.73	430.68
लाइसेन्स शुल्क	1.35	0.73	0.81	0.74	3.63
प्रपत्र आदि की बिक्री	0.24	0.34	0.33	0.37	1.28
विनियोजित धन पर ब्याज	1.44	1.89	1.17	2.14	6.64
ऋण की वापसी (कर्मचारियों से)	1.38	0.36	0.41	0.11	2.26
भवन/दुकान/कैण्टीन का किराया/अग्रिम	19.38	5.43	8.96	8.46	42.23
दुकान/कैण्टीन/भूमि की बिक्री/प्रीमियम	19.94	78.31	0.41	91.94	190.60
शमन शुल्क	1.88	6.59	3.83	5.80	18.10
बकाया मण्डी शुल्क पर ब्याज	0.52	4.07	0.48	4.07	9.14
अन्य	2.44	3.32	27.29	1.04	34.09
कुल आय (ऋण/अनुदान को छोड़कर)	**316.26**	**737.85**	**748.89**	**656.22**	**2459.22**

जनपद फिरोजाबाद की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों की मदवार आय

(धनराशि लाख रु0 में)

आय के मद	वित्तीय वर्ष 2013–14				
	फिरोजाबाद	टुण्डला	सिरसागंज	शिकोहाबाद	योग जनपद फिरोजाबाद
मण्डी शुल्क	177.90	495.39	477.64	390.30	1541.23
विकास सेस	44.47	123.85	119.41	97.71	385.44
लाइसेन्स शुल्क	1.38	0.68	0.75	0.80	3.61
प्रपत्र आदि की बिक्री	0.25	0.40	0.26	0.36	1.27
विनियोजित धन पर ब्याज	1.76	2.39	1.13	1.95	7.23
ऋण की वापसी (कर्मचारियों से)	1.18	0.12	0.21	0.12	1.63
भवन/दुकान/कैण्टीन का किराया/अग्रिम	16.94	5.99	9.17	7.58	39.68
दुकान/कैण्टीन/भूमि की बिक्री/प्रीमियम	45.69	118.45	4.30	8.96	177.40
शमन शुल्क	2.07	5.14	3.18	2.56	12.95
बकाया मण्डी शुल्क पर ब्याज	0.37	2.97	0.76	5.10	9.20
अन्य	20.69	1.51	3.47	3.87	29.54
कुल आय (ऋण/अनुदान को छोड़कर)	**312.70**	**756.89**	**620.28**	**519.31**	**2209.18**

पी0एस0यू0पी0–एल0 101 विधान सभा (155)–10–8–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।